Registration No. RAJBIL /2016 / 69093
OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

लघु उद्योग भारती

UDYOG TIMES

Volume - 09 Issue - 10 August - 2026
Total Pages - 152 Price - Rs. 100

नमो नेतृत्व

अविश्वसनीय, अविस्मरणीय एवं अतुलनीय

Celebrating Leadership,
Celebrating Progress,
Celebrating India.

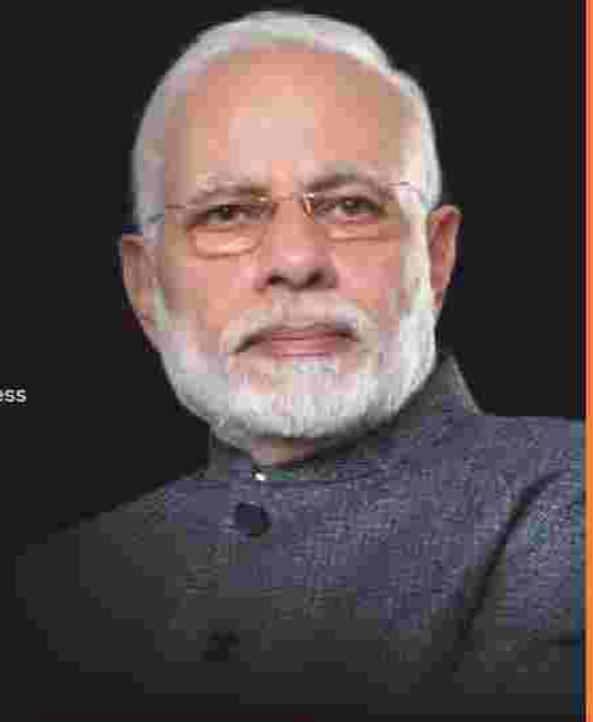

Heartiest Congratulations & Best Wishes to our
Hon'ble Prime Minister of India
A distinguished journey of visionary leadership, purposeful progress & transformative development, strengthening India's journey towards a brighter future.

India Moving Towards Viksit Bharat

HURON

JYOTI

1,40,000+
Installations across 62 Countries

Finest Range of CNC Machines

Turning / Turn-Mill Centers | Vertical Machining Centers
Horizontal Machining Centers | 5-Axis Machining Centers | Multi-Tasking Machining Centers

JYOTI CNC AUTOMATION LIMITED

Plot No. G-506 & 2839, Lodhika GIDC, Vill. Metoda, Dist : Rajkot-360021, Gujarat(India)

T +91-2827-235100/101 | E. info@jyoti.co.in, sales@jyoti.co.in | jyoti.co.in

UDYOG TIMES

OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

Volume -9 Issue - 10 Aug. 2026

Editorial Board

- *Patron*

Shri Madhusudan Dadu, National President	098102-56494
Shri Prakash Chandra ji, National Org. Secretary	099299-93660
Shri Om Prakash Gupta, National Gen. Secretary	095602-55055

- *Editor*

Dr. Kirti Kumar Jain	094141-90383

- *Co-Editor*

Dr. Sanjay Mishra	098295-58069

विवरणिका

Editorial	03
प्रधान सेवक का कोटिश: अभिनन्दन	04
लघु उद्योगों के सर्वांगीण की सार्थक यात्रा– प्रकाश चंद्र	05
हमारा उद्देश्य – राष्ट्रोद्धारो लघूद्यमै:	07
प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन – सदानंद सप्रे	09
लाल किले से प्रधानमंत्री का उद्बोधन	13
मोदी सरकार के 12 वर्ष – अश्वनी महाजन	27
कवर स्टोरी – नमो नेतृत्व	33
विशेष संस्मरण	41
विशेष आलेख –	
पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री	61
अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल, सूचना–प्रसारण मंत्री	65
डॉ. जितेन्द्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री, विज्ञान एवं तकनीक	71
शोभा करंदलाजे, केंद्रीय राज्य मंत्री, एमएसएमई	79
उद्यम यात्रा – घनश्याम औझा, राजस्थान	83
विशेष आलेख –	
भूपेंद्र भाई पटेल, मुख्यमंत्री, गुजरात	87
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र	91
भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री, राजस्थान	97
प्रमोद सावत, मुख्यमंत्री, गोवा	103
नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री, हरियाणा	109
रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली	114
मोहन चरण माझी, मुख्यमंत्री, उड़ीसा	117
सुवेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल	121
ब्रजेश पाठक, उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	125
डिजिटल भारत से एआई भारत की यात्रा	128
GST Reforms	133
12 Years of Banking Reforms	136
India's Defining Startup under NaMo Regime	141
Industry Academia Initiative	147
LUB's Office Bearers Nominated to Boards/ Committee	148

Annual Membership: Rs. 1200 Including Postage

Corporate & Head Office :
Shri Vishwakarma Bhawan 48, Deen Dayal Upadhyay Marg, Rouse Avenue, New Delhi-110002
Website : www.lubindia.com
Email : headoffice@lubindia.com
Ph.: 011-23238582
Registered Office :
Plot No. 184, Shivaji Nagar, Nagpur-440011 Ph.: 0712-2533552

PM Modi as the 'Yug Purush' of Independent India..

Editorial

Dr. Kirti Kumar Jain
kkjain383@gmail.com

One who thinks ahead by 1,000 years, one who has confidence at an extreme level, one who sees self-discipline in Indians, and one who works hard for 20 hours per day in a positive way-he is our great Prime Minister, Hon. Narendra Damodardas Modi.The list of the Modi Government's schemes is uncountable. The leaders of the whole world follow them and see the growth of India.The main slogan of the Prime Minister is 'Vocal for Local', by adopting the spirit of Swadeshi.India's GDP is the highest in the world, accelerating at 7.8% in the last quarter (the first quarter of 2026–27) despite numerous challenges. This reflects the country's strong economic fundamentals and the collective efforts of its people.Prime Minister Modi says-- "We have to move forward with our dreams, resolve and strength." - India has envisioned a very big dream: when we mark 100 years of independence in 2047, we will have built a Viksit Bharat with firm solutions. - We must believe in ourselves and take pride in building an Aatmanirbhar Bharat.- Sectors that were once seen as "No-Go Areas" are now "Go-Ahead Areas." - Every Indian is embracing the spirit of Make in India and Vocal for Local. - India has a stable political mandate, a stable government, a vibrant democracy, a strong judicial system, and a Constitution that guides us all.- We need to focus on three things: cost, quality, and scale. - Our factories must be competitive, our products should be user-friendly, and our packaging must be the best. - Places once affected by Naxal violence are witnessing peace, development, and new hope.- In the coming years, we will drive India forward and take the nation to new heights. - India is continuing to grow rapidly on the path of development.I want to know your views. ❑❑❑

प्रधान सेवक का कोटिशः अभिनन्दन

तन समर्पित, मन समर्पित और
यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ
देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ !

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री

श्री नरेंद्र मोदी जी

को

राष्ट्र में सुशासन तथा
सुराज की स्थापना करने एवं
सर्वाधिक निर्वाचित काल
सर्वाधिक सेवा काल
सर्वाधिक प्रामाणिक एवं प्रेरक काल
के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

17 सितंबर, 2026 को आपके
76वें जन्मोत्सव पर हम आपकी दीर्घायु,
स्वस्थ जीवन और आपके कुशल और
गतिशील नेतृत्व में भारत के निरंतर
अग्रसर होने की कामना करते हैं।

लघु उद्योग भारती

सर्वदा सद्भावी

समस्त उद्यमी एवं सदस्य गण

लघु उद्योग भारती

लघु उद्योगों के संरक्षण और संवर्धन की सार्थक यात्रा के तीन दशक

अंतस के उदगार
प्रकाश चंद्र
राष्ट्रीय संगठन महामंत्री,
लघु उद्योग भारती

लघु उद्योग भारती

ब्रिटिश इतिहासकार एंगस मैडिसन की पुस्तक 'द वर्ल्ड इकोनॉमीः ए मिलेनियल पर्सपेक्टिव' में भारत की ऐतिहासिक जीडीपी और विश्व अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी के बारे में बताया गया कि प्राचीन काल में विश्व जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 24 प्रतिशत थी। लेकिन कालांतर में ब्रिटिश हुकूमत ने योजनापूर्वक हमारे कुटीर और लघु उद्योगों को खत्म कर दिया, जो भारत की समृद्धि का प्रमुख स्रोत रहे हैं। इन्हीं लघु उद्योगों के संरक्षण, संवर्धन और कल्याण के लिए लघु उद्योग भारती संगठन निरंतर मिशन मोड पर कार्य कर रहा है।

उद्योग–हित, राष्ट्र–हित के ध्येय के साथ लघु उद्योग भारती का ये स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि देश का युवा नौकरियों की ओर न भागे, बल्कि वो उद्यमी बने और रोजगार सृजन में भागीदार बने। क्योंकि 2047 तक आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप उद्यमिता के माध्यम से ही संभव है। यहां के इम्पोर्टर अब एक्सपोर्टर बनें और दूसरे देशों पर उनकी निर्भरता कम हो तथा उनके गुणवत्तापरक उत्पाद कम लागत में तैयार हो सकें, इस उद्देश्य के लिए संगठन निरंतर कार्यरत है।

लघु उद्योग भारती ने एमएसएमई सेक्टर के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ समन्वित प्रयासों से नीति–निर्माण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, B2B ट्रेड फेयर– India Manufacturing Show - IMS एवं India Industrial Fair -IIF, महिला उद्यमियों के उत्पादों की B2C स्वयंसिद्धा प्रदर्शनी, डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट, तथा इंडस्ट्री – एकेडेमिया इनिशिएटिव सहित कौशल विकास से स्वरोजगार और स्वावलंबन के कार्य किये हैं। संगठन ने CSIR, IIM, IIT, BITS, GeM एवं अन्य उच्च संस्थानों के साथ एमओयू किये हैं। संगठन ITI संस्थानों के पाठ्यक्रमों को भी युगानुकूल अपडेट करने में संलग्न है।

Working State	**27**
Districts	**581**
Industry Members	**66476**
Female Members	**5577**
Total Units	**1105**
Women's Units	**62**

वैश्विक आर्थिक बदलावों की आधारभूमि

21वीं सदी के प्रारम्भ से ठीक पहले विकसित राष्ट्रों से निकली उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की तेज आंधी ने विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक मोर्चे पर बुनियादी परिवर्तन के साथ कई चुनौतियां पैदा कर दी। भारत भी इस वैश्विक बदलावों से कैसे अछूता रहता! अमेरिका और यूरोप की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गहरी दिलचस्पी भारत के बड़े उपभोक्ता बाजार पर तो पहले से ही रही थी। और उसी दौर में उन कंपनियों के आउटलेट्स गरीबी से जूझते हुए विकास की आकांक्षी योजनाओं के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में भारत जैसे विकासशील देशों में खुलने शुरू हुए। भ्रामक और लुभावने डिजिटल विज्ञापनों के साथ भारतीय जनमानस तक इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स पहुँचने लगे थे। यही वो समय था जब उन बड़े निगमों से हमारे लाखों–करोड़ों सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को संरक्षित करने की चिंता प्रकट की गई और उस पर प्रभावी पहल भी की गई।

लघु उद्योग भारती की स्थापना–

वर्ष 1994 में राम जन्मभूमि आंदोलन के मुख्य रणनीतिकार एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख और बौद्धिक प्रमुख रहे श्री मोरोपंत पिंगले जी की दूरदर्शिता से लघु उद्योग भारती की स्थापना श्री विश्वामित्र

बहल जी की अध्यक्षता में की गयी। लघु उद्योगों के संरक्षण की दिशा में इस युगांतकारी पहल के प्रबल पैरोकारों में श्री सुदर्शन सरीन जी, श्री अनंत राव भिड़े जी, श्री कृष्ण आग्रेय जी, श्री विश्राम जामदार जी, श्री शंकर तामहन जी और श्री दयानन्द खरे जी के साथ श्री (डॉ.) श्यामसुन्दर अग्रवाल जैसे प्रेरक उद्यमी सम्मिलित रहे थे जिन्होंने राष्ट्रोद्धारो लघूद्यमैः के श्रेयस्कारी ध्येय के साथ लघु उद्योग भारती के वट वृक्ष का बीज बोया।

निर्यात में एमएसएमई की बड़ी हिस्सेदारी–

संगठन के संस्थापक और नीति–नियंता ये जानते थे कि विश्व में स्थाई व सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए लघु उद्योगों को अग्रणी–तंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। और ये भी कि लघु उद्योगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने के साथ जीडीपी व निर्यात का बड़ा हिस्सा माना जाता है। चूंकि भारत इसमें कोई अपवाद नहीं था, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उनकी सुरक्षा और सतत विकास की आवश्यकता महसूस की गई।

एमएसएमई मंत्रालय गठन और नए बदलाव–

दशकों से बड़े पूँजी निवेश के कारण सरकार का ध्यान सिर्फ बड़े उद्योगों की तरफ ही रहता था और छोटे तथा मझले उद्योग सर्वथा उपेक्षित थे। लघु उद्योग भारती के सतत प्रयत्नों से केंद्र सरकार में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के लिए एक अलग मंत्रालय सृजित हुआ। साथ ही सूक्ष्म व लघु उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को राष्ट्रीय श्रम आयोग के लिए मनोनीत किया गया। गौरतलब है कि देश की कुल औद्योगिक इकाइयों में 98 प्रतिशत सूक्ष्म उद्योग हैं, जिन्हें 2006 में एसएमई एक्ट को एमएसएमई एक्ट करके अलग पहचान दिलवाई गई। सरकारी खरीद में भी न्यूनतम 20 प्रतिशत की खरीद सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से करवाने में भी संगठन ने विशेष प्रयास किये।

उत्पाद समूह की रचना–

सम्पूर्ण देश के विविध औद्योगिक क्षेत्रों और विविध उद्योगों से समस्याएं जब बड़ी संख्या में आने लगी, तो उसके प्रभावी समाधान के लिए संगठन ने सेक्टर वाइज उत्पाद समूहों की रचना की जिससे उनकी समस्याओं और संभावनाओं पर समग्र अध्ययन कर कार्य किया जा सके और नीति–निर्धारण में भी संगठन बेहतर योगदान कर सके। कुल 26 उत्पाद समूहों में शामिल हैं– फूड एंड एग्रो, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, फार्मास्युटिकल्स, पॉलिमर्स–प्लास्टिक–रबर, पेपर

सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र

प्रोडक्ट्स एंड पेपर पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स–ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, लेदर, माइंस एंड मिनरल्स, फुटवियर एंड फुटवियर कॉम्पोनेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कन्संट्रक्शन प्रोडक्ट्स, हार्डवेयर एंड फिटिंग्स, ऑटोमोटिव एंड व्हीकल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड आईटी, जनरल इंजीनियरिंग, फॉउंडरी फेरस एंड नॉन फेरस, सोलर एनर्जी इक्विपमेंट्स, एग्री इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड वुडेन, स्टील, मशीनरी मैन्युफैक्चरर, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड कटलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, एम्ब्रेला।

कौशल विकास में नयी भूमिका–

एमएसएमई सेक्टर में स्किल्ड मैनपावर की चुनौती को ध्यान में रखते हुए संगठन ने कौशल विकास केंद्रों की रचना शुरू की। जयपुर में सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना इसी दिशा में उठाया गया कदम था। इसके बाद जोधपुर, बालोतरा, सिलीगुड़ी, भोपाल एवं बैंगलोर में स्किल सेंटर्स का निर्माण हुआ। इसी तरह अजमेर के पालड़ा, उदयपुर, जालोर, ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, लखनऊ और गांधीनगर में कौशल केंद्र निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में देशभर के 16 प्रदेशों के 47 कौशल केंद्रों पर प्रशिक्षण कार्य जारी है। 13 तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में करीब 17 हजार युवक–युवतियां प्रशिक्षित हो चुके और उनमें से 250 ने स्वयं का उद्योग स्थापित भी कर लिया।

राजस्थान के पाली शहर में संगठन की पहल पर अत्याधुनिक 8700 सिलाई मशीनें, चूड़ी पर नगीने लगाने की 850 मशीनें एवं मिटटी के कुल्लड़ बनाने की 30 से भी अधिक मशीनें कम कीमत और आसान किश्तों पर स्वरोजगार के लिए विशेषकर महिलाओं को प्रदान की गई। साथ ही मेहंदी और सौंदर्य सज्जा में प्रशिक्षित 800 महिलाएं समेत 20 हजार से अधिक को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है। यहां संचालित 4 प्रकल्पों की सफलता ने देशभर में इसे 'पाली मॉडल' के नाम से पहचान दिलाई। ○○○

हमारा उद्देश्य - राष्ट्रोद्धारो लघूद्यमैः

Wide Angle

Madhu Sudan Dadu
National President
Laghu Udyog Bharati
president@lubindia.com

Om Prakash Gupta
National General Secretary
Laghu Udyog Bharati
gs@lubindia.com

National Head Quarter, New Delhi

Across the globe, the contribution of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is highly valued. Their participation is measured in terms of employment, GDP contribution, and exports, and they are accorded priority in policymaking. For a nation like India, with its population of 1.4 billion, assigning a special status to this sector is absolutely essential.

India possesses a highly dynamic economy; consequently, MSMEs must scale up their capabilities in step with this momentum, or else they risk missing out on emerging opportunities. Even if government policies are not implemented at the grassroots level as expected, we must not let the opportunity slip away.

लघु उद्योग भारती की अखिल भारतीय उपस्थिति और 32 वर्षों के अनुभव को देखते हुए केवल समस्या उठाने वाले संगठन से आगे बढ़कर एमएसएमई में ग्रोथ एंड इंप्लीमेंटेशन नेटवर्क के रूप में विकसित किया जा सकता है। विकसित भारत में वास्तविक योगदान तभी दिखेगा, जब हम सरकारी योजनाओं के बिना भी R&D, स्किल, टेक्नोलॉजी और मार्केट अपॉर्च्युनिटी सीधे सदस्य उद्यमियों में लागू करवा सकें और उनके परिणाम भी मापे जा सकें।

इसका यह मतलब कदापि नहीं कि योजनाओं का लाभ हमें ना मिले। उसके लिए भी हमें प्रयासरत रहना ही होगा। लघु उद्योग भारती अपने प्रस्तावित कार्य मॉडल को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर व इकाई स्तर तक प्रत्येक औद्योगिक संकुल तक पहुंचाने के ध्येय के साथ काम कर रही है। आज लघु उद्योगों को मूल्य संवर्धन की दिशा में, नए उत्पादों के निर्माण, नई तकनीक से भविष्य की आवश्यकता को भांपते हुए कार्य करना होगा। प्रत्येक प्रदेश में एक टेक्नोलॉजी नोडल टीम बनाकर उनके माध्यम से CSIR -इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिशन के तहत उद्योगों के लिए R&D और एक इनोवेशन नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है।

विकसित भारत के लिए लघु उद्योग भारती का प्रस्तावित कार्य मॉडल

- **प्रत्येक प्रदेश में MSME Scheme & Technology Nodal Team**

इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनुभवी उद्यमी कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाकर CSIR & Industry Technology Transfer Mission

CSIR, IIT, NIT, MSME Technology Centres एवं अन्य संस्थानों में उपलब्ध तकनीकों की Sector-wise Technology Catalogue बनाकर प्रत्येक प्रदेश स्तर की टीम के साथ समन्वय बनाकर सभी सदस्यों के सामने रखने का कार्य कर रही है। प्रत्येक Product Group का लक्ष्य है कि हर वर्ष कुछ तकनीकों को वास्तविक उद्योगों में लागू कराया जाए।

- **उद्योगों के लिए R&D और Innovation Network**

छोटे उद्योग स्वयं बड़ा R&D खर्च नहीं कर सकते, इसलिए LUB विश्वविद्यालयों, CSIR Labs और तकनीकी संस्थानों के साथ Industry-Academia R&D Projects विकसित कर, Product Development, Import Substitution, automation और Cost Reduction पर विशेष ध्यान रखते हुए कार्य कर रही है।

- **Skill Development को Demand-Based बनाना**

पहले उद्योगों से पूछा जाए कि उन्हें किस Skill की आवश्यकता है, फिर उसी आधार पर ITI, Skill Centres, NSDC और अन्य संस्थानों के साथ प्रशिक्षण कराया जाए। प्रशिक्षण का लक्ष्य केवल Certificate नहीं, बल्कि Employment और Productivity Improvement हो। इसके लिए लघु उद्योग भारती का प्रयास है कि सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि सभी प्रदेशों में, छोटे शहरों में भी अपने स्वयं के कौशल प्रशिक्षण केंद्र बने व अन्य संगठनों के साथ भी मिलकर भविष्य के लिए कौशल प्रशिक्षण का कार्य करें। आने वाले समय में ऐसे केंद्रों में 50000 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

- **Market Linkage Mission**

सदस्यों को GeM, PSU Procurement, Corporate Vendor Development, Export, E-commerce, Buyer & Seller Meets और Exhibitions से जोड़ने का कार्य भी किया गया है। प्रत्येक Product Group के लिए संभावित Buyers, PSUs और Export Markets की सूची तैयार की जा रही है व उनसे संपर्क भी स्थापित किये जा रहे हैं।

- **अपने सभी सदस्यों के लिए " Ease of Doing Business Help Desk" स्थापित किया जा रहा है।**

GST, Pollution, Factory Licence, BIS, Power, Banking, GeM, Export या अन्य regulatory समस्याओं को व्यक्तिगत शिकायत की जगह Data-based Collective Representation के रूप में सरकार के सामने रखा जाता है और आगे के लिए इस व्यवस्था को और सुचारू ढंग से चलाने का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है।

- **सफल उद्योगों को "Model MSME" बनाने का प्रयास**

सदस्यों को नई तकनीक, सरकारी योजना, Skill program, Solar, Automation, Export या R&D से लाभ दिलवा कर, उनकी Before & After Case Study कर– जैसे उत्पादन कितना बढ़ा, लागत कितनी घटी, रोजगार कितना बढ़ा और export कितना बढ़ा। इन सब आंकड़ों को संकलित कर दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनाने का प्रयास किया जाता है

- **LUB Website / Digital Knowledge Platform**

एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर Schemes + Technology + Skill + Market + Experts + Success Stories + Government Circulars उपलब्ध हैं। सदस्य अपने उद्योग और राज्य के आधार पर आवश्यक जानकारी आसानी से खोज सकते हैं।

- **उत्पाद समूह को Execution Engine बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।**

हर Product Group को केवल बैठक तक सीमित न रखकर सालाना लक्ष्य दिए जा रहे हैं–Technology Transfer, Skill Training, GeM Registration, Exporters, R&D Projects, BIS/Quality Adoption और Government Scheme beneficiaries की संख्या के लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं।

- **सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था: परिणाम मापना**

हर राज्य और Product Group के लिए एक "Viksit Bharat MSME Dashboard" द्वारा वर्ष भर के आंकड़े इकट्ठे कर हर प्रकार से आकलन किया जाएगा।

कितने उद्योगों ने योजना का लाभ लिया, कितनी Technology Transfer हुई, कितने लोगों को Skill Training मिली, कितने नए Exporters बने, कितने GeM/PSU Vendors बने, कितने R&D Projects हुए, कितनी Cost Saving / Turnover Growth हुई, कितना नया Employment सृजित हुआ।

इस पूरी पहल का एक प्रभावी सूत्र हो सकता है:

"ज्ञान से क्रियान्वयन, तकनीक से उत्पादकता, कौशल से रोजगार और बाजार से समृद्धि – विकसित भारत में लघु उद्योगों की भागीदारी।"

- **'योजना से उद्योग तक'– अभियान**

केंद्र एवं राज्य सरकार की एमएसएमई योजनाओं की सरल जानकारी तैयार कर उन्हें जिला एवं इकाई स्तर तक पहुंचाने का कार्य भी हम करते रहेंगे। प्रत्येक योजना के लिए पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और संपर्क अधिकारी की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराने की भी चेष्टा करेंगे।

इस मॉडल से लघु उद्योग भारती यह प्रमाणित कर सकेगी कि उसने केवल MSME की समस्याएँ सरकार तक नहीं पहुँचाईं, बल्कि सरकारी नीतियों और तकनीकों को जमीन पर उद्योगों में लागू कराकर रोजगार, उत्पादन, निर्यात और आत्मनिर्भरता बढ़ाने का कार्य किया।

लघु उद्योग भारती कार्यकर्ताओं का एक संगठन है। वे सभी निष्काम भाव से "राष्ट्रहित में उद्योग हित" के ध्येय और समर्पण भाव से कार्यरत हैं।

○○○

भारतीय अर्थचिंतन की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता

मंथन

सदानन्द दामोदर सप्रे

प्रख्यात चिंतक एवं सेवानिवृत्त प्राध्यापक

NIT **भोपाल**

sapresd@gmail.com

भारत के बारे में ऐसा संभ्रम है कि यहाँ केवल आध्यात्मिक उन्नति का ही विचार किया जाता है, भौतिक उन्नति का नहीं; जब कि भारत में चार सर्वमान्य पुरुषार्थों में से (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) दो आध्यात्मिक क्षेत्र के हैं (धर्म और मोक्ष) और दो भौतिक क्षेत्र के हैं (अर्थ और काम)। इस तरह भारतीय चिंतन में आध्यात्मिकता और भौतिकता में सुंदर समन्वय है, जो मानव मात्र के लिए आवश्यक है। (इसीलिए अपने लौकिक–आध्यात्मिक ज्ञान और उसे निःस्वार्थ भाव से दूसरों को देनेवाले स्वभाव के कारण जहाँ एक ओर भारत को "विश्व गुरु" कहा जाता था, वहीं दूसरी ओर अपनी भौतिक संपन्नता के कारण ही उसे "सोने की चिड़िया" भी कहा जाता था!)

अन्य सभी चिंतनों के अनुसार भारतीय चिंतन में भी मानव जीवन का लक्ष्य है – सुख प्राप्त करना। परंतु जहाँ अन्य चिंतनों में सुख बाह्य वस्तुओं में है ऐसा माना जाता है, वहीं भारतीय चिंतन कहता है कि सुख मन के अंदर है और वह व्यक्ति की चित्त–वृत्ति पर निर्भर करता है। मानव का स्वभाव ऐसा है कि एक अकेला व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। वह अपने आसपास के लोगों को भी सुखी देखना चाहता है, क्योंकि उन के दुख के कारण उस के सुख में बाधा पड़ती है। इसीलिए भारत में अपने आराध्य की प्रार्थना करते समय केवल व्यक्तिगत सुख की कामना नहीं की जाती; कहा जाता है – "सर्वे भवन्तु सुखिनः" (सब सुखी हों), "भवतु सब्ब मंगल" (सभी का मंगल/कल्याण हो), "सरबत दा भला" (सब का

भला हो)। जब भी किसी का मंगल होता है, कल्याण होता है, भला होता है तब वह सुखी होता है। (इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारत में की जानेवाली इन सभी प्रार्थनाओं में "सब" के सुख की कामना की गई है, केवल "भारतवासियों" के सुख की नहीं!)

भारतीय बनाम पश्चिमी अर्थचिंतन

पश्चिमी चिंतन में व्यक्ति के निजी सुख का विचार है। अतः उन की आर्थिक दृष्टि का (उन के अर्थचिंतन का) लक्ष्य है व्यक्ति का निजी सुख, जब कि भारतीय चिंतन में सब के सुख का विचार है। अतः हमारी आर्थिक दृष्टि का (हमारे अर्थचिंतन का) लक्ष्य है सब का सुख। इसलिए दोनों ही अर्थतंत्र अपने–अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर बने हैं, अतः स्वाभाविक रूप से वे कई मामलों में अलग–अलग हैं।

पश्चिमी चिंतन व्यक्ति केंद्रित है और उस में व्यक्ति को मुख्यतः केवल शरीर ही माना जाता है। इस की तुलना में उस में मन और बुद्धि को बहुत कम माना जाता है और आत्मा को तो उस से भी कम माना जाता है। अतः उन के चिंतन के अनुसार निजी सुख में मुख्यतः शरीर के सुख का ही विचार है।

भारतीय चिंतन में व्यक्ति का विचार शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा इस तरह समग्रता से किया जाता है। इस के साथ ही भारतीय चिंतन में सब के सुख का विचार है, अतः इस में निजी सुख के साथ सब के सुख का विचार है। दूसरों के सुख का विचार कोई व्यक्ति तभी कर सकता है जब वह उन्हें भी अपना मानता है, अपने जैसा मानता है। "एक ही परमात्म तत्त्व सब में है" (सर्वं खल्विदं ब्रह्म) ऐसा विचार हो तभी यह संभव है और यही आध्यात्मिकता है। इसलिए सब के सुख में भौतिकता और आध्यात्मिकता ये दोनों ही विचार हैं। इसलिए भारत का अर्थतंत्र "जियो और जीने दो" (Live and let live) इस सोच पर आधारित होना चाहिए, क्यों कि तभी सब सुखी होंगे।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थचिंतन

भारतीय चिंतन में अर्थ और काम का विचार तो है, लेकिन वह अनियंत्रित न होकर धर्म द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। ("धर्म" का अर्थ "religion" नहीं।) इसलिए हमारे यहाँ कितना कमाया इस से महत्त्वपूर्ण है कैसे कमाया। (धर्म–सुसंगत मार्ग से या धर्म–विरुद्ध मार्ग से?) इसी तरह कितना कमाया इस से महत्त्वपूर्ण है, कितना बांटा। काम की पूर्ति के लिए उपभोग करने की मनाही नहीं है, परंतु वह धर्म द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। इसलिए भारत में "संयमित उपभोग", "त्यागपूर्वक उपभोग" (तेन त्यक्तेन भुंजीथाः) के लिए कहा गया है। इस के लिए "इंद्रियनिग्रह" आवश्यक है।

(यद्यपि भारतीय चिंतन में कैसे कमाया, कितना बांटा, संयमित उपभोग, इंद्रियनिग्रह इत्यादि बातें हैं; परंतु इस का अर्थ यह नहीं कि इस में धन कमाने को बुरा माना गया है। अपने यहाँ तो कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति ने इतना तो कमाना ही चाहिए कि गृहस्थ जीवन के आवश्यक कर्तव्य (रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और अतिथि सत्कार) पूरे किए जाने के अलावा, पर्व–त्यौहार और अन्य विशेष दिन अच्छी तरह मनाए जा सकें तथा परिवार के सदस्यों की स्वाभाविक और उचित इच्छाओं की पूर्ति की जा सके। यह सब करने के बाद भविष्य की दृष्टि से बचत और समाजोपयोगी काम भी उस कमाई में से होना चाहिए।)

संयमित उपभोग के कारण स्वतः ही खर्च कम होकर बचत अधिक होती है। (कोरोना महामारी का भारत के लोगों पर और यहाँ की अर्थव्यवस्था पर सब से कम दुष्परिणाम होने का एक प्रमुख कारण है – हमारे परिवारों का बचत करने का स्वभाव!)

भारतीय अर्थचिंतन में कमाने के उपाय बताने के साथ ही लौटाने (giving back) के मार्ग भी बताए जाते हैं, क्यों कि भारतीय संस्कृति में उऋण होने को बहुत महत्व दिया गया है और giving back वाला विचार उसी दिशा का है।

भारत की आर्थिक व्यवस्था मानव केंद्रित होनी चाहिए, धन केंद्रित या लाभ केंद्रित या साधन केंद्रित या प्रौद्योगिकी केंद्रित नहीं। इसलिए वह सह अस्तित्व और पारस्परिक सहयोग की भावना पर आधारित होनी चाहिए। (पश्चिमी चिंतन भी अब धीरे–धीरे इसी दिशा में आ रहा है। इसीलिए अब वहाँ "मानवीय चेहरे वाला विकास पथ" (Path of development with human face) इस तरह की बात कही जाने लगी है। इसी तरह वहाँ अब प्रबंधन विज्ञान में कहा जाने लगा है – Love men, manage means (जब कि पहले वहाँ कहा जाता था – Love means, manage men.)

हमारे यहाँ सब के सुख का विचार होने के कारण अर्थार्जन के अवसर सब को उपलब्ध हों ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए स्व–रोजगार, स्व–रोजगार समूह, सहकारिता आधारित उद्योग, कुटीरोद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग, बहुराष्ट्रीय भारतीय उद्योग इत्यादि सभी को भारत में

फलने–फूलने का अवसर उपलब्ध होना चाहिए। भारत में "योग्यतम की उत्तरजीविता" वाली (Survival of the fittest) स्थिति नहीं होनी चाहिए, जो पश्चिमी अर्थतंत्र में साधारणतः होती है। इसलिए प्रत्येक छोटे स्तर के उद्योग की रक्षा हो और उसे फलने–फूलने का अवसर मिले इस दृष्टि से उस से बड़े स्तर के उद्योगों के लिए कुछ "क्या करें – क्या नहीं" (Dos - don'ts) होने चाहिए। इस के कारण "निर्बलतम की उत्तरजीविता" (Survival of the weakest) सुनिश्चित होती है, जो हमारी संस्कृति की विशेषता है।

कुछ छोटे स्तर के उद्योगों का बड़े स्तर के उद्योगों के लिए पूरक होना सब के फलने–फूलने में सहायक होता है। भारत में विकेंद्रित उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस बात की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है कि यद्यपि अपने यहाँ mass production के स्थान पर production by masses को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, किंतु फिर भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ उद्योगों द्वारा mass production किया जाना भी आवश्यक है। अतः किसी भी अतिरेक की ओर न जाते हुए उपरोक्त दोनों में उचित संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। (कहा ही गया है कि – Perfection is not an extreme, it lies in maintaining balance.)

उत्पादन के खर्चे पर आधारित लाभकारी मूल्य तो रखना चाहिए, परंतु सब का सुख हमारा लक्ष्य होने के कारण वह मूल्य ग्राहक का आर्थिक शोषण करते हुए अत्यधिक लाभ देने वाला (महंगा) न रहे, इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्वावलंबिता एवं स्वदेशी

यद्यपि हम ने पूर्ण रूप से स्वावलंबी होना चाहिए, परंतु फिर भी हमें कुछ वस्तुओं का आयात तो करना ही पड़ता है। परंतु इस के कारण देश का स्वाभिमान, संप्रभुता और सुरक्षा इन तीनों बातों को कोई आंच न आए, इस बात की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। अतः जिन देशों से हमें आयात करना पड़ता है उन देशों को यदि हम निर्यात भी करते हैं तो यह बात सरलता से हो जाती है। (यदि "लेन–देन" होता है तो दोनों में बराबरी के आधार पर परस्पर सहयोग होता है, परंतु यदि हम केवल "लेन–लेन" ही करते हैं तो हम उन से छोटे माने जाते हैं।)

स्वावलंबिता की तरह स्वदेशी का विचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल "देश में निर्मित वस्तु बनाम विदेश में निर्मित वस्तु" तक सीमित नहीं है। यह अपने आप में एक दर्शन है और उस में से उत्पन्न एक भाव है।

जनता के लिए स्वदेशी याने – जो घर में बन सकता है वह बाजार से नहीं लेना, जो अपने गांव/शहर में बन सकता है वह दूसरे गांव/शहर से नहीं लेना, जो अपने देश में बनता है वह किसी दूसरे देश में बना हुआ नहीं लेना और जो अपने देश में नहीं बनता परंतु जीने के लिए आवश्यक है केवल उतना ही विदेश में बना हुआ लेना, परंतु यथासंभव उस के बिना जीने का प्रयास करना।

शासन के लिए स्वदेशी याने – जो देश में नहीं बन सकता, केवल वही किसी ऐसे देश से लेना जिस से अपने अच्छे संबंध हों और अपनी शर्तों पर लेना। साथ ही यथाशीघ्र वह अपने देश में बन सके, ऐसी व्यवस्था करना। यदि मित्र देश से न मिल सकता हो तो जनता से उस के बिना जीने का आह्वान करना, परंतु जिस से अपने संबंध अच्छे न हों, ऐसे किसी भी देश से नहीं लेना।

इस तरह यदि भारत में अपने अर्थचिंतन की मूलभूत बातों को यथावत रखते हुए उन्हें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कालसुसंगत बनाकर अपनी आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं, तो भारत पुनः सही अर्थ में विकसित होकर संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है।

○○○

शहरी विकास से बढ़ेंगी सुविधाएं और खुशहाली

शहरी विकास के लिए
कुल ₹33,504 करोड़ का आवंटन

- बड़े शहरों में बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए **सणंद, कलोल, बारडोली, सावली** और **हीरासर को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा,** जिन्हें रीजनल ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ा जाएगा
- गांधीनगर में **नमो सेंट्रल लाइब्रेरी** तथा अन्य महानगरों में **डिजिटल लाइब्रेरी** बनाने के लिए कुल **₹150 करोड़** का प्रावधान
- **स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना** के तहत शहरी बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के लिए **₹16,116 करोड़** का प्रावधान
- राज्य के **32 शहरों** को **जीवनधारा योजना** के तहत **शुद्ध पेयजल** उपलब्ध कराया जाएगा
- **वायर-फ्री सिटी मिशन** के अंतर्गत शहरों में **मौजूदा बिजली लाइनों को भूमिगत** किया जाएगा
- अहमदाबाद को **ओलंपिक-रेडी सिटी** बनाने और **SVP स्पोर्ट्स एन्क्लेव** के विकास के लिए **₹500 करोड़** का आवंटन
- अहमदाबाद और सूरत मेट्रो विस्तार सहित **गुजरात मेट्रो रेल प्रोजेक्ट** के लिए **₹2,217 करोड़** का आवंटन
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)** के तहत गरीब परिवारों के आवास निर्माण के लिए **₹1,420 करोड़** का प्रावधान

"शहरी विकास से सुविधा और खुशहाली बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। यह ऐतिहासिक बजट गुजरात के शहरों को **'विकसित भारत'** का रोल मॉडल बनाएगा।"

- श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

आजादी के 100वें वर्ष 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र

सप्तधाराएं देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी- पीएम मोदी

जन गण मन
उद्योग टाइम्स डेस्क

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी ने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और महान क्रांतिकारियों को आदरपूर्वक नमन किया जिन्होंने बलिदान की महान परंपरा को जागृत किया। उन्होंने कहा कि भारत के पास एक स्थिर राजनीतिक जनादेश, एक स्थिर सरकार, एक जीवंत लोकतंत्र, एक मजबूत न्यायिक प्रणाली और एक संविधान है जो हम सभी का मार्गदर्शन करता है।

गरीबों का आर्थिक जीवन बदला

प्रधानमंत्री ने 2047 तक देश को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में बदलने के दृढ़ संकल्प की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों में मानव सशक्तिकरण और आर्थिक परिवर्तन पर इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 25 करोड़ नागरिकों ने गरीबी को हराया है और भारत 'फ्रैंजाइल फाइव' से सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया है।

श्री मोदी ने कहा, "भारत ने एक अविश्वसनीय नई गति पकड़ी है, और अब 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य को रोकना असंभव है।"

तेज गति से हुई तरक्की

पिछले 12 वर्षों में विनिर्माण, डिजिटल विकास और नागरिक वितरण में भारत की प्रगति का एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रक्षा उत्पादन में लगभग 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग में 5 गुना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में लगभग 7 गुना, रेलवे कोच उत्पादन में 21 गुना और मोबाइल फोन निर्माण में 33 गुना वृद्धि हुई। डिजिटल नवाचार में, इंटरनेट उपभोक्ता 4 गुना बढ़े, पेटेंट अनुदान में 4 गुना वृद्धि हुई, और डिजिटल लेनदेन 100 गुना बढ़ गया, जबकि नल जल के कनेक्शन के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं में 15 गुना तेजी से वृद्धि हुई, एलपीजी

"हमारी सरकार की नीयत, नीतियां और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा के साथ सशक्त बना रहे हैं।"
- नरेन्द्र मोदी
ग्रामीण विकास से बढ़ता जन-जन का विश्वास
नॉन स्टॉप हरियाणा
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना - 6248 गांवों में लाल डोरे के भीतर 25.16 लाख प्रापर्टी कार्ड बनाए।
सरपंच ई-टेंडरिंग के बिना अपनी ग्राम पंचायतों में 21 लाख रुपये तक के विकास कार्य करवा सकते हैं।
सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद् सदस्यों को दी जाने वाली पेंशन में बढ़ोतरी।
जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 'हर घर-नल से जल योजना' - 30.41 लाख घरों में नल से जल उपलब्ध।
हरियाणा पढ़ी-लिखी पंचायतों वाला राज्य है।
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी।
पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग 'ए' को 8 प्रतिशत आरक्षण।
आई.टी. युक्त ग्राम सचिवालय योजना - 2531 ग्राम सचिवालयों की स्थापना।
सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा

कनेक्शन का 6 गुना तेजी से विस्तार हुआ, शौचालयों का निर्माण 4 गुना और पक्के घर 3 गुना तेजी से बनाए गए और सैकड़ों अप्रचलित कानूनों को समाप्त किया गया।

विदेशी आयात नहीं, स्वदेशी विनिर्माण

मजबूत आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव की पूर्ण आवश्यकता पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने सस्ते विदेशी आयात पर निर्भरता की धारणा को दृढ़ता से खारिज कर दिया, इसके बजाय सक्रिय रूप से शक्तिशाली घरेलू क्षमताओं का निर्माण करने वाली पहलों की वकालत की। प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर के महत्वपूर्ण वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला कि तीन घरेलू संयंत्र पहले से ही चालू हैं और वैश्विक बाजारों में चिप्स का निर्यात कर रहे हैं, जबकि एक प्रमुख नीतिगत घोषणा करते हुए कि 1 से 2 वर्षों के भीतर 7 से 8 नई उत्पादन सुविधाएं चालू हो जाएंगी।

संसाधन सुरक्षा की रणनीतिक आवश्यकता का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने बजट में घोषित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे के शुभारंभ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि व्यापक अंतरराष्ट्रीय समझौतों ने भारत को विश्व स्तर पर एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े कदम

तकनीकी प्रगति को बढ़ती ऊर्जा मांगों से जोड़ते हुए, प्रधानमंत्री ने शांति अधिनियम के तहत ऐतिहासिक ऊर्जा सुधारों पर प्रकाश डाला और फास्ट ब्रीडर परमाणु प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने के साथ 6 से 7 वर्षों के भीतर 5 नए रिएक्टरों के चालू होने के साथ 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक प्रमुख नीतिगत घोषणा की।

'नो–गो एरिया' अब 'गो–अहेड एरिया'

राष्ट्रीय संसाधन अन्वेषण में गंभीर रूप से बाधा डालने वाली पिछली प्रतिबंधात्मक नीतियों की आलोचना करते हुए, प्रधानमंत्री ने घरेलू तेल और गैस विकास में एक साहसिक बदलाव पर प्रकाश डाला, समुद्र तट के 99 प्रतिशत हिस्से को 'नो–गो एरिया' से 'गो अहेड एरिया' में परिवर्तित किया और नए ऊर्जा भंडार को खोलने के लिए 85,000 करोड़ रुपये की समुद्र मंथन पहल द्वारा समर्थित व्यापक अपतटीय संचालन शुरू किया।

वैकल्पिक ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने 12 साल की व्यापक उपलब्धियों के साथ ठहराव की तुलना की, यह देखते हुए कि सिटी गैस वितरण 70 से बढ़कर 700 शहरों तक हो गया, पाइप से रसोई गैस 1.75 करोड़ घरों तक पहुंच गई, और सौर क्षमता 2 गीगावॉट से बढ़कर 160 गीगावॉट हो गई।

नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से मध्यम वर्ग को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभों का विवरण देते हुए, प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की तीव्र सफलता पर प्रकाश डाला कि मुफ्त सौर बिजली योजना ने बिजली बिलों को प्रभावी ढंग से शून्य तक कम करने और अधिशेष बिजली बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए प्रति परिवार 80,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके 50 लाख घरों को पार कर लिया है।

रेलवे के बुनियादी ढांचे में आधुनिक दक्षता के साथ ऐतिहासिक ठहराव की तुलना करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की नीतियों से 90 वर्षों में केवल 30 प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ, जबकि वर्तमान सरकार ने बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने के लिए केवल एक दशक में नेटवर्क–व्यापी कवरेज हासिल किया। भविष्य के ईंधनों में एक बड़ी सफलता की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने अपनी पहली मेड–इन–इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन पर काम शुरू कर दिया है, जिसे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन के रूप में विकसित किया जा रहा है।

वैश्विक संकटों में सरकार और जनता ने दिखाई सूझबूझ

2047 के विकास लक्ष्यों की दिशा में उथल–पुथल भरी यात्रा और यूक्रेन और पश्चिम एशिया में कोविड–19 महामारी और

अनंत अनादि
वडनगर
वडनगर म्यूज़ियम
भारत का पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरिएंशियल म्यूज़ियम
यहाँ इतिहास को सिर्फ़ देखें नहीं, बल्कि इसे महसूस करें और जियें भी!
AR, VR, 3D प्रोजेक्शन और इंटरैक्टिव वॉकवे के माध्यम से वडनगर की
गौरवशाली प्राचीन धरोहर को और भी करीब से महसूस करें।
वडनगर म्यूज़ियम की विशेषताएँ
गुजरात का गर्व
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जन्मभूमि तथा वैश्विक धरोहर
पुरातत्व स्थल
50 मीटर वॉकवे के माध्यम से देखें वास्तविक पुरातत्व स्थल
आधुनिक तकनीक
AR/VR और 3D प्रोजेक्शन से इतिहास को बनाएँ एक नया और जीवंत अनुभव
5,000+ कलाकृतियाँ
सिक्के, आभूषण और कई अन्य कलाकृतियाँ
हर उम्र के लिए यादगार अनुभव
प्राचीन ज्ञान, अतीत से जुड़ाव और अपने इतिहास व संस्कृति पर गर्व
vadnagararchaeologymuseum.com
वडनगर संग्रहालय गुजरात की प्राचीन विरासत, समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को
आधुनिक प्रस्तुति शैली के माध्यम से दुनिया के सामने जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है।
– श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

भू–राजनीतिक संघर्षों जैसे गंभीर वैश्विक संकटों से निपटने पर विचार करते हुए, प्रधानमंत्री ने भारत के लचीलेपन की सराहना की और दुर्भावनापूर्ण अफ़वाहें और भय फैलाने वालों की तीखी आलोचना की। घरेलू किसानों को गंभीर वैश्विक आर्थिक झटकों से बचाने में सरकार की अत्यधिक सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कृषि कल्याण के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 3,000 रुपये यूरिया 300 रुपये से कम में और 5,000 रुपये से अधिक की लागत वाले डीएपी को केवल 1,350 रुपये में उपलब्ध कराने के लिए भारी लागत वहन की है।

भारत स्वीकृत और गहराई से सम्मानित देश बन रहा

देश के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय सम्मान का श्रेय एक स्थिर राजनीतिक जनादेश और जीवंत लोकतंत्र को देते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस मान्यता प्राप्त घरेलू स्थिरता ने 2014 के बाद लगभग 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को सफलतापूर्वक सुगम बनाया है, जिससे कृषि, मत्स्य पालन, कपड़ा और एमएसएमई में बड़े पैमाने पर निर्यात के अवसर खुले हैं। घरेलू उद्योगों से बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसरों का आक्रामक रूप से लाभ उठाने का आग्रह करते हुए, प्रधानमंत्री ने लुधियाना और तिरुपुर से लेकर तटीय समुद्री खाद्य केंद्रों तक भारतीय उत्पादों के लिए गुणवत्ता और समग्र सामर्थ्य में अंतरराष्ट्रीय मानकों को सख्ती से पार करके वैश्विक बाजारों पर हावी होने के लिए एक साहसिक जनादेश निर्धारित किया।

राष्ट्रीय कार्य संस्कृति, सोच और निष्पादन की गति में आमूलचूल परिवर्तन की मांग करते हुए, प्रधानमंत्री ने देश के मेहनती कार्यबल में अपार विश्वास व्यक्त करते हुए पिछले दशकों में गंभीर रूप से रुके हुए पांच से सात वर्षों के भीतर पूरा करने का एक आक्रामक लक्ष्य निर्धारित किया। संरचनात्मक परिवर्तन के लिए प्रशासन की अथक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि व्यापक शासन और प्रशासनिक बदलाव बाहरी मजबूरी के बजाय गहन आंतरिक विश्वास से सख्ती से संचालित होते हैं। उन्होंने सहकारी संघवाद का आह्वान किया, जहां केंद्र, राज्य और समाज अगले स्तर के सुधारों को चलाने के लिए एकजुट होते हैं।

सप्त सिंधु की प्राचीन सभ्यतागत शक्ति का आह्वान करते हुए, प्रधानमंत्री ने एक शक्तिशाली नए रणनीतिक ढांचे की घोषणा की और परिवर्तनकारी सप्तधारा या सप्त शक्ति का अनावरण करके भारत की अगली छलांग की दिशा में एक भविष्य का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शक्ति की ये सात गतिशील धाराएं, युवाओं की अपार क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करते हुए, देश को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएंगी।

गुजरात

द सेमीकंडक्टर हब

सेमीकंडक्टर उद्योग बना साणंद की नई पहचान

सेमीकंडक्टर सेक्टर में गुजरात ने रचा इतिहास

- सेमीकंडक्टर सेक्टर में गुजरात ने लगभग **₹1.24 लाख करोड़** का निवेश आकर्षित किया है।
- राज्य में **50,000** से अधिक **प्रत्यक्ष** एवं **अप्रत्यक्ष** रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- सेमीकंडक्टर नीति घोषित करने वाला **गुजरात** देश का पहला राज्य।
- **धोलेरा SIR** में 28 नैनोमीटर चिप प्रोडक्शन से भारत को नई औद्योगिक पहचान मिलेगी।
- धोलेरा को **'सेमीकंडक्टर-रेडी'** स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- IIT गांधीनगर में **₹194.21 करोड़** की लागत से संचालित **'SAMARTH'** पहल के अंतर्गत अगले **5 वर्षों में 2,600 से अधिक विशेषज्ञ इंजीनियर** तैयार किए जाएंगे।

माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। साणंद अब केवल गुजरात का ही नहीं बल्कि नए भारत की **सेमीकंडक्टर क्रांति** का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। **-हर्ष संघवी,** उपमुख्यमंत्री, गुजरात

विनिर्माण शक्ति–

प्रधानमंत्री ने पूर्ण घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं में छोटे घटकों और बड़े पैमाने पर अंतिम उत्पादों दोनों में महारत हासिल करके विनिर्माण क्षेत्र का आक्रामक रूप से विस्तार करने का आह्वान किया, जिसमें शून्य–दोष परिशुद्धता, लागत दक्षता और वैश्विक पैमाने और गुणवत्ता के लिए एक समझौता न करने वाली प्रतिबद्धता पर सख्त ध्यान देने की मांग की गई। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, "डिजाइन से लेकर संपूर्ण विनिर्माण तक, भारत को निश्चित रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अत्यधिक विश्वसनीय केंद्र बनना होगा।'

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण–

प्रधानमंत्री ने रसायन मुक्त खेती के लिए एक राष्ट्रव्यापी परिवर्तन का समर्थन किया और एकीकृत कृषि–से–निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं की दिशा में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने का आग्रह किया, जिससे पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थ तेजी से बढ़ते वैश्विक बाजारों में निर्बाध रूप से परिवर्तित हो सकें।

प्रौद्योगिकी और नवाचार–

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष, उन्नत रोबोटिक्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और मेड–इन–इंडिया 6जी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में नवाचार का अंतिम केंद्र बनने के लिए केवल एक वैश्विक बाजार के रूप में आगे बढ़ना चाहिए।

PM GatiShakti
National Master Plan for Multi-Modal Connectivity

गति शक्ति–

प्रधानमंत्री ने निर्बाध मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स बनाने के लिए एक प्रभावी बुनियादी ढांचे में बदलाव को अनिवार्य किया, जिसमें हाई–स्पीड रेल, आधुनिक राजमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग और बंदरगाह–आधारित विकास के अत्यधिक गतिशील केंद्रों में बंदरगाह को शामिल किया गया है।

रक्षा शक्ति–

प्रधानमंत्री ने पूर्ण रणनीतिक आत्मनिर्भरता को एक अनिवार्य राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया, जिसमें ड्रोन, काउंटर–ड्रोन सिस्टम और हाइपरसोनिक्स सहित अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों का निर्यात करके एक अग्रणी वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने के भारत के लक्ष्य पर जोर दिया गया।

साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय रक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में तैयार करते हुए, प्रधानमंत्री ने देश की डिजिटल सीमाओं और वैश्विक साइबर परिदृश्य दोनों की आक्रामक रूप से रक्षा करने के लिए भारतीय युवाओं की अपार डिजिटल क्षमता का उपयोग करने पर जोर दिया।

हरियाणा सरकार

"भारत के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार जनता को सशक्त बना रही है।"
- नरेन्द्र मोदी

ऊर्जा से सुनहरा भविष्य सुनिश्चित

अक्तूबर, 2014 के बाद एच.वी.पी.एन.एल. ने 83 नए सब-स्टेशन चालू किए। इसके अतिरिक्त, वर्तमान सब-स्टेशनों में 719 ट्रांसफार्मर स्थापित, 3027.80 किलोमीटर की प्रसारण लाइनें बिछाई गईं। इन प्रसारण कार्यों पर कुल 6466.92 करोड़ रुपये की राशि खर्च।

बिजली आपूर्ति प्रणाली में सुधार लाने तथा बिजली चोरी रोकने के लिए 'फीडर सैनिटेशन प्रोग्राम' शुरू।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी अविद्युतिकृत घरों को विद्युतिकृत किया गया।

घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों को निगम द्वारा निःशुल्क हटाया जा रहा है।

विभिन्न शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए गुरुग्राम में 'स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड' स्थापित करने का निर्णय।

बिजली वितरण निगम के तकनीकी कर्मचारियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों की सुरक्षा किट उपलब्ध।

कृषि क्षेत्र में लोड बढ़ाने हेतु 'स्वैच्छिक घोषणा' योजना -2025 के तहत 18,407 किसानों ने 117.71 मेगावाट अनाधिकृत लोड घोषित।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों पर सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए सभी घरेलू उपभोक्ताओं को केन्द्र सरकार द्वारा 1 किलोवॉट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवॉट पर 60,000 रुपये तथा 3 किलोवॉट पर 78,000 रुपये की सब्सिडी।

प्रदेश में एक लाख बी.पी.एल. परिवारों को सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा अधिकतम 1.10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 1,20,961 सोलर रूफटॉप लगाए गए।

सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा

हरित और नीली अर्थव्यवस्था–

प्रधानमंत्री ने भारत को जलवायु परिवर्तन में एक सक्रिय वैश्विक समस्या–समाधानकर्ता के रूप में स्थापित किया, जिसमें हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और व्यापक हरित रोजगार पैदा करने के लिए महासागर, समुद्री क्षमता और तटीय पर्यटन के व्यापक विकास के माध्यम से सतत विस्तार पर जोर दिया गया।

सॉफ्ट पावर–

प्रधानमंत्री ने योग को एक एकीकृत वैश्विक ऊर्जा बताया और भारत की विरासत, आयुर्वेद और पर्यटन के वैश्वीकरण का समर्थन किया, जबकि वीएफएक्स, एनीमेशन, गेमिंग और वेव्स समिट में फैली रचनात्मक अर्थव्यवस्था में आक्रामक नेतृत्व को अनिवार्य किया। भारत के वन्य जीवन और राष्ट्रीय उद्यानों की विशाल अप्रयुक्त क्षमता को स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री ने वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करके और अत्यधिक आकर्षक, बड़े पैमाने पर संगीत अर्थव्यवस्था के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को संगठित करके इस सॉफ्ट पावर का लाभ उठाने के लिए एक आक्रामक अभियान चलाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने और वैश्विक मानकों को पार करने के लिए अलग–अलग क्षेत्रीय प्रगति के बजाय अत्यधिक सिंक्रनाइज़, क्रॉस–सेक्टोरल दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

देश की कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षाओं को चुनौती देने के लिए एक शक्तिशाली आह्वान करते हुए, प्रधानमंत्री ने वैश्विक रैंकिंग में भारतीय प्रभुत्व के लिए आक्रामक रूप से जोर दिया, सरकारों से साहसिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों का तेजी से आधुनिकीकरण करने का आग्रह किया, जिसमें फॉर्च्यून 500 में 50 भारतीय कंपनियां, एक शीर्ष स्तरीय वैश्विक बैंक, दुनिया के शीर्ष पांच में एक फार्मा दिग्गज और कानून, रेटिंग, परामर्श, लेखांकन और प्रौद्योगिकी फर्म जैसे प्रमुख वैश्विक नेतृत्व शामिल हैं।

युवाओं को राष्ट्रीय परिवर्तन के पूर्ण केंद्र में स्थापित करते हुए, प्रधानमंत्री ने पुष्टि करते हुए कहा कि युवा भारतीय इस तीव्र प्रगति के प्राथमिक वास्तुकार और अंतिम लाभार्थी दोनों हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक विकसित राष्ट्र की ओर पूरी यात्रा उनके सशक्तिकरण से अटूट रूप से जुड़ी होनी चाहिए।

पिछले एक दशक में 2.5 लाख पंजीकृत संस्थाओं के लिए घरेलू स्टार्टअप इकोसिस्टम की विस्फोटक वृद्धि का जश्न मनाते हुए, प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान और नवाचार कोष, किफायती डिजिटल डेटा के क्रांतिकारी प्रभाव और स्किल इंडिया, खेलो इंडिया सहित सक्रिय ढांचे जैसे बेजोड़ संसाधनों द्वारा संचालित युवा सशक्तिकरण के व्यापक युग पर प्रकाश डाला। नेशनल ड्रोन पॉलिसी, प्राइवेट स्पेस पार्टिसिपेशन और ऐतिहासिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी–2020 करीब 35 साल बाद आई है।

सी. दास फाउंडेशन

"सेवा से संकल्प तक — बदलाव की एक सतत पहल"

ECO वन परियोजना

फरीदाबाद में विकसित

बी. आर. भाटिया जी के नेतृत्व में सी. दास फाउंडेशन हरियाणा के "इको वन अभियान" को जनभागीदारी से मज़बूती दे रहा है। यह पहल हरित आवरण, स्वच्छ वायु और जैव-विविधता को बढ़ावा देते हुए प्रकृति और विकास के संतुलन का संदेश देती है।

स्वास्थ्य सेवा सहयोग

सी. दास फाउंडेशन के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं।

शिक्षा सहयोग

विद्यार्थियों को शैक्षिक सहयोग देकर सीखने, विकास और समान अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि हर विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने का अवसर मिल सके।

रक्तदान अभियान

नियमित रक्तदान शिविरों के माध्यम से आपातकालीन स्वास्थ्य जरूरतों में सहयोग तथा स्वैच्छिक रक्तदान, मानवता और सेवा की भावना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

C.DASS FOUNDATION

सौजन्य से

Maharani Innovative Paints Pvt. Ltd.

51/156, N.I.T. Faridabad-121001, Haryana

उच्च शिक्षण संस्थानों की ऊँची उड़ान

प्रधानमंत्री ने पिछले सुस्त विकास की तुलना की, 350 से कम विश्वविद्यालयों से लगभग 1,000 और मेडिकल कॉलेजों की छलांग को 400 से कम से लगभग 850 तक पहुंचाया, जबकि 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स द्वारा संचालित एक नवाचार इकोसिस्टम और युवाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप द्वारा अपने पहले प्रयासों में निजी उपग्रहों और रॉकेटों को लॉन्च करने की अविश्वसनीय सफलता की प्रशंसा की।

एआई कौशल से युक्त होंगे भारतीय युवा

उभरती प्रौद्योगिकियों में पूर्ण वैश्विक प्रभुत्व हासिल करने के लिए एक व्यापक पहल की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री ने आने वाले वर्ष के भीतर एक करोड़ युवाओं को औपचारिक रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए लाल किले से एक बड़ी घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने जैव अर्थव्यवस्था की विस्फोटक वृद्धि को इंगित करते हुए बताया कि 2014 में 60,000 करोड़ रुपये से आज लगभग 20 लाख करोड़ रुपये हो गई, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में सालाना सिर्फ 1.5 लाख से 25 लाख तक की ऊंची छलांग लगाई गई।

ग्रामीण शासन के साथ–साथ विमानन और एयरोस्पेस क्षेत्रों के तेजी से विस्तार पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने नए विमानों के रखरखाव केंद्रों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और मेड–इन–इंडिया सी–295 रक्षा परिवहन विमान की सफल उड़ान के बारे में चर्चा की। साथ ही, 3.25 करोड़ परिवारों में ग्रामीण आर्थिक क्षमता में 140 लाख करोड़ रुपये का लाभ उठाने के लिए ड्रोन संचालित स्वामित्व संपत्ति मानचित्रण योजना की अविश्वसनीय सफलता की प्रशंसा की।

मध्यम वर्गीय परिवारों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के गंभीर वित्तीय और भावनात्मक बोझ को कम करने के लिए एक बड़ी नई पहल की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री ने मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत की, जो राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धी तैयारी नेटवर्क के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए मजबूत डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और शीर्ष शिक्षकों का लाभ उठाती है।

विश्व स्तरीय खेलों में होगा उत्कृष्ट प्रदर्शन

टॉप्स योजना और खेलो इंडिया जैसी अत्यधिक रणनीतिक जमीनी स्तर की पहलों के माध्यम से वैश्विक खेल क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभुत्व का जश्न मनाते हुए, प्रधानमंत्री ने गर्व से अंतरराष्ट्रीय पोडियम पर तिरंगे की बढ़ती उपस्थिति का उल्लेख किया, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए देश की साहसिक बोली और 2036 ओलंपिक के लिए इसकी मजबूत उम्मीदवारी की पुष्टि की।

5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को लक्षित करते हुए राष्ट्रव्यापी खेल प्रतिभा हंट का शुभारंभ करते हुए, प्रधानमंत्री ने वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए भविष्य के ओलंपिक चैंपियनों की सक्रिय रूप से पहचान करने, प्रशिक्षित करने और उनका निर्माण करने के लिए हर गांव और स्कूल में जमीनी स्तर पर एक आक्रामक रणनीति की घोषणा की।

मादक द्रव्यों के सेवन के गंभीर राष्ट्रीय संकट का समाधान करते हुए, प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त भारत को एक बड़ी सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में घोषित किया, जो भविष्य की पीढ़ी की ताकत को मजबूती से सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

लाखों लोगों के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद करने वाले हिंसक उग्रवाद के विनाशकारी, चार दशक लंबे शासन पर विचार करते हुए, प्रधानमंत्री ने 3,500 से अधिक सुरक्षाकर्मियों के बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करते नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर एक विशाल, आधुनिक, स्वैच्छिक नागरिक सुरक्षा नेटवर्क के निर्माण की घोषणा की,

साथ ही साथ इस बात पर प्रकाश डाला कि रक्षा निर्यात लगभग 100 देशों में 50 गुना से अधिक बढ़ गया है।

आर्थिक मोर्चे पर ग्रामीण महिलाओं की प्रभावी उपस्थिति

एनडीए के माध्यम से विमानन, एसटीईएम और सशस्त्र बलों में आधुनिक राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के अविश्वसनीय योगदान का जश्न मनाते हुए, प्रधानमंत्री ने सशक्त ग्रामीण महिलाओं के बड़े पैमाने पर आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला और तकनीकी विदेशी प्रशिक्षण के बाद साणंद में उन्नत माइक्रोचिप्स बनाने में आत्मविश्वास से भरी आदिवासी बेटियों पर बहुत गर्व व्यक्त किया। यह देखते हुए कि 3 करोड़ लखपति दीदियों की उपलब्धि के साथ आर्थिक रूप से सशक्त ग्रामीण महिलाओं के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरी तरह से पार कर लिया गया है, उन्होंने अभूतपूर्व क्षेत्रीय परिवर्तन को चलाने के लिए 6 करोड़ का एक साहसिक नया लक्ष्य निर्धारित किया।

महिला का राजनीतिक सशक्तिकरण जरूरी

जन प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने वाली ऊर्जावान महिलाओं के सक्षम नेतृत्व की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से दशकों की देरी को समाप्त करने और संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई विधायी आरक्षण को तेजी से लागू करने की एक शक्तिशाली अपील की।

अतीत के न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा कवरेज की तुलना करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समावेशी कल्याण अब लगभग 100 करोड़ नागरिकों की रक्षा करता है, जो 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ था। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना पर प्रकाश डाला, जिसने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा कवरेज प्रदान किया है और आधिकारिक तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को चिकित्सा बिलों को कुचलने में अनुमानित 2 लाख करोड़ रुपये की बचत की है। पंच प्रण को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से राष्ट्रीय हित को स्थायी रूप से स्वार्थ से ऊपर उठाने, औपनिवेशिक मानसिकता को मिटाने और भव्य सपनों को एक विकसित राष्ट्र की निर्विवाद सफलता में तेजी से बदलने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का विजयी आह्वान किया।

○○○

LUB's Mumbai Western unit was formally inaugurated by National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji on 8th August. Maharashtra state GS Shri Harish Hande introduced the newly formed Mumbai Western team, led by President Shri Mahesh Jogani. The program was attended by Shri Ravindra Vaidya, Shri Ravindra Sonvane, Shri Bhushan Marde, Shri Gaurav Joshi and Shri Jayesh Dedhia, along with other distinguished members and entrepreneurs. Addressing the gathering, President Shri Mahesh Jogani presented the roadmap and plan of action for Mumbai Western unit. He outlined the unit's vision to actively engage with entrepreneurs, understand their challenges, facilitate solutions and undertake initiatives contributing to the growth and development of MSMEs across western Mumbai.

On this occasion, Shri Prakash Chandra ji encouraged entrepreneurs and members to work with dedication, unity and a strong sense of responsibility towards society and the nation. The gathering resonated strongly with the spirit of 'Udyog Seva - Rashtra Seva', inspiring all present to work collectively towards strengthening entrepreneurship, empowering MSMEs and contributing to the journey of Viksit Bharat.

उत्सव 2027
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश के विकास में
समर्पित लघु उद्योगों के विकास की प्रदर्शनी
लघु उद्योग भारती
सशक्त भारत के बढ़ते कदम.....
पश्चिमी राजस्थान
उद्योग हस्तशिल्प उत्सव
2027
02 जनवरी 2027 से
12 जनवरी 2027
स्थान : रावण का चबूतरा मैदान, जोधपुर
आयोजक
जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र एवं उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जोधपुर
लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रान्त
माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी
माननीय मुख्यमंत्री
श्री भजनलाल शर्मा जी
सम्पूर्ण भारत की कला, संस्कृति, हस्तशिल्प एवं लघु उद्योग उत्पादों का अनूठा प्रदर्शन,
सेमिनार, प्रतियोगिताएं, मनोरंजन के साधन, सांस्कृतिक संध्याएं व खाने-पीने की स्टॉलें

हर घर स्वदेशी
घर-घर स्वदेशी
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
श्री भूपेन्द्रभाई पटेल
माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात
गुजरात की गौरवपूर्ण उपलब्धि
'PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के तहत
५ लाख से अधिक घर अब...
सौर ऊर्जा से रोशन
२५% राष्ट्रीय योगदान के साथ गुजरात है प्रथम
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से गुजरात ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया मानक स्थापित किया है।
अब तक, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गुजरात में ११ लाख से अधिक रूफटॉप सोलार इंस्टॉलेशन्स किए जा चुके हैं,
जिनकी कुल सौर ऊर्जा क्षमता ६,३१५ मेगावाट है।
योजना का उद्देश्य
• पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह ३०० यूनिट तक निःशुल्क बिजली
• देशभर में १ करोड़ परिवारों तक सौर ऊर्जा का लाभ पहुँचाने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता
सब्सिडी
आवासीय उपयोग हेतु
₹७८,०००*
३ किलोवाट या इससे अधिक
ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज के लिए
₹१८,०००*
प्रति किलोवाट
क्या आप रूफटॉप सोलार स्थापित कर अपने घर को निःशुल्क बिजली से सशक्त बनाना चाहते हैं? आज ही pmsuryaghar.gov.in पर जाएँ
और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम बढ़ाएँ।
"गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक नई ऊँचाइयाँ हासिल की हैं। हमारा लक्ष्य केवल बिजली उत्पादन तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि आने वाली
पीढ़ियों को प्रदूषण-मुक्त और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भविष्य प्रदान करने का भी है।" - श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

मोदी सरकार के 12 वर्ष – प्रधानमंत्री मोदी की अजेय यात्रा

चर्चा में
डॉ. अश्वनी महाजन
जाने–माने आर्थिक विश्लेषक
राष्ट्रीय सह–संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच
पूर्व प्रोफ़ेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय
ashwanimahajan@rediffmail.com

जहां आज़ादी के बाद के शुरुआती तीन दशकों में भारत की आर्थिक विकास दर 3 से 4 प्रतिशत के बीच रही, वहीं पश्चिमी एशिया और दूसरी जगहों के छोटे देशों ने तकनीकी तरक्की के साथ–साथ बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास किया। जहां भारत को एक विकासशील देश माना जाता रहा, वहीं ये छोटे देश "एशियन टाइगर्स" के तौर पर मशहूर हो रहे थे। गरीबी कम होने की रफ़्तार भी बहुत प्रभावशाली नहीं थी।

एक खास ढांचे के आधार पर गरीबी का पहला आकलन 1973–74 में किया गया; जब योजना आयोग ने गरीबी रेखा की अवधारणा पेश की, जिसके मुताबिक 54.9 प्रतिशत आबादी इसके नीचे रह रही थी। हालांकि समय के साथ गरीबी रेखा की परिभाषाएं बदलती रहीं, लेकिन 2012–13 में भी 21.9 प्रतिशत आबादी–यानी 269.3 मिलियन (26.93 करोड़) लोग–गरीबी रेखा से नीचे माने जाते थे। इस बीच, वर्ल्ड बैंक की परिभाषा के मुताबिक–जिसमें 2012–13 में रोज़ाना 1.25 अमेरिकी डालर से कम कमाने वालों को घोर गरीबी में रहने वाला माना गया था–दुनिया के 1.2 अरब गरीब लोगों में से एक–तिहाई, यानी 40 करोड़ लोग, भारत में थे।

हालांकि, 2025 तक, वर्ल्ड बैंक की परिभाषा– जिसे बढ़ाकर 2.15 अमेरिकी डालर प्रति दिन कर दिया गया था–के आधार पर घोर गरीबी में रहने वाली कुल आबादी का हिस्सा घटकर सिर्फ़ 2.3 प्रतिशत रह गया है; 3 अमेरिकी डालर प्रति दिन की ज़्यादा नई परिभाषा के तहत भी, यह आंकड़ा सिर्फ़ 5.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसे निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है, जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुई।

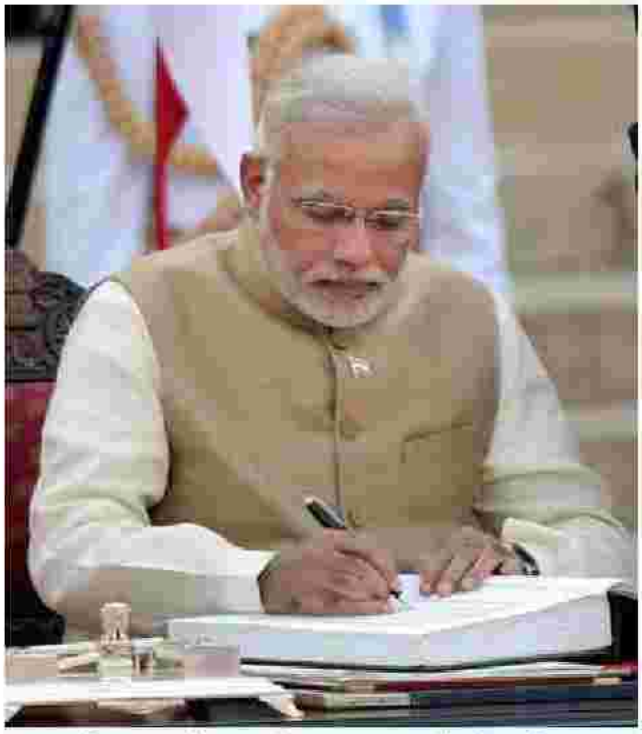

26 मई 2014 को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और पहली पूर्ण गैर–कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया।

आज भारत और दुनिया भर में गरीबी की एक ऐसी परिभाषा मौजूद है जो इस घोर गरीबी से आगे जाती है, यानी "बहुआयामी गरीबी"। इसे मापने में दस पैमाने शामिल हैं: दो शिक्षा से जुड़े, दो स्वास्थ्य से, और बाकी छह में आवास,

बिजली, स्वच्छता, खाना पकाने के लिए साफ़ ईंधन, पीने का पानी और संपत्ति का मालिकाना हक शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अनुसार, 2015–16 और 2019–21 के बीच, सिर्फ़ पाँच सालों में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 0.117 से घटकर 0.069 हो गया। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि बहुआयामी गरीबी 2013–14 में 29.17% से घटकर 2022–23 में अनुमानित 11.28% हो गई, जो एक दशक में लगभग 18 प्रतिशत अंकों की कमी को दर्शाता है।

दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि भारत में न केवल घोर गरीबी में, बल्कि बहुआयामी गरीबी में भी उल्लेखनीय कमी आई है। आम तौर पर, कई आर्थिक विशेषज्ञ यह तर्क देते हैं कि यदि आर्थिक विकास के दौर में गरीबी कम करने के प्रयासों के तहत संसाधनों के पुनर्वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो विकास की गति धीमी हो सकती है। इसलिए, उनका मानना है कि आर्थिक विकास के चरणों के दौरान पुनर्वितरण को प्राथमिकता देना उचित नहीं है। इस विचार को मानने वाले अर्थशास्त्री–जो मुक्त व्यापार और मुक्त बाज़ार के समर्थक भी हैं– उनमें न केवल वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के विशेषज्ञ शामिल हैं, बल्कि प्रो. जगदीश भगवती और उनके सह–लेखक प्रो. अरविंद पनगढ़िया जैसी बड़ी हस्तियाँ भी इसी श्रेणी में आती हैं।

ऐसे अर्थशास्त्रियों की दलीलों के बावजूद, न केवल भारत ने आर्थिक विकास दर ऊंचा रखा, बल्कि बहुआयामी और अत्यधिक गरीबी को कम करने में भी बड़ी सफलता हासिल की। कोविड–19 के कारण एक साल के झटके के बावजूद– नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत की वास्तविक जीडीपी लगभग 7.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ती रही।

हमें यह भी पहचानना होगा कि देश में असमानता और गरीबी को कम करने में कौनसी नीतियां असरदार साबित हुईं। यह समझना ज़रूरी है कि जहां आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में गरीबी कम होने की रफ़्तार बहुत धीमी थी, वहीं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में गरीबी कम करने की दिशा में कैसे बड़ी प्रगति हुई, जिससे विकास पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा समावेशी हो गया।

वित्तीय समावेशन

आज़ादी और 2014 के बीच विकास की कई कोशिशों के बावजूद, देश में वित्तीय समावेशन के मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई। इसका सबूत यह है कि 2014 और 2026 के बीच 580 मिलियन (58 करोड़) जन–धन खाते खोले गए। और इन जन धन खातों में कुल ₹3 लाख करोड़ जमा हो गए थे। जन–धन खाते ज़ीरो–बैलेंस खाते होते हैं, यानी इन्हें खोलने के लिए किसी शुरुआती जमा राशि की ज़रूरत नहीं होती।

वित्तीय समावेशन का एक और पहलू 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (डीबीटी) है। पहले, सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित फंड का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ सही लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाता था। जन–धन खाते खुलने के बाद, उन्हें आधार (यूआईडी) और मोबाइल फोन नंबरों से जोड़ा गया; नतीजतन, अब पूरी कल्याणकारी राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पैसे के बीच में ही गायब होने या चोरी होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस प्रक्रिया को 'जैम त्रय' के नाम से जाना जाता है– जिसमें जन–धन खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी शामिल हैं– यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे भारत ने अपनी तकनीकी क्षमता के दम पर हासिल किया है।

महिलाओं के लिए खास: आवास, स्वच्छता, स्वच्छ ईंधन, बिजली और पानी

आज़ादी से लेकर 2014 तक के सफर की एक बहुत बड़ी सच्चाई यह थी कि 2014 में भी देश में 12.3 करोड़ लोग कच्चे (अस्थायी) घरों में रहते थे, जबकि 31.7 करोड़ लोग अर्ध–स्थायी घरों में रहते थे। इसके विपरीत, सिर्फ़ पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ और शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाए गए हैं, और उसके अलावा 1.2 करोड़ घर या तो मंजूर हो चुके हैं या बन रहे हैं।

खुले में शौच करने की मजबूरी को लंबे समय से देश के लिए एक बड़ा कलंक माना जाता था। यह संतोष की बात है कि 2014 के बाद से देश भर में 12.8 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिससे खुले में शौच की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान हो गया है। आज, देश में लगभग पूरी तरह से बिजली पहुँच चुकी है, और 'हर घर नल से जल' योजना के तहत ज़्यादातर इलाकों में पीने का पानी उपलब्ध हो गया है। स्वच्छ ईंधन की बात करें तो, जहाँ 2014 में केवल 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, वहीं अब यह संख्या 34 करोड़ से ज़्यादा हो गई है; खास बात यह है कि इनमें से 10 करोड़ नए कनेक्शन 'उज्ज्वला योजना' के तहत दिए गए, जिसके ज़रिए गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ़्त सिलेंडर और गैस स्टोव उपलब्ध कराए गए। आवास, पानी, बिजली, स्वच्छता सुविधाएँ और एलपीजी कनेक्शन ऐसी उपलब्धियाँ हैं जिनसे पूरे समाज और खासकर गरीबों को फ़ायदा हुआ है। हालाँकि, महिलाओं का सबसे ज़्यादा सशक्तिकरण हुआ है, क्योंकि शौचालय, पानी और एलपीजी कनेक्शन मिलने से वंचित परिवारों की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में न सिर्फ़ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बल्कि कानूनों के ज़रिए सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान दिया है, जिससे महिलाओं – और खासकर मुस्लिम महिलाओं – की ज़िंदगी बदल गई है। 15 से 80 साल और उससे ज़्यादा उम्र की मुस्लिम महिलाएं हमेशा इस डर में जीती थीं कि उनके पति कभी भी 'तलाक–तलाक–तलाक' कहकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं और उन्हें एक मिनट के लिए भी घर में रहने नहीं दिया जाएगा। एक कानून बनाकर इस काम को अपराध

घोषित करने से मुस्लिम महिलाएं हमेशा के लिए इस डर से आज़ाद हो गई हैं।

गौरतलब है कि इस सरकार द्वारा शीघ्रता से महिला आरक्षण करने का भी प्रयास हुआ, लेकिन विपक्ष द्वारा महिला आरक्षण में बाधा डालने के कारण महिलाओं के बारे में लोगों की सोच पर बड़ा असर पड़ा। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की ज़्यादा वोटिंग ने असंतोष का संकेत दिया, जिससे ममता बनर्जी की टीएमसी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा।

जीडीपी ग्रोथ के साथ–साथ, नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां कई क्षेत्रों में साफ़ तौर पर दिखती हैं। सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, डिजिटल पेमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की और डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम; ये सभी विकास कार्य बहुत अहम रहे हैं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ग्लोबल लेवल पर भारत का बढ़ा हुआ कद एक मज़बूत और आत्मविश्वास से भरी राष्ट्रीय उपस्थिति को दिखाता है।

इन बातों का सरकार के प्रति लोगों की सोच पर सकारात्मक असर पड़ा है। शायद यही वजह है कि सर्वे लगातार दिखाते हैं कि इतने सालों में सरकार और प्रधानमंत्री, दोनों की लोकप्रियता पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।

विपक्ष को भी इससे एक ज़रूरी सबक लेना चाहिए। बिना किसी ठोस आधार के आलोचना करने या बेकार के मुद्दों पर सरकार का विरोध करने के बजाय, एक सोच–समझकर बनाया गया और भरोसेमंद रोडमैप पेश करने की ज़रूरत है। ऐसे रोडमैप में देश के सामने मौजूद अहम सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का समाधान होना चाहिए और आगे की तरक्की के लिए सार्थक विकल्प भी होने चाहिए।

○○○

विकसित भारत
विकसित गुजरात

सेमीकंडक्टर मिशन

- **धोलेरा SIR** और **साणंद** में विकसित हो रहे सेमीकॉन हब ने गुजरात को **चिप** उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है
- गुजरात **सेमीकंडक्टर पॉलिसी** के तहत **₹1100 करोड़** का प्रावधान
- धोलेरा **SIR** को निरंतर पानी की सुविधा मिलती रहे, इसके लिए नया **100 एम.एल.डी बल्क पाइपलाइन नेटवर्क** स्थापित किया जाएगा
- धोलेरा **SIR** भविष्य के लिए उद्योग, नवाचार और रोजगार का वैश्विक केंद्र बने, इसके लिए बजट में **"विकसित गुजरात फंड"** सहित कुल **₹610 करोड़** का प्रावधान

शहरी विकास

- अहमदाबाद बनेगा **'ओलंपिक रेडी सिटी'**
- अहमदाबाद और सूरत के सैटेलाइट टाउन को जोड़ने वाली **रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम** शुरू की जाएगी
- **"गुजरात वायर-फ्री सिटी मिशन"** के तहत शहरों में मौजूदा **ओवरहेड बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड** किया जाएगा
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0** के तहत शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए बजट में **₹1420 करोड़** का प्रावधान
- गांधीनगर में **सभी सेंट्रल लाइब्रेरी** बनेगी
- हर महानगर पालिका में **स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स** और **फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर** का विकास होगा

ग्रामीण विकास

- **VB-G RAM G योजना** के तहत **काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने से रोजगार में वृद्धि होगी**
- **स्वयं सहायता समूहों की बहनों** को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए स्थायी जगह मिल सके, इसके लिए **ग्राम हाट** की स्थापना की जाएगी
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष लगभग **1 लाख 60 हजार से अधिक आवासों** का निर्माण होगा

"स्मार्ट सिटी से लेकर समृद्ध गांवों और अब वैश्विक सेमीकंडक्टर हब तक, गुजरात की विकास यात्रा अविरत है। शहरी बुनियादी ढांचे, ग्रामीण रोजगार और अत्याधुनिक तकनीक के त्रिवेणी संगम के माध्यम से हम **आत्मनिर्भर** और **विकसित गुजरात** का निर्माण कर रहे हैं।"

- श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

"प्रत्येक भारतीय के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा हमेशा से हमारा लक्ष्य रहा है। जन औषधि केंद्रों से आयुष्मान भारत तक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल को सभी के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाने की अपनी यात्रा जारी रखेंगे।"
- नरेन्द्र मोदी
स्वस्थ नागरिक - स्वस्थ समाज
सर्वे सन्तु निरामया
सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के अंतर्गत गंभीर बीमारी से पीड़ित श्रमिकों को अब तक 42.05 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में वितरित की गई।
200 बिस्तरों के सिविल अस्पताल, पानीपत को 300 बिस्तरों में अपग्रेड किया।
किडनी रोग से पीड़ित रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं सभी नागरिक जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में 18 अक्तूबर, 2024 से दी जा रही है।
70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत 5 लाख रुपये वार्षिक मुफ्त इलाज सुविधा।
करनाल के बीबीपुर जाटान व दनियालपुर गांवों में लगभग 1.28 करोड़ रुपये की लागत से उप-स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन।
सरसाना, जिला हिसार में 71.75 लाख रुपये की लागत से उप-स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण
सिरसा में 1010 करोड़ रुपये की लागत से 21 एकड़ क्षेत्र में संत सरसाई नाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन।
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद तथा नूंह में क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किये जा रहे हैं।
नॉन स्टॉप हरियाणा
सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा

नमो नेतृत्व - अविश्वसनीय, अविस्मरणीय एवं अतुलनीय

(राष्ट्र की राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक स्वायत्तता, एकता-अखंडता और सांस्कृतिक अस्मिता के गौरव की पुनर्स्थापना के लिए ये मोदी युग स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा)

कवर स्टोरी
डॉ. संजय मिश्रा
को-एडिटर, उद्योग टाइम्स
dr.sanjay.jpr@gmail.com

नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे विरले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पहले बतौर मुख्यमंत्री विकास के एजेंडे को राजनीति के केंद्र में स्थान दिलवाया और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर सर्वाधिक काल तक निरंतर निर्वाचित होकर नेतृत्व किया। और नेतृत्व भी ऐसा, कि जैसा पहले कभी न देखा और न सुना। आज मोदी की तुलना किसी भी पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री से नहीं हो सकती। उन्होंने लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग, स्टेट क्रेडिबिलिटी एवं गुडविल, ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस एंड लिविंग, सोशल इन्क्लूजन एंड सोशल सिक्योरिटी, पोल परफॉरमेंस के क्षेत्र में ऐसे रेकॉर्ड बना दिए, जिसे तोड़ना किसी भी राजनेता के लिए असंभव नहीं, तो कम से कम आसान तो नहीं ही होगा।

इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप अब क्लासरूम का विषय भी बन गई है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा के एक एकेडमिक मॉड्यूल का वे अब हिस्सा बन गए हैं। यूनिवर्सिटी ने "सोशियोलॉजी ऑफ़ पैट्रियटिज़्म" (देशभक्ति का समाजशास्त्र) नाम से एक सोशियोलॉजी कोर्स शुरू किया है, जो "मोदी तत्व" पर केंद्रित है और स्थापित सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के ज़रिए उनकी लीडरशिप स्टाइल की पड़ताल करता है।

जर्मनी के जाने-माने समाजशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक अर्थशास्त्री मैक्स वेबर अपने करिश्माई नेतृत्व सिद्धांत में बताते हैं कि ऐसे नेता अपने अनुयायियों को औपचारिक नियमों या परंपराओं के बजाय अपने करिश्मे, दूरदर्शी सोच और असाधारण आत्मविश्वास से प्रेरित करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व में असाधारण गुण होते हैं जिनकी वजह से वे आम लोगों से बिलकुल अलग दिखते हैं और उन्हें अलौकिक, अति-मानवीय या कम से कम असाधारण शक्तियों या गुणों वाला माना जाता है। ये ऐसे गुण हैं जिससे उन्हें दैवीय या अनुकरणीय माना जाता है, और इसी के आधार पर उनका नेतृत्व भी स्वीकार किया जाता है।

भारतीय राजनीति में ऐसे करिश्माई व्यक्तित्वों में श्री महात्मा गाँधी, श्री सुभाष चंद्र बोस, श्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार श्री वल्लभभाई पटेल, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री अटलबिहारी वाजपेयी और वर्तमान में देश का नेतृत्व कर रहे श्री नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत शामिल हैं। इन सब में अगर कोई सामान्य गुण रहा है, तो वो है उनकी मास अपील। यानी वे जन नेता की श्रेणी में आते हैं और जब वे कुछ भी कहते हैं, या करते हैं तो उसका सीधा असर लोगों पर होता भी है। वे उनका अनुसरण करते हैं और उनकी एक आवाज पर घर से निकल पड़ते हैं।

हम हमारी आँखों के सामने श्री नरेंद्र भाई मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व को देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग ने दुनिया के शीर्ष नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। उनके विराट व्यक्तित्व, उनके आभामंडल (Aura) और उनकी उपलब्धियों ने उन्हें Larger than Life और Living Legends

की श्रेणी में खड़ा कर दिया है जो करोड़ों लोगों में और सौ बरसों में कोई एक होता है।

ऐसे करिश्माई नेतृत्व में एक उदाहरण कांग्रेस का भी लेते हैं। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव अभियान के दौरान एक लोकप्रिय नारा दिया था– 'ग़रीबी हटाओ'। वाकई, केवल दो शब्दों के उस नारे में बहुत जबरदस्त अपील थी। क्योंकि गरीबी से उबरने के लिए देश की अधिकांश जनता में बेताबी जो थी। उस चुनाव में गरीबी से कसमसाती जनता के समर्थन से इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारी जीत मिली; पार्टी ने 518 में से 352 सीटें जीतीं। यानी करीब 68 प्रतिशत। 68 के मानी हैं दो तिहाई बहुमत।

ये बात अलग है कि लोग कभी उस दौर को याद करते हुए तंज कसते हैं कि गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन गरीब ही हट गए। बात बिलकुल साफ़ थी कि जनता ने इंदिरा के उस आह्वान पर यकीन किया, लेकिन उसका उतना असरदार परिणाम नहीं आ सका, जिसकी आम आवाम को उम्मीद थी। खैर, पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–1978) के दौरान इस पर काम किया गया। इस योजना की मुख्य रणनीति में शामिल किए जाने से पहले, यह नारा मूल रूप से रोज़गार बढ़ाने, जीवन–स्तर को ऊपर उठाने और सामाजिक न्याय में सुधार करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था।

जिस नारे को कांग्रेस ने देकर केवल राजनीतिक लाभ ही लिया, उसे नरेन्द्र मोदी ने साबित कर दिखाया। करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उबार दिया। क्योंकि खुद मोदी ने गरीबी की उस विषमता को करीब से देखा और भोगा था, तो उसे खत्म करने में उन्होंने कारगर कदम उठाये।

सभी जानते हैं कि लम्बी अवधि तक कांग्रेस ने देश में राज किया, लेकिन अपनी फाइव स्टार कल्चर के कारण देश की प्रगति में ख़ास योगदान नहीं कर सकी। इसका साफ़ कारण था कमजोर नेतृत्व, संस्थागत भ्रष्टाचार और प्रामाणिकता का अभाव।

कांग्रेस से दूसरा उदाहरण राजीव गांधी का भी ले लेते हैं। इंदिरा की हत्या के बाद अक्टूबर, 1984 को विरासत में प्रधानमंत्री का पद मिला राजीव गाँधी को। लेकिन एक वर्ष के भीतर ही 1985 में राजस्थान के झुंझुनू जिले के अरड़ावता गांव में आयोजित एक रैली में मिस्टर क्लीन ने बड़ी साफगोई से अपनी प्रशासनिक अक्षमता को स्वीकारते हुए कहा था – "हम ऊपर से एक रुपया भेजते हैं, तो नीचे पहुंचते–पहुंचते वह केवल 15 पैसे ही रह जाता है।" उनका सीधा इशारा बिचौलियों, प्रशासनिक कड़ियों और भ्रष्टाचार पर था, जो गरीब कल्याण के पैसों को जनता तक नहीं पहुंचने देते थे। ये दो उदाहरण ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि वंशवादी दलीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री जैसे अति महत्वपूर्ण पद पर योग्यता बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती।

मुख्यमंत्री के अवतार में मोदी

जिस तरह से मोदी को गुजरात की कमान मिली, वो उस समय के राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों के लिए घोर आश्चर्य का विषय था। क्योंकि नरेंद्र मोदी को उस समय तक किसी भी निर्वाचित पद पर कार्य करने का औपचारिक अनुभव नहीं था, लेकिन गुजरात जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व उन्हें दे दिया गया और उन्होंने अक्टूबर, 2001 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। श्री केशुभाई पटेल की प्रशासनिक क्षमताओं के बारे में जो भी फीडबैक शीर्ष नेतृत्व के पास रहा हो, लेकिन ये निर्णय निश्चित रूप से साहसिक था।

अचानक से मुख्यमंत्री के तौर पर जब मोदी गुजरात आये, तो उनके सामने खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती थी। हालांकि गुजरात के लिए वे नए नहीं थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने गुजरात में प्रवास किये थे और समाज के सभी गणमान्य जनों से उनका अच्छा परिचय था। फिर भी नए–पुराने सभी विधायकों, मंत्रियों और बरसों से काबिज नौकरशाही को साथ लेकर काम करना इतना सहज भी नहीं था। लेकिन संगठन की अपेक्षाओं पर मोदी न केवल खरे उतरे, बल्कि उन्होंने प्रशासनिक सूझबूझ की ऐसी नजीर पेश की, जिसकी तुलना उनके समकक्ष या पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों से नहीं की जा सकती।

मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 12 वर्ष से कुछ अधिक रहे, जबकि ओडिशा में श्री नवीन पटनायक और बंगाल में श्री ज्योति बसु जैसे कई मुख्यमंत्री 23–24 वर्ष तक उस पद पर बने रहे, लेकिन इतनी समयावधि के शासन के बाद भी प्रदेश में वो विकास नहीं हो सका, जो मोदी ने कर दिखाया। 2001 और 2014 के बीच, गुजरात में तेज़ी से औद्योगिक विकास हुआ और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में सालाना औसतन लगभग 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक थी।

प्रशासन में नई कार्य संस्कृति का आगाज

मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही बिना देरी किये अपनी प्राथमिकताओं से अपनी टीम और नौकरशाही को अवगत करा दिया था। मोदी जानते थे कि गुजरात में वे जिस गति से विकास की परिकल्पना का खाका खींचना चाहते थे, वहां मौजूदा नौकरशाही को भरोसे में लेकर ही वे इसे पूरा कर सकते थे। उन्होंने विभागीय समन्वय (Departmental Coordination) और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से संपन्न (Time Bound Execution) करने पर ज़ोर दिया।

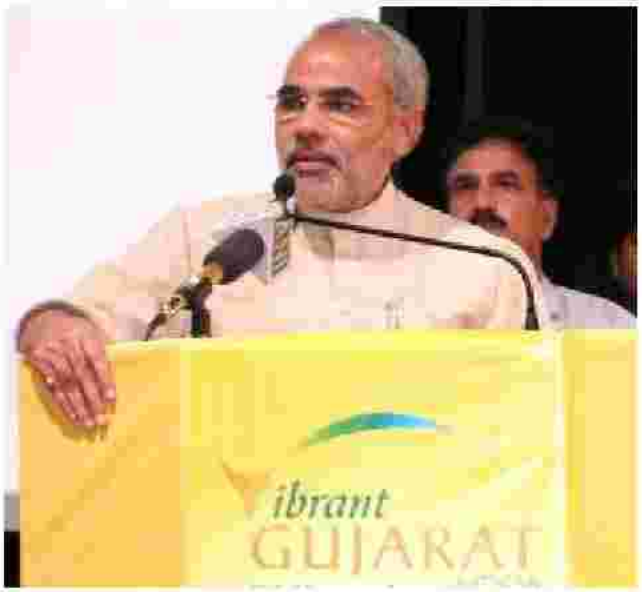

मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की छवि निर्माण (Image Building) में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली योगदान दिया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में शुचिता तथा शासन और प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को प्राथमिकता दी। त्वरित निर्णय लेने की कार्यशैली और सुशासन के माध्यम से उन्होंने गुजरात को एक सशक्त, कुशल और निवेश–अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित किया। उनके नेतृत्व में गुजरात की पहचान लोकतांत्रिक सुशासन और निवेश के सर्वश्रेष्ठ गंतव्य (Best Destination for Investments) के रूप में मजबूत हुई। विकास, पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्णायक नेतृत्व पर आधारित इस कार्यशैली को आगे चलकर 'मोदी डॉक्ट्रिन' यानी 'गुजरात मॉडल' के नाम से जाना गया। गुजरात व्यापार में आसानी लाने (Ease of Doing Business) की रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर भी रहा।

प्रशासन में स्थायित्व के लिए ट्रांसफर पर लगाम–

गुजरात राज्य के पूर्व चीफ सेक्रेटरी श्री जीआर आलोरिया इस बारे में बताते हैं कि मोदी सरकार के दौरान गुजरात के प्रशासनिक ढांचे में अनावश्यक फेरबदल से बचा जाता था। ब्यूरोक्रेट्स के तबादले आसानी से नहीं किए जाते थे और मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रशासन में स्थायित्व को विशेष महत्व दिया। उनका मानना था कि बार–बार अधिकारियों के स्थानांतरण से न केवल प्रशासन में गलत संदेश जाता है, बल्कि अधिकारी अपने दायित्वों पर पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते और उनका मनोबल भी प्रभावित होता है।

मोदी यह समझते थे कि 'आया राम, गया राम' की संस्कृति के बजाय यदि प्रशासन में स्थायित्व कायम रहे, तो अधिकारियों को अपने विभाग और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझने तथा दीर्घकालिक परिणाम देने का अवसर मिलता है। साथ ही, सरकार भी अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञता का निरंतर लाभ उठा सकती है। प्रशासन में इस स्थायित्व का सकारात्मक असर शासन की कार्यक्षमता के साथ–साथ निवेश के माहौल पर भी पड़ता है और सरकार की एक स्थिर एवं भरोसेमंद छवि बनती है। श्री आलोरिया ने स्वयं का उदाहरण देते हुए बताया कि गुजरात सरकार में वे अर्बन डेवलपमेंट विभाग में 15 वर्षों तक विभिन्न पदों पर रहे।

ब्यूरोक्रेसी को मिली राजनीतिक दखल से आजादी

इस नीति का नौकरशाही में भी सकारात्मक संदेश गया। अधिकारियों को यह भरोसा मिला कि उन्हें एक विभाग में निरंतर काम करने और अपनी योजनाओं को परिणाम तक पहुंचाने का पर्याप्त अवसर मिलेगा तथा अनावश्यक तबादले की तलवार उनके सिर पर नहीं लटकेगी। जब ब्यूरोक्रेट्स आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं, तो वे अपने दायित्वों का

निर्वहन अधिक स्वतंत्रता, निरंतरता और बेहतर परिणामों के साथ कर पाते हैं। मोदी ने लोक सेवकों को ये यकीन भी दिलाया कि सरकार की किसी योजना पर कार्य करते हुए अगर उनसे गैर इरादतन कोई गलती हो भी जाये, तो उन पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं होगी। मोदी ने गुजरात में टॉप ब्यूरोक्रेसी की तरह अधीनस्थ नौकरशाही को लेकर होने वाले राजनीतिक दखल को भी लगभग ख़त्म ही कर दिया था। ऐसा होने से ब्यूरोक्रेसी ने भी सरकार के कार्यक्रमों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता का परिचय दिया।

मोदी ने गुजरात में आम जनता की पहुंच (Access) में सरकार और नौकरशाही दोनों को ही ला दिया। इसका सीधा फायदा उनको चुनाव में मिलता था सरकार के पास आसान पहुँच के कारण जनता में एंटी इंकम्बैंसी फैक्टर बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता था। इसके साथ ही उन्होंने कुछ खास निर्णय लिए जिससे प्रशासन और नागरिकों दोनों को सरकारी कामकाज में पहले से अधिक सहजता अनुभव हुई।

- **लम्बी कागजी प्रक्रिया (Procedure) को आसान बनाया**
- **त्वरित निर्णयों के लिए नियमित कैबिनेट बैठकों का आयोजन**
- **पॉलिसी में स्पष्टता, किसी को विवेकाधीन शक्तियां नहीं**
- **इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाया एक्शन प्लान**
- **सरकारी भर्तियों में निष्पक्षता और पारदर्शिता**

और जब मोदी भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर छा गए

26 मई, 2014 भारतीय राजनीतिक इतिहास में दर्ज ये वो विशेष दिन था जब करोड़ों देशवासियों के दिलों में जज्ब बरसों की निराशा और हताशा की कई–कई परतें समाप्त हो गई थीं। इससे पहले कांग्रेस की अगुवाई में बने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार ने भ्रष्टाचार के वो रिकॉर्ड बनाये, जिसने नागरिकों की आकांक्षाओं को धूमिल कर दिया था।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों के सभी शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्री हामिद करज़ई, श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिंदा राजपक्षे, मालदीव के राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला यामीन, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना की जापान यात्रा के कारण वहां की संसद की स्पीकर श्रीमती शिरीन शर्मिन चौधरी इस ख़ास अवसर पर मौजूद रहे। ये जमावड़ा किसी ख़ास वजह से हुआ था और उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि पड़ौसी और एशियाई देशों के तत्कालीन नेताओं ने चुनाव से पहले और बाद में मोदी के बढ़ते जनाधार को लगातार देखा था और उन्हें इस बात का अहसास भी था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी जैसे व्यक्तित्व को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा।

मोदी है, तो आखिर मुमकिन क्यों है!

कोविड काल का उदाहरण हमारे सामने है, जब सम्पूर्ण मानवता काल–कवलित हो रही थी और विकसित कहे जाने वाले देशों की सरकारों के पास भी उस समय कोई मुकम्मल उपाय नहीं था, उस समय मोदी आगे आये और राष्ट्र को सम्बोधित किया। उन्होंने कोरोना जनित वायरस की उस विभीषिका का सामना करने का सरकार का ब्लू प्रिंट बताया। उन्होंने सरकारी कार्मिकों, पुलिस बल, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, स्वयंसेवी संस्थाओं, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स और समस्त नागरिकों को उस कठिन समय के लिए दायित्व बताये। उन्होंने कोविड की पहली और दूसरी लहर के वक्त कई–कई बार सीधे संवाद किया और

कई तरह के अनुशासनों के लिए आह्वान किया, उसका जादूई असर था कि लोगों ने उनकी बात पर सौ फीसद अमल किया। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि शासन, प्रशासन और जनता के अनुशासन की उस समन्वित त्रिवेणी ने अन्य देशों के बजाय भारत में होने वाली अपार जन हानि को न्यूनतम करने में बड़ी मदद की।

इतना ही नहीं, मोदी ने उदारता का परिचय देते हुए भारत के बाहर भी कई देशों को कोविड से छुटकारा पाने के लिए उस वैक्सीन को supply kiya जिसकी न तो वे R&D कर पाए और न ही उसका प्रोडक्शन। भारत ने अपनी 'वैक्सीन मैत्री' पहल के तहत ग्रांट, कमर्शियल बिक्री और ग्लोबल COVAX सुविधा के ज़रिए लगभग 94 से 98 देशों को COVID-19 वैक्सीन सप्लाई की और कुल मिलाकर मेडिकल मदद / दवाओं के लिए 150 से ज्यादा देशों को सप्लाई की।

मोदी की उस वैक्सीन डिप्लोमेसी से न केवल विश्व बिरादरी में भारत के अपने वैश्विक उद्घोष 'वसुधैव कुटुंबकम' को और मजबूती से स्थापित किया वरन मोदी का कद पश्चिम की नज़रों में और बढ़ गया। यहीं नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी की लीडरशिप में हमारे फार्मा सेक्टर ने भी अपनी कैपेबिलिटी को साबित किया। मोदी के आह्वान पर यहां के उद्यमियों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, मास्क और अन्य सभी जरूरी इक्विपमेंट्स और संसाधनों का मास प्रोडक्शन किया जिससे आज वे उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं।

ऐसे कई और अवसर भी आये, राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय सुरक्षा, नोटबंदी, राम मंदिर, कश्मीर का विशेष दर्जा या जीएसटी जैसा जटिल विषय, मोदी ने देश में ऐसा विश्वास कायम किया कि जैसे घर में अभिभावक या पिता की किसी बात को घर के अन्य सदस्य पूरा मान देते हैं, वैसा ही मोदी के कठोर और असंभव से लगने वाले सभी निर्णयों पर जनता ने भी पूरे विश्वास के साथ मुहर लगा दी।

मोदी के पांच मास्टर स्ट्रोक जिसने बदला दुनिया का नजरिया

राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ा जम्मू–कश्मीर

कितनी ही कत्ल–औ–गारत की अनकही कहानियों को अपने सीने में जज़्ब करने वाली कश्मीर की वादियों की यकीनी तौर पर वो एक नयी सुबह थी जब करीब 70 बरसों बाद 5 अगस्त, 2019 को J&K को विशेष दर्जा देने वाले अनु. 370 और 35a के प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। राष्ट्र के सपूत स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी दो विधान, दो प्रधान और दो निशान वाली व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करते हुए बलिदान हो गए थे।

कांग्रेस और विभाजनकारी शक्तियों ने देश के शांतिपूर्ण वातावरण खराब करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी शक्तियों से भारत के इस स्टैंड को मौन स्वीकृति मिली। क्षेत्र के रुके हुए विकास ने गति पकड़ी और साथ ही उन सभी पत्थरबाज बाशिंदों को भी अपनी जिंदगी को बिल्कुल नए सिरे से शुरू करने, शिद्दत से जीने और उसमें नए रंगों को भरने की पूरी गुंजाइश दी है। क्षेत्र में औद्योगिक निवेश से रोजगार सृजन जारी है।

भारतीय विदेश नीति का नव–सृजन

भारतीय विदेश नीति ने पारंपरिक कूटनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय हित, रणनीतिक स्वायत्तता और

वैश्विक नेतृत्व को केंद्र में रखकर एक नई दिशा प्राप्त की। भारत ने 'पड़ोसी प्रथम', 'एक्ट ईस्ट' 'इंडो–पैसिफिक'और 'ग्लोबल साउथ' जैसे दृष्टिकोणों से संबंधों को व्यापक और अधिक रणनीतिक बनाया। अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी सक्रिय और स्वतंत्र भूमिका को मजबूत किया है। भारत की जी–20 अध्यक्षता के दौरान 'ग्लोबल साउथ' की आवाज को कूटनीतिक ढंग से प्रमुखता दी गई।

आतंकी नेटवर्क पर सफल स्ट्राइक

आतंकवाद–रोधी रणनीति केवल हमले के बाद जवाबी कार्रवाई तक सीमित न रहकर इंटेलिजेंस–लेड, प्रिसिजन स्ट्राइक और नेटवर्क–डिसरप्शन पर केंद्रित हुई है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में LoC के पार आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया, जबकि 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक में खुफिया जानकारी के आधार पर जैश–ए–मोहम्मद के प्रशिक्षण ढांचे पर प्रिसिजन एयर ऑपरेशन किया गया। इसके बाद 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन और बहुस्तरीय एयर–डिफेंस जैसी तकनीकों के इस्तेमाल के साथ पाकिस्तान और पाक अधिकृत क्षेत्र में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया। रणनीति का दूसरा तकनीकी स्तंभ नेटवर्क मैपिंग और फाइनेंशियल डिसरप्शन है–NIA, MHA की CTCR व्यवस्था और अन्य एजेंसियां आतंकी फंडिंग, डिजिटल / ऑनलाइन कट्टरपंथ, हथियार–तस्करी, भर्ती और अंतरराज्यीय / अंतरराष्ट्रीय लिंक की जांच पर काम करती हैं। FATF की 2024 मूल्यांकन रिपोर्ट ने भी भारत के आतंकवाद–वित्तपोषण विरोधी ढांचे को प्रभावी परिणाम देने वाला बताया है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व प्राचीन की प्रतिष्ठा

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को शासन की विमर्श–धारा में अधिक प्रमुखता मिली, जिसमें भारत की सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं और राष्ट्रीय पहचान को आधुनिक विकास के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम पुनर्विकास, महाकाल लोक जैसी परियोजनाएँ तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। 'विरासत भी, विकास भी' की सोच के तहत सरकार ने प्राचीन तीर्थस्थलों, आध्यात्मिक केंद्रों और सांस्कृतिक स्थलों के पुनर्विकास को पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही, भारतीय भाषाओं, पारंपरिक कला, आयुर्वेद और स्वदेशी ज्ञान–परंपराओं को वैश्विक मंच पर स्थापित किया।

'मेक इन इंडिया' को मिली नई ऊर्जा

वर्ष 2014 में शुरू 'मेक इन इंडिया' अभियान भारत को वैश्विक विनिर्माण, निवेश और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं, कारोबारी सुगमता, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से विनिर्माण को नई गति मिली। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन 2024–25 में ₹11.3 लाख करोड़ एवं निर्यात ₹ 3.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया। PLI योजना में दिसंबर 2025 तक 14 क्षेत्रों में ₹ 2.16 लाख करोड़ से अधिक निवेश, ₹ 20.41 लाख करोड़ से अधिक उत्पादन / बिक्री और 14.39 लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए। वहीं, चंद्रयान–3 की सफल लैंडिंग ने भारत की वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया।

○○○

हरियाणा सरकार
"देश में तेजी से हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का काम, भारत को उतनी ही तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बनाएगा।"
- नरेन्द्र मोदी
सुदृढ़ आधारभूत संरचना
विकास का आधार
नॉन स्टॉप हरियाणा
'प्रादेशिक सड़क उत्थान' परियोजना का शुभारम्भ।
योजना के तहत 4827 करोड़ रुपये की लागत से 9410 किलोमीटर लम्बी 4227 सड़कों का मरम्मत कार्य जारी।
वर्ष 2025-26 के दौरान नई सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर लगभग 212 करोड़ रुपये खर्च तथा 66 किलोमीटर लम्बी 28 सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु 36.18 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी।
वर्ष 2025-26 के दौरान सड़कों की विशेष मरम्मत पर लगभग 286 करोड़ रुपये खर्च तथा 1545 किलोमीटर लम्बाई की 567 सड़कों की विशेष मरम्मत हेतु 308 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी।
वाई.एम.सी.ए. चौक से बल्लभगढ़, बहादुरगढ़-मुंडका (दिल्ली), बदरपुर-मुजेसर (वाई.एम.सी.ए. चौक) व सिकंदरपुर स्टेशन से सैक्टर-56 तक मेट्रो रेल सेवा शुरू।
महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या, दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए हवाई सेवा शुरू। जल्द ही, जम्मू व अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा की होगी शुरुआत।
अम्बाला हवाई अड्डे के सभी सिविल कार्य पूर्ण। प्रस्तावित मार्गों पर जल्द होगी हवाई सेवा शुरू।
हिसार के गांव सिसाय में बनाया जाएगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ड्रोन हब।
सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा

हरियाणा के
विकास का
एक नया दौर
- नरेन्द्र मोदी
हरियाणा अब केवल कृषि का केंद्र नहीं, बल्कि ये तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग और अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बनने जा रहा है। राज्य सरकार लाई है 10 नीतियाँ, जो निवेश लाएंगी, इनोवेशन को बढ़ावा देंगी और बनाएंगी नए रोजगार के अवसर।
मेक इन हरियाणा नीति और अन्य सेक्टोरल नीतियों का हुआ शुभारम्भ
देश का नया ग्रोथ इंजन,
हमारा हरियाणा
औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग
विकास नीतियां
मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति
खिलौना एवं खेल उपकरण विनिर्माण नीति
फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेज़ नीति
डिजिटल और टेक्नोलॉजी
अर्थव्यवस्था की नीतियां
नई हरियाणा डेटा सेंटर नीति
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति
आईटी-आईटीईएस, एआई एवं इमर्जिंग प्रौद्योगिकी नीति
ई.एस.डी.एम. नीति
एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स (AVGC-XR) नीति
सतत विकास और ग्रीन
फ्यूचर से जुड़ी नीतियां
एग्री-बिज़नेस एवं फूड प्रोसेसिंग नीति
इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रीसाइक्लिंग नीति
सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा

नरेंद्रभाई मोदी- प्रचारक से प्रधानमंत्री तक की प्रामाणिक यात्रा

संस्मरण

हसुभाई दवे
(गुजरात गरिमा पदक–2026, सूरत)
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ
सूरत, गुजरात

वैसे तो मैं 1951 से बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बन गया था और 1967 से भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा। 1974 से पहले और बाद में मुझे आ. नरेंद्रभाई मोदी के साथ काम करने का अवसर मिला। अक्सर संघ के कार्यक्रमों में उनसे मुलाकात होती रहती थी। 1974 में 1 वर्ष तक हम अहमदाबाद कार्यालय में साथ रहे। सुबह संघ की शाखा पूरी होने के बाद, उनके हाथों से रात की बची हुई भाखरी का मसालेदार नाश्ता और चाय पीने को मिलती थी। एक प्रचारक के नाते मैंने उन्हें कपड़े धोने सहित सभी काम खुद करते देखा है। उनका स्वभाव, रहन–सहन और हर काम को सटीकता से करना उनके स्वभाव में ही शामिल था।

भारतीय जनता पार्टी में जब उन्हें गुजरात संगठन का प्रदेश महामंत्री बनाया गया, तब मैं गुजरात में शीर्ष टीम में होने के कारण अक्सर कई निर्णय लेते समय उनके साथ काम कर चुका हूँ। शुरुआत से ही उनका प्रभाव हर जगह था। उस समय गुजरात में तीन कार्यकर्ता प्रभावशाली थे, जिनमें से एक वे थे। आपातकाल (इमरजेंसी) के दौरान उन्होंने भूमिगत रहकर काम किया। गुजरात में भाजपा का विस्तार करने और विभिन्न चुनावों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। भाजपा के इस विस्तार और एक मजबूत नींव के पत्थर के रूप में उनकी रणनीति हमेशा बनी रही। उन्होंने डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया का भरपूर उपयोग किया।

गुजरात में स्वर्गीय आ. केशुभाई पटेल की सरकार के खिलाफ श्री शंकरसिंह वाघेला द्वारा किए गए विद्रोह के बाद जब राजनीतिक माहौल बदला, तब नरेंद्रभाई का मुख्यालय अहमदाबाद से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय 1994 में जब मैं भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय

महामंत्री बना, तो मेरा मुख्यालय भी दिल्ली हो गया और वहाँ भी उनसे मिलना–जुलना होता था। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने बिना किसी दिखावे के, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में और बिना किसी प्रचार की भूख के शांति से काम किया, जिसका मैं साक्षी हूँ।

हम सभी जानते हैं कि जब कच्छ में भयानक भूकंप आया और हर तरफ बड़ा हाहाकार मच गया था, तब 2001 में उन्हें प्रचारक जीवन से निकालकर एक राजनीतिज्ञ के रूप में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई और वे सक्रिय राजनीति में आए। सत्ता का कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद, उन्होंने शुरुआत से ही प्रशासन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। आज कच्छ का जो विकास हुआ है, उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। कच्छ को कभी बिना पानी और बबूल के पेड़ों वाला बीहड़ क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज वह औद्योगिक रूप से बहुत आगे है। उन्होंने नर्मदा का पानी कच्छ के अंतिम छोर तक पहुँचाया और कच्छ के रेगिस्तान को आज हरा–भरा बना दिया है। अमिताभ बच्चन जी की आवाज आज पूरे देश में गूँजती है।

उस समय जब गोधरा कांड हुआ और कारसेवकों की बलि ली गई, तब उनकी भूमिका हम सबने देखी है। उनके कार्यकाल में गुजरात में कभी कोई "सांप्रदायिक दंगा" या "कर्फ्यू" नहीं लगा। वे अपने चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात में अक्सर कहते थे कि आज की नई पीढ़ी को तो यह भी नहीं पता कि "कर्फ्यू" क्या होता है। वास्तव में उनकी यह बात बिल्कुल सच है। जिले–जिले में आयोजित उनके 'सदभावना' कार्यक्रमों की अनूठी छाप गुजरात की जनता आज भी याद करती है।

आज पूरे देश में "गुजरात मॉडल" शब्द गूँज रहा है। "वाइब्रेंट गुजरात" के माध्यम से गुजरात और देश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नए–नए उद्योगों और रोजगार के अवसरों को बढ़ाया गया। गुजरात में ऐसा विकास हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुजरात में जब तक वे 2014 तक मुख्यमंत्री रहे, तब तक उनसे नियमित मुलाकात होती रहती थी। जब भी मैं दिल्ली से गुजरात प्रदेश की समन्वय बैठक में जाता, तो उनसे मिलना तय रहता था।

अब 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की विजय हुई और दिल्ली जाने के बाद उनकी भूमिका, काम करने की पद्धति, स्वभाव, और विपक्ष के साथ–साथ एनडीए के सभी घटकों के साथ समन्वय बनाकर आगे कैसे बढ़ना है, काम कैसे करना है और करवाना है–इस बदलाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मेरी दृष्टि में, अपने स्वभाव के विपरीत जाकर भी वे सभी को साथ लेकर काम कर रहे हैं।

2019 में लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन राज्यसभा में पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण कई ऐसे कार्य थे जिन्हें वे दिल से करना चाहते थे, लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे थे। उस पीड़ा को हम देख सकते थे। एक बार जब मैं उनसे मिलने गया, तब वे चारों ओर से घिरे हुए थे; कई समस्याएँ और आपदाएँ आई थीं, लेकिन वे एक शब्द भी बोले बिना उन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। कांग्रेस उनके पीछे पड़ी हुई थी, फिर भी मैंने पूछा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं? यह सुनकर उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि ऐसी परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती ही हैं। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए और कहा कि मैं अपने सामने आने वाली "समस्या" को कभी समस्या नहीं मानता। बल्कि मैं अपने जीवन में आने वाली समस्या को एक अवसर (चुनौती) मानकर आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने बताया कि गांधीनगर में मेरे खिलाफ जो जांच हुई और 24 घंटे तक प्रश्नों की जो बौछार हुई, वह मेरे जीवन की एक दुखद घटना थी, फिर भी मैंने उसका दृढ़ता से सामना किया और मुझे 'क्लीन चिट' मिली, उसका कारण भी यही दृष्टिकोण है।

पहले हमारा भारत देश 'विश्व गुरु' के रूप में जाना जाता था, वही फिर से "विश्व–गुरु" बने–यही भावना है। यदि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा, तो परम पूजनीय डॉ. हेडगेवार जी के शब्द सत्य सिद्ध होंगे और हम इसे अपने जीवनकाल में देख सकेंगे। दूसरी बात, हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि एक समय ऐसा भी आएगा, जब भारत पुनः 'हिंदू राष्ट्र' बनेगा, जैसा कि वह पहले था। उनकी वर्तमान की सभी गतिविधियां और "राम मंदिर" का निर्माण इसी दिशा में उठाया गया कदम है। अत्यधिक अपेक्षाएं रखने के बजाय धीरे–धीरे आगे बढ़ने में ही सबका हित है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

हम सभी जानते हैं कि किस तरह से कश्मीर से धारा 370 और 35–ए को हटाया, वो हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। हमारे मन में यह सवाल आ सकता है कि ऐसा विचार कब और किसने किया होगा? आ. आडवाणी जी की सोमनाथ से रथ यात्रा या आ. मुरलीमनोहर जोशी जी की "तिरंगा झंडा" फहराने की योजना (जिसमें आ. नरेंद्रभाई मोदी कश्मीर के लाल चौक में उपस्थित थे)–स्वाभाविक रूप से हमारे मन में आता है कि यही दो कारण रहे होंगे।

लेकिन आ. नरेंद्रभाई मोदी 1984–85 में प्रचारक थे और उनका कश्मीर से संबंध उनके प्रधानमंत्री बनने के बहुत समय पहले ही शुरू हो गया था। 1984–85 में पुणे में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग में "वर्तमान भारत की समस्याएं" शीर्षक से दिए गए उनके भाषण में इस उद्देश्य के प्रति उनका उत्साह और समर्पण साफ झलकता था। उस समय महज 35 वर्ष की आयु के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक मोदी ने जम्मू–कश्मीर मुद्दे पर अपने भाषण में धारा 370 और धारा 35(ए) के तहत लागू भेदभावपूर्ण भूमि कानूनों की कड़ी आलोचना की थी। इन दो भेदभावपूर्ण धाराओं के कानूनी और तकनीकी पहलुओं सहित इस मुद्दे पर मोदी की समझ की गहराई आश्चर्यजनक थी। उन्होंने लागू की गई भेदभावपूर्ण व्यवस्था के आत्मघाती परिणामों और ये दोनों धाराएं सामान्य रूप से भारत के लिए और विशेष रूप से कश्मीर के लोगों के कल्याण के लिए कैसे हानिकारक थीं, इस बारे में विस्तार से बताया और इसके राजनीतिक परिणामों को भी समझाया।

2001 में मुख्यमंत्री बनने से लेकर 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक, बिना एक भी छुट्टी लिए निरंतर देश की चिंता करना ही हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

परमकृपालु परमेश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें स्वस्थ रखे और वे राष्ट्र निर्माण में एक सेवक, चौकीदार और एक आम आदमी (कॉमन मैन) के रूप में कार्य करते रहें।

○○○

युगदृष्टा नरेंद्र भाई की सोच राजनेता की नहीं, बल्कि स्टेट्समैन की

संस्मरण

ज्योतिंद्र मेहता
टैक्स प्रैक्टिशनर एवं समाजसेवी
राजकोट, गुजरात

नरेंद्र भाई से मेरा पहला परिचय संघ के स्वयंसेवक के नाते ही हुआ। संपर्क हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक में। ये बात वर्ष 1973–74 की रही होगी। राजकोट के मेयर और विधायक रहे मेरे जीजाजी श्री अरविन्द भाई मनियार गुजरात में जनसंघ को खड़ा करने वाले शुरुआती प्रमुख लोगों में से रहे हैं।

मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिस करता था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् में सक्रिय रहा और बाद में सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व भी मिला। संघ की बैठकों में सहज रूप से नरेंद्र भाई से मिलना होता रहा। आपातकाल में मीसा में कैद कर मुझे भी जेल में रखा गया। जेल में बिताये 11 महीनों में पहले साबरमती जेल में और फिर भावनगर में ट्रांसफर किया था। उस समय भी नरेंद्र भाई हम सबकी जानकारी रखते थे।

गुजरात में वर्ष 1974 में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ। ये वास्तव में एक ऐतिहासिक सामाजिक–राजनीतिक आंदोलन था जो छात्रों और मध्यम वर्ग द्वारा कमरतोड़ महंगाई, खाद्य संकट और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया गया। चिमन भाई पटेल उस समय मुख्यमंत्री थे और पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ था। जनता में अपार असंतोष था और उस समय जनता के बीच से ही निकले उस आंदोलन में हम सब 20 से 25 बरस के युवाओं ने सक्रिय भागीदारी की थी। यानी उस समय के हम ही जेन–जी रहे थे। और आखिरकार उसका परिणाम ये हुआ कि तत्कालीन सभी विधायकों ने जनता के उस आंदोलन के दबाव में अपने इस्तीफे दे दिए। और गुजरात विधानसभा भंग हो गई।

वर्ष 2001 में जब नरेंद्र भाई को दिल्ली से सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने का आदेश हुआ, तो बिना निर्वाचित हुए उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला और हमारे राजकोट से ही उन्होंने चुनाव लड़ा। तो फिर उस चुनाव में भी कार्य किया। वोटिंग के दिन उनके साथ कार में ही था पूरे दिन जब लगातार बूथ से बूथ हम जा रहे थे।

सबसे खास बात ये है कि नरेंद्र भाई किसी सामान्य राजनेता की तरह नहीं सोचते, जो चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव की चिंता करते हैं। बल्कि वे स्टेट्समैन की तरह, राज्यकर्ता की तरह से सोचते हैं आने वाली कई पीढ़ियों तक के बारे में। इसलिए लोग उन्हें विजनरी यानी युगदृष्टा भी कहते हैं। मोदी जी अपने जादुई शब्दों से आत्मविश्वास से भरा ऐसा वातावरण पैदा कर देते हैं, जो उन्हें जन नेता के तौर पर स्थापित करता है।

मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, तो कहते थे कि 'मैं पांच करोड़ गुजरातियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ' इसी तरह प्रधानमंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों से वे 140 करोड़ भारतीयों को अपने कथन से जोड़ते हैं, तो वो अंदाज लोगों को अपील करता है। उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास की तुलना जर्मनी और जापान से होनी चाहिए, देश के अन्य राज्यों के साथ नहीं। उन्होंने गुजरात मॉडल को भी सफल करके बताया। ○○○

In conversation with Dr. Sanjay Mishra, Co-Editor, Udyog Times

- नरेन्द्र मोदी
हमारे खिलाड़ी - गर्व हरियाणा का - गौरव भारत का
स्वर्ण
रजत
कांस्य
कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 के पदक विजेता तथा प्रतिभागी खिलाड़ियों को
कुल ₹13,97,50,000 की नकद पुरस्कार राशि देकर किया सम्मानित
स्वर्ण पदक ₹1.5 करोड़
रजत पदक ₹75 लाख
कांस्य पदक ₹50 लाख
प्रतिभागी खिलाड़ी ₹7.5 लाख
देश के कुल पदकों में से
28 प्रतिशत पदक केवल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते
सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा

मित्रता और निजी संबंधों को जीवन भर निभाते हैं नरेंद्र भाई

संस्मरण
गिरीश भाई भट्ट
वरिष्ठ अधिवक्ता
राजकोट, गुजरात

5 जून, 1972 का वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने और नरेंद्र भाई दोनों ने साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर अपनी नई यात्रा शुरू की। उन्हें कर्णावती महानगर की जिम्मेदारी दी गई और मुझे कच्छ जिला प्रचारक की। तब से उनसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।

वर्ष 1944 में राजकोट में संघ की शाखा शुरू हुई, मेरे पिताजी और चाचाजी दोनों ही पहले स्वयंसेवक बने, उन्होंने शाखा में जाना शुरू किया और फिर स्वयंसेवक बनाते भी रहे। इसलिए बचपन से ही मुझे शाखा का संस्कार भी मिला।

बात वर्ष 1975 की है; जब देश में इमरजेंसी लागू की गई। 4 जुलाई को संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसका आभास हमें पहले ही हो गया था। प्रान्त के अधिकारियों से उससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें मिलती रहती थी। गुजरात में उस समय कांग्रेस की सरकार में बाबुलभाई जसनाथ भाई पटेल उपमुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने प्रदेश में मीसा का कायदा–कानून तो लागू नहीं किया, लेकिन डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को जेल में जरूर डाल दिया। ऐसे कठिन समय में अंडर ग्राउंड रहकर स्वयंसेवकों से और जेलों में बंद स्वयंसेवकों के परिवारों से मिलकर उनको हिम्मत बढ़ाने का कार्य करना हमारी प्राथमिकता थी।

नरेंद्र भाई उस समय पूरे गुजरात प्रदेश का मार्गदर्शन करते थे और मैं खेड़ा जिले में प्रचारक था। भूमिगत रहकर हमें यहां विविध प्रचार सामग्री को तैयार भी करना होता था क्योंकि इसकी जिम्मेदारी भी इसी जिले पर थी; तो यहीं से पत्रिका छपकर देशभर में वितरित की जाती थी।

इमरजेंसी के खात्मे के बाद वर्ष 1986 में नरेंद्र भाई को संघ से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का दायित्व मिला। वर्ष 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर नरेंद्र भाई को ये जिम्मेदारी दी गई और जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, वो सब हम जानते ही है।

नरेंद्र भाई में जो विशेष गुण है, वो है उनकी सहजता। वे जिनसे भी सम्बन्ध बनाते हैं, उसे जीवन भर निभाते भी हैं। परिवार के मांगलिक कार्यों में अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल कर शामिल होते हैं। अभी 11 जनवरी, 2026 को मेरे 75वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने सभी को प्रेरित किया और ये संदेश दिया कि बड़े पद पर रहकर भी वे अपने स्वयंसेवक के दायित्व बोध को आज तक निभाते हैं। ○○○

In conversation with Dr. Sanjay Mishra, Co-Editor, Udyog Times

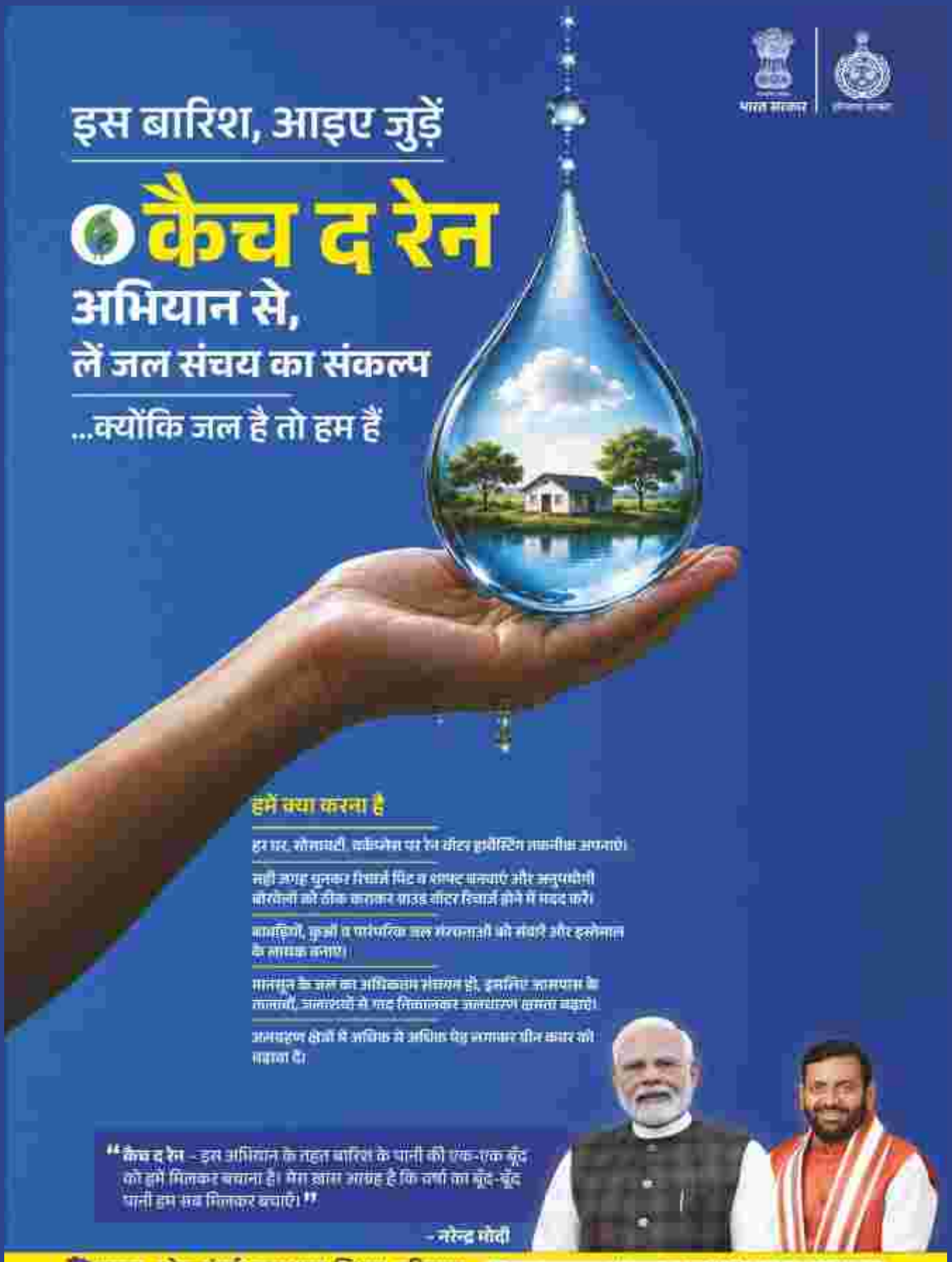

इस बारिश, आइए जुड़ें
कैच द रेन
अभियान से,
लें जल संचय का संकल्प
...क्योंकि जल है तो हम हैं
हमें क्या करना है
हर घर, सोसायटी, कॉम्प्लेक्स पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं।
सही जगह चुनकर रिचार्ज पिट व शाफ्ट बनवाएं और अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक कराकर ग्राउंड वॉटर रिचार्ज होने में मदद करें।
बावड़ियों, कुओं व पारंपरिक जल संरचनाओं को संवारें और इस्तेमाल के लायक बनाएं।
मानसून के जल का अधिकतम संचयन हो, इसलिए आसपास के तालाबों, जलाशयों से गाद निकालकर जलधारण क्षमता बढ़ाएं।
जलग्रहण क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ लगाकर ग्रीन कवर को बढ़ावा दें।
"कैच द रेन - इस अभियान के तहत बारिश के पानी की एक-एक बूंद को हमें मिलकर बचाना है। मेरा खास आग्रह है कि वर्षा का बूंद-बूंद पानी हम सब मिलकर बचाएं।"
- नरेन्द्र मोदी
सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा

जब नरेंद्र भाई ने राष्ट्रीय एकता यात्रा में मुझे जोड़ा

संस्मरण

वजुभाई वघासिया
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
लघु उद्योग भारती

बात है वर्ष 1991 की, जब भारतीय जनता पार्टी की चर्चित राष्ट्रीय एकता यात्रा की तैयारी हो रही थी। राष्ट्रीय एकात्मता का सूत्रपात्र करने वाली उस यात्रा की अगुवाई करने वाले थे भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर जोशी। वास्तव में उस महत्वपूर्ण यात्रा का उद्देश्य ये दर्शाना भी था कि भाजपा राष्ट्रीय एकता का समर्थन करने के साथ अलगाववादी आंदोलनों का पुरजोर विरोध करती है।

यह यात्रा महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती 11 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू–कश्मीर के श्रीनगर तक 26 जनवरी को समाप्त होनी थी जहाँ लाल चौक पर तिरंगा फहराने का संकल्प पूरा करना था।

श्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर जोशी, श्रीमती विजया राजे सिंधिया के साथ श्री नरेंद्र मोदी

14 राज्यों से होकर गुजरने वाली उस यात्रा को सफल बनाने में श्री नरेंद्र मोदी ने भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। यात्रा से पहले नरेंद्र भाई ने मुझे बुलाया और कहा कि वजूभाई, इस ऐतिहासिक यात्रा में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं को राखी बांधनी है और उसके लिए हमें हजारों की संख्या में राखियां बनानी भी हैं। तो उसके लिए कुछ धन संग्रह कीजिये। मैंने दुबई में मेरे मित्र से बात की और 17 हजार रुपये की व्यवस्था की। उस सहयोग राशि से बनी राखियां नरेंद्र भाई ने यात्रा के दौरान हजारों कार्यकर्ताओं की कलाई पर बाँधी।

गौतम अडानी और नरेंद्र भाई की पहली मुलाक़ात का बना सूत्रधार और साक्षी

वैसे तो वर्ष 1982 से ही मेरा व्यापारिक तौर पर श्री गौतम अडानी से सीधा जुड़ाव रहा। लेकिन 1992 से उनकी कंपनी द्वारा आयात किये गए प्लास्टिक के रॉ मटेरियल को गुजरात और पड़ौसी राज्यों में मैं ब्रोकर के रूप में सप्लाई करता रहा था। और उसके बाद 1994 में मैंने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई जिसमें इजराइल के साथ हमने कोलेबोरेशन किया ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए। इस अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल, श्री नरेंद्र भाई मोदी, श्री अमित शाह और श्री शंकर सिंह वाघेला सभी कंपनी ऑफिस के शुभारंभ पर आये थे। जब हम कंपनी का पब्लिक इश्यू लाये, तो कंपनी के शुरुआती 7 शेयर होल्डर्स में श्री गौतम अडानी के भाई श्री वसंत अडानी भी शामिल हुए जो अडानी रियलिटी सेक्टर का काम देखते थे।

फिर प्रदेश में चुनाव का दौर आया और मैं उस समय लघु उद्योग भारती का गुजरात प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कोष कमेटी का सदस्य था, इसमें अमित भाई शाह और मोदी जी भी शामिल थे। और इसी सिलसिले में नरेंद्र भाई और गौतम भाई के बीच पहली मीटिंग मैंने ही कराई। दोनों आज के दिग्गज –एक विजनरी लीडर और एक विजनरी एंटरप्रिन्योर। दोनों के बीच देश की औद्योगिक प्रगति और चुनौतियों के बारे में गहन चिंतन चला।

○○○

In conversation with Dr. Sanjay Mishra, Co-Editor, Udyog Times

मोदी जी की छोटी-छोटी आदतों में छिपा होता है जीवन-दर्शन

संस्मरण

प्रोफेसर (डॉ.) अजय पारीख
अधिष्ठाता, फैकल्टी ऑफ
इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन,
गुजरात विद्यापीठ, कर्णावती

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदीजी के साथ जुड़े जीवन के कुछ अनुभव केवल व्यक्तिगत स्मृतियाँ नहीं, बल्कि उनसे मिली सीख और जीवन–मूल्यों के महत्वपूर्ण पड़ाव भी हैं।

मातृभाषा के प्रति उनका विशेष आग्रह

यह बात वर्ष 1991–92 के आसपास की है। उस समय भारत में कंप्यूटर का उपयोग प्रारंभिक चरण में था। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के कंप्यूटरीकरण का कार्य मुझे सौंपते हुए नरेंद्रभाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस कार्य से संबंधित सभी रिपोर्ट मातृभाषा गुजराती में ही होनी चाहिए। उस समय कंप्यूटर पर गुजराती भाषा में काम करना तकनीकी रूप से काफी कठिन था। फिर भी उनके मातृभाषा के प्रति दृढ़ आग्रह को देखते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया और अंततः यह कार्य बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ। इस अनुभव से मैंने सीखा कि आधुनिक तकनीक अपनाते हुए भी अपनी भाषा और सांस्कृतिक पहचान साथ लेकर चलना संभव है।

छोटी सजगता में बचत का सन्देश

उस समय नरेंद्रभाई अहमदाबाद स्थित हेडगेवार भवन में रहते थे। एक दिन बैठक समाप्त होने के बाद मुझे हॉस्टल जाना था। उन्होंने कहा, "मैं भी पालडी की ओर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूं। तुम स्कूटर चलाओ।" मैंने स्कूटर चालू किया, उसे स्टैंड से उतारा और थोड़ा पीछे किया। इसके बाद मैंने उनसे बैठने के लिए कहा। तब उन्होंने मुझे समझाया कि यदि स्कूटर को पहले बंद अवस्था में ही पीछे ले लिया जाता और उसके बाद इंजन चालू किया जाता, तो कुछ पेट्रोल की बचत हो सकती थी। यह बात देखने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन यह एक बड़ी सीख थी। संसाधनों का सदुपयोग, अनावश्यक खर्च से बचना और छोटी–छोटी बातों के प्रति सजग रहना– ये जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार हैं।

समाज के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा

वर्ष 1980 में मैंने दसवीं कक्षा की परीक्षा दी थी। उस समय नरेंद्रभाई हमारे घर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान किसी एक गाँव में जाकर कुछ समय बिताऊँ और वहाँ शाखा का कार्य प्रारंभ करूँ। उनके मार्गदर्शन के अनुसार मैं भिलोडा तालुका के लगभग सौ घरों वाले एक छोटे से गाँव में दस दिनों तक रहा और वहाँ शाखा का कार्य किया। उस दौरान नरेंद्रभाई का एक पत्र भी मुझे प्राप्त हुआ था। उसमें व्यक्त मार्गदर्शन और अपनापन आज भी मेरी स्मृतियों में जीवंत है। मेरे जीवन में समाज के प्रति संवेदनशील बनने, ग्रामीण समाज को निकट से समझने और लोगों के साथ जुड़ने की जो पहली प्रेरणा मिली, उसमें इस अनुभव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ○○○

अदभुत स्मरण शक्ति और हंसमुख स्वभाव के धनी हैं नरेंद्र भाई

संस्मरण

जयभाई मवानी

राजकोट में सीएनसी मशीन टूल्स के अग्रणी निर्माता और सफल उद्योगपति स्वर्गीय श्री वजुभाई मवानी जी के पुत्र श्री जयभाई मवानी मोदी जी के साथ अपने पिता के संबंधों को याद करते हुए बताते हैं कि सामान्य तौर पर लोग नरेंद्र मोदी जी को बहुत सख्त और गंभीर व्यक्ति ही मानते हैं। लेकिन वास्तव में उनका व्यक्तित्व बहुत ही मिलनसार और मजाकिया स्वभाव का रहा है। और इसके साथ ही उनकी याददाश्त भी उतनी ही अद्भुत थी। मेरे पिताजी श्री वजुभाई मवानी के साथ उनका बहुत अच्छा मेलजोल रहा था। पिताजी जब भी उनसे मिलते, तो उसी मजाकिया लहजे में उनसे पूछते भी कि आजकल नागपुरी संतरों का क्या हालचाल है! अब ये तो सभी को मालूम है ही कि नागपुर के संतरे तो सर्व विख्यात है, लेकिन नागपुर में संघ का मुख्यालय भी तो है, तो ये सांकेतिक भाषा हुआ रहती थी विनोद के लिए कि वहां सब ठीक–ठाक है ना? और मोदी जी ये सुनकर मुस्कुरा के बोलते थे कि सब ठीक–ठाक है।

अब बात उस समय की है जब पिताजी राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे और करीब 20 वर्षों के बाद जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें एक कार्यक्रम में वहां आमंत्रित किया गया था। तय समय मोदी जी कार्यक्रम में आये, और जब वो मंच की ओर साथ में बढ़ रहे थे तभी मोदी जी ने पिताजी की ओर देखते हुए कहा कि वजुभाई, नागपुरी संतरे आजकल बिलकुल ठीक हैं। और उनके ये कहने के बाद दोनों एक साथ ठहाका लगाते हुए आगे बढ़ गए। ○○○

In conversation with Dr. Sanjay Mishra, Co-Editor, Udyog Times

Prime Minister Modi as BRAND AMBASSADOR

Shaping a Positive Image of India Globally

Perception

Dr. Anil Kalera

Medical Practitioner & Entrepreneur

Moscow, Russia

I am a doctor by profession, but later transitioned into the natural stone business. I came to Russia in 1991 and, after nearly three decades of living and doing business here, became a Russian citizen in 2021. Despite having settled in Russia, I have continued to closely follow every significant development in India and remain deeply interested in the country's progress and transformation.

Among the people I know, the general mood towards the Modi government has been positive. The Swachh Bharat cleanliness drive is frequently mentioned, particularly because its impact is highly visible when one returns to India after spending time abroad, rather than living in the same environment continuously. Beyond this, there is a clear perception of India's improved international standing and its growing influence in global politics. National security has also strengthened, alongside greater structural integration within the country. At the same time, India's digital public infrastructure has received international recognition, with UPI emerging as a highly successful payment system that outperforms many established international alternatives.

Public opinion regarding Shri Narendra Modi abroad has consistently remained positive, and Russia is no exception; in fact, the friendship between India and Russia ranks among those select international relationships that have always remained stable and steadfast- a fact that instils confidence when mentioned in discussions.

In my view, the following are some sectors with promising future potential for India and Russia where further progress can be achieved:

Construction, Agriculture, Mining and Machine Manufacturing.

○○○

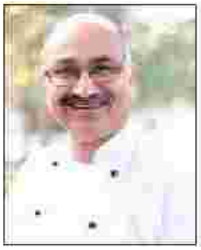

Perspective

Dayashankar Sharma

Celebrity Chef & Businessman

London, United Kingdom

I hail from a village near Jaipur, the capital of Rajasthan; my journey took me to Sri Lanka, Switzerland, France, and finally London, where I worked as a chef and made a name for myself in the culinary world. I have been working in this industry for the past 40 years and have been based in London since 2000, where we run Indian restaurants including Heritage Dulwich London, Jhakaas London, Bauji Worthing UK.

Over the past 12 years, India has undergone a significant transformation under Prime Minister Narendra Modi, gaining greater confidence, modernisation, economic momentum and global influence. For NRIs, particularly in the UK, this progress has strengthened their pride in India and deepened their connection with their motherland. India is increasingly viewed not only as a nation of rich heritage and tradition but also as a country of innovation, opportunity, ambition and a promising future.

The growing India-UK relationship also offers significant opportunities in the hospitality and food sectors. Collaboration in modern Indian cuisine, premium food brands, chef exchanges, culinary education, food technology, sustainable sourcing, tourism, hospitality training, franchising and food processing could create jobs, encourage entrepreneurship and further strengthen bilateral ties.

Thus, food and hospitality can serve as an important bridge between India and the UK, combining India's culinary heritage with British expertise and global markets.

I had the opportunity to serve India's Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, his favourite dish; however, I would love the chance to cook something special for Modi ji as well, whenever he visits London.

In conversation with Dr. Sanjay Mishra, Co-Editor, Udyog Times

○○○

मोदी जी के व्यक्तित्व पर पद कभी हावी नहीं हुआ, वे सहज कार्यकर्ता ही बने रहे

संस्मरण

डॉ. विद्याधर वैद्य
वरिष्ठ शिक्षाविद, आणद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी
पूर्व गुजरात प्रदेश अध्यक्ष एवं
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, विज्ञान भारती

वर्ष 2003 में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से पहला परिचय पुणे में हुआ, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जिला ग्राम विकास प्रमुख की जवाबदारी मेरे पास थी। मोदी जी मुख्यमंत्री थे और उनसे ये परिचय कराया हमारे पश्चिम महाराष्ट्र के प्रांत कार्यवाह श्री वार्ष्णेय जी ने, जो बाद में 2004 में आणद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी नियुक्त किये गए।

वर्ष 2009 में मुझे विज्ञान भारती में प्रांत संगठन मंत्री का दायित्व मिला। तो वर्षभर में आयोजित दो समन्वय बैठकों में जाना होता था। नरेंद्र भाई अपनी व्यस्तता के बावजूद इन बैठकों में पहुंचने की पूरी कोशिश करते। ऐसी ही एक बैठक में मा. भैयाजी जोशी पधारे थे, मैं मंच के सामने दूसरी पंक्ति में बैठा था, और नरेंद्र भाई 11 वीं पंक्ति में। उन्होंने कभी ये जताने की कोशिश नहीं की, कि वे बड़े पद पर हैं। बैठक के बाद जमीन पर ही बैठकर सब कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करते। ये ही उनके व्यक्तित्व की विलक्षणता भी रही।

2011 में ऊर्जा जनजागरण विषय को लेकर देशभर में 4 यात्राएं निकली थी, उनमें से पश्चिम क्षेत्र की यात्रा के संयोजन की जिम्मेदारी मेरे पास थी जिसे राजकोट से शुरू होकर 8 दिन तक गुजरात के विविध क्षेत्रों से गुजरना था। तो उसके फ्लैग ऑफ़ के लिए नरेंद्र भाई को आमंत्रित करने के लिए हमारा शिष्टमंडल मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा। चश्मा तब भी लगा था, लेकिन उनकी आँखों में अलग ही तेज था और बॉडी लेंगुएज बहुत पॉजिटिव। उन्होंने यात्रा के लिए संदेश भी दिया, और अपेक्षित अर्थ सहयोग भी करवाया। हमारे साथ राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री जयंत सहस्रबुद्धे भी थे जिनसे उन्होंने उनकी भाषा मराठी में बात की। करीब 20 मिनट की इस मीटिंग में उन्होंने न कोई फोन रिसीव किया, न कोई अधिकारी बीच में आया।

गोधरा दंगों का समय बहुत कठिन था, कई तरह के सवाल उठाये गए, लेकिन नरेंद्र भाई ने सद्भावना यात्रा के साथ सभी तथ्यों को लोक जीवन (पब्लिक डोमेन) में रखा और फिर से गुजरात में विश्वास का वातावरण बनाया। उसी दौरान उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसमें विविध क्षेत्रों में कार्यरत सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी माँगा। इस तरह से वे समाज के सभी वर्गों के लोगों और पेशेवरों से निरंतर संवाद रखते थे।

○○○

हरेक कार्यकर्ता की खोज-खबर रखते हैं मोदी जी

संस्मरण

हंसराज भाई गजेरा
प्रदेश महामंत्री
लघु उद्योग भारती, गुजरात

खोड़धाम का जब निर्माण हो रहा था, तब मैं संगठन का प्रदेश महामंत्री था। कई कार्यक्रमों में मोदी जी ने स्वयं आकर हम सभी को प्रेरित किया। ऐसा ही एक कार्यक्रम था कृषि मेला – एग्रीविजन। मोदीजी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उद्घाटन समारोह में आए थे। उनके पास उससे जुड़ी बहुत महीन डिटेल्स थी, एक–एक बात की जानकारी, बैठक व्यवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि। इसी तरह से ये उनका स्वभाव ही रहा कि जो भी विषय उनके सामने आता, तो उसकी पूरी पड़ताल वे करवाते।

मोदी जी अपने पुराने साथी कार्यकर्ता की भी पूरी खबर रखते। जब भी उनकी विजिट कहीं होती थी, तो वे उस क्षेत्र के आसपास के पुराने कार्यकर्ता से आकस्मिक मिलने पहुंच जाते, या उन्हें सूचना पहुंचा देते। ये संपर्क उनका इतना सजीव होता था कि उनकी राजनीति और समाज दोनों ही जगह सहज स्वीकार्यता गहरी होती चली गई।

छोटे–बड़े आंदोलन नरेंद्र भाई के सामाजिक–राजनीतिक जीवन में कई आये। लेकिन वे हमेशा धीरज से काम लेते। वर्ष 2017 में चुनाव के अगले ही दिन मुझे श्री अमित भाई और मोदी साहब को मिलने का अवसर मिला। पाटीदार आरक्षण से जुड़ा बिन अनामत आंदोलन की वजह से स्थिति गंभीर थी। लेकिन दोनों नेताओं के चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था।

In conversation with Dr. Sanjay Mishra, Co-Editor, Udyog Times

○○○

नमो नेतृत्व – 'गुजरात मॉडल' से उभरते नए भारत तक

अंतर्मन
पराक्रम जाडेजा
चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर
ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड
राजकोट, गुजरात

बदला हुआ भारत, और ध्यान देती दुनिया–

केवल बारह वर्षों में भारत ने एक ऐसा परिवर्तन रच दिया है, जो कभी कल्पना से परे लगता था। जब श्री नरेन्द्र मोदीजी ने 2014 में प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, तब दुनिया भारत को एक महान संभावनाओं वाले देश के रूप में देखती थी। आज वह तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आईएमएफ, ओईसीडी और संयुक्त राष्ट्र – सभी भारत को विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताते हैं। वॉशिंगटन से ब्रुसेल्स तक और टोक्यो से रियाद तक की सरकारें अपनी योजनाएँ भारत को केंद्र में रखकर नए सिरे से लिख रही हैं।

लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने गुजरात की धरती पर अपने व्यवसाय खड़े किए हैं, इनमें से कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। हमने यह कहानी बहुत पहले शुरू होते देखी थी – अपने ही राज्य में, अपने ही कारखानों में – जब श्री मोदीजी ने 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वह मॉडल गढ़ा, जिसे आज दुनिया "गुजरात मॉडल" कहती है। जो उन्होंने बाद में भारत के लिए किया, वह पहले गुजरात के लिए कर दिखाया था। एक ऐसे उद्यमी के रूप में, जिसने दोनों अध्यायों को जिया है, मैं इस अद्भुत यात्रा पर अपना दृष्टिकोण साझा करना चाहता हूँ – और यह भी बताना चाहता हूँ कि इसका मेरी अपनी कंपनी, ज्योति सीएनसी के लिए क्या अर्थ रहा है।

गुजरात मॉडल–शुरुआत कैसे हुई...

जब श्री मोदीजी ने अक्टूबर 2001 में पदभार संभाला, तब गुजरात भुज के विनाशकारी भूकंप से उबर रहा था, बिजली की भारी कमी से जूझ रहा था, और राज्य विद्युत बोर्ड लगभग दिवालिया हो चुका था। अगले तेरह वर्षों में उनकी सरकार ने गुजरात को भारत का सबसे औद्योगिक और निवेशक–हितैषी राज्य बना दिया – एक ऐसा मॉडल, जो इतना सफल रहा कि आज देश भर के नेता कहते हैं कि हर राज्य को इसे अपनाना चाहिए।

परिणाम स्वयं बोलते हैं–

गुजरात ने 2026 में नीति आयोग के पहले निवेश मित्रता सूचकांक (Investment Friendliness Index) में प्रथम स्थान प्राप्त किया, हाल के वर्षों में लगभग 74 अरब अमेरिकी डॉलर का संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया, और देश की केवल लगभग 5 प्रतिशत जनसंख्या होते हुए भी भारत के वस्तु निर्यात में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देता है।

उनका सबसे परिवर्तनकारी प्रारंभिक योगदान था बिजली व्यवस्था को सुधारना, जिसके बिना कोई कारखाना चल ही नहीं सकता। ज्योतिग्राम योजना (2003–2006) के माध्यम से 18,000 से अधिक गाँवों में कृषि फीडरों को घरेलू और औद्योगिक फीडरों से अलग किया गया, जिससे गुजरात 24×7 निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण थ्री–फेज़ बिजली देने वाला भारत का पहला राज्य बना। उन्होंने घाटे में चल रहे विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन कर इस क्षेत्र को लाभ में ला दिया। हम जैसे निर्माताओं के लिए यह क्रांतिकारी था – मोरबी, सूरत, अंकलेश्वर, वापी, भावनगर और राजकोट के ऊर्जा–प्रधान उद्योगों को अब न डीज़ल जनरेटरों की आवश्यकता रही, न उत्पादन ठप होने की चिंता। सोलर पॉलिसी–2009 और चारणका सोलर पार्क के माध्यम से उन्होंने गुजरात को नवीकरणीय ऊर्जा का अग्रदूत भी बनाया – सौर ऊर्जा के राष्ट्रीय मिशन बनने से वर्षों पहले 2003 में उन्होंने वाइब्रेंट

गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत की, जो भारत का प्रमुख निवेश आयोजन बन गया और भारतीय शासन–व्यवस्था में सबसे अधिक अपनाया गया विचार सिद्ध हुआ। उन्होंने स्वयं वैश्विक सीईओ को प्रोत्साहित किया, अपना कार्यालय निवेशकों के लिए सीधे सुलभ बनाया, और मौके पर ही एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

संदेश सरल और सशक्त था–

गुजरात में सरकार स्वयं व्यवसाय की सबसे बड़ी सहायक है। उन्होंने गुजरात की 1,600 किलोमीटर लंबी तटरेखा – जो किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबी है – का आक्रामक विकास किया, और मुंद्रा तथा पिपावाव जैसे बंदरगाह भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में बदल गए। आज गुजरात भारत के लगभग 40 प्रतिशत बंदरगाह कार्गो का संचालन करता है, और वह भी देश के सबसे कम टर्नअराउंड समय के साथ।

वे चुनावी चक्रों में नहीं, दशकों में सोचते थे–

2009 के विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) अधिनियम से धोलेरा जैसे नियोजित मेगा–औद्योगिक क्षेत्र बने – जो आज भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब का स्थल है – जबकि 2007 में परिकल्पित गिफ्ट सिटी आज भारत का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। नर्मदा नहर नेटवर्क और सुजलाम सुफलाम योजना ने सूखे सौराष्ट्र और कच्छ तक पानी पहुँचाया, और भारत के कुछ सर्वश्रेष्ठ राजमार्गों ने हर औद्योगिक क्लस्टर को बंदरगाहों और बाज़ारों से जोड़ दिया। भरोसेमंद बिजली, भरोसेमंद पानी और भरोसेमंद सड़कें–यह त्रिवेणी गुजरात की अजेय अधोसंरचना बन गई।

ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस– गुजरात के निर्माताओं को वास्तव में क्या मिला

यही गुजरात मॉडल का हृदय है, और मैं यह अपने जिए हुए अनुभव से कह रहा हूँ। श्री मोदीजी के नेतृत्व में गुजरात में इकाई स्थापित करने वाले निर्माता को ऐसे लाभ मिले, जिनकी बराबरी बहुत कम राज्य कर सकते थे:

- तेज़ और विवाद–मुक्त भूमि
- सिंगल–विंडो क्लियरेंस
- निर्णय लेने की गति
- स्थिर, दीर्घकालिक नीतियाँ
- शांतिपूर्ण श्रम वातावरण

इसके परिणाम उन कंपनियों में स्पष्ट दिखते हैं, जो गुजरात आईं और फली–फूलीं:

- साणंद में टाटा मोटर्स, जिनका स्वागत मोदीजी के प्रसिद्ध एक–शब्द के संदेश "सुस्वागतम" से हुआ;
- हंसलपुर में सुजुकी का विश्व का सबसे बड़ा विस्तार, जहाँ आज प्रतिवर्ष दस लाख से अधिक कारें बनती हैं; साणंद में फोर्ड;
- विट्ठलापुर में होंडा और हालोल में हीरो मोटोकॉर्प; हालोल में जनरल मोटर्स का संयंत्र, जो अब जेएसडब्ल्यू के साथ एमजी मोटर चला रही है;
- जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी – विश्व की सबसे बड़ी;
- अदाणी का मुंद्रा;
- मोरबी का सिरेमिक क्लस्टर, जो भारत के लगभग 90 प्रतिशत सिरेमिक का उत्पादन करता है;
- दहेज, अंकलेश्वर और वापी की फार्मा एवं केमिकल बेल्ट;
- सूरत के टेक्सटाइल और हीरे;
- और अब सेमीकंडक्टर युग – साणंद में माइक्रोन,
- धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स–पीएसएमसी फैब, और
- वडोदरा में टाटा–एयरबस C295 विमान संयंत्र।

इनमें से हर एक उस पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) की पुष्टि है, जिसे उन्होंने खड़ा किया – और यही गुजरात मॉडल की सफलता है।

ज्योति सीएनसी की कहानी–गुजरात मॉडल का हमारा अपना अनुभव

मैं गुजरात मॉडल के बारे में पूरे विश्वास से बोल सकता हूँ, क्योंकि ज्योति सीएनसी ने इसे जिया है। राजकोट में 3,00,000 वर्ग मीटर में फैली हमारी नई विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन स्वयं श्री नरेन्द्र मोदीजी ने 2008 में किया था, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसी दिन से ज्योति सीएनसी निरंतर तीव्र विकास की यात्रा पर है – और मैं गर्व से कहता

हूँ कि हमें गुजरात सरकार से किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए कभी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जो भी आवश्यक था, वह समय पर मिला – बिना दौड़–भाग के, बिना विलंब के।

हमारे जैसी विनिर्माण इकाई के लिए ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस का महत्व सर्वोपरि है, और गुजरात मॉडल इसके लिए सचमुच वरदान सिद्ध हुआ है। गुजरात में विनिर्माण इकाइयों के लिए जो पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ है, वह असाधारण है। राजकोट में हमारे लिए इसका क्या अर्थ रहा, वह मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ:

- **कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता–**
  क्षेत्र और उसके आसपास के 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों से प्रतिभाशाली इंजीनियरों की निरंतर धारा, जिसने हमें विश्वस्तरीय सीएनसी मशीनें बनाने की मानव पूँजी दी। गुजरात सरकार के विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों का भी इसमें बड़ा योगदान रहा है।
- **औद्योगिक शांति एवं स्थिर औद्योगिक नीतियाँ–**
  राजकोट में कोई श्रमिक संघ (लेबर यूनियन) नहीं है – हमारे कर्मचारी और प्रबंधन एक परिवार की तरह काम करते हैं, और औद्योगिक अशांति के कारण हमारा उत्पादन कभी नहीं रुका। साथ ही, ब्याज सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी छूट और कर प्रतिपूर्ति वाली स्पष्ट औद्योगिक नीतियाँ।
- **स्थिर 24×7 बिजली–**
  परिशुद्ध (प्रिसिज़न) मशीन–टूल निर्माण में, जहाँ बिजली की एक रुकावट घंटों की मशीनिंग बर्बाद कर सकती है, निर्बाध गुणवत्तापूर्ण बिजली विलासिता नहीं – जीवन–रेखा है। गुजरात ने हमें यह दिया।
- **त्वरित निर्णय एवं राज्य सरकार का एक कदम आगे बढ़कर सहयोग–**
  हमें जब भी किसी स्वीकृति की आवश्यकता पड़ी, वह गुजरात सरकार से शीघ्र मिली। मुख्यमंत्री स्तर तक सहज पहुँच और हस्तक्षेप।
- **सुरक्षित वातावरण –**
  सबसे बढ़कर, गुजरात एक अत्यंत सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है – हमारे कारखानों, हमारे कर्मचारियों, हमारे परिवारों और दुनिया भर से आने वाले हमारे ग्राहकों के लिए। एक उद्यमी के लिए यह मानसिक शांति अमूल्य है।

इसी नींव पर ज्योति सीएनसी भारत की अग्रणी सीएनसी मशीन टूल निर्माता कंपनियों में से एक बनी है, जो हमारी फ्रांसीसी सहायक कंपनी हुरॉन ग्राफेनस्टाडेन (Huron Graffenstaden) सहित विश्व भर के ग्राहकों को सेवाएँ देती है। हमारी यात्रा, सच्चे अर्थों में, गुजरात मॉडल की संतान है।

इन सबसे ऊपर, मेरे लिए गुजरात मॉडल का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि ज्योति सीएनसी के व्यवसाय के लिए किसी भी प्रकार की स्वीकृति (NOC) आदि हेतु मुझे कभी किसी सरकारी अधिकारी के पास जाना ही नहीं पड़ा।

मेरे लिए गुजरात मॉडल का अर्थ है – स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ शहर, सुगम सड़कें, महिलाओं की सुरक्षा और एक शांतिपूर्ण जीवन।

नवीनतम अध्यायः ज्योति सीएनसी को MeitY की स्वीकृति और गुजरात सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया

अब मैं गुजरात मॉडल का सबसे ताज़ा उदाहरण साझा करता हूँ – जो इसी महीने घटित हुआ, और जिसे मैंने स्वयं अनुभव किया।

17 अगस्त, 2026 को ज्योति सीएनसी को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के अंतर्गत औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई। इस स्वीकृति के अंतर्गत हम अगले पाँच वर्षों में अपनी राजकोट इकाई में ₹1,020.65 करोड़ का निवेश करेंगे, जिससे हमारी स्थापित क्षमता का विस्तार होगा और सीएनसी मशीनों के निर्माण में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक बैकवर्ड–इंटीग्रेटेड विनिर्माण व्यवस्था तैयार होगी। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार इन निवेशों पर 25 प्रतिशत तक का पूँजीगत व्यय प्रोत्साहन (कैपेक्स इंसेंटिव) प्रदान करेगी। हमारे लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है – यह ज्योति सीएनसी को इलेक्ट्रॉनिक्स में और गहराई तक ले जाता है, हमारी आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त करता है, आयात पर निर्भरता घटाता है, और हमें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के राष्ट्रीय मिशन के साथ सीधे जोड़ता है।

लेकिन असली बात, जो गुजरात मॉडल की आत्मा को दर्शाती है, वह यह है। जैसे ही केंद्र सरकार की इस स्वीकृति की घोषणा हुई, गुजरात सरकार ने तुरंत संपर्क कर कहा:

जिस क्षण ज्योति सीएनसी केंद्र सरकार की स्वीकृति के दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगी, राज्य सरकार (गुजरात सरकार) भी अतिरिक्त 25 प्रतिशत का योगदान देगी – और वह भी 30 दिनों के भीतर।

सोचिए, इसका क्या अर्थ है। मुझे न आवेदन करना पड़ा, न पैरवी करनी पड़ी, न अनुवर्तन (फॉलो–अप) करना पड़ा, न प्रतीक्षा करनी पड़ी। यही गुजरात मॉडल का उदाहरण है – एक ऐसी सरकार, जो साझेदार की तरह कार्य करती है, उद्योग की आवश्यकताओं को पहले से भाँप लेती है, और स्वयं उद्यमी से भी तेज़ चलती है। जब ऐसी राज्य सरकार हो, तो मुझ जैसे उद्यमियों का राष्ट्र के लिए और अधिक करने का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। यही सक्रिय भावना – जिसे मुख्यमंत्री के रूप में श्री मोदीजी ने सबसे पहले स्थापित किया और जिसे आज गुजरात सरकार आगे बढ़ा रही है – गुजरात को शेष सबसे अलग करती है।

भारत का आर्थिक रूपांतरण–

जो श्री मोदीजी ने गुजरात के लिए किया, उसे फिर उन्होंने राष्ट्र के स्तर पर विस्तारित किया – और आँकड़े स्वयं बोलते हैं। वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी – वर्षों की सबसे तेज़ गति और पूरे जी–20 में सर्वाधिक। और यह तब हुआ, जब विश्व परिस्थितियाँ कठिन थीं: ऊँचे अमेरिकी टैरिफ, मध्य–पूर्व में तनाव और महँगी ऊर्जा। संयुक्त राष्ट्र ने भारत को "चुनौतीपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था में उजला बिंदु" कहा, और ओईसीडी का अनुमान है कि भारत आने वाले वर्षों में भी विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सरल शब्दों में कहें, तो भारत अधिकांश समृद्ध देशों की तुलना में तीन गुना से भी अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है – अमेरिका लगभग 2 प्रतिशत पर है, जबकि जर्मनी, फ्रांस और जापान 1 प्रतिशत से भी नीचे हैं।

विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) – जो मेरे हृदय के सबसे निकट का क्षेत्र है – ऊँचाइयाँ छू रहा है। मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाओं के माध्यम से वैश्विक दिग्गज अब अपने उत्पाद भारत में बना रहे हैं। देश आईफोन सहित स्मार्टफोनों का प्रमुख निर्यातक बन चुका है, और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रक्षा क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। जैसे–जैसे कंपनियाँ किसी एक स्रोत पर निर्भरता घटाना चाहती हैं, भारत स्वाभाविक विकल्प के रूप में उभरता है: विशाल पैमाना, लोकतंत्र, युवा कार्यबल, और निरंतर सरल होता व्यावसायिक वातावरण। मेरी दृष्टि में इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गुजरात मॉडल का स्पष्ट डीएनए है – निर्बाध बिजली, तैयार अधोसंरचना, त्वरित स्वीकृतियाँ, ईमानदार प्रशासन और नीतिगत स्थिरता – जो अब 140 करोड़ के राष्ट्र पर लागू हो रहा है।

विश्व मंच पर भारत का बदलता चेहरा–

विदेशों में भारत का उदय शायद देश के भीतर के उदय से भी अधिक प्रभावशाली है। श्री मोदीजी के नेतृत्व में भारत विश्व मामलों के हाशिये से उठकर मुख्य मंच के केंद्र तक पहुँचा है।

2023 की जी–20 अध्यक्षता निर्णायक मोड़ थी। "वसुधैव कुटुम्बकम्" – एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य – की थीम के साथ भारत ने अपने प्राचीन मूल्यों को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया। ऐसे समय में, जब बड़ी शक्तियाँ किसी भी बात पर मुश्किल से सहमत हो पाती थीं, भारत ने हर जी–20 राष्ट्र से नई दिल्ली घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करवाए–एक ऐसी कूटनीतिक उपलब्धि, जिसे कई लोग असंभव मानते थे – और अफ्रीकी संघ को जी–20 का स्थायी सदस्य बनवाकर ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में अपना स्थान सुदृढ़ किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध रक्षा, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष तक फैली एक गहरी रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं, और भारत क्वाड का एक प्रमुख स्तंभ है। यूरोप के साथ भारत ने ईएफटीए देशों के साथ व्यापार समझौता और यूनाइटेड किंगडम के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है, जबकि यूरोपीय संघ के साथ वार्ता पहले से कहीं आगे बढ़ी है। मध्य–पूर्व में परिवर्तन उल्लेखनीय है: यूएई ने प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, सीईपीए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, और भारत–मध्य–पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे में हाथ मिलाया।

यूक्रेन युद्ध और मध्य–पूर्व के तनावों के बीच भारत ने अपना संतुलन बनाए रखा–सभी पक्षों से मित्रता रखते हुए, अपनी शर्तों पर ऊर्जा खरीदी। उनके शब्द–"यह युद्ध का युग नहीं है"–पश्चिमी राजधानियों में उद्धृत हुए और जी–20 की भाषा में गूँजे।

चंद्रयान–3 का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरना, आदित्य–एल1 सूर्य मिशन, महामारी के दौरान 100 से

अधिक देशों को टीकों की आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व, और भारत की पहल पर विश्व का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाना – इनमें से प्रत्येक ने भारत के कद और सॉफ्ट पावर को बढ़ाया है।

मेरे विचार

राष्ट्र केवल परिस्थितियों से नहीं उठते, बल्कि उन नेताओं से उठते हैं, जो अपने समय से बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं – और श्री नरेन्द्र मोदीजी के रूप में भारत को ऐसा ही नेता मिला है। एक ऐसा व्यक्ति, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने से उठकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने तक पहुँचा।

मुझे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी से कई बार मिलने का सौभाग्य मिला है। वास्तव में, 3,00,000 वर्ग मीटर में फैली ज्योति की नई विनिर्माण इकाई का उद्घाटन 2008 में श्री नरेन्द्र मोदीजी ने किया था, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

मुझे उस दिन की एक छोटी–सी घटना याद है। उद्घाटन के दौरान मैंने श्री मोदीजी का कुछ महत्वपूर्ण अतिथियों से संक्षिप्त परिचय कराया। उनमें हमारी फ्रांसीसी सहायक कंपनी ह्यूरॉन ग्राफेनस्टाडेन के CEO श्री बर्नार्ड एशेवार भी थे। यह 30 सेकंड के हाथ मिलाने से ज़्यादा कुछ नहीं था।

सात साल बाद, अप्रैल 2015 में, श्री मोदीजी तत्कालीन राष्ट्रपति श्री फ्रांस्वा ओलांद के साथ रणनीतिक वार्ता के लिए फ्रांस गए। राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक विशेष रात्रिभोज के लिए फ्रांस की प्रमुख कंपनियों के म्ब् को आमंत्रित किया। ह्यूरॉन 150 वर्ष पुरानी फ्रांसीसी कंपनी है और यूरोप में सटीक CNC यूनिवर्सल मिलिंग मशीनों की अग्रणी है, इसलिए श्री एशेवार को भी आमंत्रित किया गया।

रात्रिभोज में श्री मोदीजी सीधे उनके पास गए और बोले, "हैलो मिस्टर बर्नार्ड, हम राजकोट में आपके उद्घाटन समारोह में मिले थे।" श्री एशेवार अभिभूत हो गए और दो बातों पर हैरान रह गए।

पहली, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि सात साल पहले के केवल 30 सेकंड के हाथ मिलाने के बाद भी प्रधानमंत्री को वे याद थे– और उनका नाम भी सही उच्चारण के साथ।

दूसरी, वे इस बात से प्रभावित हुए कि श्री मोदीजी कितने ज़मीन से जुड़े हैं। भारत के प्रधानमंत्री होते हुए भी वे सीधे उनसे मिलने आए। पूरा कमरा सोच रहा था कि यह कौन सज्जन हैं जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से जानते हैं।

यह छोटी–सी कहानी बहुत कुछ कहती है– उनकी अद्भुत स्मरणशक्ति, उनकी आत्मीयता, और हर मिलने वाले व्यक्ति के प्रति उनका सच्चा सम्मान।

मैंने यह यात्रा एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखी है–

इतिहास इस युग के बारे में बहुत कुछ लिखेगा, लेकिन सबसे ऊपर वह यह लिखेगाः कि अपनी यात्रा के एक निर्णायक मोड़ पर भारत सौभाग्यशाली था कि उसे एक ऐसा नेता मिला, जिसे अपने लोगों पर विश्वास था – और ऐसे लोग मिले, जिन्हें अपने नेता में अपना विश्वास प्रतिबिंबित होता दिखा। उनकी दूरदृष्टि से आलोकित पथ पर, भारत की कहानी का – और मैं कहने का साहस करूँ तो गुजरात और ज्योति सीएनसी की कहानी का भी – सर्वश्रेष्ठ अध्याय अभी लिखा जाना शेष है।

लघु उद्योग भारती, गुजरात के प्रदेश महासचिव श्री हंसराज भाई गजेरा से बातचीत पर आधारित

○○○

'वाइब्रेंट गुजरात' – मोदी नेतृत्व की वो पहल जो भारत में इंवेस्टमेंट्स की बनी आइकॉन

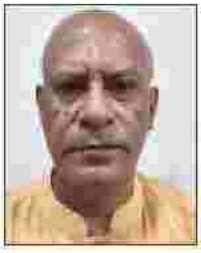

इनसाइडर
हितेन्द्र जोशी
वर्ष 2002–03 में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के साथ राजनीतिक स्वयंसेवक के रूप में कार्यरत तत्कालीन राज्य महासचिव
लघु उद्योग भारती, गुजरात

वर्ष 2003 में गुजरात एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती थी; गुजरात के उद्योग के सामने विश्वास और व्यापार की चुनौती थी; और देश तथा विदेश में गुजरात की छवि को भी गंभीर नुकसान पहुँचा था। कच्छ के भूकंप ने आर्थिक स्थिति पर और दबाव डाला था। दूसरी ओर, प्रभावशाली अंग्रेजी समाचार–पत्र गुजरात को मुख्यतः नकारात्मक दृष्टि से प्रस्तुत कर रहे थे। गुजरात के उद्यमियों – विशेषकर MSME क्षेत्र – के सामने तत्काल आवश्यकता थी विश्वास, निवेश और व्यापार की निरंतरता की। गुजरात के पास प्रतीक्षा करने का समय नहीं था। जल्दी, साहसिक और विश्वसनीय कदम उठाना आवश्यक था।

The Real Invention

- श्री नरेन्द्र मोदी ने इस नकारात्मक माहौल का जवाब केवल शब्दों से देने के बजाय गुजरात की आर्थिक शक्ति से देने का निर्णय किया। उनका विजन था – गुजरात की अपनी कहानी को भारत और पूरी दुनिया तक स्वयं पहुँचाई जाए।
- पहला बड़ा विचार था – एक ऐसा नाम और ब्रांड बनाया जाए जो केवल एक Investors Conference का नाम न रहे। इस तरह सामने आया – "Vibrant Gujarat"। यह नाम गुजरात की ऊर्जा, उद्यमशीलता और आत्मविश्वास को दर्शाने वाला बन गया।

सोच बहुत सीधी थी, "निवेशकों के गुजरात आने की प्रतीक्षा मत करो – गुजरात को निवेशकों तक लेकर जाओ।" मुख्यमंत्री स्वयं प्रमुख उद्योगपतियों से संपर्क करने लगे। साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश था – प्रोजेक्ट

पहचानो, अवसर तैयार करो, निवेशकों को सही अधिकारियों से मिलाओ और समस्याओं का समाधान तेजी से करो।

- iNDEXTb, Industries Department और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम इस पूरी सोच को जमीन पर उतारने में जुट गई। श्री पी. के. लहरी और श्री हसमुख अढिया जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनेक अधिकारियों ने इस विजन को वास्तविक कार्यवाही में बदला।
- उस समय गुजरात में लघु उद्योग भारती (LUB) का नेटवर्क आज की तरह बड़ा नहीं था, फिर भी संगठन के नेतृत्व ने राज्य के अधिकारियों के लिए उपयोगी बनने का प्रयास किया। उद्योग जगत की भागीदारी को जोड़ने और समन्वय करने में LUB ने अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग दिया।
- मेरे लिए और उस समय गुजरात LUB के अध्यक्ष श्री वजुभाई वघासिया के लिए यह केवल एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं थी। उद्योग, सरकार और प्रशासन के बीच इस प्रकार के समन्वय का वह हमारे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण self-learning experience था।
- Industry Associations भी इस प्रयास के मजबूत भागीदार बने। FICCI, CII और गुजरात के प्रमुख उद्योग नेताओं ने उद्योग जगत को जोड़ने, विश्वास पैदा करने और इस नए प्रयास को विश्वसनीयता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका सबसे मजबूत संदेश था: "गुजरात का अपना उद्योग, गुजरात के साथ खड़ा है।"

- पहला Vibrant Gujarat आज की तुलना में बहुत छोटा था। न कोई विशाल Convention Centre था, न आज जैसी Global Exhibition की व्यवस्था और न ही कोई तैयार International Summit machinery। केवल एक साहसिक विचार, दृढ़ नेतृत्व, समर्पित अधिकारी और इस विचार पर विश्वास करने वाला उद्योग जगत था। और उद्योग आया।
- लेकिन उद्देश्य केवल MoU करना नहीं था। असली उद्देश्य था Government और Industry के बीच एक नया सीधा संबंध बनाना – जहाँ निवेशक निर्णय लेने वाले अधिकारियों से मिल सके, अवसर समझ सके और अपने व्यावहारिक प्रश्नों का समाधान पा सके।

वह सरल Model

Brand Gujarat → Projects → Investors → Government Facilitation → Implementation → Confidence → More Investments

यही सरल चक्र आगे चलकर Vibrant Gujarat की सबसे बड़ी ताकत बना।

असली सफलता

पहले Vibrant Gujarat की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि एक कठिन परिस्थिति को गुजरात की नई पहचान बनाने के अवसर में बदल दिया गया। श्री नरेन्द्र मोदी ने दिया – विजन, गति और व्यक्तिगत नेतृत्व। वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया–प्रशासनिक प्रयास और Execution। Industry Associations और उद्यमियों ने दिया – विश्वास, भागीदारी और विश्वसनीयता। और उद्योग संगठनों के छोटे–बड़े कार्यकर्ताओं ने अपनी क्षमता के अनुसार सरकार और उद्योग के बीच संवाद तथा भागीदारी का सेतु बनने का प्रयास किया। गुजरात के MSME उद्योग के लिए इसका महत्व और भी बड़ा था। राज्य धीरे–धीरे ऐसी पहचान बना रहा था जहाँ उद्योग के लिए अवसर, Government की Facilitation और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण एक साथ दिखाई देने लगा।

एक छोटे Summit ने एक बड़ा Brand बनाया। Brand ने Confidence बनाया। Confidence ने Investment को आकर्षित किया। Investment ने नए अवसर पैदा किए। Vibrant Gujarat ने केवल दुनिया के सामने गुजरात का प्रचार नहीं किया। इसने गुजरात के उद्यमियों को दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक मजबूत मंच दिया।

LUB's Jaipur Prant conducted a meeting on August 14, attended by office bearers and members from 14 districts and 59 units. National Org. Secretary Shri Prakash ji urged the members to work for the organization with complete honesty, sincerity, and dedication. On this occasion, Former National President and In-charge for Rajasthan-Gujarat Shri Ghanshyam Ojha, National Jt. GS Shri Naresh Pareek, National Secretary Smt. Anju Singh, State VP Shri Natwarlal Ajmera & GS Shri Sudhir Garg, President-Jaipur Prant Shri Mahendra Mishra and General Secretary Ms. Sunita Sharma, Jt. GS Smt. Ritu Agarwal were present. The core agenda was focussed on LEAP Portal, Membership Drive, StoneMart. Innovations & exhibitions. Jt. GS Jaipur Prant Shri Chandra Prakash Vyas delivered the vote of thanks.

Joint EC Meeting of all 3 units of Laghu Udyog Bharati, Bhilwara was held in the presence of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji and State President Shri Yogendra Sharma on August 14. The meeting discussed strengthening the organization, adding new members, constructing a skill development centre, and increasing employment opportunities for youth.

गुजरात के विकास में नरेंद्र भाई की दूरदृष्टि और विशिष्ट कार्यपद्धति

संस्मरण

यशोधर भट्ट
पूर्व अध्यक्ष,
गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड
भावनगर, गुजरात

जब मोदी जी ने ड्राइवर्स को व्यसनों से बचाया

सरकार किसी की भी हो, सचिवालय में कर्मचारी गण के साथ मधुर संबंध बनाये रखना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। हां, जहां जरूरत पड़े वहां कठोर होकर भी सबके हित में निर्णय लेने पडते हैं। सचिवालय परिसर में बहुत बड़ी संख्या में ड्राइवर लोग मंत्री गण और लोकसेवकों को सुबह–शाम गाड़ियों में उनके बंगलों–घरों से लाने–ले जाने का काम करते थे। दिनभर में खाली समय ये ड्राइवर सब इकट्ठे होकर नशे आदि व्यसनों में लग गए। लेकिन दूषित हो रहे वातावरण को बहुत जल्दी और सूक्ष्मता के साथ नरेंद्र भाई ने भांप लिया और उस समस्या का तुरंत निदान कर दिया। निर्णय हुआ कि ड्राइवर्स दिनभर सम्बद्ध मंत्री या अधिकारी के ऑफिस में ही रहकर पियन का काम संभालेंगे और दोनों वक्त अपनी ड्राइवर की ड्यूटी भी करेंगे। ये निर्णय आसान नहीं था। लेकिन नरेंद्र भाई ने कहीं प्रेम से, तो कहीं कठोरता से यूनियन कर्मचारियों को इसके लिए राजी किया। इससे परिवर्तन ये हुआ कि गांधीनगर सचिवालय में ड्राइवर कम पियन की नयी कार्य पद्धति शुरू हुई। ऐसे छोटे–छोटे प्रयास से गुजरात मॉडल में बदलाव आने शुरु हुए।

योग्यता के आदर का प्रबल आग्रह

रहमारा यानी अनुकंपा नियुक्ति की प्रथा भी राज्य सरकारों में पहले से चली आ रही है। अपने सेवाकाल में अगर किसी सरकारी कर्मचारी का देहांत हो जाए, तो उसके आश्रित बेटे या बेटी को न्यूनतम अर्हता के आधार पर वर्ग 4 या अन्य उचित पद पर नौकरी दी जाती रही है। नरेंद्र भाई ने उसे बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार की मदद करने में समाज और सरकार दोनों जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन उसके बच्चों को मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर नियुक्ति देना बिलकुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे उन युवाओं के साथ गलत हो जाता है जो उस पद के योग्य हैं और रोजगार पाने की कोशिश कर रहे हैं। अवसर उनको भी मिलना चाहिए। जिस व्यक्ति की हानि हुई है, उसके परिवार के बच्चों की पढ़ाई–लिखाई के खर्च को वहन करना सुनिश्चित किया गया। और अगर उसके बच्चे वेल एजुकेटेड है, तो उसकी तरह ही लाखों अन्य युवाओं के टैलेंट को भी नियुक्ति देने का कार्य नरेंद्र भाई के कार्यकाल में जो शुरू हुआ, जो निरंतर आज भी लागू है।

हर व्यक्ति का रखा मान–सम्मान

नरेंद्र भाई को मुख्यमंत्री के रूप में 4–6 महीने ही हुए होंगे। सचिवालय परिसर में एक फाउंटेन का उद्घाटन उन्हें ही करना था। सभी अधिकारी–कर्मचारीगण निश्चित समय पर वहां पहुंचे। लेकिन सभी आश्चर्य में पड़ गए, जब उन्होंने ग्रुप–चार के कर्मचारी, जिसका अगले ही दिन रिटायरमेंट होने वाला था, को बुलाया और वो उद्घाटन उस कर्मचारी साथी के हाथों करवाया। ये बहुत संवेदनशील क्षण था, वहां उपस्थित सभी को ऐसा महसूस हुआ कि मुख्यमंत्री ने एक छोटे से कर्मचारी को कितना मान दिया। लोकार्पण के बाद नरेंद्र भाई ने उसकी सेवा का उल्लेख कर उसके आरोग्य जीवन के लिए शुभकामना दी। इस एक घटना ने उनको सभी कर्मचारीगण से हमेशा के लिए जोड़ दिया था।

कार्य किया निष्पक्षता और पारदर्शिता से

ये बात वर्ग 3 और 4 की भर्ती से जुड़ी थी। बड़ी संख्या में भर्तियां होनी थी। ये नाजुक विषय होता है। इसकी जिम्मेदारी मुझे दे दी गई, यानी तलवार की धार पर चलना था। मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने मुझे बुलाकर भरोसा दिया कि आपको अपना काम बहुत ही स्पष्टता और जिम्मेदारी से करना है और जब भी मेरी आवश्यकता पड़े, तो ही मेरे को आप बताना। उन्होंने कहा कि ये विषय युवाओं से सीधा जुड़ा है, इसलिए पूरी प्रामाणिकता के साथ करना है और किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी कैंडिडेट के लिए अगर किसी भी छोटे–बड़े अधिकारी की सिफारिश आ जाए, उसे भी नजरअंदाज ही करना है। योग्य और सक्षम उम्मीदवार के साथ न्याय होना चाहिए। मैं भी अगर किसी की सिफ़ारिश करूं, तो भी उसे आप नहीं मानोगे, बिना किसी डर के आप ये काम करो। मुझे सुखद संतोष है इस बात का, कि ऐसे ईमानदार नेतृत्व के साथ काम किया और 9 वर्षों में करीब 30 हजार नियुक्तियां पूर्ण पारदर्शिता से कर पाया। ○○○

My First Meeting with Shri Narendra Bhai Modi

First Impression
Dr. Dashrathbhai V. Patel
Ex. Scientist, Govt. of India
Former Chairman,
Gujarat Multi Gas Group of Companies
Mehsana, North Gujarat

After completing my education at the prestigious IIT Bombay, I joined a CSIR Govt. of India national laboratory. During my early years there, I observed that many talented, highly educated, and well-known scientists and scholars were leaving India in search of better opportunities and a brighter future abroad. This deeply concerned me. I began thinking: Why should our talented people have to leave India to build their future? Why can we not create an environment in our own country where our scientists and scholars can contribute to India's development?

With this thought, I started an activity to understand the reasons behind the growing **brain drain from India**. I collected information from various scientific and educational institutions and also personally gathered views from individual scientists and scholars who had either left India or were planning to go abroad.

After studying the information, I could clearly make out that the major and common reason was that the governments of that time had not been able to create the **proper environment, facilities, infrastructure, and opportunities** required for highly talented scientists and scholars to pursue their work in India.

I strongly felt that this issue should not remain confined to scientific and educational circles. It needed to reach the **Parliament of India**, so that our elected representatives could seriously consider this important national issue and take appropriate steps to prevent the loss of India's intellectual talent.

With this objective, one of my well-known BJP workers, **Shri Prahlad Bhai Patel**, accompanied me to the BJP/Jan Sangh office at **Khadia, Ahmedabad**. There, I met **Shri Nathabhai Jaghda**, who was a

prominent fighter for various public issues.

It was during this period, in **1982-83**, that I saw **Shri Narendra Bhai Modi** for the first time, along with other BJP workers.

My first impression of him was quite striking. Even at that young age, there was something distinctly different about him. **His eyes had a special spark, and his personality reflected a strong determination and an aggressive spirit to do something for the nation.** That first impression has remained in my memory even after so many years.

Shri Nathabhai Jaghda and Shri Prahlad Bhai Patel subsequently helped take my brain-drain issue forward. Through their efforts and guidance, I was introduced to **Shri Atal Bihari Vajpayee ji**, with the objective of taking this important national issue to the Parliament.

Later, I had the opportunity to meet **Atal ji** in the presence of **Shri Rajendra Sharma**, who was then the office secretary of the BJP in Parliament.

That period was a very important phase of my life. My concern about the migration of India's scientific talent had taken me from a national laboratory to the political platform, with the hope that the issue could receive attention at the highest level.

Looking back today, I feel privileged to have witnessed those early years and to have had the opportunity to meet **Shri Narendra Bhai Modi** when he was still a young and emerging worker.

That first meeting in **1982-83** remains a memorable chapter of my life. ○○○

When Reform Reaches the Shop Floor

Opinion
Dr. Sachin Sabnis
MD-Belgaum Ferrocast (India) Pvt. Ltd.
Member-Central Board of Trustees-EPFO
National Vice President-Laghu Udyog Bharati
Belagavi, Karnataka

For years, industry has grown used to hearing about reform long before feeling its effects. That is beginning to change. Under the current government, some genuine shifts have reached the shop floor - changes business owners can actually feel, not merely read about in policy briefings.

The PLI scheme, the simplified Udyam Registration process, and the easy availability of collateral-free loans through the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) have made starting, formalizing, and expanding businesses in India's MSME sector significantly easier than before. While businesses previously struggled for extended periods due to cumbersome paperwork and financial constraints, digital processes and improved credit facilities now offer entrepreneurs the opportunity to grow rapidly. The experiences of MSME entrepreneurs associated with Laghu Udyog Bharati also corroborate this transformation.

The recently launched Employment Linked Incentive (ELI) scheme has linked these reforms to job creation. Under this scheme, employers receive incentives for making new hires, while employees securing formal employment for the first time are integrated into the social security system through EPFO registration. This is particularly significant for the MSME sector, which generates massive employment in the country yet has long had a portion of its workforce operating in the informal sector.

Significant changes have also taken place within the EPFO. The Employees' Provident Fund Scheme-2026, has replaced the old 1952 framework to simplify withdrawal processes, strengthen coverage for contract workers, and promote digital features-such as UPI-based withdrawals and auto-settlement-as part of the move towards EPFO 3.0. These measures have accelerated claim settlements and reduced documentation complexities.

Overall, these reforms are not merely announcements but structural changes aimed at extending benefits to workers, small entrepreneurs, and the informal workforce. They have imparted fresh momentum to the formalization of industry, employment, and social security in India.

Efforts of the 'Double-Engine' Govt. Resonate Far & Wide

Opinion
Raman Saluja
MD- Oriental Engineering Works Pvt. Ltd.
State President-
Laghu Udyog Bharati, Haryana

The Central Government under Prime Minister Narendra Modi and the Haryana Government have introduced several policy reforms to strengthen the manufacturing and MSME sector, improve working capital and enhance Haryana's position as a manufacturing hub.

Key measures include capital investment subsidies of up to ₹4 crore under the Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy, particularly for sectors such as electric vehicles, aerospace and defence, and renewable energy. The expansion of TReDS is helping MSMEs convert pending invoices into faster cash, while strengthened Micro and Small Enterprises Facilitation Councils (MSEFC) aim to ensure timely resolution of delayed-payment disputes. Emergency collateral-free credit support is also being provided to help businesses manage external shocks and supply-chain disruptions. At the national level, the RAMP program is supporting MSMEs through digital assistance, green clusters and enhanced credit guarantees. Laghu Udyog Bharati Haryana has urged entrepreneurs to actively use these schemes and platforms to protect cash flow, sustain operations and contribute to the vision of an Aatmanirbhar Bharat.

○○○

India's Develops with PM's Decisive, Compassionate GOVERNANCE

Governance
Piyush Goyal
Union Minister of Commerce & Industry
Govt. of India
New Delhi

India's development in the 12 years since the country voted emphatically for Prime Minister Narendra Modi has been guided by a decisive, compassionate and citizen-friendly approach to governance. This approach has opened up immense opportunities for our farmers, fishermen, MSMEs, youth and women.

Prime Minister Modi has steered the Indian economy with resolve while ensuring generous welfare schemes for the poor and needy during a period marked by heightened global turmoil, economic volatility and the catastrophic Covid-19 pandemic. He has successfully converted every challenge into an opportunity.

Inflation compared with any other 12-year period

In these difficult times, under the Prime Minister's leadership, India has maintained its lowest average inflation compared with any other 12-year period in the

past. The government has insulated citizens from hardship by providing free foodgrains, direct benefit transfers, financial inclusion and corruption-free leadership, while steering India decisively towards its Viksit Bharat- 2047 mission.

Despite global uncertainty, India's exports have reached record levels, foreign direct investment (FDI) has risen sharply, and the government has taken focused legislative and administrative measures to improve the ease of doing business for small entrepreneurs and the ease of living for every citizen.

Ease of Living

For decades, India's regulatory architecture treated citizens with deep mistrust, often regarding them as criminals for minor procedural violations or even on the basis of mere suspicion by a person in authority. In a refreshing departure from the past, the Modi government has consistently framed policies based on trust and compassion for the common citizen.

PM Modi has taken significant steps to improve India's legislative landscape by supporting citizens and businesses, simplifying compliances and recognising the practical challenges faced by enterprises.

Supporting MSMEs and shielding them from harassment has been a focus area in PM Modi's Ease of Doing Business initiatives whether through reducing compliance burdens, promoting digitisation or introducing single-window clearances, the broader shift has been towards making governance more reasonable and efficient.

A cornerstone of the Prime Minister's Ease of Living initiative is the Government-e-Marketplace (GeM), a digital platform for transparent and efficient public procurement.

In the decade since the Prime Minister launched this transformative initiative, GeM has revolutionised public procurement by weeding out corruption while promoting startups, MSMEs, women entrepreneurs and businesses in smaller towns.

It is truly a gem that has replaced the notorious Directorate General of Supplies and Disposals, whose opaque and uncompetitive systems gave an unfair advantage to a privileged few entrenched in the procurement process. Befittingly, the Commerce and Industry Ministry's modern office, Vanijya Bhawan, now stands on the land once occupied by that obsolete institution.

Trust and Compassion

The Prime Minister's mantra of governance based on trust and compassion is clearly reflected in the Jan Vishwas Act passed by Parliament this year, as well as in the similar law enacted in 2023.

The scale of this reform is unprecedented. The Jan Vishwas Act amends 784 provisions across 79 Central Acts administered by 23 Ministries. It decriminalises 717 provisions and rationalises another 67 to improve ease of living. It represents the largest decriminalisation exercise in independent India's legislative history.

The reform goes beyond individual amendments. It rationalises more than 1,000 offences, removes outdated and redundant provisions, omits obsolete colonial-era offences, and strengthens adjudication and appeal mechanisms outside criminal courts. These initiatives ensure that start-ups and MSMEs can focus on their business activities instead of worrying about criminal proceedings for procedural lapses.

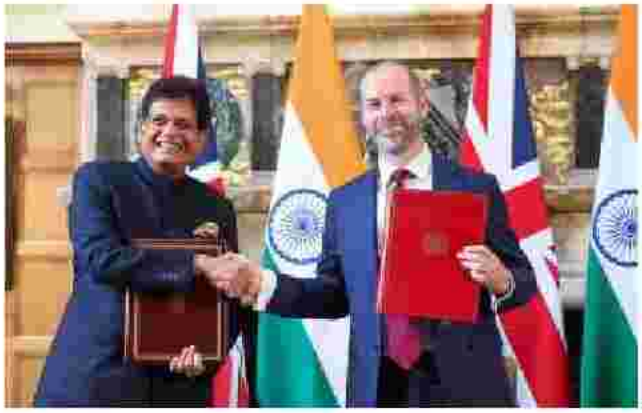

Free Trade Agreements

PM Modi is confident that Indian farmers, workers, MSMEs, artisans, women, youth and entrepreneurs can make a global impact with effective policies and government support. Under his leadership, India has signed Free Trade Agreements (FTAs) with several developed economies, including the European Union, the United Kingdom, Australia, New Zealand, the United Arab Emirates and the European Free Trade Association (EFTA), comprising Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

These agreements provide a clear competitive edge to India's labour-intensive sectors such as leather and

footwear, textiles, sports goods, fisheries and artisanal products. These FTAs will help MSMEs operate profitably in the global arena. They will create millions of jobs in the years ahead while opening up enormous opportunities for our youth. They will also attract billions of dollars in investment. In fact, the agreements with the EFTA countries and New Zealand include commitments for significant investment in India.

For farmers, these FTAs are a blessing as their produce will enjoy duty-free access to major markets. At the same time, India has protected all sensitive agricultural sectors, including dairy, wheat, rice, sugar and other products.

Startups: The Sky is the Limit

India has emerged as one of the world's largest and most diverse startup ecosystems, with a rapidly growing number of entrepreneurs identifying business opportunities in the challenges faced by people. They have developed innovative products and services that solve real-world problems, creating jobs and prosperity in line with Prime Minister Narendra Modi's vision.

The sky is the limit for Indian startups. Last month, space startup Skyroot achieved the first-ever private rocket launch of Vikram-S, marking a truly historic achievement for India under PM Modi's leadership.

The Prime Minister first articulated his vision of making India a global startup hub and transforming the country into a nation of job creators during his Independence Day address in 2015. Four months later, the transformative Startup India initiative was launched.

The achievements of this game-changing initiative, which began its 10th year on January 16, are remarkable. The Government has recognized more than 55,200 startups during Financial Year 2025-26, marking the highest number in a single year since the launch of the Startup India initiative.

Since inception, the number of recognized startups has crossed 2.23 lakh as on 31st March 2026, growing sharply from about 500 in 2016. They have generated more than 23.36 lakh direct jobs. In line with PM Modi's vision of women-led development, more than 1.07 lakh recognized startups have at least one-woman director or partner, accounting for approximately 48% of total recognized startups.

These ventures span more than 55 sectors, including financial technology, e-commerce, nanotechnology, agriculture, healthcare and space, helping India emerge as a cradle of technology-driven startups.

Many startups are setting new benchmarks in customer service, quality control and efficiency. They are emerging as powerful engines of growth that will help India realise its dream of becoming a developed nation by 2047.

Equally remarkable is the success of entrepreneurs from remote regions. About half of India's startups are located outside major metropolitan cities. They have developed tools that help farmers and created innovative, eco-friendly products using agricultural waste and local materials.

As India moves towards the vision of Viksit Bharat-2047, the defining feature of the past 12 years has been governance built on trust, compassion and opportunity along with a focus on MSMEs.

From improving the ease of living for every citizen to empowering farmers, entrepreneurs, startups and small businesses, these reforms have laid the foundation for sustained growth. They have demonstrated that when government acts as an enabler rather than a barrier, the aspirations of 140 crore Indians become the driving force behind the nation's transformation.

○○○

TRANSFORMING THE NATION WITH POWER

Kamakhya Poles

Manufacturers of PSC Poles

APDCL approved

Address: Palashbari, Guwahati

Email: kamakhyapoles@yahoo.co.in

Phone: 9954024033

www.welkm.in

Welkm®

सुरक्षा के लिए निर्मित
गुणवत्ता से परिपूर्ण

MANUFACTURER OF ELECTRICAL GOODS

MOUR GROUP OF COMPANIES

KP

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

APDCL Approved

MANUFACTURING : DISTRIBUTION TRANSFORMER OF 11 KV & 33 KV

CLASS RATING 5 KVA TO 2.5 MVA CAPACITY

KALITA POWER

Factory : Gorchuk, Pamohi, Near HP Petrol Pump, Guwahati-781035

Ph. : 98640-63730 (M)

E-mail : kalitapower2021@gmail.com

Safer, Faster & more Comfortable: INDIAN RAILWAYS in a *NEW ERA*

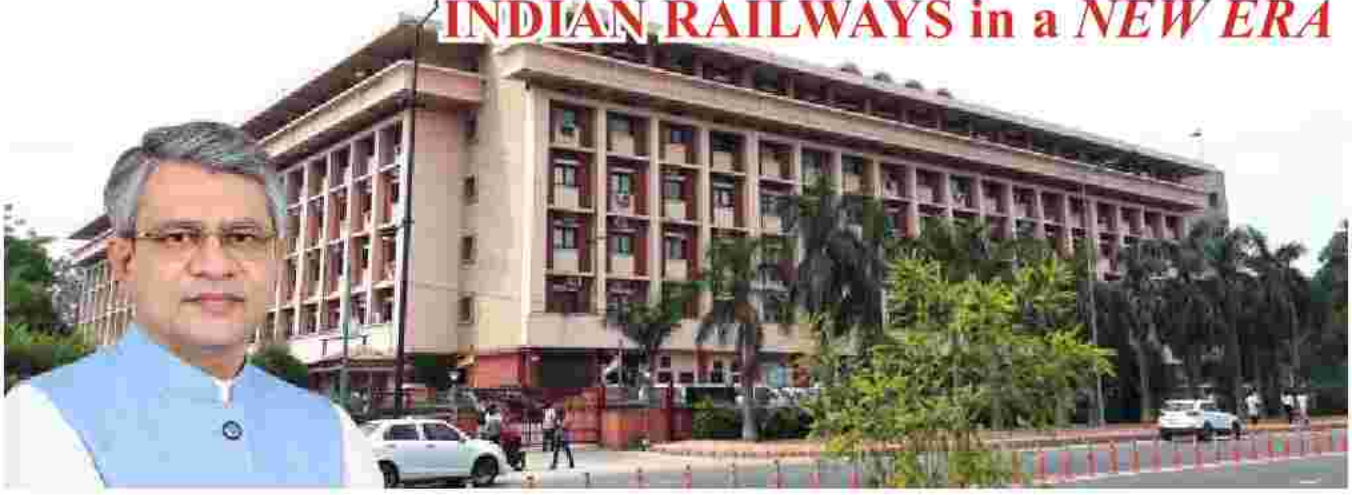

New Heights

Ashwini Vaishnav
Minister for Railways, Information & Broadcasting, Electronics & Information Technology
Govt. of India

The Indian Railways is more than a mode of transport; it is the thread that binds our nation together, carrying not just passengers and freight but the hopes and everyday lives of crores of countrymen. Every day it runs more than 25,000 trains and carries over 2 crore passengers safely, serving as a lifeline for workers, farmers, students and the small and medium entrepreneurs who depend on it to move goods swiftly and affordably.

Over the last decade, Indian Railways has undergone a transformation in speed, safety, comfort and scale. Annual budgetary support, which hovered around ₹25,000-30,000 crore a decade ago, now stands at nearly ₹2.8 lakh crore. This reflects a shift in how the nation views its railways: not a legacy system to be maintained, but critical national infrastructure to be built afresh, enabling continuous project sanctioning and technology adoption.

Connecting Bharat

To run more trains, more network capacity is required.

Indian Railways added more than 36,000 km of new tracks in the last twelve years, compared to about 14,000 km in the preceding decade, easing congestion and improving punctuality. Project execution has accelerated since the introduction of the PM Gati Shakti National Master Plan, which synchronizes inter-departmental planning.

Some of the most remarkable feats of recent times lie in connecting parts of Bharat that railways could never reach before. The Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Link connected Kashmir Valley to the rest of the country by an all-weather rail line. Its centerpiece, the Chenab Bridge, rises 359 meters above the riverbed, making it the world's highest railway arch bridge, 35 meters taller than the Eiffel Tower. This line has cut travel time between Katra and Srinagar to about three hours only.

Chenab Bridge

In the south, the new Pamban Bridge at Rameswaram which is Bharat's first vertical-lift sea bridge has replaced the century-old British-era bridge, restoring rail access to this sacred island while allowing large ships to pass safely beneath.

Pamban Bridge

In the Northeast, the 51 km Bairabi-Sairang line, built through 48 tunnels and over 140 bridges, has connected Mizoram's capital Aizawl to the national rail network for the very first time, making it only the fourth northeastern state capital to be linked by rail.

Connecting India has also meant conquering its rivers and mountains. Major new rail bridges have been built across our largest rivers including the 4.94 km long Bogibeel Bridge across the Brahmaputra in Assam, India's longest rail-cum-road bridge, and the 4.56 km Digha-Sonpur Bridge across the Ganga ji in Bihar along with numerous other crossings that have opened up previously isolated regions.

Underground, the transformation has been just as dramatic: The rail-tunnel length has grown from around 125 km in 2014 to nearly 600 km today, an addition of close to 500 km in a single decade. Much of this has been accomplished in the treacherous geology of the Himalayas, where Indian Railways engineers developed the indigenous Himalayan Tunnelling Method to safely bore through unstable rock and water-bearing strata that had defeated conventional techniques for decades, a solution now being deployed across our most challenging mountain projects.

New-Age Trains for a New Bharat

The first and most visible thrust of this transformation has been the reinvention of the passenger experience. In 2019, India entered a new era of indigenous rail travel with the launch of Vande Bharat, a semi-high-speed trainset designed for speeds of up to 160 kmph and equipped with automatic doors, CCTV surveillance, GPS-based passenger information and enhanced accessibility features for Divyangjan. What began as a symbol of India's growing railway manufacturing capability has rapidly evolved into a nationwide movement. In just seven years, the Vande Bharat fleet has expanded to 162 Chair Car services across the country, bringing faster, safer, smarter and more comfortable rail travel within the reach of millions of passengers.

Vande Bharat Express

At the same time, it was imperative that this transformation reach the common man travelling in the general and non-AC segments. For the price-sensitive and less-privileged traveler, the indigenously designed Amrit Bharat Express has brought a new standard of affordable, dignified and comfortable long-distance travel. These non-air-conditioned trainsets combine affordability with modern amenities like improved cushioned seating, better lighting and ventilation, mobile charging facilities and sealed gangways that enable safer movement between coaches. Importantly, this enhanced travel experience comes without putting it beyond the reach of the common passenger. Today, 72 Amrit Bharat services are running across the country, taking the benefits of modernization to the very people for whom affordable rail travel matters most.

Amrit Bharat Express

For the daily commuter travelling shorter distances, the fully air-conditioned Namo Bharat trainsets have been introduced to serve regional routes, offering comfortable, reliable and swift inter-city commuting for the millions who travel these corridors every single day.

For the millions of passengers who travel overnight across long distances, the fully air-conditioned Vande Bharat Sleeper has been introduced, extending the comfort and safety features of the Vande Bharat platform to long-distance overnight journeys for the very first time.

Across the wider fleet, older ICF coaches are steadily being replaced by modern LHB coaches, valued for their stainless-steel bodies and crashworthiness. About 50,000 LHB coaches have been manufactured since 2014, against a meagre 2,300 in the preceding decade, strengthening domestic manufacturing under Atmanirbhar Bharat.

Jaisalmer Amrit Bharat Station

Electrification and the Hydrogen Train

Electric traction is not only environmentally friendly but energy efficient also. It removes dependence on imported diesel and the foreign exchange spent on it, cuts operating costs, delivers higher haulage capacity and faster acceleration, and produces about 90% less CO_2 than road transport for the equivalent load.

Recognizing this, Indian Railways has pursued electrification in mission mode over the last decade. Electrification began in 1925, but till 2014 only about 21,000 route km had been electrified. Since then, an additional 49,000 route km have been electrified, taking coverage to 99.6% of the broad-gauge network, making Bharat the world's second most electrified large railway system after Switzerland, well ahead of China, Spain, Japan, France and the UK.

This is saving the exchequer approximately ₹6,000 crore annually in fuel costs, with diesel consumption falling from about 293 crore litres in 2015-16 to 108 crore litres in 2024-25.

Indian Railways is also looking beyond electrification. In July 2026, Bharat's first hydrogen fuel-cell train was flagged off by the Prime Minister on the Jind-Sonipat section in Haryana. The 10-coach indigenous trainset, carrying around 2,600 passengers, is the world's longest hydrogen train in passenger service, emitting nothing but water vapour, a step towards Indian Railways' goal of net-zero carbon emissions by 2030.

Hydrogen Train Freight Corridors and Cargo Terminals

On Indian Railways, both passenger and freight trains use common infrastructure. To segregate freight traffic from passenger traffic and thus to improve efficiency of freight transportation, fully electrified freight-only Dedicated Freight Corridors have been developed. The 1,337 km Eastern DFC (Ludhiana to Sonnagar) and 1,506 km Western DFC (Dadri to Jawaharlal Nehru Port) are now fully commissioned, spanning nearly 2,850 route km. Freight trains here run up to 100 kmph carrying double-stacked containers, cutting transit times by 40-50% and freeing capacity on the shared network for more passenger trains.

Increasing Freight carrying capacity is not just about creating corridors; it is also about how quickly cargo can be loaded and unloaded close to where it is produced or consumed. Under the Gati Shakti Multi-Modal Cargo Terminal (GCT) policy, private investment is being invited to build modern cargo terminals near industrial clusters, ports, mandis and mines.

So far, 142 terminals have been commissioned, with combined capacity of 224 million tonnes a year and nearly ₹10,000 crore of private investment; approval has been granted for 310 more. These terminals handled 146 million tonnes of freight in 2025-26.

New Rewari Gati Shakti Cargo Terminal

For our small and medium industries in particular, this means more reliable, more affordable movement of raw material and finished goods across the country, shorter lead times to reach distant markets, and a genuine

reduction in logistics costs that had long weighed on the competitiveness of our MSME sector.

Overall freight loading rose to 1,670 MT in 2025-26, making India the world's second-largest freight carrier, benefiting small and medium industries through more reliable, affordable movement of goods and shorter

lead times.

Bharat's First Bullet Train takes Shape

Alongside the upgrades to the conventional network, Bharat is also building its first high-speed rail corridor, the 508-kilometre Mumbai-Amadavad High Speed Rail line, designed for operational speeds of 320 kmph and expected to cut travel time between the two cities to about two hours. Land acquisition and utility shifting are fully complete, with viaducts, bridges, tunnels and stations progressing steadily. The first stretch, Vapi-Surat, is targeted to open by 2027.

Safety first

For Indian Railways, safety is not one priority among many, it is the foundation on which every other achievement rests. Faster trains, modern stations and better passenger amenities have little meaning unless passengers can travel with confidence. Over the past decade, Indian Railways has therefore pursued safety not as a program, but as a mission backed by unprecedented investment, technology and systematic renewal of its assets. The results are now unmistakable.

The scale of this commitment is reflected in the numbers. Budgetary support for safety works has increased from around ₹39,000 crore in 2013-14 to ₹1.2 lakh crore in 2026-27 i.e. more than three times the level of a decade ago.

This investment has translated into a fundamental strengthening of the railway network. To improve asset reliability, around 1.63 lakh km of high-quality 60 kg rails and stronger 260-metre rail panels covering over 87,000 km have been laid since 2014. The impact is significant: rail fractures and weld failures have fallen by more than 90% compared with 2014 levels, making the track structure substantially more reliable and thus reducing chances of accidents.

Safety has also been strengthened at some of the network's most vulnerable points. More than 4,000 stations have been digitized, every unmanned level crossing on the broad-gauge network has been eliminated, and over 10,000 manned level-crossing gates have been interlocked. These are not merely infrastructure statistics; they represent thousands of potential points of risk systematically removed or controlled.

At the heart of the next generation of railway safety is Kavach, India's indigenous Automatic Train Protection system. Certified to the highest Safety Integrity Level (SIL-4), Kavach is designed to act when human intervention falls short automatically applying brakes if a loco pilot fails to respond appropriately and helping prevent collisions and over-speeding, including under challenging conditions such as dense fog.

Adopted as the national Automatic Train Protection system in 2020, Kavach has since evolved further. Kavach 4.0, approved in July 2024, is now commissioned on more than **2**,600 route km of the Delhi-Mumbai and Delhi-Howrah corridors, while trackside works are progressing on a further 21,000 route km. This marks a fundamental shift in railway safety from relying predominantly on human vigilance to creating an additional technology-driven layer of protection.

But safety is not only about preventing accidents; it is equally about ensuring that maintenance is timely, planned and disciplined. In November 2023, Indian Railways introduced the Rolling Block system, under which maintenance and repair of tracks, signaling systems and other safety-critical assets are planned up to 26 weeks in advance on a continuously rolling basis. This replaces the earlier practice of arranging maintenance blocks on a more ad-hoc basis and brings greater predictability, accountability and discipline to the upkeep of the network.

Together, these measures represent a fundamental change in the safety philosophy of Indian Railways: invest more, renew earlier, automate where possible, eliminate known risks and plan maintenance before problems arise. The objective is simple that every passenger should be able to board a train with the confidence that safety has been built into every kilometer of the journey.

The combined impact is stark:

consequential train accidents have fallen from 135 in 2014-15 to just 16 in 2025-26, an 88% reduction, even as traffic has grown busier and faster. The Consequential Accident Index has fallen from 0.11 to 0.01, a 91% reduction.

Affordable for Every Passenger

Despite the scale and ambition of this transformation, the common passenger remains at the heart of Indian Railways. Modernization has not come at the cost of affordability. In 2024-25, Indian Railways provided around ₹60,239 crore in passenger subsidy, effectively absorbing about 43% of the cost of every passenger journey. In simple terms, for every ₹100 spent on providing the service, the passenger pays only about ₹57.

The scale of this social commitment is enormous. It supports more than 750 crore passenger journeys every year, ensuring that millions of Indians can continue to travel across the country at fares that remain among the most affordable and lower than those in many neighboring and developed countries.

This is the distinctive character of Indian Railways' transformation: modernization without abandoning affordability; better services without pricing out the common passenger. It demonstrates that a world-class railway need not be an expensive railway and that efficiency, technology and social responsibility can move forward together.

None of this would be possible without the more than 12 lakh-strong workforces of Indian Railways who keep this vast network running safely and punctually, in every season and every corner of the country.

Towards a Viksit Bharat

The Indian Railways of today is not the railway of a decade ago. It is faster, safer and more comfortable, rebuilt not for its own sake but for the aspirations of 140 crore Indians. As the next generation of Vande Bharat, Namo Bharat and Amrit Bharat trains rolls out, as high-speed rail corridors take shape, as Kavach spreads across the network, and as the Dedicated Freight Corridors power greater trade, Indian Railways will continue to cut travel time, strengthen logistics, and power India's journey towards a Viksit Bharat.

○○○

Twelve Years of SCIENCE in Service of BHARAT

New Wave

Dr. Jitendra Singh
Union Minister of State (Ind. Charge) for
Science & Technology, Earth Sciences
MoS, Prime Minister's Office, Personnel,
Atomic Energy & Space
Govt. of India

When a lavender farmer in the Doda district of Jammu plucks the first blossoms of the season, she is not thinking about science policy. Yet it is precisely a decade of deliberate, mission-driven scientific investment that transformed barren hillsides in the Union Territory into fragrant fields of purple - a revolution in rural livelihoods born in a laboratory. This, in essence, is what twelve years of sustained commitment to science and technology in India has meant: not the advancement of knowledge for its own sake, but science as a living, breathing force in the daily lives of our citizens.

When Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, he articulated a vision that challenged us to think of science not as a departmental function but as a national mission. The years that followed have borne that vision out in ways that would have seemed extraordinary a generation ago. Today, India has landed a spacecraft at the Moon's south pole, developed its own antibiotic for the first time, built supercomputers from Pune to Patna, and created a space economy teeming with homegrown startups. But the deeper story - the one that deserves to be told - is how each of these achievements rippled outward into the lives of ordinary people. **Science is no longer confined to laboratories - it has become the single most powerful driver of national development and citizen empowerment.**

Consider the farmer. Weather, always the silent sovereign of Indian agriculture, has become far more legible over the last decade. A comprehensive overhaul of our earth observation and forecasting infrastructure now gives farmers accurate, hyperlocal weather predictions - not in the vague language of probability, but with the kind of precision that allows a family to

decide whether to harvest tomorrow or wait. When a cyclone forms over the Bay of Bengal today, our early warning systems give coastal communities hours - sometimes days - of advance notice. The difference is not statistical; it is counted in lives saved and livelihoods preserved.

In the mountains and river valleys of Jammu and Kashmir, science arrived in the form of the Aroma Mission - a program that introduced lavender cultivation and supported farmers with technology, seeds and market linkages. What began as a pilot has since transformed into what is now celebrated as India's Purple Revolution: thousands of farming families earning dignified incomes from aromatic and medicinal plants, with science as the quiet architect of this prosperity. Similar work in saffron expansion, medicinal herb cultivation, and the first-ever introduction of asafetida cultivation in India has demonstrated that innovation, rooted in the soil, can be as transformative as any industrial technology.

Rural empowerment through science has extended well beyond agriculture. From 3D-printed housing prototypes designed for affordable rural construction to AI-powered systems that detect food adulteration, technology is being deliberately directed at solving the problems that matter most to the people who can least afford them. The National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems - which connects computing, sensing and physical engineering - has established twenty-five Technology Innovation Hubs across the country, seeding more than a thousand startups working on problems as varied as precision agriculture, clean water access, and rural healthcare delivery.

Healing India: The Biotechnology Breakthrough

Perhaps no domain illustrates the transformative power of Indian science more vividly than biotechnology and healthcare. For decades, India's pharmaceutical strength lay in manufacturing - in producing generic versions of drugs discovered elsewhere. That story is changing. The development of Nafithromycin, India's first indigenously discovered antibiotic in decades, is not merely a scientific milestone: it is a declaration of pharmaceutical self-reliance. Born from a government-supported collaboration between researchers and industry, it signals that India's laboratories can now do what only a handful of nations have managed - innovate at the frontier of drug discovery.

Equally significant is the country's first successful indigenous gene therapy clinical trial for Haemophilia - a condition that requires lifelong, expensive treatment - conducted at the Christian Medical College in Vellore. Gene therapy works by correcting the underlying genetic fault rather than managing its symptoms; for a country with a large burden of genetic disease, the implications are profound. Combined with the GenomeIndia Project, which has now sequenced over ten thousand human genomes drawn from India's extraordinarily diverse population, we are laying the scientific foundation for a future in which medicine is tailored to each patient's biology.

The COVID-19 pandemic revealed, with painful clarity, how essential domestic biomedical capacity is to national security. India's response - developing and manufacturing its own vaccines at scale, deploying them across a population of 1.4 billion - drew on years of investment in our biotechnology ecosystem.

The Biotechnology Industry Research Assistance Council, or BIRAC, has been instrumental in nurturing biotech startups, bridging the gap between academic research and commercial scale-up, and ensuring that scientific innovation finds its way into the hands of those who need it most. Today, a new generation of bio-entrepreneurs is working on precision medicine, sustainable bio-based materials and next-generation diagnostics - and they are doing so from Indian cities and campuses, not just Silicon Valley.

The GenomeIndia Project has sequenced over ten thousand human genomes - laying the foundation for medicine tailored to every Indian's unique biology.

Reaching for the Stars, Grounding Every Citizen

On the 23rd of August 2023, as the Vikram lander of Chandrayaan-3 made its final descent toward the lunar south pole - a region no nation had ever reached - millions of Indians watched with a collective held breath. The moment of touchdown was not just a technological triumph; it was a national affirmation. India had done what no one else had managed. What followed - the analysis of the Moon's surface, the data transmitted back across three hundred and eighty thousand kilometers of space - mattered enormously to planetary science. But what mattered just as much was what that landing did to the imagination of a country.

India's space story over the past twelve years has been one of simultaneous ambition and utility. While Chandrayaan-3 captured the world's attention, Aditya-L1 - our first dedicated solar observatory - quietly began its mission to study the Sun, advancing our understanding of space weather that affects satellites, power grids, and communication systems on Earth. The SpaDeX mission placed India in an elite club of nations that have demonstrated the ability to dock two spacecraft in orbit - a capability essential for future space stations and crewed missions. Group Captain Shubhanshu Shukla's historic eighteen-day stay aboard the International Space Station brought India's human spaceflight ambitions from aspiration to lived experience. The transformation of India's space sector goes beyond missions, significant as they are.

The Indian Space Policy of 2023 opened the entire value chain - launch vehicles, satellites, ground systems - to private enterprise. The result has been electric. From just eleven space startups in 2014, India today hosts over four hundred, building rockets, designing satellites and creating applications that range from agricultural monitoring to disaster response. Indian launch vehicles have carried three hundred and ninety-nine foreign satellites into orbit since 2014, making us a preferred partner for space agencies around the world. The space economy is no longer a public-sector preserve; it is a national asset being built by thousands of young engineers and entrepreneurs. With the Bharatiya Antariksh Station - India's own space station - envisioned for 2035, and a crewed lunar mission targeted for 2040, the arc of this ambition is long, and its trajectory is upward.

Self-Reliance Through Innovation

Atmanirbhar Bharat - self-reliant India - is not merely a political slogan. In science and technology, it has become a governing philosophy. The National Quantum Mission, backed by more than six thousand crore rupees, is an investment not just in a technology but in India's strategic position in the twenty-first century's most consequential technological race. Quantum computing promises to solve problems that classical computers cannot; quantum communication offers theoretically unbreakable encryption; quantum sensing could transform navigation, medical imaging and geological exploration. India is now building all of these capabilities at home, through Thematic Hubs that bring together universities, research institutions and industry.

भरोसे के 100 दिन

8 स्तंभ
विकसित
पश्चिम बंगाल
के निर्माण हेतु

पश्चिम बंगाल में नए अध्याय का
शुभारंभ

उद्योग | स्वास्थ्य | शिक्षा | सुशासन
सशक्तीकरण | सेवा | सुरक्षा | समृद्धि

100 दिन | परिवर्तन एक नज़र में

उद्योग के 100 दिन

- ₹54,000+ करोड़ का निवेश प्रस्तावित
- ₹5,000 करोड़ के निवेश प्रोत्साहन रूपरेखा
- ₹100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वालों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था
- ₹100 करोड़ का स्टार्टअप फंड। नए उद्यमों व युवाओं के नये सोच को प्रोत्साहन

स्वास्थ्य के 100 दिन

- 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा' योजना के अंतर्गत ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज
- 'आयुष्मान भारत' योजना के दायरे में 1.43 करोड़ परिवार
- न्यू टाउन में निजी निवेशक समूह की पहल से 2,000 बेड वाले अत्याधुनिक अस्पताल का कार्य प्रारंभ। गरीबों के लिए 1,000 बेड आरक्षित
- उत्तर बंगाल में एम्स व अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल, सुंदरवन एवं जंगलमहल में आधुनिक राज्य सरकारी अस्पताल

शिक्षा के 100 दिन

- मिड डे मील के बजट में वृद्धि और इस्कॉन के सहयोग से भोजन की गुणवत्ता में सुधार
- पश्चिम बंगाल के विभिन्न पुस्तकालयों की लगभग 35,000 पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं
- सरकारी एवं बांग्ला माध्यम के विद्यालयों की स्थिति सुधारने हेतु ₹296 करोड़ की आर्थिक सहायता
- सरकारी विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन स्थापित। 10 लाख से अधिक छात्राओं को 'कन्या रत्न'

सुशासन के 100 दिन

- 'गुंडा दमन कानून' लागू किया गया है
- 'जनता दरबार' के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री तक शिकायतें दर्ज हो रही हैं
- राज्य में 'भारतीय न्याय संहिता', 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' एवं 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' लागू
- घूस, रंगदारी (तोलाबाज़ी), अवैध टोल बूथ एवं अवैध शराब कारोबार की शिकायत हेतु टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर शुरू

सशक्तीकरण के 100 दिन

- 1.19 करोड़ अवपूर्ण उपभोक्ताओं के बैंक खाते में प्रतिमाह पहुँच रहे ₹3,000
- महिलाओं के लिए सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा
- युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से आगामी एक वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का कार्य प्रारंभ
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा

सेवा के 100 दिन

- आवास योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्येक किस्त में ₹60,000 की आर्थिक सहायता प्रेषित
- माँ आहार कैंटीन में मछली-चावल की व्यवस्था
- वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन में ₹500 की वृद्धि
- सरकारी अस्पतालों में रोगियों के भोजन का दैनिक बजट ₹56 से बढ़ाकर ₹110 किया गया

सुरक्षा के 100 दिन

- सीमा सुरक्षा हेतु बीएसएफ को 1,000+ एकड़ भूमि हस्तांतरित
- सड़कों पर 'दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड' एवं 'पिंक गश्ती दल' की तैनाती
- साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु प्रत्येक थाने में 'साइबर हेल्प डेस्क'
- प्रत्येक सब-डिवीजन में महिला पुलिस स्टेशन, प्रत्येक थाने में 'महिला सहायता केंद्र'

समृद्धि के 100 दिन

- कोलकाता में पश्चिम बंगाल का पहला 'अटल इनक्यूबेशन सेंटर' (AIC Techno) शुरू। यह केंद्र युवा उद्यमियों एवं स्टार्टअप्स के विकास हेतु कार्य करेगा
- पारदर्शी ओबीसी आरक्षण ढांचा : 17% अवैध आरक्षण को निरस्त कर 7% न्यायसंगत आरक्षण सुनिश्चित
- 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत राज्यभर में 2 करोड़+ वृक्षारोपण संपन्न
- पुरुलिया, बालूरघाट एवं मालदा में नए एयरपोर्ट तथा कल्याणी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की पहल

भरोसे के 100 दिन

विकास के संकल्प के साथ समृद्ध पश्चिम बंगाल के निर्माण का लक्ष्य

नई सरकार | नई दिशा | नया पश्चिम बंगाल

The National Supercomputing Mission has seeded high-performance computing infrastructure across the country - in Pune, Chennai, Kharagpur and beyond - giving Indian researchers, engineers and startups access to computational power that was once the preserve of a handful of elite institutions. Alongside this, BharatGen - the country's first government-funded multilingual Generative AI program - is developing large language models that can think and communicate in Indian languages, ensuring that the benefits of artificial intelligence are not confined to English-speaking users.

CSIR's contribution to this vision of self-reliance deserves particular mention. The indigenously developed HANSA-NG trainer aircraft, produced for domestic and export markets, represents a capability built from scratch by Indian engineers. India's first hydrogen fuel-cell powered vessel points toward clean maritime transport. Work on sustainable aviation fuel opens pathways to decarbonizing air travel without dependence on foreign technology. The CSIR Innovation Complex, India's first such facility, is designed to be a crucible where laboratory research meets entrepreneurial energy - a place where the distance between a scientific idea and a market-ready product is systematically compressed.

From just 11 space startups in 2014, India today hosts over 400 - a testament to the power of policy, public investment, and entrepreneurial spirit working in concert.

Energy Security and Future-Ready Technologies

No account of India's scientific transformation is complete without acknowledging the strategic depth being built in nuclear energy. The first criticality of the 500 MWe Prototype Fast Breeder Reactor at Kalpakkam in April 2026 is a milestone of historic proportions. Developed entirely by Indian scientists and engineers at the Indira Gandhi Centre for Atomic Research and built by Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam, this reactor is the critical bridge to the second stage of India's three-stage nuclear program - a pathway designed to eventually harness our country's vast reserves of thorium, one of the most abundant elements in Indian soil. In an era of energy transition, the ability to generate clean, continuous power from domestic fuel is not merely economical; it is a matter of sovereign security.

The nuclear sector has also extended its reach into medicine. The Tata Memorial Hospital's recognition by the International Atomic Energy Agency as a 'Rays of Hope' Anchor Centre, the expansion of cancer hospitals under the Homi Bhabha Cancer Hospital network, and the deployment of advanced radiopharmaceuticals - medicines that use radioactive particles to diagnose and treat cancer - are bringing world-class oncology care to

patients across the country. The SHANTI Act of 2025 has modernised the legal architecture of India's nuclear sector, enabling greater participation and investment in an industry that will be central to our clean energy future.

Meanwhile, the Deep Ocean Mission is extending India's scientific reach into the last great unexplored frontier on our planet. Our ocean floor holds vast reserves of minerals essential for clean energy technologies - polymetallic nodules and cobalt-rich crusts that could reduce India's dependence on imported critical minerals. The mission is also building the underwater vehicle and sensor technologies that give India strategic and scientific presence in its maritime domain.

Towards Viksit Bharat: Science as Destiny

As India counts down the years to 2047 - the centenary of our independence and the target year for becoming a fully developed nation - science and technology will not merely support that journey; they will determine its pace and character. The investments made over the last twelve years have created not just institutions and infrastructure, but something more durable: a culture of scientific ambition, entrepreneurial energy and national confidence.

The Anusandhan National Research Foundation, created to transform India's research ecosystem through mission-led science, academia-industry collaboration and empowerment of young researchers, and the newly constituted Research, Development and Innovation Fund with a corpus of one lakh crore rupees, represent the largest bet India has ever placed on its own intellectual capacity. They signal a conviction - hardened by twelve years of evidence - that the solutions to our most pressing challenges lie within our own laboratories, campuses and communities.

The lavender farmer in Doda, the genomics researcher in Vellore, the space startup founder in Bengaluru, the nuclear engineer in Kalpakkam - they are all characters in the same story. It is the story of a nation that chose, deliberately and decisively, to place science at the centre of its development. What the last twelve years have built is not a portfolio of achievements but a foundation - sturdy, deep and wide - upon which a developed, self-reliant and scientifically confident India will rise.

○○○

On the occasion of Independence Day, a flag-hoisting ceremony was organized by Laghu Udyog Bharati, Delhi Prant at Head Office Shri Vishwakarma Bhawan. The event was attended by Delhi Prant President Shri Diwan Chand Gupta, Treasurer Shri Kumar Pal Mehta, and staff members.

LUB's Tamil Nadu delegation met Union Minister Dr. L. Murugan and invited him for LUB SANGAMAM Expo to be held at Hosur, Tamil Nadu. State President Shri VerChezhiyan and Shri Balaji were present.

Heartiest
Congratulations
& Best Wishes
VIKSIT BHARAT
To our Beloved Prime Minister of India
for his historic tenure, visionary leadership,
and unwavering commitment to building a
Viksit Bharat.
"Empowering the nation through progress,
development, and visible transformation at every level."
REDROSE SYNTHETICS PVT LTD KOLKATA
REDROSE
SYNTHETICS PVT. LTD.
REDROSE SYNTHETICS PVT LTD KOLKATA
Your Trusted Partner in
Textile & Garment Accessories
OUR PRODUCT SPECIALTIES
ALL TYPES OF YARNS:
High-tenacity, synthetic, and
specialty yarns customized
to your specifications.
GARMENT DORI (CORDS):
Premium quality drawstrings
and cords for hoodies,
sportswear, and ethnic wear.
Redrose Synthetics Pvt. Ltd.
Room No. 529 (5th Floor),
40, Strand Road, Kolkata – 700001, West Bengal
Email: redrosesynthetics@gmail.com
Phone: 033 40012949
Mobile: +91 9874393543
Contact us today for all types of
Yarn, Garment Dori, requirements!

MSME Industries Getting a New Lease of Life under NaMo's Leadership

Growth Story

Shobha Karandlaje
Union Minister of State for Ministry of
Micro, Small & Medium Enterprises and
Labour & Employment
Govt. of Bharat

How a decade of formalisation, credit reform and digital infrastructure has rewritten the story of India's smallest enterprises

For India's small entrepreneurs, 2014 was a year of transformation. Prior to this, millions of micro, small and medium enterprises (MSMEs) functioned largely outside the formal economy, unseen by banks, unreachable by large buyers and unheard by the state. A decade later, the picture looks fundamentally different. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, a sustained, deliberate program of reform has moved MSMEs from the periphery of policy to the centre of India's growth story, and in doing so has given the sector, in every sense, a new lease of life.

The 2014 Inheritance: A Sector Held Back

When the Modi government took office in 2014, India's MSME sector was large in numbers but weak in standing. Registration was cumbersome, paper-based and scattered across multiple state and central authorities, which meant a huge share of enterprises simply never formalised. Without a formal identity, these units could not access institutional credit, government schemes or public procurement.

Credit was perhaps the sharpest constraint. Banks viewed small enterprises as high-risk, collateral-light borrowers, and lending to the sector was accordingly cautious and limited. **As of 2014, total bank credit outstanding to the MSME sector stood at approximately Rs 10.40 lakh crore, against an**

estimated credit gap of Rs. 20-25 lakh crore, a shortfall that left a large share of viable small enterprises without access to formal, affordable finance.

Delayed payments compounded the problem. Small suppliers routinely waited months to be paid by larger buyers and government departments alike, with no efficient recourse, forcing many into expensive informal borrowing simply to survive between invoices. Public procurement, too, was largely closed to small enterprises, which lacked the scale, connections or bureaucratic staying power to compete for government contracts.

Skilling infrastructure was thin, technology upgradation support was patchy, and there was no single, transparent digital gateway through which a small entrepreneur could register a business, access a scheme, sell to the government or resolve a dispute. The sector's contribution to the economy was real but under-realised, a reservoir of enterprise that the architecture of governance had not yet learned to tap.

A Decade of Deliberate Reform

Rather than a single flagship scheme, the Modi government's approach to MSMEs has been cumulative, with each term building institutional and digital infrastructure on top of the last.

Term-1 (2014-2019): Laying the Foundation

The first term focused on widening access to credit and formal identity. The Pradhan Mantri Mudra Yojana was launched in 2015 to extend collateral-free micro-credit to small and micro units. The Udyog Aadhaar Memorandum, also introduced in 2015, simplified registration into a one-page, self-certified process which was a precursor to today's Udyam Portal. The Stand-Up India scheme (2016) opened bank loans of up to Rs. 1 crore for women and entrepreneurs from Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities to set up greenfield enterprises. The Government e-Marketplace (GeM) was launched in 2016 to give small suppliers direct, transparent access to government procurement, and the Trade Receivables Discounting System (TReDS) went live in 2017 to help MSMEs convert unpaid invoices into working capital.

Term-2 (2019-2024): Formalisation and Resilience

The second term brought structural change alongside crisis response. In 2020, the definition of MSMEs was revised to raise investment and turnover thresholds, allowing many growing units to retain MSME benefits rather than being pushed out of the category. The same year saw the launch of the Udyam Registration Portal, replacing older, more fragmented registration systems with a paperless, Aadhaar-linked, self-declaration process.

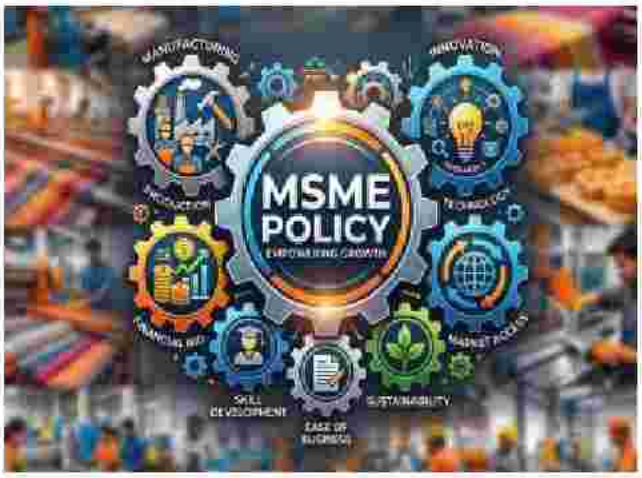

When the COVID-19 pandemic threatened to shut down small businesses end masse, the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) provided collateral-free, fully guaranteed credit to help enterprises survive the shock. The Champions Portal was set up as a single-window grievance and handholding platform, and the RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) program was approved to strengthen market access, finance and technology adoption across the sector.

Term-3 (2024-present): Deepening and Digitising

The current term has focused on inclusion at the margins and the next generation of digital tools. The Udyam Assist Platform was extended to bring informal micro enterprises which were without the documentation for standard registration into the formal fold, and the PM Vishwakarma Scheme has continued to support traditional artisans and craftspeople with skilling, financial assistance and modern tools.

The MSME Online Dispute Resolution (ODR) Portal has added online conciliation and arbitration to the justice toolkit alongside the MSME Samadhaan Portal for delayed-payment cases. Targeted efforts for women entrepreneurs including the Mahila Coir Yojana, the Yashasvini Awareness campaign and the Women Entrepreneurship Cell have been scaled up, and the government has announced next-generation platforms: PMEGP 2.0, MSME Samadhaan 2.0 and an ONDC-integrated MSME Global Mart 2.0 to take small enterprises onto national and global digital marketplaces.

This term has also delivered a landmark legislative upgrade with both Houses of Parliament having passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2026, modernising a two-decade-old law to match today's ecosystem. The Amendment enables free, voluntary registration on a national digital platform, makes classification more responsive to changes in technology and markets, and tackles delayed payments through a prevent-resolve-enforce framework built around mandatory TReDS onboarding for CPSEs, additional Facilitation Councils and statutory recognition of online dispute resolution. It also shifts compliance towards a more trust-based approach, replacing penalties for first-time minor lapses with a warning.

Taken together, credit to MSMEs has grown from Rs. 10.40 lakh crore as on 31st March, 2014 to Rs. 38.35 lakh crore as on 31 March, 2026 which is a 269 per cent increase in twelve years while more than 9.29 crore enterprises have registered on Udyam Registration Portal, including 4.06 crore informal micro units on-boarded through Udyam Assist.

Contribution to GDP and Exports

The MSME sector today accounts for close to 31.1 per cent of India's GDP, over 35 per cent of manufacturing output, and approximately 48.58 per cent of the country's total exports, figures that place small enterprises at the heart of India's production and trade story rather than at its margins. A closer, sector-wise look at where this contribution is concentrated further illustrates the breadth of the sector's reach. This diversification matters because MSME growth is not dependent on the fortunes of any single industry, and reform that strengthens the sector's common infrastructure i.e. credit, procurement access, digital registration-carries a multiplier effect across manufacturing, services and traditional crafts alike.

Contribution to Employment Generation and Women's Empowerment

MSMEs are, by a wide margin, India's largest source of non-farm employment, providing livelihoods to an estimated 41 crore workers, a workforce larger than the population of most countries in the world. This employment is spread across manufacturing, trade and services, and is particularly significant in semi-urban and rural India, where MSMEs are often the only formal or semi-formal employers available.

Schemes such as the Prime Minister's Employment Generation Program (PMEGP) and the PM

Vishwakarma Scheme have been specifically designed to expand this employment base by helping new entrepreneurs set up non-farm micro enterprises and by equipping traditional artisans with skills, tools and finance. Women's participation has grown notably: over 3.48 crore women-led enterprises are now registered on the Udyam and Udyam Assist platforms, accounting for roughly 40 per cent of all registered MSMEs, and 39 per cent of PMEGP beneficiaries over the past five years have been women.

Overall Impact and the Way Forward

The cumulative effect of a decade of reform is a sector that is more visible, more financed and more connected than at any point in independent India's history. Formalisation through Udyam and Udyam Assist has brought crores of enterprises out of the shadows and into the ambit of state support. **GeM has opened public procurement with more than 11.74 lakh MSME sellers now registered and cumulative procurement crossing Rs. 18.40 lakh crore. TReDS has unlocked over Rs. 8.71 lakh crore in receivables financing since 2021,** keeping small suppliers' solvent even when large buyers are slow to pay. And digital grievance and dispute-resolution platforms have begun to give small entrepreneurs a fair and swift hearing when problems arise.

The task ahead is to deepen this architecture rather than rest on it. That means extending formalisation to the last mile of informal micro enterprises still outside Udyam Assist's reach; ensuring credit growth keeps pace with the sector's expanding ambitions, particularly for women- and first-generation entrepreneurs; integrating MSMEs more fully into global value chains through quality certification, technology upgradation and platforms like the forthcoming ONDC-linked Global Mart 2.0; and continuing to reduce the compliance burden that still weighs disproportionately on the smallest units.

As India works towards the goal of a Viksit Bharat by 2047 and a $30 trillion economy, the MSME sector is not a peripheral actor in that ambition but one of its principal engines. The digital and financial scaffolding built over the past decade with Udyam, GeM, TReDS, Champions, Samadhaan, ODR and the next generation of platforms now taking shape and is, in the most concrete sense, the infrastructure of that promise. For the small entrepreneur who once waited weeks for a registration certificate and months for an overdue payment, that infrastructure has already meant a new lease of life; the work now is to make sure no enterprise, however small or remote, is left outside it.

○○○

उद्यमिता के साथ
सेवा, सादगी और समर्पण का रखा उच्च आदर्श

उद्यम यात्रा
घनश्याम ओझा
अग्रणी उद्यमी एवं
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष– लघु उद्योग भारती
पूर्व महापौर– जोधपुर

राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर के सफल उद्योगपति श्री घनश्याम ओझा संगठन क्षमता और जन सेवा के साथ समाज समर्पण के अद्भुत उदाहरण हैं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में जिस तरह से ईमानदारी, सादगी, विकास दृष्टि और कर्मनिष्ठ नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया, वो सभी के लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है। श्री ओझा का जीवन संघर्ष, सफलता, सेवा और संस्कारों की ऐसी गाथा है जिससे सन्देश मिलता है कि सच्ची सफलता वही है, जो समाज और राष्ट्र के हित में समर्पित हो।

परिवार एवं प्रारंभिक जीवन

12 अगस्त, 1954 को जोधपुर जिले के गंगाणी गांव में एक प्रतिष्ठित एवं संस्कारित परिवार में श्री घनश्याम ओझा का जन्म हुआ। वे स्वर्गीय श्री रामपाल जी के सबसे छोटे पुत्र हैं। उनकी माताश्री श्रीमती भंवरी देवी, बुडकिया निवासी श्री रामचन्द्र जी लव ओझा की सुपुत्री थीं। ग्रामीण परिवेश में पले–बढ़े घनश्यामजी ने बचपन से ही श्रम, अनुशासन और संस्कारों को अपने जीवन का आधार बनाया। उन्हें बड़े भ्राता श्री रामप्रसाद जी एवं श्री रामकिशोर जी तथा बहनों श्रीमती रामज्योत बाई एवं श्रीमती सीता देवी का भरपूर स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

घनश्यामजी की प्रारंभिक शिक्षा गंगाणी गांव में हुई। पांचवीं के बाद वे जोधपुर आए और मंडी स्कूल से आठवीं तथा न्यू गवर्नमेंट स्कूल से उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। इसके

जोधपुर आगमन पर हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते श्री घनश्याम ओझा

बाद उन्होंने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की शिक्षा वर्ष 1975 में पूर्ण की। उन्होंने चिकित्सक बनने का सपना लेकर प्री–मेडिकल टेस्ट (PMT) भी दिया, किन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई। बाद में विधि शिक्षा हेतु प्रवेश लिया और प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किया, परंतु पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आगे अध्ययन जारी नहीं रख सके। किन्तु परिस्थितियों ने उनके आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं किया। उन्होंने संघर्षों को अवसर में बदलने का मार्ग चुना और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे।

सफल उद्यमी और समाजसेवी श्री घनश्याम ओझा को श्री सुन्दर सिंह भंडारी चेरिटेबल ट्रस्ट, लोक संगीत माड शोध संस्थान ने लोक सेवा श्री सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय सारस्वत ब्राह्मण महासम्मेलन ने एक्सीलेंस अवॉर्ड और लायंस क्लब इंटरनेशनल सहित कई संगठनों ने सम्मानित किया।

नौकरी में सीखा कौशल और प्रबंधन क्षमता

पारिवारिक दायित्वों को निभाने हेतु उन्होंने प्रारंभ में जीवन बीमा निगम में एजेंट के रूप में कार्य किया। वर्ष 1975 में उन्हें जोधपुर के प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं उद्यमी श्री भगवान सिंह परिहार की संस्था "लक्ष्मी उद्योग" में मात्र 180 रुपये प्रतिमाह वेतन पर कैशियर के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। उनके बड़े भ्राता श्री रामकिशोर जी उसी संस्थान में मैनेजर थे। कठोर अनुशासन और किसी भी कार्य को सीखने की ललक ने उन्हें शीघ्र ही दक्ष प्रशासक बना दिया। एक वर्ष के भीतर ही उन्हें "रामा इंडस्ट्रीज" में मैनेजर के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं से उन्होंने व्यापार, उत्पादन प्रक्रिया, मशीनरी संचालन और औद्योगिक प्रबंधन की गहन समझ विकसित की।

कठिन दौर में धैर्य और दूरदृष्टि

वर्ष 1983 में स्टील उद्योग में आई भारी मंदी ने जोधपुर के अनेक उद्योगों को बंद होने पर मजबूर कर दिया। ऐसे कठिन समय में भी श्री ओझा ने धैर्य नहीं खोया। उनके पिता स्वर्गीय श्री रामपाल जी के अनुभव और मार्गदर्शन ने उद्योग को संकट से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह संघर्षपूर्ण दौर उनके व्यक्तित्व को और अधिक मजबूत बनाकर सामने लाया।

उद्यम यात्रा में संघर्ष से छूआ शिखर को

श्री ओझा का व्यावसायिक जीवन भी समान रूप से प्रेरणादायी है। उन्होंने अत्यंत साधारण परिस्थितियों से अपनी यात्रा प्रारंभ कर परिश्रम, अनुशासन और दूरदृष्टि के बल पर उद्योग जगत में विशिष्ट पहचान स्थापित की। वर्ष 1981 में उन्होंने मात्र 23 हजार रुपये की बचत से किराये की फैक्ट्री में "श्रीराम मेटल्स" की स्थापना की। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी गुणवत्ता आधारित कार्यशैली, विश्वसनीयता और अथक मेहनत ने उद्योग को निरंतर आगे बढ़ाया।

वर्ष 1991 में "एसआरएम एलॉयज प्रा.लि." तथा 1996 में "एसआरएम स्टील" की स्थापना कर उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार किया। इन उद्योगों में स्टेनलेस स्टील पाटा का निर्माण किया जाता है, जो बर्तन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है।

वर्ष 2010 में बर्तन उद्योग तथा 2022 से हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में भी उन्होंने सफलतापूर्वक कार्य प्रारंभ किया। आज उनका औद्योगिक समूह गुणवत्ता, रोजगार सृजन और विश्वसनीयता का प्रतीक माना जाता है। उनकी सफलता केवल व्यापारिक उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, संघर्ष और स्वदेशी उद्योगों के प्रति समर्पण की प्रेरक कहानी है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिला संगठनात्मक जीवन

वर्ष 1990 से श्री ओझा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और राष्ट्रसेवा की भावना से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हुए। उन्होंने सेवा भारती एवं स्वदेशी जागरण मंच में भी सक्रिय योगदान दिया। वर्ष 1996 से वे लघु उद्योग भारती से जुड़े और संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जोधपुर प्रांत अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए सेवाएं प्रदान कीं। उनके नेतृत्व में लघु उद्योग भारती का संगठनात्मक विस्तार पूरे देश में हुआ तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को नई दिशा मिली।

जोधपुर महापौर के रूप में जनसेवा का लिखा स्वर्णिम अध्याय

वर्ष 2014 से 2019 तक श्री घनश्याम ओझा ने जोधपुर नगर निगम के महापौर के रूप में ऐतिहासिक सेवाएं प्रदान कीं। उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम माना, सत्ता का साधन नहीं। उनका पांच वर्षीय कार्यकाल विकास, पारदर्शिता, अनुशासन और जनहितकारी निर्णयों के लिए विशेष रूप से स्मरण किया जाता है। जोधपुर के सफल महापौर के रूप में उन्होंने जो कार्य किए, वे आज भी जनमानस में आदर्श प्रशासन और पारदर्शी नेतृत्व के प्रतीक हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि यदि व्यक्ति में ईमानदारी, दूरदृष्टि और समाज के प्रति समर्पण हो, तो वह सीमित संसाधनों से भी असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है।

महापौर के रूप में उन्होंने शहर के आधारभूत विकास, स्वच्छता, जन–सुविधाओं, सामाजिक समरसता और प्रशासनिक कार्यक्षमता को नई दिशा प्रदान की। उनके नेतृत्व में शहर में विकास की एक नई धारा प्रवाहित हुई। जोधपुर के नागरिक आज भी उनके कार्यकाल को नगर विकास के स्वर्णिम कालखंड के रूप में स्मरण करते हैं।

श्री ओझा की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और मितव्ययिता की ऐसी मिसाल कायम की, जो बेमिसाल है। वे ऐसे विरले महापौर रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सादगी और नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने महापौर रहते हुए कार्यालय संचालन खर्च एवं आवागमन के लिए निजी संसाधनों का उपयोग किया तथा अनावश्यक सरकारी खर्चों से सदैव दूरी बनाए रखी। उनका मानना था कि जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व जनता के धन की रक्षा करना है। यही कारण है कि उनका कार्यकाल जनविश्वास, स्वच्छ छवि और आदर्श प्रशासन का पर्याय बन गया।

आदर्श पारिवारिक जीवन में सादगी और उच्च नैतिकता

अपार सफलता प्राप्त करने के बावजूद श्री ओझा का जीवन प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आत्मीयता और सम्मान से परिपूर्ण रहता है। वे मानते हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र और व्यवहार होता है। उनकी यही सरलता उन्हें समाज में विशेष सम्मान दिलाती है। श्री ओझा का पारिवारिक जीवन भी अत्यंत प्रेरणादायी है। उनकी स्व. धर्मपत्नी श्रीमती शांति देवी ओझा ने जीवन के प्रत्येक संघर्ष और सफलता में उनका साथ दिया। परिवार में पुत्र श्री कैलाश एवं श्री राजेश के साथ पुत्री संगीता जी, दामाद अधिवक्ता श्री वीरेंद्र सारस्वत, पुत्र वधु श्रीमती रीना एवं श्रीमती राधिका तथा पौत्र–पौत्रियां दिव्यांश, योजित, आर्य, मैत्री एवं आराध्या हैं। उन्होंने सदैव परिवार, संस्कार और सामाजिक मूल्यों को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना है।

सर्व समाज के हितैषी और जन–सेवक

वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सारस्वत ब्राह्मण महासम्मेलन के विराट आयोजन की सफलता में श्री ओझा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। लेकिन वे हमेशा मानवता और जनसेवा को समर्पित रहे। वे सर्व–समाज के लिए समान आत्मीयता, संवेदनशीलता और समर्पण की भावना रखने वाले जन–सेवक के रूप में प्रतिष्ठित हैं।

उनका जीवन "सबका साथ, सबका सम्मान और सबकी सेवा" की भावना का जीवंत उदाहरण है। वे समाज के प्रत्येक वर्ग – गरीब, जरूरतमंद, श्रमिक, व्यापारी, युवा, बुजुर्ग और

सामाजिक संस्थाओं के सुख–दुःख में सदैव सहभागी रहे हैं। चाहे सामाजिक सहयोग का विषय हो, किसी जरूरतमंद परिवार की सहायता, शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, चिकित्सा सहायता, धार्मिक आयोजन, गौ–सेवा, राष्ट्रहित के कार्य अथवा सामाजिक समरसता को मजबूत करने का प्रयास हो– श्री ओझा सदैव अग्रणी भूमिका में दिखाई देते हैं।

उद्योग क्षेत्र में भी उन्होंने केवल व्यापारिक लाभ को लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि रोजगार सृजन और अनेक परिवारों के जीवन को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। उनकी संस्थाओं से जुड़े अनेक कर्मचारी उन्हें अभिभावक और मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। श्री ओझा उन विरले लोगों में से हैं जिन्होंने अपने कर्म, व्यवहार और सेवा भावना से समाज के प्रत्येक वर्ग के हृदय में विशेष स्थान बनाया है। आज उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए यह प्रेरणा देता है कि वास्तविक सफलता केवल पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति में नहीं, बल्कि मानवता और जनसेवा के लिए समर्पित जीवन में निहित होती है। ○○○

लघु उद्योग भारती, राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जोधपुर अंचल के प्रभारी श्री महावीर चोपड़ा के साथ विशेष बातचीत पर आधारित।

LUB's Rampur Unit (UP) organised the Trader Dialogue Program in the presence of Cabinet Minister, UP Govt. Shri Bhupendra Singh Chaudhary on 10th August. Shri Varendra Jindal highlighted the crisis facing the local plywood industry-and the challenge to its very survival-due to rising competition from imported products. Unit President Shri Deepak Goyal called for the resolution of various issues concerning trade and industry, including the abolition of market fees. On this occasion, five prominent traders were also honored for their outstanding contributions to industry and trade.

LUB's delegation led by National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji met the Union Minister of Food & Public Distribution Shri Prahlad Joshi to apprise him of the problems being faced by rice millers with respect to the procurement of CMR at New Delhi on 1st August. The delegation also raised the matter related to the QCO of grey iron castings. The Minister gave a patient hearing and assured the delegation that the issues would be looked into positively. The delegation included National General Secretary Shri Om Prakash Gupta, National Vice President Shri Sachin Sabnis & National Jt. GS Shri Naresh Pareek.

A three-day 'Swayamsiddha Exhibition' organized by the Women's Wing of Laghu Udyog Bharati Rajsamand, was inaugurated in the presence of LUB's National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji, MLA Smt. Deepti Maheshwari, District Collector Shri Arun Hasija on 4th August.

Chittor Prant President Shri Mahesh Hurkat, Swayamsiddha Prant In-charge Smt. Reena Rathore, and Women's Wing President Smt. Kiran Bapna visited the exhibition and commended the innovation, skills, and self-reliance of the women entrepreneurs. Women entrepreneurs from more than 15 districts of Rajasthan, as well as from other states, showcased their products at the exhibition.

'नमो' नेतृत्व में विकसित गुजरात मॉडल और गुजरात प्रदेश

आदर्श प्रतिमान
भूपेंद्र भाई पटेल
मुख्यमंत्री गुजरात

भारत के सुशासन के इतिहास में जब भी दूरदर्शिता, संकल्प और समावेशी विकास की चर्चा होगी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व का उल्लेख अवश्य होगा। आज विश्व जिस विराट नेतृत्व क्षमता का साक्षी बन रहा है, उसकी मजबूत नींव गुजरात की इसी धरती पर वर्षों पहले रखी जा चुकी थी। श्री नरेन्द्र मोदी जी का नेतृत्व केवल एक राजनीतिक अध्याय नहीं, बल्कि विकास की उस यात्रा का प्रतीक है, जिसने दुनिया को गुजरात मॉडल दिया और आज यही मॉडल 'विकसित भारत–2047' के महान संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत आधार बन चुका है।

संकटों से स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर गुजरात

दो दशक पहले, जब गुजरात विनाशकारी भूकंप और गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था, तब श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला। समय कठिन था और परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, लेकिन उनके दूरदर्शी विजन और अथक परिश्रम ने गुजरात को उस मलबे से उठाकर पुनर्निर्माण और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया। 'आपदा में अवसर' खोजने का जो मंत्र उन्होंने दिया, उसने प्रदेश की जनता में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया।

यहीं से गुजरात के विकास की वह यात्रा शुरू हुई, जिसे आज दुनिया 'गुजरात मॉडल' के रूप में देखती है। यह मॉडल केवल गगनचुंबी इमारतों, बड़े उद्योगों या विशाल परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। इसकी वास्तविक शक्ति 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की भावना में निहित है। नीति आधारित शासन, पारदर्शी प्रशासन, जनभागीदारी और परिणामोन्मुख कार्यसंस्कृति इसके मजबूत स्तंभ रहे हैं।

उद्यमशीलता से वैश्विक औद्योगिक पहचान तक

गुजरात सदियों से व्यापार, उद्यमशीलता और नवाचार की भूमि रहा है। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व ने गुजरात की इसी स्वाभाविक ताकत को एक नई वैश्विक पहचान दी। वर्ष 2003 में 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट' की शुरुआत इसी सोच का परिणाम थी। इसके माध्यम से गुजरात ने दुनिया के निवेशकों के लिए अपने द्वार खोले और धीरे–धीरे राज्य एक प्रमुख वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित हुआ।

इस विकास यात्रा में बड़े उद्योगों के साथ–साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला। 'लघु उद्योग भारती' जैसी संस्थाएं इस बात की साक्षी हैं कि गुजरात की अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। छोटे उद्यमियों को बेहतर अवसंरचना, सरल नीतियां, व्यापार सुगमता, विश्वसनीय बिजली और वैश्विक बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना इसी दूरदृष्टि का परिणाम है।

राजकोट के इंजीनियरिंग उद्योग से लेकर मोरबी के सिरेमिक उद्योग और सूरत के वस्त्र एवं हीरा उद्योग तक, गुजरात के छोटे और मध्यम उद्यम आज 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को मजबूत कर रहे हैं। यही उद्यमशीलता गुजरात को देश के प्रमुख विनिर्माण केंद्रों में स्थापित करती है और राष्ट्रीय निर्यात में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करती है।

औद्योगिक विकास के साथ गुजरात ने शहरी और भौतिक अवसंरचना के क्षेत्र में भी नई मिसालें कायम की हैं। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित साबरमती रिवरफ्रंट शहरी पुनर्विकास और नियोजन का एक अनुपम उदाहरण बना। कच्छ में विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क आकार ले रहा है। पत्तन आधारित विकास, रो–रो फेरी सेवा और बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाएं यह बताती हैं कि गुजरात केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने पर ही नहीं, बल्कि आने वाले अवसरों के लिए भी आज से तैयारी कर रहा है।

वर्तमान की चुनौतियों से आगे, भविष्य की तैयारी

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक यह रही है कि उन्होंने वर्तमान की समस्याओं का समाधान करते हुए हमेशा भविष्य की आवश्यकताओं को सामने रखा। गुजरात में इस सोच के अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं।

हर गांव में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने वाली 'ज्योतिग्राम योजना' हो या नर्मदा मैया के जल को सौराष्ट्र और कच्छ के शुष्क क्षेत्रों तक पहुंचाने वाली 'सौनी योजना', ऐसे अनेक कार्य कभी कठिन और लगभग असंभव प्रतीत होते थे। लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति, स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर प्रयासों ने उन्हें जमीन पर साकार किया।

इसी विकास दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए हमने 15 जून, 2026 को 'विकसित गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026' का शुभारंभ किया। यह नीति गुजरात की औद्योगिक यात्रा के अगले चरण की आधारशिला है। आगामी पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने के लक्ष्य के साथ तैयार की गई यह नीति नवाचार, निवेश और समावेशी विकास को केंद्र में रखती है। इसमें MSMEs और स्टार्टअप्स को विशेष महत्व दिया गया है।

हमारा लक्ष्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य ऐसा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करना है, जहां बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्यम, युवा स्टार्टअप्स, कुशल मानव संसाधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी समान रूप से आगे बढ़ें। 2047 तक गुजरात को विश्व के सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्रों में स्थापित करने की दिशा में यह नीति एक महत्वपूर्ण कदम है।

नई अर्थव्यवस्था के केंद्र में गुजरात

आज गुजरात में धोलेरा SIR के रूप में एक विश्वस्तरीय ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी आकार ले रही है। GIFT City वैश्विक वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। लेकिन बदलती दुनिया के साथ गुजरात की महत्वाकांक्षाएं भी बदल रही हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हमने डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण पहल की है। 9 जुलाई, 2026 को महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर से 'विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी 2026–29' लागू की गई। इस नीति के अंतर्गत धोलेरा में 7 से 8 गीगावाट क्षमता वाला विशाल डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है और पहले ही चरण में 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

इस नीति के साथ गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बना, जिसने डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए समर्पित नीति औपचारिक रूप से लागू की। यह केवल एक नई औद्योगिक नीति नहीं है, बल्कि आने वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था की जरूरतों को समझते हुए तैयार किया गया एक दीर्घकालिक विजन है।

इसी दूरदृष्टि की एक महत्वपूर्ण कड़ी 'गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022–27' भी रही है। इस नीति ने धोलेरा को भारत की पहली 'सेमीकॉन सिटी' के रूप में विकसित करने की दिशा में मजबूत आधार तैयार किया। आज माइक्रोन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी वैश्विक कंपनियों की परियोजनाएं गुजरात को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के केंद्र में स्थापित कर रही हैं। सेमीकंडक्टर से लेकर डेटा सेंटर तक, गुजरात का प्रयास स्पष्ट है। दुनिया जिन तकनीकों को कल की अर्थव्यवस्था का आधार मान रही है, उनकी नींव गुजरात आज ही तैयार कर रहा है।

विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं

गुजरात मॉडल की सफलता को केवल निवेश, उद्योग या अवसंरचना के आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। इसकी असली कसौटी यह है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंचा है। यही कारण है कि गुजरात की विकास यात्रा में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को उतना ही महत्व दिया गया है, जितना उद्योग और निवेश को।

'कृषि महोत्सव' के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक

और नई कृषि पद्धतियों से जोड़ने का प्रयास किया गया। 'सुजलाम–सुफलाम जल अभियान' ने जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण परिणाम दिए। इन पहलों ने यह साबित किया कि जब सरकार की नीतियां जनभागीदारी से जुड़ती हैं, तो उनका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक और स्थायी होता है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'मुख्यमंत्री अमृतम' योजना ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को गुणवत्तापूर्ण उपचार का भरोसा दिया। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में 'शाला प्रवेशोत्सव' और 'कन्या केलवणी' जैसे अभियानों ने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के साथ सामाजिक सोच में भी बदलाव लाने का काम किया। आज 'विद्या समीक्षा केंद्र' जैसी आधुनिक पहल तकनीक के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और परिणामों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित कर रही है। इन पहलों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें विकास को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसे सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ा गया।

'विकसित भारत–2047' का ग्रोथ इंजन बनेगा गुजरात

आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'विकसित भारत–2047' का विराट संकल्प देश के सामने रखा है, तब गुजरात इस राष्ट्रीय यात्रा में अपनी भूमिका को लेकर पूरी तरह सज्ज और प्रतिबद्ध है। जिस गुजरात मॉडल ने राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वही अनुभव अब विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

हमारा प्रयास है कि विकास की इस यात्रा में बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्यमी, किसान, युवा, महिलाएं और स्टार्टअप्स भी समान रूप से भागीदार बनें। यही 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की भावना गुजरात की विकास यात्रा की आधारशिला है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमें बड़े सपने देखने और उन्हें संकल्प, सुशासन तथा निरंतर परिश्रम से साकार करने की प्रेरणा दी है। गुजरात की धरती पर विकसित यह मॉडल आज 'विकसित भारत–2047' के संकल्प से जुड़कर एक व्यापक राष्ट्रीय विकास दृष्टि का आधार बन रहा है।

मेरा विश्वास है कि गुजरात आने वाले वर्षों में भारत की विकास यात्रा का एक प्रमुख ग्रोथ इंजन बनेगा और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के इस महान संकल्प में अपनी भूमिका पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाएगा।

○○○

12 वर्ष की अवधि को हमारी परंपरा में सहज ही उसे एक तप कहा जाता है। तप शब्द अपने आप में संघर्ष, तपकर निखरने की प्रक्रिया, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास और अटूट संकल्प का प्रतीक है। इसलिए जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का एक तप पूर्ण हुआ है, तब इस कालखंड का मूल्यांकन इन्हीं तीन कसौटियों पर किया जाना चाहिए। यदि इस दृष्टि से देखा जाए, तो यह कालखंड सेवा, समर्पण और सुशासन का स्वर्णिम युग सिद्ध होता है।

तपस्या के दो पक्ष होते हैं। तपस्या का फल पूरे समाज और उसके विभिन्न वर्गों तक पहुँचता है। प्राचीन काल में भी हमने ऋषि–मुनियों की तपस्या के माध्यम से यही देखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस तपस्या का फल भारत के सामान्य नागरिक के जीवन में आए अभूतपूर्व परिवर्तन और व्यापक जनकल्याण के रूप में दिखाई देता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की वर्ष 2014 से 2026 तक की 12 वर्षों की यात्रा एक ऐसे परिवर्तनकारी युग की साक्षी रही है। यह केवल सत्ता के 12 वर्ष नहीं हैं, बल्कि विश्वास, विकास, सुशासन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और जनकल्याण का अभूतपूर्व संगम हैं।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव

श्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। यह केवल समय का संयोग नहीं, बल्कि देशवासियों द्वारा उन पर व्यक्त किए गए अटूट विश्वास का प्रमाण है।

देशवासियों को अपने मताधिकार का महत्व समझ में आ चुका था। वे अपनी आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के प्रति पूरी तरह सजग थे। उन्हें यह भी स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि सरकार का उद्देश्य जनकल्याण होना चाहिए। ऐसे समय में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। इसलिए वर्ष 2014 में जनता ने उन्हें प्रचंड जनादेश देकर यह अपेक्षा व्यक्त

Heartiest
CONGRATULATIONS
& BEST WISHES
To our Beloved
Shri Narendra Modi Ji
Prime Minister of India
for his historic tenure, visionary leadership, and unwavering commitment to building a
VIKSIT BHARAT
Empowering the nation through progress, development, and visible transformation at every level.
VIKSIT BHARAT
NITIKA
Pioneering Nitrosamine - Safe Excipients
NATIONAL AWARD FOR OUTSTANDING ENTREPRENEURSHIP
presented by
the Honorable Prime Minister of India
By Narendra Modi Ji
OUR PROUD ACHIEVEMENTS
STATE MSME AWARD
Excellence in Export Category
2026
NATIONAL PHARMA AWARD
Excellence in Quality
2025
NATIONAL PHARMA AWARD
Make in India Initiatives
2024
TABCELL® LN
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE LN
NOVALUBE® LN
SODIUM STEARYL FUMARATE LN
TABLUBE® LN
MAGNESIUM STEARATE LN
Contact : +91-7122554812
Email : enquiry@nitikapharma.com
Website : www.nitikapharma.com

की; कि वे वह कर दिखाएँ, जो कांग्रेस सरकारें नहीं कर सकीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जनादेश को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए "सबका साथ, सबका विकास" के मंत्र के साथ अपनी विकास यात्रा को आरंभ किया। समय के साथ इसमें "सबका विश्वास" और "सबका प्रयास" भी जुड़ते गए, जिसने इस संकल्प को और अधिक व्यापक तथा समावेशी बनाया।

वर्ष 2014 में देश ने श्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। वर्ष 2019 में यह विश्वास और अधिक मजबूत हुआ तथा 2024 में लगातार तीसरी बार देश की जनता ने उन्हें राष्ट्रसेवा का अवसर प्रदान किया। विश्व के अनेक लोकतांत्रिक देशों में वर्ष 2024 सत्ता–विरोधी लहर का वर्ष सिद्ध हुआ।

अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और पोलैंड जैसे देशों में सत्तारूढ़ दलों को जनता के असंतोष का सामना करना पड़ा और कई स्थानों पर सत्ता परिवर्तन भी हुआ। किंतु इस वैश्विक प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत भारत ने एक अलग दिशा प्रस्तुत की। भारतीय जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल प्रदान किया। वर्ष 2014 और 2019 में मिले स्पष्ट जनादेश के बाद वर्ष 2024 की विजय केवल एक चुनावी सफलता नहीं थी, बल्कि यह विकास, सुशासन और स्थिर नेतृत्व के प्रति जनता द्वारा व्यक्त किया गया पुनः विश्वास था।

वर्ष 1962 के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वाले श्री नरेंद्र मोदी देश के पहले नेता बने। जब विश्व की अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही थीं, तब भारत ने स्थिरता, निरंतरता और निर्णायक नेतृत्व के मार्ग को चुना। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने राजनीतिक स्थिरता से विकास को नई गति प्रदान की। आर्थिक सुधारों, सामाजिक परिवर्तन, आधारभूत संरचना के व्यापक विस्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और प्रभावी विदेश नीति के माध्यम से भारत आज वैश्विक स्तर पर एक अधिक सक्षम, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है।

यह केवल एक नेतृत्व की यात्रा नहीं थी, बल्कि इस परिवर्तन में भारत की जनता समान रूप से सहभागी रही। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है। यदि इसके परिणामों की बात करें, तो भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गई है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी स्थान रखता है।

यदि सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है, तो सबसे पहले देश की आर्थिक नींव मजबूत और समृद्ध होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्य को केवल समझा ही नहीं, बल्कि इसे साकार करने के लिए हर स्तर पर निरंतर प्रयास भी किए। "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसे अभियानों ने न केवल भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, बल्कि भारतीय उत्पादों और भारत की निर्माण क्षमता के प्रति विश्व का विश्वास भी बढ़ाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में अधिक दृढ़ और निर्णायक नीति अपनाई। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध भारत ने कड़े और प्रत्यक्ष जवाब दिए। "ऑपरेशन सिंदूर" जैसी कार्रवाई ने विश्व को यह स्पष्ट संदेश दिया कि "नया भारत निर्णय भी लेता है और उसे दृढ़ता के साथ लागू भी करता है।" आज स्वदेशी रक्षा उपकरणों और हथियारों की मांग इतनी बढ़ चुकी है कि

आने वाले वर्षों का उत्पादन भी अग्रिम आदेशों से भरा हुआ है। यही आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती सामर्थ्य और भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता का प्रमाण है। देश के 12 राज्यों में नक्सलवाद के प्रभाव को उल्लेखनीय रूप से कम करना मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है। कई दशकों तक विकास से वंचित रहे क्षेत्रों तक अब विकास की धारा पहुँच रही है। लंबे समय तक देश के करोड़ों लोग भय और गरीबी के माहौल में जीवन जीने को मजबूर थे। नक्सलवाद के कारण इन क्षेत्रों में विकास कार्य बाधित रहे और हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ। आज यह स्थिति तेजी से बदल रही है।

गढ़चिरौली जैसे क्षेत्रों में अब इस्पात उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और अन्य बड़े शैक्षणिक संस्थान शुरू हो रहे हैं। यह परिवर्तन इस बात का प्रतीक है कि हिंसा और बंदूक की संस्कृति पर विकास और अवसरों की संस्कृति ने विजय प्राप्त की है। आने वाले दशक में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को दुनिया की सबसे आधुनिक, वैज्ञानिक और तेज़ न्याय व्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तकनीक–आधारित न्याय, त्वरित प्रक्रिया और पारदर्शी व्यवस्था–यही नए भारत का संकल्प है।

पिछले 12 वर्षों में भारत ने आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास में अभूतपूर्व प्रगति की है। राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क लगभग 91 हजार किलोमीटर से बढ़कर लगभग 1. 46 लाख किलोमीटर तक पहुँच गया है। प्रतिदिन औसतन 34 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, जिससे किसानों, विद्यार्थियों और ग्रामीण नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आया है।

रेलवे क्षेत्र में लगभग संपूर्ण ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत स्टेशन योजना तथा आधुनिक रेलवे स्टेशनों ने भारतीय रेल की नई पहचान स्थापित की है। देश का मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर से बढ़कर 1,095 किलोमीटर से अधिक हो गया है। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है और देश में 90 से अधिक नए हवाई अड्डों का विकास किया गया है। उड़ान (UDAN) योजना के माध्यम से आम नागरिक के लिए भी हवाई यात्रा अधिक सुलभ और किफायती बनी है।

मोदी सरकार ने देश के अन्नदाता किसानों को विकास के केंद्र में रखा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की गई। तीसरे कार्यकाल में सरकार द्वारा हस्ताक्षरित पहली फाइल भी किसान कल्याण से संबंधित थी, जिसने सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" अभियान से लाखों हेक्टेयर भूमि सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में आई। कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और भारत आज विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है।

PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJANA

मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत ने डिजिटल क्रांति का नया इतिहास रचा। जनधन, आधार और मोबाइल (JAM Trinity) के माध्यम से लाखों करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए। यूपीआई (UPI) लेनदेन के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक नेतृत्व स्थापित किया है। भारतनेट परियोजना के अंतर्गत लाखों ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है। डिजिटल गवर्नेंस, फेसलेस टैक्स प्रणाली और GeM पोर्टल ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी और दक्ष बनाया है।

एक समय ऐसा था जब विश्व भारत को SWIFT प्रणाली से बाहर करने की बात करता था। तब भारत ने आत्मविश्वास के साथ कहा– "हम अपनी स्वयं की व्यवस्था विकसित करेंगे।" आज विश्व भारत की UPI प्रणाली की सराहना कर रहा है। सिंगापुर, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने भारतीय यूपीआई को अपनाया है। यह भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और डिजिटल नेतृत्व का प्रतीक है। आज भारतीय रुपया भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। 20 से अधिक देशों ने रुपया–आधारित वोस्ट्रो (Vostro) खाते खोले हैं। भारत अब विश्व के साथ समानता, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के आधार पर संवाद कर रहा है। भारत को व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी चाहिए, किंतु अपनी राष्ट्रीय गरिमा के साथ। रूस–यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और वैश्विक दबावों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 81 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के घर मिले। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 11 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त हुई। जल जीवन मिशन के माध्यम से 16 करोड़ से अधिक घरों तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुँचाया गया।

मोदी सरकार की नीतियों में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया। जनधन खातों में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही है। "लखपति दीदी" अभियान के माध्यम से लाखों महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त बनी हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, मातृत्व लाभ, स्वयं सहायता समूहों का सशक्तीकरण तथा सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने महिला–नेतृत्व वाले विकास की अवधारणा को व्यावहारिक रूप दिया है।

आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और पीएलआई (PLI) योजनाओं ने विनिर्माण क्षेत्र को नई गति प्रदान की है। भारत

विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए बड़े निवेश आकर्षित हुए हैं और भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप संस्कृति को मिले प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप देश में दो लाख से अधिक स्टार्टअप और सैकड़ों यूनिकॉर्न स्थापित हुए हैं।

मोदी सरकार के 12 वर्षों में भारत ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और विरासत का गर्व के साथ पुनर्स्मरण किया है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और केदारनाथ पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं ने देश की आध्यात्मिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान की है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थ, बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस का सम्मान, कर्तव्य पथ तथा नया संसद भवन राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक बनकर उभरे हैं।

आज भारत विश्वभर में अपनी संस्कृति का गौरवपूर्वक परिचय दे रहा है। विदेशों में भी भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के प्रति सम्मान बढ़ा है। अबू धाबी का भव्य हिंदू मंदिर नए भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। बहरीन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में मंदिर निर्माण को स्वीकृति मिल रही है। कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आज विश्व यह समझने लगा है कि भारत केवल एक अर्थव्यवस्था नहीं है; भारत एक संस्कृति है, भारत एक जीवन–दृष्टि है।

जी–20 की सफल अध्यक्षता, वैक्सीन मैत्री पहल, मुक्त व्यापार समझौते, बढ़ता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तथा वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा मोदी सरकार की विदेश नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। आज विश्व भारत को केवल एक विशाल बाज़ार के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत करने वाले, विश्वसनीय और उत्तरदायी राष्ट्र के रूप में देखता है।

आज का भारत आत्मविश्वास के साथ विश्व के सामने खड़ा है। विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में ये 12 वर्ष एक मजबूत आधारशिला सिद्ध हुए हैं। विश्वास, विकास और जनभागीदारी की यह यात्रा आने वाले समय में और अधिक गति के साथ आगे बढ़ेगी – यही देशवासियों का दृढ़ विश्वास है।

○○○

नमो नेतृत्व में विश्वास, विकास और जनकल्याण के 12 वर्ष

सशक्त होता भारत, बदलता राजस्थान

प्रगति-पथ
भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में परिवर्तन, आत्मविश्वास और विकास के एक नए युग के रूप में दर्ज हुए हैं। मई 2014 से प्रारंभ हुई यह यात्रा केवल सरकार के कार्यकाल की कहानी नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास, आकांक्षाओं और सामूहिक संकल्प की यात्रा है। इन वर्षों में भारत ने गरीब कल्याण से लेकर वैश्विक नेतृत्व तक, डिजिटल क्रांति से लेकर आधारभूत संरचना के विस्तार तक और आत्मनिर्भरता से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शासन को सेवा और जनभागीदारी का माध्यम बनाया। "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मंत्र के साथ विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से करोड़ों परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

इन राष्ट्रीय उपलब्धियों के साथ राजस्थान भी विकास की नई गाथा लिख रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व और

केंद्र–राज्य के बेहतर समन्वय से राजस्थान आज ऊर्जा, निवेश, उद्योग, जल प्रबंधन और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।

इस दौरान राजस्थान को मिली सबसे बड़ी विकास सौगातों में पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना प्रमुख है। लगभग 79 हजार करोड़ रुपये से अधिक की यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देगी। 9 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाली यह रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल उद्योगों के विस्तार, निवेश वृद्धि और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का आधार बनेगी। यह परियोजना राजस्थान को ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्र में नई मजबूती प्रदान करेगी।

समर्थ महिला समृद्ध राजस्थान

- लाडो प्रोत्साहन योजना योजनान्तर्गत **1.50 लाख** तक की सहायता, **8.84 लाख** बालिकाएं लाभान्वित
- गर्भवती महिलाओं को **6,500** तथा **दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,000 की सहायता।**
- **15 लाख** आंगनबाड़ी बच्चों को सप्ताह में **5 दिन गर्म दूध**
- **45,985 छात्राओं** को स्कूटी **13.85 लाख** बालिकाओं को साइकिल
- **24.92 लाख** परिवार कृषि एवं पशुपालन तथा **6.42 लाख** परिवार एग्री न्यूट्री गार्डन गतिविधियों से लाभान्वित
- **18.21 लाख** महिलाएं बनीं लखपति दीदी
- **61,078 महिलाओं को ₹443 करोड़ का ऋण;** ऋण सीमा बढ़कर **₹1.50 लाख।**
- **1.55 लाख** स्वयं सहायता समूहों को **₹739 करोड़ का ऋण**
- **3,432 महिला उद्यमियों** को **₹343 करोड़** के ऋण स्वीकृत
- **65 एंटी रोमियो स्क्वॉड** एवं **600 कालिका** पेट्रोलिंग यूनिट सक्रिय
- महिला सुरक्षा को और सशक्त बनाने हेतु **2,216 पद स्वीकृत**
- सार्वजनिक एवं शैक्षणिक संस्थानों में **14,122 सीसीटीवी कैमरों** की स्थापना
- **25,000** महिलाएं बनीं सोलर दीदी
- नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत **₹2,500 प्रति हेक्टेयर सहायता**
- **₹450** में रसोई गैस सिलेंडर, **5.87 करोड़** रिफिल पर **₹1,128 करोड़** की सब्सिडी
- **33,321** परिवारों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ
- **24.92 लाख** परिवार कृषि एवं पशुपालन तथा **6.42 लाख** परिवार एग्री न्यूट्री गार्डन गतिविधियों से लाभान्वित।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

राजस्थान की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रामजल सेतु लिंक परियोजना एक ऐतिहासिक पहल है। चंबल नदी पर बन रहा यह प्रोजेक्ट प्रदेश के 17 जिलों के लगभग 3.25 करोड़ लोगों को पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक होगा। लगभग 2,330 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा रामजल सेतु प्रदेश की जल सुरक्षा और किसानों की समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा।

इसी प्रकार यमुना जल समझौते ने शेखावाटी क्षेत्र के लिए नई उम्मीद जगाई है। सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों के लगभग तीन लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। क्षेत्र के जल संकट के समाधान की दिशा में यह पहल कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।

आधुनिक राजस्थान की तस्वीर में जयपुर मेट्रो फेज–2 परियोजना भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लगभग 13 हजार करोड़ रुपये की यह परियोजना राजधानी जयपुर की परिवहन व्यवस्था को नई गति देगी। 41 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर और 36 स्टेशनों वाली यह मेट्रो परियोजना पर्यावरण अनुकूल, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहरी विकास का प्रतीक बनेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान यात्राओं ने प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान की है। इन यात्राओं के दौरान ऊर्जा, सड़क, जल, उद्योग और परिवहन से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिली। माही–बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित अनेक योजनाएं राजस्थान की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक क्षमता को मजबूत कर रही हैं।

ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। भड़ला सोलर पार्क विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्कों में शामिल है। राजस्थान की विशाल सौर क्षमता आज प्रदेश को अक्षय ऊर्जा के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है। स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार से निवेश, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिल रही है।

नई तकनीक और भविष्य के उद्योगों के क्षेत्र में भी राजस्थान आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने से युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर तैयार होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप राजस्थान आधुनिक उद्योगों का केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

RISING RAJASTHAN

REPLETE • RESPONSIBLE • READY

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में मिले 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव यह दर्शाते हैं कि देश और दुनिया के निवेशकों का विश्वास राजस्थान में बढ़ा है। बेहतर आधारभूत संरचना, नीति आधारित शासन और मजबूत कनेक्टिविटी ने प्रदेश को निवेश के आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया है।

सड़क, रेल और हवाई संपर्क के क्षेत्र में भी राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतमाला परियोजना, दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस–वे, रेलवे विद्युतीकरण, वंदे भारत ट्रेनों और अमृत भारत स्टेशन योजना ने प्रदेश को आधुनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ा है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष भारत के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास के वर्ष रहे हैं। यह यात्रा केवल योजनाओं और परियोजनाओं की नहीं, बल्कि जनविश्वास, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की यात्रा है। आज राजस्थान विकसित भारत / 2047 के संकल्प में एक मजबूत आधार स्तंभ के रूप में उभर रहा है। विश्वास के 12 वर्ष, विकास के 12 वर्ष और जनकल्याण के 12 वर्ष – यही नए भारत की पहचान है।

○○○

विकसित भारत – विकसित हरियाणा
श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री
के कर-कमलों द्वारा
लगभग ₹15,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया गया
लोकार्पण एवं शिलान्यास
जींद और सोनीपत के बीच चली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन
जींद-गोहाना राष्ट्रीय राजमार्ग
कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक (लागत - लगभग ₹400 करोड़)
पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सिख संग्रहालय, कुरुक्षेत्र
हांसी-बरवाला राष्ट्रीय राजमार्ग

World Class Education

Right Here In Goa!

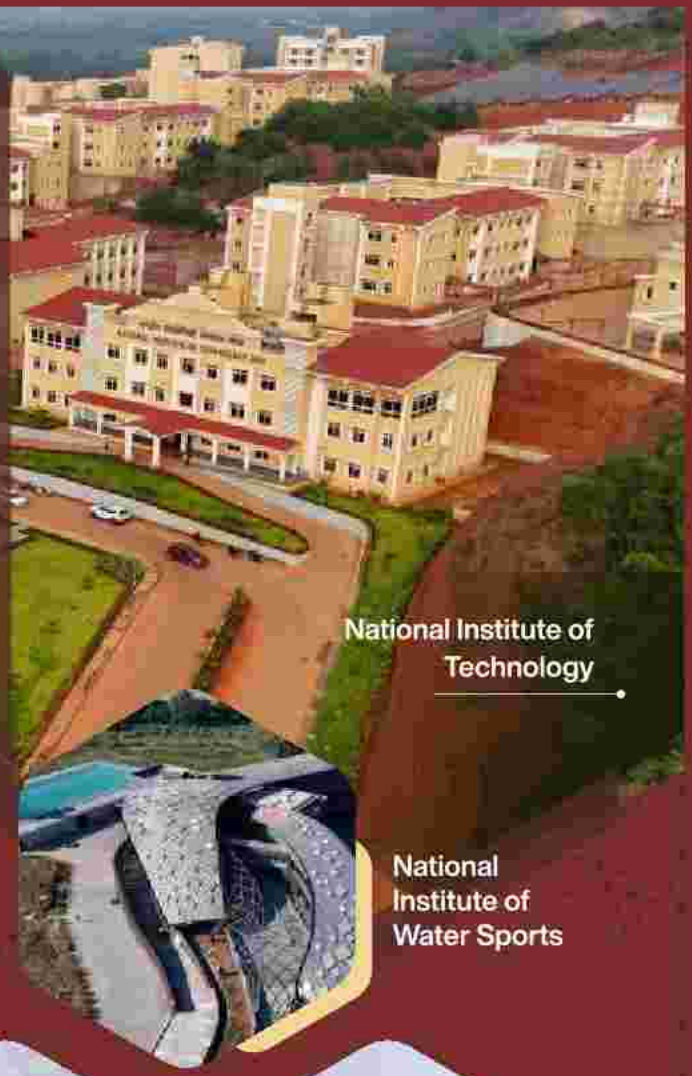

National Institute of Technology

National Institute of Water Sports

Diverse Educational Opportunities and Vast Array of Premium Faculties

India International University of Legal Education and Research

Indian Institute of Technology

National Forensic Sciences University

Issued by Department of Information and Publicity Government of Goa

VIKSIT BHARAT VIKSIT GOA 2047

Emerging New Goa for Viksit Bharat @ 2047 *under* Narendra Modiji's Leadership

New Horizons

Dr. Pramod Sawant
Chief Minister, Goa

India is standing at a historic crossroads, experiencing an unprecedented socio-economic resurgence that has redefined its global standing. This monumental transformation is the direct result of the able, tireless, and visionary leadership of our Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. As we mark the completion of 12 glorious years of his tenure at the helm of the nation, we celebrate a decade of governance rooted in reform, perform, and transform. Prime Minister Modi ji has infused the nation with a collective resolve, channeling the aspirations of 1.4 billion citizens toward a singular, definitive goal: building a self-reliant, prosperous, and developed nation a Viksit Bharat by 2047.

A Glorious Decade of Visionary Leadership:

A core pillar of this massive national growth story is the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector-our beloved *Laghu Udyog*. The Prime Minister has consistently championed these enterprises as the silent engines of India's GDP, innovators of indigenous technology, and the largest providers of employment

after agriculture. Guided by the ethos of *Atmanirbhar Bharat*, the grassroots industries of India have transitioned from survival mode to global competitors. Organizations like Laghu Udyog Bharati have done exemplary work over the last 32 years, acting as a bridge between policymakers and micro-enterprises to facilitate rapid issue resolution, skill development, and industrial formalization.

In the beautiful state of Goa, our administration is deeply committed to translating the Prime Minister's national vision into local reality. By aligning our state policies with central schemes, we are ensuring that the spirit of entrepreneurship thrives in every village and town of Goa, laying a robust foundation for an economic powerhouse.

The Landscape of Laghu Udyog in Goa

Goa's economic identity is undergoing a profound evolution. While traditionally celebrated as a global tourism paradise, Goa is rapidly emerging as a preferred destination for clean manufacturing, technology, sustainable food processing, and vibrant retail services. The foundation of this new identity is our thriving MSME sector.

Goa boasts an impressive **91,034 MSMEs registered on the Udyam Portal**. A closer look at this data reveals the true character of our grassroots economy:

This heavy concentration of micro-scaled operations highlights exactly why targeted state intervention is so vital. Furthermore, our MSME ecosystem is heavily service-oriented, with **82.8%** of enterprises engaged in services and retail trade, while **17.2%** operate within the manufacturing sector. Our strategic goal in Goa is clear: we want to handhold these micro-units, provide them with the financial and structural pathways to scale up into small and medium enterprises, and systematically expand our manufacturing footprint to encourage production-led economic growth.

Synergy of Central & State Schemes: Empowering Entrepreneurs

To drive this growth, the Government of Goa has facilitated the aggressive implementation of both Central Sector schemes and specialized State Umbrella initiatives, ensuring that financial aid, seed capital, and structural mentorship reach the absolute grassroots.

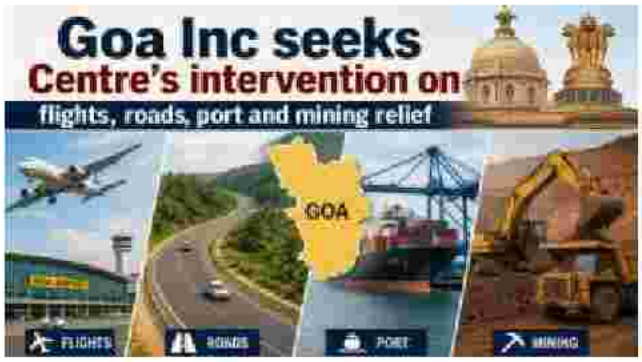

Central Sector Interventions and Achievements

- **The RAMP Program:** The *"Raising and Accelerating MSME Performance"* (RAMP) initiative, a World Bank-supported Central Sector Scheme launched by the Government of India, has become a game-changer for Goa. Out of a total sanctioned budget of **INR 61.57 Crores**, our state has already utilized **INR 28.41 Crores** (representing a 46% utilization rate). Through RAMP, more than **20,000 existing and aspiring entrepreneurs**, including members of Self-Help Groups (SHGs), have received tangible benefits.

Under this program, we are executing seven key interventions. Most notably, the state is launching the **Unified Digital Platform (UDP)**, which will act as an end-to-end digital solution offering single-window deregulation, application compliance modules, and an online dispute resolution framework. Additionally, we have established Business Facilitation Centres (BFCs) and Women Entrepreneurship Facilitation Centres (WEFCs) to provide hands-on, ground-level support. These experts visit panchayats and industrial estates to assist with Udyam registrations, ONDC onboarding, and PMEGP loans. To date, over **10,000 candidates have undergone skill development training**, and more than **50 MSMEs have been selected for dedicated corporate mentorship** under the CHAMPION MSME initiative.

- **Prime Minister's Employment Generation Program (PMEGP):** Over the last five years, this flagship central scheme has approved **114 new industrial and service projects** across Goa, releasing a total marginal money subsidy of **Rs. 504.72 Lakhs** to clear financial roadblocks for budding entrepreneurs.

- **Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME):** Food processing holds immense potential for Goa's agrarian and coastal economy. Over the past five years, the PMFME scheme has seen **154 applications approved** for credit-linked subsidies, generating an overall investment of more than **Rs. 20 Crores**. Out of the sanctioned subsidy of Rs 6.07 Crores, Rs 4.39 Crores has already been disbursed to 125 active beneficiaries, alongside a seed capital disbursement of **Rs 6.54 Crores to 1,734 SHG members**, formalizing local culinary and agro-products.

State-Government Driven Support Frameworks

Complementing these central schemes, the Goa state government has designed targeted financial and regulatory cushions to look after our local units:

- **State Umbrella Scheme:** Operating between FY 2019 and FY 2026, this customized state fund received 147 applications, successfully disposing of 123 of them (an 84% achievement rate). Out of a sanctioned budget of Rs 5.31 Crores, **Rs 4.56 Crores** has been successfully disbursed to local businesses.
- **Goa Micro & Small Enterprises Facilitation Council (Goa MSEFC):** Liquid capital is the lifeblood of a small business. To protect our micro-units from the crippling effects of delayed payments, the Goa MSEFC has been working proactively. Between FY 2022-23 and FY 2025-26, the council processed a massive caseload of 1,374 disputes, successfully resolving and disposing of 471 complex cases.
- **Employment Subsidy Scheme for Cashew Industry (ESSCI):** The cashew industry is deeply tied to Goa's heritage and rural economy. To modernize processing units and safeguard employment, our government approved 24 specialized applications over the last five years, distributing a dedicated subsidy of **Rs 139.35 Lakhs**.
- **Goa Tribal's Employment Generation Program Scheme:** Focused on inclusive growth, this state initiative has approved **219 applications** over the last five years, disbursing **Rs. 500 Lakhs** to empower tribal youth and entrepreneurs to establish self-sustaining business ventures.

Global Ambitions: Connecting Goa's Laghu Udyog to the World

Our micro-industries are not just limited to domestic borders. Empowered by the state's logistical enhancements including the world-class Manohar International Airport at Mopa and expanding maritime trade routes Goa's MSMEs are going global.

A shining testament to this is our performance at the **Amazing Goa Global Expo & Summit-2024**, orchestrated via the RAMP program. The event successfully hosted a Reverse Buyer-Seller Meet (RBSM) that brought together **over 100 international buyers from 30+ countries** to meet face-to-face with more than 100 Goan MSME exporters spanning 5 major industrial sectors. During the summit alone, five of our local MSME exporters successfully closed

international purchase orders worth an immediate **INR 3.00 Crores**, with an additional 15 micro-units currently entering advanced procurement discussions.

Furthermore, we are ensuring our businesses look toward the future by embedding sustainable practices early on. GIDC has been successfully onboarded to develop a localized **Green Index and Green Credit Model**, incentivizing eco-friendly manufacturing methods among our small-scale industrial plots.

Marching Boldly Toward Viksit Bharat-2047

As we reflect on the remarkable milestone of **12 years of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji's governance**, the state of Goa stands tall as a testament to what cooperative federalism can achieve. Through bold deregulation, unwavering financial handholding, and an absolute trust in our industrial workforce, we have turned Goa into a bustling hub of economic self-reliance.

The contribution of our *Laghu Udyog*-the micro-entrepreneur running a local cashew processing unit, the self-help groups formalizing traditional Goan food products, the small-scale tech and manufacturing innovators-forms the bedrock of this success. They are not just businesses; they are the socio-economic pillars of our society.

On behalf of the Government of Goa, I extend my heartfelt gratitude to the Prime Minister for his transformative leadership. We pledge to continue working with the same vigor, unity, and dedication. By nurturing our small-scale industries and continuously simplifying the business ecosystem, we will ensure that an **Emerging New Goa** stands at the absolute vanguard of India's journey toward becoming a fully developed, self-reliant **Viksit Bharat by 2047**.

○○○

SHAPING GOA INTO INDIA'S CREATIVE CAPITAL

ड्रोन दीदी योजना

नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत

* महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण एवं मुफ्त ड्रोन की सुविधा
* पात्रता एवं नियमानुसार सब्सिडी का भी प्रावधान

नॉन-स्टॉप हरियाणा

अब राज्य सरकार द्वारा ड्रोन दीदी योजना के तहत 5000 महिलाओं को ड्रोन एवं सहायक उपकरण की लागत का 80% अनुदान या अधिकतम ₹8 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी

सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा

- नरेन्द्र मोदी
स्वस्थ हरियाणा
समृद्ध हरियाणा
अभियान
हरियाणा सरकार द्वारा
स्वास्थ्य के क्षेत्र में ₹114 करोड़ की
7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं
का शुभारंभ
परियोजनाएं
1
2
3
4
5
6
7
स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा
सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा

उभरता हुआ हरियाणा: अंत्योदय से आत्मनिर्भरता तक

अभ्युदय

नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री, हरियाणा

भारत के हृदय में बसा हमारा हरियाणा आज केवल लहलहाते खेतों और पदकों से सजे खेल के मैदानों तक ही सीमित नहीं है; बल्कि यह 21वीं सदी के 'नए भारत' के विकास का एक धड़कता हुआ पॉवरहाउस बन चुका है। विकसित हरियाणा महज़ एक नारा नहीं, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न और उनके नेतृत्व में हमारी 'डबल इंजन सरकार' की उस अंत्योदय साधना का जीवंत प्रमाण है, जिसने समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ दिया है।

यदि किसी सरकार का मूल्यांकन करना है तो उसके नारों से नहीं, बल्कि उसके पूरे किए गए वादों और फैसलों से किया जाना चाहिए। 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव के घोषणा–पत्र में हमने कुल 217 वादे हरियाणा की जनता से किये थे, जिसमें से 70 वादों को हमने डेढ़ साल के कार्यकाल में ही पूरा कर दिखाया है जो एक रिकॉर्ड है।

आज मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र माटी ने कभी दुनिया को गीता का कर्मयोग सिखाया था, वही हरियाणा आज ई–गवर्नेंस,

औद्योगीकरण और जनकल्याण के अपने अभिनव मॉडल से पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहा है। हमने सत्ता को सचिवालय के गलियारों से निकालकर एक 'क्लिक' के माध्यम से सीधे आम जन के मोबाइल और द्वार तक पहुंचा दिया है। विकास की यह यात्रा उसी अटूट विश्वास, व्यवस्था परिवर्तन और उस स्वर्णिम भविष्य की रूपरेखा है, जिसे हम 2.8 करोड़ परिश्रमी हरियाणवियों के साथ मिलकर गढ़ रहे हैं।

लघु उद्योग: 'आत्मनिर्भर भारत' की धुरी और लोकल टू ग्लोबल की उड़ान

बड़े उद्योगों के साथ–साथ हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSMEs) हरियाणा की

अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ और रोज़गार सृजन के सबसे बड़े केंद्र हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, हमारी डबल इंजन की सरकार ने छोटे उद्यमियों, कारीगरों और शिल्पकारों के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं। केंद्र सरकार की 'मुद्रा योजना', 'पीएम विश्वकर्मा योजना' और कोलेटरल फ्री लोन जैसी ऐतिहासिक पहलों ने हमारे छोटे व्यवसायियों को एक नया हौसला और आर्थिक सुरक्षा दी है। 'वन डिस्ट्रिक्ट – वन प्रोडक्ट' योजना ने हर जिले के पारंपरिक उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। वहीं 'वन स्टेशन – वन प्रोडक्ट' के माध्यम से स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुँचाने का जो अभूतपूर्व अवसर मिला है, वह उद्यमियों को सशक्त कर रहा है।

इसी दिशा में कदम से कदम मिलाते हुए, हरियाणा में हमने 'पद्मा' (PADMA - Program to Accelerate Development for MSME Advancement) जैसी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत हरियाणा के हर ब्लॉक में एक औद्योगिक क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लघु उद्योगों का जाल बिछ सके। हमारी 'हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति' के तहत छोटे उद्योगों को सस्ती बिजली, भूमि खरीद पर सब्सिडी और 'सिंगल विंडो सिस्टम' के ज़रिए मात्र कुछ ही दिनों में सभी मंजूरियां देकर हमने दशकों पुराने 'इंस्पेक्टर राज' को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसी का परिणाम है कि आज हरियाणा का छोटा उद्यमी केवल अपने ज़िले के बाज़ार तक सीमित नहीं है, बल्कि 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र को आत्मसात करते हुए 'लोकल टू ग्लोबल' की उड़ान भर रहा है और दुनिया भर में अपने उत्पादों का निर्यात कर रहा है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने 'सिंगल रूफ क्लीयरेंस सिस्टम' को प्रभावी ढंग से लागू किया है। साथ ही, उद्यमियों को एक ही छत के नीचे स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए 'E-biz Portal' और प्रदेश में पहली बार व्यापारियों के लिए ई–रिफंड की ऑनलाईन सुविधा शुरू की गई है। हमारी सरकार ने गुरुग्राम के साथ–साथ पंचकूला, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक जैसे शहरों को भी औद्योगिक काउंटर–मैग्नेट के रूप में विकसित किया है। हम केवल बड़े उद्योगों पर निर्भर नहीं हैं; हरियाणा के युवा आज अपने स्टार्टअप्स के माध्यम से नई तकनीक और एआई (AI) के क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी धाक जमा रहे हैं।

डबल इंजन की ताकत: इंफ्रास्ट्रक्चर का नया क्षितिज

विकास के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पहली शर्त है, और डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में इसके नए मापदंड स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से आज हरियाणा के कोने–कोने में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस–वे का जाल बिछ चुका है। केएमपी और केजीपी एक्सप्रेस–वे ने न केवल दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाई है, बल्कि हरियाणा के कई जिलों को लॉजिस्टिक हब में बदल दिया है। दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस–वे का एक बड़ा हिस्सा हरियाणा से होकर गुज़र रहा है, जो विकास के नए द्वार खोल रहा है। आज हरियाणा का कोई भी ज़िला राष्ट्रीय राजमार्गों से अछूता नहीं है। यह कनेक्टिविटी केवल ईंट–पत्थर का निर्माण नहीं है; यह किसानों के खेतों को सीधे बाज़ार से और युवाओं को सीधे रोज़गार से जोड़ने का मजबूत सेतु है। हिसार में महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केवल एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि एक पूरा 'एविएशन हब' है, जो आने वाले दशकों में उत्तरी भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल देगा। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें, हाइड्रोजन ट्रेन की नूतन पहल और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण प्रदेश की रफ्तार को पंख लगा रहे हैं।

एक क्लिक पर सुशासन: तकनीक से जन–कल्याण

जिस तरह हरियाणा में सभी सुविधाएं आम लोगों तक 'एक क्लिक' पर पहुंची हैं, वह अद्भुत है। हमने 'परिवार पहचान पत्र' जैसी अनूठी पहल शुरू की है, जिसे बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके माध्यम से आज 164 कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।

हमने व्यवस्था से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 'पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली' लागू की है। जमीन की ऑनलाइन खरीद–फरोख्त के लिए 'ई–भूमि' पोर्टल और राशन वितरण में पारदर्शिता के लिए 'ई–पीडीएस' पोर्टल जैसी डिजिटल क्रांतियों ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी को खत्म कर दिया है। पुलिस विभाग में आई.टी. का प्रयोग करते हुए सिटीजन पोर्टल 'हर समय' 24X7 स्थापित किया गया है, जिससे लोग घर से ही एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अध्यापकों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति बनाने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य है।

युवाओं का सशक्तिकरण

युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हमने नौकरियों में एक ऐसा पारदर्शी सिस्टम स्थापित किया है, जिस पर आज हर हरियाणवी को गर्व है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के दिन ही हमने लगभग 26 हजार युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी। अब तक 1.80 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए ग्रुप सी व डी की भर्तियों में साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। 'सक्षम युवा योजना' के तहत युवाओं को हर महीने 100 घंटे काम की गारंटी देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए हमने 'हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024' लागू किया है। सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण, टैबलेट वितरण और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से गरीब का बच्चा भी अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक से जुड़कर पढ़ाई कर रहा है।

जब बात खेलों की आती है, तो हरियाणा का कोई सानी नहीं है। ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो या एशियन गेम्स, भारत के पदकों की तालिका हरियाणा के पसीने के बिना अधूरी है। हमारी खेल नीति देश में सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ पदक विजेताओं को न केवल करोड़ों का नकद इनाम मिलता है, बल्कि क्लास–1 की नौकरियां भी दी जाती हैं। इस बार भी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा ने देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है।

कृषि एवं किसान कल्याणः देश को दिखाई नई राह

हरियाणा का किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम केवल नारे नहीं देते, हमने किसानों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हरियाणा आज देश का इकलौता राज्य है जो अपने किसानों से सर्वाधिक फसलों की खरीद एमएसपी पर कर रहा है। हमने बागवानी फसलों के लिए 'भावान्तर भरपाई योजना' और 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' की शुरुआत कर नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। मेरा पानी मेरी विरासत' योजना के माध्यम से हमने किसानों को धान की जगह कम पानी लेने वाली फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया है और उन्हें प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल बचाने का हमारा यज्ञ है। जब फसल खराब होती है, तो मुआवज़ा सीधे किसान के खाते में बिना किसी देरी के पहुंचता है।

स्वास्थ्य सेवा बना संबल

स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने 'एनीमिया मुक्त भारत अभियान' में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हैपेटाइटिस–सी व बी की मुफ्त

दवाइयां और किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं देने में हम अग्रणी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 'आयुष्मान भारत' योजना का विस्तार करते हुए हमने 'चिरायु हरियाणा' योजना लागू की है, जिससे लाखों और परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। आज हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा संकल्प ज़मीनी हकीकत बन रहा है।

सामाजिक सुरक्षा का कवच

अंत्योदय की भावना को चरितार्थ करते हुए हरियाणा आज 3,200 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। मनरेगा दैनिक मजदूरी 409 रुपये भी देश में सर्वाधिक है। 'दयालु योजना' के तहत 1.80 लाख रुपये तक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। गावों को 'लाल डोरा मुक्त' करके जमीन का मालिकाना हक देने की हमारी ऐतिहासिक पहल काफी सफल रही है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से आर्थिक रूप से आज़ाद कर रही है। आज हरियाणा की बेटियाँ 'लखपति दीदी' और 'ड्रोन दीदी' बनकर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रही हैं।

हमारा प्रयास, आपका विश्वास

आज का 'उभरता हुआ हरियाणा' अपनी पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आसमान छूने को तैयार है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ नीतियां फाइलों में धूल नहीं खातीं, बल्कि धरातल पर उतरकर लोगों का जीवन बदलती हैं। डबल इंजन की सरकार का मतलब ही यह है – विकास की गति दोगुनी, संकल्पों की सिद्धि दोगुनी और जनता का विश्वास दोगुना।

मैं हरियाणा के प्रत्येक नागरिक, हमारे युवाओं, किसानों, माताओं और बहनों को विश्वास दिलाता हूँ कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा हर क्षण, मेरा हर निर्णय आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए समर्पित है। हमारा लक्ष्य केवल विकसित हरियाणा बनाना नहीं है, बल्कि 2047 के 'विकसित भारत' के निर्माण में हरियाणा को सबसे अग्रणी, सबसे समृद्ध और सबसे सुसंस्कृत राज्य बनाना है। आइए, जाति–पाति और क्षेत्रवाद की सीमाओं से ऊपर उठकर, 'हरियाणा एक–हरियाणवी एक' के मूल मंत्र के साथ हम सब मिलकर एक ऐसे हरियाणा का निर्माण करें, जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके।

○○○

LUB's delegation of Punjab visited Raj Bhavan to express heartfelt gratitude to the Governor for his esteemed presence in the meeting of Punjab State and Sthapana Diwas Program at Derabassi on 3nd August. During the meeting, the Governor spoke with the Dy. Commissioner, Mohali regarding the progress of land allotment for the proposed Kaushal Vikas Kendra & LUB's office. Delegation consists of state President Shri Pardeep Mongia, State Jt. GS Shri Anil Sharma and State Jt. Treasurer Shri Suresh Gupta.

राजस्थान आवासन मण्डल

हमारा प्रयास, सबको आवास

जयपुर के प्रताप नगर में विकसित देश के पहले

कोचिंग हब

में ई- ऑक्शन के माध्यम से टावर संख्या-1 में प्रिमियम सम्पत्तियों को खरीदने का सुनहरा अवसर

आवेदन अवधि : 23.9.2026 से 25.9.2026

(रेरा पंजीकरण संख्या RAJ/P/2022/2068)

RERA Website: www.rera.rajasthan.gov.in

RERA

फूड कोर्ट, शोरूम, केन्द्रिय वातानुकूलित लाइब्रेरी, दोपहिया और चार पहिया वाहन पार्किंग, जॉगिंग ट्रेक, बास्केटबॉल कोर्ट

सम्पत्ति का वर्गीकरण	संख्या	सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	न्यूनतम बोली मूल्य (लाखों में)
Type-1A भूतल	02	745-59	574
Tybe-IB प्रथम तल	02	745.59	558
Type-II	08	372.80	264
Type-III	03	260.94	185
Type-IV	02	223-89	159
Type-V	04	225.26	159
Type-VI	02	147.53	105

नोट - उपरोक्त कीमत के अतिरिक्त अन्य विविध व्यय पृथक से देय होंगे।

पात्रता - ई-आक्शन के लिए केवल कोचिंग संस्थाएं ही पात्र होंगी, आवंटित सम्पत्तियों का उपयोग केवल कोचिंग के लिए किया जा सकेगा।

वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी एवं अन्य शर्तों के लिए QR कोड स्कैन करें

हेल्पलाइन नं. कार्यालय समय में :

0141-2744688, 2740009

कार्यालय समय उपरान्त :

9461054291/92/319 एवं 6376868696, 9460254319

कर्तव्य-पथ
रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री, दिल्ली

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष और दिल्ली की विकास यात्रा

दिल्ली की हर सुबह में मुझे बदलते भारत की तस्वीर दिखाई देती है। कहीं एक रेहड़ी वाला यूपीआई से भुगतान स्वीकार कर रहा है, कहीं एक मां धुएं से मुक्त रसोई में भोजन बना रही है, कहीं एक उद्यमी कम कागजी प्रक्रियाओं और डिजिटल व्यवस्थाओं के सहारे अधिक आसानी से अपना कारोबार आगे बढ़ा रहा है, और कहीं एक बुजुर्ग आयुष्मान कार्ड लेकर इस भरोसे के साथ अस्पताल जा रहा है कि बीमारी उसके परिवार को कर्ज में नहीं डुबोएगी। मेरे लिए विकास का अर्थ वह निश्चितता है जो सामान्य नागरिक के चेहरे पर दिखाई देती है।

जब 26 मई, 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब भारत ने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" के मंत्र के साथ आशा और परिवर्तन की ओर बढ़ने का निर्णय लिया था। बारह वर्ष बाद यह विश्वास और भी मजबूत हुआ है। 10 जून, 2026 को मोदी जी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे कर पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। यह उपलब्धि सेवा, सुशासन और जन विश्वास पर टिकी इस यात्रा का प्रमाण है।

इन बारह वर्षों में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। वर्ष 2013–14 से 2022–23 के बीच लगभग 24.8 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए, और डिजिटल भारत ने आर्थिक भागीदारी को जन–जन तक पहुंचाया – मई, 2026 में यूपीआई से 2,320 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए, कुल कीमत लगभग ₹30 लाख करोड़ रुपये।

एक बेटी और मां के रूप में उज्ज्वला योजना का प्रभाव मुझे विशेष रूप से भावुक करता है। जुलाई 2026 तक देशभर में 10.56 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी हो चुके हैं, जिनमें दिल्ली की 2.88 लाख बहनों को मिले नए कनेक्शन भी शामिल हैं – ये उस मां की आंखों से धुआं हटाने का प्रयास था, जिसने वर्षों तक परिवार का पेट भरते हुए अपने स्वास्थ्य की कीमत चुकाई। मोदी जी की योजनाओं की यही विशेषता है – वे समस्या को फाइल में नहीं, परिवार के जीवन में पहचानती हैं।

20 फरवरी, 2025 को जब मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तब पद का गौरव नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी का आभास हुआ। 27 वर्षों बाद दिल्ली की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया – लंबे समय तक राजनीतिक टकराव और अहंकार के कारण केंद्र की कई कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में लागू ही नहीं हो सकीं।

हमने तय किया कि हमारी ऊर्जा आरोप–प्रत्यारोप में नहीं, समाधान में लगेगी, केंद्र और दिल्ली सरकार सहयोगी बनेंगी, और हमारी पहचान विज्ञापनों से नहीं, धरातल पर दिखने वाले परिणामों से बनेगी। इस बदलाव का सबसे मानवीय उदाहरण आयुष्मान भारत है। मई, 2026 तक दिल्ली में 7.72 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके थे और ₹86.22 करोड़ रुपये के उपचार दावों का निपटारा हुआ।

प्रधानमंत्री मोदी जी के जन–केंद्रित शासन का प्रतिबिंब दिल्ली की बदलती कनेक्टिविटी में भी दिखाई देता है। 8 मार्च, 2026 को उन्होंने दिल्ली मेट्रो के 12.3 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क–मौजपुर बाबरपुर पिंक लाइन खंड का उद्घाटन किया, जिससे 71.6 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन देश की पहली पूर्ण परिचालित 'रिंग मेट्रो' बन गई। इसी तरह नमो भारत का 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली–गाज़ियाबाद – मेरठ कॉरिडोर अब यह दूरी एक घंटे से भी कम समय में पूरी करता है।

प्रधानमंत्री जी का मंत्र केवल बड़े निर्माण तक सीमित नहीं है; यह शासन की उन दीवारों को हटाने का भी संकल्प है जो वर्षों से आम उद्यमी की राह रोकती रही हैं। कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर जीएसटी की व्यवस्था लागू की गई और 2025 के सुधारों के माध्यम से कर संरचना तथा अनुपालन को और सरल बनाकर छोटे व्यापारियों को राहत दी गई।

उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ने पंजीकरण इतना सरल बनाया कि जुलाई, 2020 में शुरुआत के बाद से आज लगभग 9 करोड़ एमएसएमई औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं, जिन्हें बैंक ऋण और सरकारी खरीद तक सीधी पहुंच मिल रही है। गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस से अब तक ₹18 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हो चुका है। छोटी–मोटी प्रक्रियागत गलतियों पर व्यापारियों को जेल भेजने वाले पुराने कानून भी बदले गए – 2014 से अब तक 3,700 से अधिक प्रावधान अपराध की श्रेणी से हटाए गए हैं, और पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी–पटरी वालों को बिना गारंटी माइक्रो–लोन देकर अब तक 75 लाख से अधिक रेहड़ी–पटरी विक्रेता को लाभान्वित किया है। दिल्ली में भी पुलिस सत्यापन और प्रमाण–पत्रों की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, और कम–प्रदूषण वाली इकाइयों के लिए मंजूरी की समय–सीमा घटाई गई है, ताकि हमारे लघु उद्यमियों का समय लालफीताशाही में नहीं, कारोबार बढ़ाने में लगे।

विकसित दिल्ली का अर्थ स्वच्छ हवा, निर्मल यमुना और टिकाऊ परिवहन भी है। वर्ष 2026–27 के ग्रीन बजट में 22,236 करोड़ रुपये – कुल बजट का 21.44 प्रतिशत –

हरित उद्देश्यों के लिए निर्धारित हैं, जिसमें यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ₹6,485 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी प्राथमिकता शामिल है। 1 जुलाई से लागू इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सरकार ने ईवी अवसंरचना के विस्तार और रोड टैक्स संबंधी रियायतों पर लगभग ₹8,000 करोड़ रुपये लगाने की योजना बनाई है, जबकि दिल्लीवासियों को कुल लगभग ₹15,000 करोड़ रुपये के लाभ का अनुमान है।

दिल्ली की प्रगति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती, जब तक

उसकी महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित और सक्षम न हों। पात्र महिलाओं को ₹2,500 रुपये मासिक सहायता देने के संकल्प को पूरा करने के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना की रूपरेखा तैयार हो रही है, जिसके लिए बजट में ₹5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसी भावना से अनुसूचित जाति–जनजाति बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लगभग ₹85 करोड़ रुपये की 146 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं – विकसित दिल्ली वही होगी, जहां विकास की रोशनी अंतिम गली तक पहुंचे।

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने हमें सिखाया है कि बड़े

सपने तभी विश्वसनीय बनते हैं, जब उनके साथ स्पष्ट लक्ष्य, समयबद्ध क्रियान्वयन और अंतिम व्यक्ति की चिंता जुड़ी हो। हमारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है – यमुना को निर्मल, दिल्ली की हवा को स्वच्छ, और शासन की हर योजना को हर नागरिक के द्वार तक पहुंचाना अभी शेष है। लेकिन दिशा स्पष्ट है, संकल्प दृढ़ है, और केंद्र तथा दिल्ली के बीच विकास का विश्वासपूर्ण सेतु तैयार है।

मुझे विश्वास है कि 2047 के विकसित भारत की यात्रा में दिल्ली पथ–प्रदर्शक बनेगी, और जिस स्वच्छ, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर राजधानी का सपना हमने देखा है, वह अब दूर नहीं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, दिल्ली को उसका खोया हुआ गौरव लौटाने के इस संकल्प की मैं एक छोटी–सी कड़ी बन सकी हूं।

○○○

Emerging New Odisha for Viksit Bharat @ 2047

Driving Growth under PM Modi's Visionary Leadership

New Hope

Mohan Charan Majhi
Chief Minister
Odisha

All things we achieve in life start with a vision. When a new government was set in Odisha two years back in mid-2024, the only thing on top of our mind was creating jobs for our millions of youths. But we had an inkling that we will definitely succeed. The vision of Hon'ble Prime Minister Narendra Modi Ji would certainly pave our way in realisation of this humongous objective.

We know that his aura has changed India for better, for ever. Under his towering leadership, Indian youth now see their unlimited potential take shape- from making digital innovations to making high-tech innovative products in space and defence sector- they are now the real drivers of Atmanirbhar Bharat.

Odisha stands today at a momentous crossroads in its proud history. As we look ahead to the milestone year of 2036- marking a century of our state's formation- and march resolutely toward the national vision of *Viksit Bharat-2047*, Odisha is undergoing a profound economic and social transformation. Under the

inspiring and visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, our state has transitioned from a land of untapped potential into one of India's most dynamic, progressive, and preferred economic powerhouses.

Driven by the philosophy of *Purvodaya*- the accelerated development of Eastern India-our "Double Engine" government is scripting a new chapter of inclusive, robust, and sustainable industrialization. We are building an ecosystem of limitless possibilities where every farmer, artisan, youth, and woman entrepreneur is an empowered partner in our growth journey.

In 2025, when we hosted Utkarsh Odisha- Make in Odisha in capital city Bhubaneswar, joining this mega event, the Hon'ble Prime Minister made just one point. Calling upon the investors present, he

said, "*Odisha mein nivesh ke liye, yahi samay hai, sahi samay hai.*" That completely changed the mindset of investors toward Odisha. Since then, in just a little over 1.5 years, we already attracted investments over Rs. 20 lakh crore.

While big investors are welcome, our focus is on the downstream industries. Apart from the metal sector, we are diversifying into metal downstream, chemical & petro-chemical downstream, apparels, food processing and we are actively striving to connect our youth in the entire value chain of big industries.

At the core of Odisha's economic resurgence are our Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Recognized globally as the backbone of economic vitality, the MSME sector in Odisha acts as the primary engine of employment generation second only to agriculture. Accounting for roughly 30% of our nation's GDP and a massive share of manufacturing output, small businesses form the individual institutional bedrock of an *Atmanirbhar Bharat*.

With approximately 19 lakh MSMEs operating across our state, our strategy is comprehensive: we are

providing robust infrastructure, financial backing, skill development, technology support, and seamless market linkages. Recent transformative initiatives illustrate this commitment vividly:

We have inaugurated key regional growth hubs, such as the Rice Milling Cluster in Balasore and the famous Pahala Rasgulla Cluster, alongside upcoming engineering, printing, packaging, and cashew clusters.

To give local products a global footprint, we are establishing dedicated MSME parks in every district. Recent milestones include the inauguration of advanced MSME parks in Barapalli in Ganjam and Kesinga in Kalahandi.

Through national and state frameworks like PMEGP, the PM Vishwakarma Yojana, and collateral-free credit guarantees totalling over ₹23,000 crore, our youth and artisans are freed from the burdens of debt bondage, pursuing enterprise securely.

Odisha's total merchandise exports scaled new heights last year, touching ₹95,568 crore alongside the securing of 8 new G.I. tags to protect our unique regional heritage.

GI Tag Products

No society can truly achieve developed status without the active, unhindered leadership of its women. In Odisha, we have firmly shifted our focus from mere financial empowerment to absolute economic leadership. The launch of the Subhadra Yojana has been nothing short of a generational revolution. Empowering over a crore of our mothers and sisters, this pioneering initiative has sparked a wave of grassroots entrepreneurship.

Building upon this profound momentum, we proudly launched the Women Entrepreneurship Platform -

Odisha Chapter in collaboration with Niti Aayog. This unified ecosystem merges Mission Shakti, Startup Odisha, and banking networks under one roof. Our ultimate vision is clear: we want the women of Odisha to not look for jobs, but to create jobs; to not just be consumers, but creators; and to lead our state's historic march into the future.

Odisha's industrial landscape is expanding at an unprecedented pace. Over the past two years alone, our government has approved projects worth roughly ₹10 lakh crore, successfully grounding ₹3.50 lakh crore worth of projects and generating over 2.50 lakh jobs. Our recent high-level investment outreach missions to New Delhi- highlighted by landmark conclaves like Odisha Food Pro-2026 and the Textile and Apparel Conclaves- have cemented our status as Eastern India's premier investment destination.

Food processing is much more than an industrial sector for us. Recent roadshows in New Delhi secured massive investment proposals worth ₹43,437 crore in the food sector alone, ensuring our agricultural and marine bounties are value-added right here at home.

Craftsmanship

Capitalizing on our rich heritage of handlooms-from Western Odisha's traditional weaves to Bomkai, Berhampur silk, and Maniabandha craftsmanship- we are rapidly emerging as a leading hub for technical textiles and apparel. We aim to generate over 5 lakh direct jobs in the textile sector over the coming decade.

From engineering goods and electronics to aluminium downstream units and green energy corridors, global and domestic investors are placing immense trust in our stable policies, world-class port infrastructure, and responsive governance.

As we look toward the next decade, Odisha is poised on the brink of an extraordinary historical epoch. Our clear, unwavering goal is to elevate Odisha's economy to a $500 billion size by the year 2036, coinciding with the centenary of our state's statehood.

This ambitious target will not be achieved by government policy alone; it will be built upon the sweat, skill, and spirit of our 4.5 crore people. Backed by the visionary national framework of *Viksit Bharat-2047* and the dynamic guidance of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, Odisha is ready to step forward as the beating heart of India's economic renaissance.

Let us walk together down this path of progress. Together, we will build a prosperous, self-reliant, and glorious Odisha.

Vande Mataram! Vande Utkal Janani!

With Best Compliments from:-

LAGHU UDYOG BHARATI

PUNJAB

लघु उद्योग भारती

MONGIA
Estd. Since 1981

MONGIA & CO. (Mfg. Div.)

Mfg : Deep Freezers, Water Coolers, Dehumidifiers, Chillers and Commercial Kitchen Equipment

R.O. : Village Saidpura, Barwala Road, Derabassi
M.: 92161 25255, 56, Email: mongia@mongia.co.in

Perfection our attitude

Livia

Valve Guides & Valve Seat Inserts

For Two Wheelers, Three Wheelers, Automotive, Marine Engines & Diesel Engines

An ISO 9001:2015 Certified Co.

Manufacturers & Exporters
PARDEEP ENGG. INDUSTRIES

RVL

RAHUL GUPTA
+91 98764 57799

RVL POLY INDUSTRIES PVT. LTD.
[A FSSC 22000 CERTIFIED COMPANY]

Printed Wrappers for Copier Paper, Paper Based Wrappers, PE Coated Papers & Boards, Liners & Liner Bags, Shrink Films & HDPE/PP Woven Fabric/Bags

H.O. & Works : Saidpura Industrial Park, Block – A, Barwala Road Derabassi, Distt. Mohali, Punjab – 140 507 (INDIA).
Website : www.rvlpoly.com
Email : rvlpoly@yahoo.co.in, rahul.gupta@rvlpoly.com

SANT
VALVES
— SINCE 1953 —

For Guaranteed Trouble-Free Service

'SANT' Group **Product Line**

Valves		DI Screwed Fittings	
Forged Fittings		Water Meters	
DI Grooved Fittings		UL / FM Valves	

SANT VALVES PVT. LTD.
G.T.Road By Pass, Jalandhar 144012 (Pb.)

www.santvalves.com

Phone : 0181 508 4693/94/95
info@santvalves.com

NEW ASPIRATIONS of WEST BENGAL under NaMo's Dynamic Leadership

New Wave

Suvendu Adhikari
Chief Minister
West Bengal

There are moments in the life of a nation when aspiration ceases to be an abstraction and becomes a collective call to action. Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of Viksit Bharat-2047 represents precisely such a moment.

Be it the nearly 9 crore enterprise registrations on the Udyam platforms, with more than 3 crore led by women and together sustaining an estimated 38 crore livelihoods; the disbursal of over 40 lakh crore through 57.79 crore collateral-free loans under the Pradhan Mantri Mudra Yojana since 2015; more than 2 lakh startups securing DPIIT recognition; or the ₹10,000 crore Fund of Funds, support for deep technology and Artificial Intelligence and credit guarantees for enterprise loans up to 20 crore, the transformation underway is unmistakable. These initiatives have democratised entrepreneurship to an extraordinary scale and made it evident that our Prime Minister wants every Indian to imagine not merely a wealthier nation, but a civilisation confident in its capabilities, entrepreneurial in temperament and audacious in ambition.

The question, however, is: what place shall West Bengal occupy in this great national renaissance? The answer is unequivocal. West Bengal must be among its principal architects. For this aspiration is neither fanciful nor unsupported by history.

Enterprise is embedded in the civilisational memory of this soil. Long before "startup" entered the economic vocabulary, West Bengal produced men who dared to build, manufacture, trade and compete. Dwarkanath Tagore ventured into banking, coal, shipping and tea; Acharya Prafulla Chandra Ray began with 2700 and built Bengal Chemical and Pharmaceutical Works,

India's first pharmaceutical company; Alamohan Das created India Machinery Company and Bharat Jute Mill. Thus, West Bengal was not peripheral to India's economic imagination; it was one of its epicentres.

The Hooghly reverberated with shipbuilding and commerce. Howrah became synonymous with engineering ingenuity. Jute mills lined the river; Darjeeling and the Dooars carried West Bengal's tea to distant shores and Kolkata stood proudly among Asia's great commercial cities. Then came the long period of attrition. Decades of political hostility towards enterprise progressively weakened this magnificent inheritance. West Bengal's share of India's industrial output declined from 9.8% in 1981 to barely 5.1% within 2 decades. Factories shut down, entrepreneurs departed and generations of young people were compelled to look elsewhere for opportunities their own soil should have provided. Singur became the most poignant symbol of this abdication.

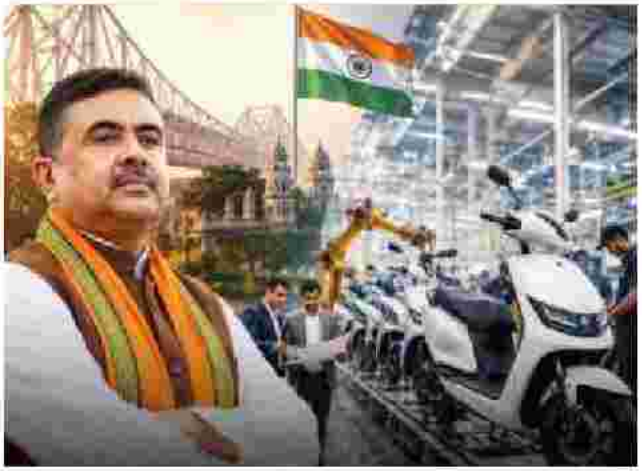

But the people of West Bengal never reconciled themselves to the idea that decline was their destiny and in 2026, West Bengal chose to turn the page on decades of regression and embark upon a determined journey to reclaim its lost glory.

Within just 3 months of the new government assuming office, the first contours of that resurrection are visible. Be it Shyam Steel's ₹15,000 crore integrated expansion at Mejia, expected to generate nearly 20,000 direct and indirect employment opportunities; the modernisation of Durgapur Steel Plant and expansion of IISCO; the ₹250 crore Indo-Thai electric-scooter manufacturing partnership between Mercstone EV and Assara Electric; or Amul's ₹700 crore commitment towards dairy infrastructure, the signs of West Bengal traversing the path from industrial stagnation to renewed investment, enterprise and opportunity are vivid.

At Baruipur, Indian Association for the Cultivation of Science (IACS) is developing its second campus at an investment of ₹400 crore being developed for AI, battery technology, while Himadri Speciality Chemical is constructing India's first domestic carbon nanotube facility. The Indian Chamber of Commerce has committed to facilitating 1 lakh crore of member investment, while another ₹20,000 crore is being pursued across steel, food processing and allied sectors, collectively infusing new vigour into West Bengal's economic landscape.

The ambition of West Bengal is consequently unapologetically immense; 1 crore jobs in 5 years; 4 industrial zones; rejuvenated jute; globally resurgent Darjeeling tea; Haldia as a premier eastern port hub. To turn these into reality, the Budget has been proposed with a ₹5,000 crore industrial investment fund, an Investment Promotion Framework, dedicated industrial corridors and single-window clearances. West Bengal's first Atal Incubation Centre is expected to incubate 500 startups over 5 years, while the forthcoming Startup Policy will tell every young dreamer that no one should have to leave West Bengal to fulfil their ambition.

But industries cannot flourish on aspiration alone. They require arteries. Projects paralysed for years by administrative lethargy and land bottlenecks are now being unlocked under the able leadership of Prime Minister, Shri Narendra Modi. The Union Government has raised West Bengal's railway allocation to 14,205 crore, while approximately 293,000 crore of railway projects stand sanctioned. The 2,100-kilometre Dankuni-Surat Dedicated Freight Corridor, the East Coast Industrial Corridor with Durgapur as a node and expanded freight connectivity will transform West Bengal from a geographical gateway into an economic gateway.

At its heart, the aspiration is simple; West Bengal has always been a land of possibilities and the time has come to make it a land where possibilities become realities. A West Bengal where the youth build their dreams on their own soil; where artisans become entrepreneurs, entrepreneurs become employers and innovation becomes instinctive; where the din of factories, the bustle of ports and the audacity of startups once again become the bugle of prosperity.

The vision is to make West Bengal the undisputed economic leader of the East, the gateway to the East and the crown jewel of Purvodaya under the Double Engine Sarkar. For when West Bengal realises the full measure of its possibilities, Viksit Paschimbongo will not merely accompany Bharat's transformation into Viksit Bharat by 2047; it will help propel it.

○○○

A Two-Day 'Swayamsiddha' Exhibition was inaugurated by LUB's National Org. Secretary Shri Prakash Chandra ji & Dr. Manju Baghmar, State Minister- Public Works, Govt. of Rajasthan at Jaipur. On this occasion, LUB's National Jt. GS Shri Naresh Pareek, National Secretary Smt. Anju Singh, Prant President Shri Mahendra Mishra & GS Ms. Sunita Sharma and other entrepreneurs were present.

A fruitful and constructive meeting was held between Shri Arup K. Roy, GS-Central Sambhag, West Bengal and Sushri Moumita Biswas Mishra, MoS for Industries, Commerce & Enterprises, Govt. of West Bengal on 4th August. The discussion focused on various industry-related issues concerning the Asansol and Durgapur region.

"Hyzicplus
Care You Trust,
Quality You Deserve"
hyzicmart@gmail.com
www.hyzicmart.com
Address:

STEELS
KAVACH STEELS
STRENGTH THAT BUILDS TOMORROW
STRUCTURAL STEEL
ANGLE
CHANNEL
FLAT
ROUND
HIGH STRENGTH
PRECISE TOLERANCES
CONSISTENT QUALITY
ON-TIME DELIVERY
CUSTOMER SATISFACTION
BUILT WITH TRUST. DELIVERED WITH PRIDE.
KAVACH STEELS
Friends Alloys
District- Solan, Himachal Pradesh

HTP
TM
SINCE 1972
HIMACHAL TEREPENE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
OUR PRODUCTS
Alpha Pinene
Camphene
Turpentine Oil EP
DD Turpentine
Terpin Hydrate IP
Lemon Grass Oil

able
pharma
Estd.2006
PRECISION CARE.
NATURALLY BETTER.
Manufacturers of
EYE, EAR & NASAL
FORMULATIONS
+91 87259 46339
ajitesh.bindal@ablepharma.com
www.ablepharma.com
Committed to Quality. Trusted by Healthcare
WHO-GMP

नमो नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का आरोग्य उत्थान
गांव से मेडिकल कॉलेज तक मजबूत स्वास्थ्य सेवाओं ने बनाया उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश

आरोग्यम
ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बीते वर्षों में तेजी से बदली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं और प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता ने स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा दी है। आज सरकारी अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या के साथ ओपीडी, भर्ती, जांच, प्रसव और ऑपरेशन जैसी सेवाओं का विस्तार हुआ है। गांवों तक एंबुलेंस, मोबाइल मेडिकल यूनिट और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंचे हैं, वहीं ई–संजीवनी, आभा आईडी और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड ने स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक से जोड़ा है। मातृ–शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, टीबी नियंत्रण, डायलिसिस, कैंसर, हृदय रोग और गंभीर बीमारियों के उपचार तक स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को बेहतर इलाज के लिए अपने गांव और जिले से दूर जाने की मजबूरी न हो। यही नमो नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का आरोग्य उत्थान है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एचएमआईएस आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2024–25 की तुलना में 2025–26 में सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं 23.26 करोड़ से बढ़कर 26.21 करोड़ हो गईं। भर्ती मरीजों की संख्या भी 1.03 करोड़ से बढ़कर 1.23 करोड़ पहुंची। संस्थागत प्रसव 24.38 लाख से बढ़कर 24.79 लाख हुए।

लैब जांच लगभग 20 करोड़ से बढ़कर 23.81 करोड़ और एक्स–रे जांच 77.69 लाख तक पहुंचीं। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं हैं, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास और सेवाओं की बढ़ती पहुंच का प्रमाण हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में है। सरकारी प्रसव केंद्रों की संख्या बढ़ाने के साथ मानकों के अनुरूप कार्य करने वाले फर्स्ट रेफरल यूनिट्स यानी एफआरयू को मजबूत किया गया है। जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन मिला है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत नियमित जांच शिविरों के माध्यम से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर समय पर उपचार और रेफरल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मातृ मृत्यु को कम करने के लिए

प्रत्येक मातृ मृत्यु की समीक्षा की जा रही है, ताकि कमियों की पहचान कर उनमें सुधार किया जा सके। वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप लाने की दिशा में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है।

नवजात से बच्चों तक सुरक्षा का मजबूत घेरा

गंभीर रूप से बीमार नवजातों के उपचार के लिए एसएनसीयू सेवाओं का विस्तार किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर–घर नवजात और छोटे बच्चों की देखभाल पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य अस्पताल और परिवार के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी मजबूत कड़ी तैयार करना है, जिसमें बच्चे को समय पर उपचार और आवश्यक देखभाल मिल सके। नियमित टीकाकरण में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। जेई टीकाकरण, विटामिन–ए की खुराक और फरवरी 2026 से शुरू एचपीवी टीकाकरण के माध्यम से बच्चों एवं किशोरियों को गंभीर बीमारियों से सुरक्षित करने का दायरा बढ़ा है। पल्स पोलियो अभियान के माध्यम से करोड़ों बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों की स्वास्थ्य जांच के साथ जन्मजात बीमारियों से पीड़ित बच्चों के उपचार और आवश्यक ऑपरेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपात स्थिति में समय पर अस्पताल पहुंचना उपचार की पहली आवश्यकता है। प्रदेश में 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गंभीर मरीजों के लिए एएलएस एंबुलेंस की सुविधा भी मजबूत की गई है। जहां अस्पताल तक पहुंच आसान नहीं है, वहां मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से ओपीडी और जांच सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच शहरों से निकलकर दूरदराज के क्षेत्रों तक हुई है।

डायलिसिस से गंभीर बीमारियों के उपचार तक राहत

किडनी रोगियों के लिए डायलिसिस जैसी महंगी चिकित्सा सेवा सरकारी व्यवस्था के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सीटी स्कैन और टेली–रेडियोलॉजी जैसी आधुनिक जांच सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से कैंसर, हृदय रोग और हड्डियों से जुड़ी गंभीर बीमारियों सहित अनेक महंगे उपचार जरूरतमंद परिवारों के लिए सुलभ हुए हैं। आयुष्मान आरोग्य

मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की नई आधारशिला बन रहे हैं। इन केंद्रों पर बड़ी संख्या में मरीजों को ओपीडी सेवाएं और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आवश्यक दवाओं की सूची बढ़ाकर 84 की गई है। बड़ी संख्या में आरोग्य मंदिरों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता प्रमाणन मिलना इस बात का प्रमाण है कि हम केवल सेवाओं का विस्तार ही नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता पर भी समान रूप से ध्यान दे रहे हैं। ई–संजीवनी ने स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल माध्यम से आम नागरिक के और करीब ला दिया है। अब दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले मरीज भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सकीय सलाह प्राप्त कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन को 976 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक विस्तारित करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह उनके निकट उपलब्ध कराना है।

टीबी से लेकर मलेरिया तक नियंत्रण

रोग नियंत्रण के क्षेत्र में भी प्रदेश ने लगातार प्रयास किए हैं। वर्ष 2025–26 में सरकारी संस्थानों द्वारा 6.86 लाख टीबी मामलों की अधिसूचना की गई। टीबी सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक ले जाने के लिए कुछ जिलों में पायलट परियोजनाएं संचालित की गईं। मलेरिया की 33 लाख से अधिक जांच की गईं। कुष्ठ रोग की प्रचलन दर में भी कमी दर्ज की गई है। बीमारी की निगरानी, जांच और उपचार में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य व्यवस्था हुई डिजिटल

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़ी संख्या में आभा आईडी बनाई गई हैं और नागरिकों के इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री का भी

तेजी से विस्तार हुआ है। सरकारी अस्पतालों में स्कैन एंड शेयर जैसी सुविधाओं से ओपीडी पंजीकरण को आसान और तेज बनाने में मदद मिली है। यूपी हेल्थ डैशबोर्ड और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और मूल्यांकन को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। यानी तकनीक अब केवल अस्पतालों के प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीज की सुविधा से लेकर उसके स्वास्थ्य रिकॉर्ड और उपचार की निगरानी तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

आयुष्मान भारत से आर्थिक सुरक्षा

आयुष्मान भारत योजना के तहत वर्ष 2025–26 में 46.35 लाख नए कार्ड बनाए गए। प्रदेश में कुल आयुष्मान कार्डों की संख्या 5.98 करोड़ तक पहुंच चुकी है। योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र के 6,402 अस्पताल जुड़े हैं। कैंसर, हृदय रोग और हड्डियों से संबंधित गंभीर उपचारों के लिए बड़ी संख्या में प्री–ऑथराइजेशन किए गए हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को महंगे उपचार के आर्थिक बोझ से राहत मिली है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है– बीमारी किसी परिवार को आर्थिक संकट में न धकेले।

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार

प्रदेश में 83 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। 1,240 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति–पत्र दिए गए हैं और 6,351 स्टाफ नर्स पदों पर नियमित चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। चिकित्सा शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए संविदा के आधार पर नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज की गई है। चिकित्सक भर्ती बोर्ड के माध्यम से भी स्वास्थ्य मानव संसाधन को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सुपर स्पेशियलिटी और क्वार्टनरी केयर सेवाओं के विस्तार पर भी जोर है, ताकि गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। कैंसर की समय रहते पहचान और उपचार के लिए राज्य कैंसर मिशन की दिशा में काम किया जा रहा है। इमरजेंसी और ट्रॉमा सेवाओं को मजबूत करने के लिए मिशन यूपीटीईएन, आईसीयू सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए मिशन केयर यूपी और ऑपरेशन थिएटरों को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सुश्रुत जैसी पहल प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही वन हेल्थ मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हेल्थ इकोसिस्टम और डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को आगे बढ़ाया जा रहा है। पीपीपी मॉडल के

माध्यम से सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार भी स्वास्थ्य व्यवस्था को नई क्षमता प्रदान करेगा।

आज उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था केवल बड़े शहरों और मेडिकल कॉलेजों तक सीमित नहीं है। गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जरूरत के समय एंबुलेंस, दूरदराज क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ सेवाएं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे चिकित्सकीय सलाह–ये सभी मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं की एक नई श्रृंखला तैयार कर रहे हैं। 139 ग्रामीण सीएचसी – एफआरयू में ब्लड स्टोरेज यूनिट लगाए गए हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है और गुणवत्ता सुधार के लिए एनक्यूएएस प्रमाणन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह परिवर्तन केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। अब हमारा जोर समय पर जांच, घर के पास उपचार, निःशुल्क परिवहन, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, विशेषज्ञ चिकित्सकीय सलाह और गंभीर बीमारी के उपचार में आर्थिक सुरक्षा पर भी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत, डिजिटल हेल्थ और मातृ–शिशु स्वास्थ्य जैसी योजनाओं को उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारा जा रहा है। हमारा संकल्प है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक केवल संसाधनों के अभाव में बेहतर इलाज से वंचित न रहे। स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का अधिकार और हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। गांव से घर तक, आरोग्य मंदिर से मेडिकल कॉलेज तक, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था नए विश्वास, नई तकनीक और नई गति के साथ आगे बढ़ रही है। यही है नमो नेतृत्व में नए उत्तर प्रदेश का आरोग्य उत्थान। ○○○

DIGITAL भारत से AI भारत की यात्रा: महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और भविष्य की नई उड़ान

नया सफर

अनिल पाठक

प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियरिंग लीडर एग्जीक्यूटिव काउंसिल -IEEE (इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स), दिल्ली चैप्टर

इतिहास में कुछ दशक ऐसे होते हैं जो केवल समय का अंतराल नहीं होते, बल्कि किसी राष्ट्र की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। भारत के लिए वर्ष 2014 से 2026 का ऐसा ही एक परिवर्तनकारी काल रहा है। इस दौरान देश ने तकनीक को केवल आधुनिकता का प्रतीक नहीं बनाया, बल्कि उसे सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बनाया।

यदि आज कोई छोटा व्यापारी मोबाइल फोन से डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहा है, कोई ग्रामीण उद्यमी पूरे देश में अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच रहा है, कोई युवा बिना बड़े निवेश के तकनीकी स्टार्टअप शुरू कर रहा है, या कोई MSME वैश्विक ग्राहकों के साथ डिजिटल माध्यम से व्यापार कर रहा है, तो यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आया। इसके पीछे पिछले एक दशक में तैयार की गई डिजिटल आधारशिला है।

आधार ने पहचान को डिजिटल बनाया, UPI ने भुगतान प्रणाली को सरल बनाया, Digi Locker ने दस्तावेज़ों को मोबाइल तक पहुँचाया, GST ने कर व्यवस्था को एकीकृत किया, ONDC ने छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल बाज़ार के नए द्वार खोले और 5G ने तेज़ कनेक्टिविटी की नई संभावनाएँ पैदा कीं। इन पहलों ने मिलकर भारत में ऐसा डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया, जिसकी चर्चा आज विश्व स्तर पर हो रही है। लेकिन यह केवल "डिजिटल भारत" तक सीमित नहीं है।

दुनिया अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के नए युग में प्रवेश कर रही है और भारत इस परिवर्तन का केवल दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय सहभागी बनने की तैयारी कर चुका है। पिछले दशक में जो डिजिटल नींव तैयार हुई, वही अब AI आधारित अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रही है।

आज प्रश्न यह नहीं है कि AI आएगा या नहीं। प्रश्न यह है कि भारत इस अवसर का उपयोग कितनी तेज़ी और कितनी दूरदर्शिता से करता है। विशेष रूप से भारत के करोड़ों सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इस परिवर्तन के सबसे बड़े लाभार्थी बन सकते हैं।

एक दशक जिसने भारत की तकनीकी पहचान बदल दी

जब हम पिछले दस – बारह वर्षों पर नज़र डालते हैं, तो स्पष्ट दिखाई देता है कि भारत ने तकनीकी विकास को अलग–अलग परियोजनाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक समग्र राष्ट्रीय रणनीति के रूप में अपनाया।

पहले चरण में देश ने डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) तैयार की। दूसरे चरण में स्टार्टअप, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अंतरिक्ष विज्ञान, 5G, ड्रोन, रक्षा प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया। अब तीसरे चरण में भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा, स्वचालन और बुद्धिमान प्रणालियों के माध्यम से अगली औद्योगिक

क्रांति की तैयारी कर रहा है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: भारत की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि

दुनिया के अनेक देशों ने डिजिटल सेवाएँ विकसित कीं, लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने ऐसे सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तैयार किए, जिन पर सरकार, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप और नागरिक सभी नवाचार कर सकें। इसे आज Digital Public Infrastructure (DPI) के नाम से जाना जाता है।

आधार: पहचान से सशक्तिकरण तक

डिजिटल अर्थव्यवस्था की पहली आवश्यकता विश्वसनीय पहचान है। आधार ने करोड़ों नागरिकों को एक ऐसी डिजिटल पहचान दी जिसने बैंक खाते खोलने, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, मोबाइल कनेक्शन लेने और अनेक सेवाओं तक पहुँच को सरल बनाया। इससे समावेशी विकास को नई गति मिली।

UPI: भुगतान नहीं, विश्वास की क्रांति

UPI ने भारत में भुगतान का तरीका बदल दिया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल तेज़ भुगतान नहीं है। इसने डिजिटल लेन–देन पर विश्वास स्थापित किया। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े उद्योग तक, हर स्तर पर डिजिटल भुगतान सामान्य बात है। इससे नकदी पर निर्भरता घटी, लेन–देन का रिकॉर्ड बना और औपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।

DigiLocker: कागज़ से क्लाउड तक

डिजिटल दस्तावेज़ों ने नागरिकों और व्यवसायों दोनों के लिए समय और लागत की बचत की। प्रमाण–पत्र, लाइसेंस और अन्य दस्तावेज़ों की डिजिटल उपलब्धता ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया।

ONDC: डिजिटल व्यापार का लोकतंत्रीकरण

ई–कॉमर्स लंबे समय तक कुछ बड़े प्लेटफ़ॉर्म तक सीमित रहा। ONDC ने छोटे व्यापारियों और MSME को भी डिजिटल बाज़ार में प्रतिस्पर्धा का अवसर दिया। यह केवल एक तकनीकी मंच नहीं, बल्कि व्यापार के नए लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन पहलों का सबसे बड़ा लाभ MSME क्षेत्र को मिला है। आज एक छोटा उद्यम: पूरे देश में अपने उत्पाद बेच सकता है। डिजिटल भुगतान आसानी से स्वीकार कर सकता है। सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है। डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच बना सकता है। कम लागत में तकनीक आधारित व्यवसाय चला सकता है। यही कारण है कि भारत का डिजिटल परिवर्तन केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की कहानी भी है।

भारत की तकनीकी छलांग: नवाचार से आत्मविश्वास तक

यदि पिछले दशक की तकनीकी उपलब्धियों को केवल अलग–अलग घटनाओं के रूप में देखा जाए, तो शायद उनका वास्तविक महत्व समझ में न आए। लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़कर देखा जाता है, तो एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है–भारत ने योजनाबद्ध तरीके से एक ऐसा तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है जो उसे वैश्विक नवाचार की दौड़ में एक मजबूत स्थान प्रदान करता है।

यह यात्रा डिजिटल भुगतान या इंटरनेट तक सीमित नहीं रही। इस दौरान भारत ने विनिर्माण, दूरसंचार, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टार्टअप, डीप–टेक और

अनुसंधान जैसे अनेक क्षेत्रों में समानांतर रूप से प्रगति की। यही समन्वित विकास आज भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।

स्टार्टअप से स्टैंड-अप तक : नवाचार की नई संस्कृति

एक दशक पहले भारत में स्टार्टअप की चर्चा सीमित थी। आज नवाचार देश की आर्थिक रणनीति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। फिनटेक, हेल्थटेक, एग्रीटेक, एडटेक, SaaS, डीप–टेक और AI जैसे क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप न केवल घरेलू समस्याओं का समाधान विकसित कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक बाज़ारों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं।

इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि तकनीक कुछ चुनिंदा कंपनियों तक सीमित नहीं रही। नवाचार अब विश्वविद्यालयों, छोटे शहरों और युवा उद्यमियों तक पहुँच चुका है। आज प्रत्येक MSME को स्वयं हर तकनीक विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ साझेदारी करके वे कम लागत में आधुनिक समाधान अपनाकर अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ा सकते हैं।

5G:केवल तेज़ इंटरनेट नहीं, बल्कि स्मार्ट उद्योगों की आधारशिला

अधिकांश लोग 5G को केवल मोबाइल इंटरनेट की अगली पीढ़ी मानते हैं। वास्तव में 5G उद्योगों के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। स्मार्ट फैक्ट्री, स्वचालित उत्पादन, मशीन–टू–मशीन संचार, दूरस्थ उपकरण प्रबंधन, ऑगमेंटेड रियलिटी आधारित प्रशिक्षण और वास्तविक समय में गुणवत्ता निगरानी जैसी अनेक तकनीकें 5G नेटवर्क पर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती हैं। आने वाले वर्षों में Industry 4.0/5.0 की सफलता का एक बड़ा आधार उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल कनेक्टिविटी होगी। छोटे विनिर्माण उद्योग भी अब बड़े निवेश के बिना स्मार्ट उत्पादन, दूरस्थ निगरानी और डिजिटल संचालन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर: आत्मनिर्भरता की नई दिशा

डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्य केवल सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं है। उसके लिए मजबूत हार्डवेयर पारिस्थितिकी तंत्र भी आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने, मोबाइल निर्माण क्षमता विकसित करने और सेमीकंडक्टर उद्योग की नींव रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

यदि यह प्रयास सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है, तो आने वाले वर्षों में केवल बड़े उद्योग ही नहीं, बल्कि हजारों MSME भी मशीनिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, पैकेजिंग, टेस्टिंग, औद्योगिक ऑटोमेशन, विशेष रसायन और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में नए अवसर प्राप्त करेंगे। हर बड़ा उद्योग अपने साथ सैकड़ों छोटे उद्योगों का विकास भी लेकर आता है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र इसका महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकते हैं।

ड्रोन और रक्षा प्रौद्योगिकी: नए उद्योगों का उदय

ड्रोन अब केवल रक्षा तक सीमित नहीं हैं। कृषि, सर्वेक्षण, खनन, आपदा प्रबंधन, आधारभूत संरचना निरीक्षण और लॉजिस्टिक्स जैसे अनेक क्षेत्रों में उनका उपयोग बढ़ रहा है। इसी प्रकार रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकों पर बढ़ते ध्यान ने भारतीय उद्योगों के लिए नए अवसर खोले हैं। इन क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, बैटरी, कंपोजिट सामग्री, एम्बेडेड सिस्टम और मैकेनिकल कंपोनेंट्स जैसे अनेक क्षेत्रों में MSME की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि: तकनीकी आत्मविश्वास

पिछले दशक की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल नई तकनीकों का विकास नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि है– भारत का बढ़ता तकनीकी आत्मविश्वास। आज भारत केवल नई तकनीकों का उपभोक्ता नहीं बनना चाहता। वह उन्हें विकसित करना, बड़े पैमाने पर लागू करना और विश्व के

लिए समाधान के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। यही परिवर्तन आने वाले AI दशक की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा।

AI भारत: अगली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत

AI: केवल एक तकनीक नहीं, एक नई सोच

पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) ने दुनिया भर में अभूतपूर्व चर्चा प्राप्त की है। लेकिन AI को केवल एक नई तकनीक मानना इसकी क्षमता को सीमित करके देखना होगा। AI वास्तव में निर्णय लेने, सीखने, विश्लेषण करने और कार्यों को अधिक बुद्धिमानी से सम्पन्न करने की क्षमता है। जिस प्रकार बिजली ने मशीनों को शक्ति दी और इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ा, उसी प्रकार AI आने वाले वर्षों में प्रत्येक उद्योग, प्रत्येक संस्था और प्रत्येक व्यवसाय की कार्यशैली को बदलने जा रहा है।

भारत AI के लिए सबसे तैयार देशों में क्यों है ?

दुनिया के अनेक देशों के पास उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थान हैं, अनेक देशों के पास विशाल पूंजी है, और कई देशों के पास उन्नत प्रौद्योगिकी कंपनियाँ हैं। फिर भी भारत के पास कुछ ऐसी विशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो उसे AI युग में अलग पहचान देती हैं।

1. **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना** (Digital Public Infrastructure)

   पिछले दशक में भारत ने जो डिजिटल आधार तैयार किया, वह AI के लिए एक मजबूत नींव है। डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डिजिटल दस्तावेज़, डिजिटल शासन और व्यापक डिजिटल सेवाओं ने डेटा–आधारित प्रणालियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। AI के लिए केवल एल्गोरिद्म पर्याप्त नहीं होते; एक सक्षम डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र भी आवश्यक होता है। भारत ने यह आधार पहले ही तैयार कर लिया है।

2. **विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल उपभोक्ता आधार**

   भारत में करोड़ों लोग प्रतिदिन डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हैं। यह केवल संख्या नहीं है। यह विविधता है– भाषाओं की, व्यवसायों की, उद्योगों की, उपयोग के तरीकों की। AI मॉडल तभी अधिक उपयोगी बनते हैं जब वे विविध परिस्थितियों में सीखते और विकसित होते हैं। भारत की यही विविधता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है।

3. **विश्वस्तरीय IT प्रतिभा**

   पिछले तीन दशकों में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, डेटा इंजीनियरिंग और डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञों का योगदान दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। AI के विकास और व्यापक उपयोग के लिए यही मानव संसाधन सबसे बड़ी पूँजी है।

4. **स्टार्टअप और नवाचार का बढ़ता इकोसिस्टम**

   AI में नवाचार केवल बड़ी कंपनियाँ नहीं करेंगी। स्टार्टअप, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और MSME भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। भारत का तेजी से विकसित होता स्टार्टअप इकोसिस्टम AI आधारित समाधान विकसित करने की दिशा में नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है।

5. **भारतीय भाषाओं की शक्ति**

   AI का वास्तविक प्रभाव तभी होगा जब वह करोड़ों भारतीयों तक उनकी अपनी भाषा में पहुँचे। भारत की भाषाई विविधता एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। भारतीय भाषाओं के लिए विकसित AI समाधान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, न्याय, प्रशासन और व्यापार को अधिक समावेशी बना सकते हैं। यही भारत को अनेक अन्य देशों से अलग बनाता है।

AI अब केवल बड़ी कंपनियों की तकनीक नहीं रही। आज एक छोटा उद्योग भी AI की सहायता से– ग्राहक सेवा को बेहतर बना सकता है। गुणवत्ता निरीक्षण को स्वचालित कर सकता है। बिक्री का पूर्वानुमान लगा सकता है। इन्वेंटरी का बेहतर प्रबंधन कर सकता है। विपणन सामग्री तैयार कर सकता है। अनेक भारतीय भाषाओं में ग्राहकों से संवाद कर सकता है। उत्पादन लागत कम कर सकता है। AI छोटे उद्योगों के लिए केवल दक्षता नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक समानता (Competitive Equality) का अवसर लेकर आया है।

भारत सरकार ने India AI Mission के माध्यम से स्पष्ट संकेत दिया है कि AI केवल निजी क्षेत्र का विषय नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय विकास का प्रमुख आधार बनेगा। भारतीय AI कंपनियाँ भी नवाचार की एक नई पहचान बन रहीं हैं जैसे– Sarvam AI, BharatGen, Krutrim, Fractal, Zoho, CoRover, Soket AI आदि इत्यादि

BharatGen

GenAI for Bharat, by Bharat

भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक India AI Impact Summit का आयोजन कर यह संदेश दिया है कि वह AI क्रांति का केवल सहभागी नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यह सम्मेलन उत्तरदायी, समावेशी और मानव–केंद्रित AI के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता तथा वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में उसकी सक्रिय भूमिका का महत्वपूर्ण प्रमाण है।

भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर

आने वाले दशक में विश्व की प्रतिस्पर्धा केवल श्रम लागत या उत्पादन क्षमता पर आधारित नहीं होगी। प्रतिस्पर्धा इस बात पर होगी कि कौन–सा देश–AI को सबसे व्यापक स्तर पर अपनाता है, नवाचार को सबसे तेज़ी से उद्योग तक पहुँचाता है, और अपने नागरिकों तथा उद्यमों को नई तकनीकों के उपयोग के लिए सबसे बेहतर तरीके से तैयार करता है।

भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय संभावनाएँ हैं। यदि पिछले दशक ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया है, तो आने वाला दशक भारत को बुद्धिमान, नवाचारी और AI – सक्षम अर्थव्यवस्था में बदल सकता है।

डिजिटल भारत ने डेटा, डिजिटल विश्वास और डिजिटल अवसंरचना का निर्माण किया। तकनीकी भारत ने नवाचार, अनुसंधान और विनिर्माण की क्षमता विकसित की। अब AI भारत इन दोनों शक्तियों को जोड़कर एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है जहाँ तकनीक केवल कार्यों को तेज़ न करे, बल्कि निर्णयों को अधिक बुद्धिमान, उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी और समाज को अधिक समावेशी बनाए। यही भारत की अगली तकनीकी छलांग होगी। ○○○

LUB's delegation of Mumbai Western unit led by President Shri Mahesh Jogani met Union Minister for Commerce & Industry Shri Piyush Goyal to discuss various matters concerning the growth, development and strengthening of MSMEs in Mumbai. Shri Goyal appreciated the efforts being undertaken by LUB towards strengthening the MSME ecosystem and empowering small and medium entrepreneurs.

LUB's Haryana delegation met Chief Minister Shri Nayab Singh Saini at Chandigarh on 3rd August. The delegation held detailed discussions on various challenges faced by entrepreneurs and industrial units, along with policy-related matters, infrastructure requirements, ease of doing business, and measures to strengthen the competitiveness of MSMEs. The delegation comprising North Zone Sah Prabhari Shri Shubhadesh Mittal, State President Shri Raman Saluja, State General Secretary Shri Manoj Rungta, State Treasurer Shri Sanjay Data, Shri Sudhir Chandra, and Shri Bhim Rana.

GST Reforms under the Modi Government:
A Data-Driven Transformation of India's Indirect Tax System

New Wave
CA Mahesh Gupta
Noted Tax Consultant &
National Treasurer LUB
Kota, Rajasthan
mgupta@kalanico.com

A Decade of Structural Simplification

India's indirect tax system before 2017 was defined by fragmentation, complexity and inefficiency. Multiple levies such as VAT, excise duty, service tax, octroi and state-specific charges created a maze that businesses especially MSMEs struggled to navigate. Compliance consumed valuable time, logistics were slowed by interstate check-posts, and cascading taxes inflated costs across the value chain. The introduction of the Goods and Services Tax (GST) in July 2017 marked a decisive break from this past. It was not merely a tax reform but a structural overhaul aimed at simplifying compliance, modernizing administration and creating a unified national market.

Over the next decade, GST evolved through continuous refinement, culminating in the landmark GST 2.0 reform of 2025, which rationalized rates and further reduced compliance friction. The transformation has been both systemic and measurable, reshaping India's indirect tax architecture and strengthening its fiscal foundation.

GST 2017: Unifying India's Indirect Tax Landscape

The rollout of GST replaced a patchwork of indirect taxes with a single, destination-based levy. This unification eliminated cascading taxes and enabled seamless input tax credit, reducing the overall tax burden on businesses. For MSMEs, GST brought a shift from multiple state-wise registrations to a single national registration, significantly reducing administrative overhead. The removal of interstate check-posts improved logistics efficiency, cutting transit times by 20 to 30 percent on major corridors. Digital compliance became central to the new system, with the GST Network enabling electronic filing, automated reconciliation and real-time data flows. Although the initial years involved a steep learning curve, the structural benefits of GST began to materialize as businesses adapted to the new digital ecosystem.

Continuous Refinement: 2017 to 2024

Between 2017 and 2024, GST underwent continuous refinement through decisions of the GST Council. The introduction of the e-way bill system in 2018 streamlined the movement of goods across states, reducing average stoppage time from several hours to under one hour. E-invoicing, rolled out in phases beginning in 2020, brought real-time invoice authentication and significantly reduced invoice-related fraud. Simplified return formats replaced the earlier multi-form structure, making compliance more predictable. Rate rationalization reduced the number of items in the highest slab, lowering the burden on consumers and reducing classification disputes. MSMEs benefited from quarterly filing options, composition schemes and improved refund mechanisms. These incremental improvements strengthened formalization, broadened the tax base and enhanced transparency across supply chains.

GST 2.0: The 2025 Structural Upgrade

The most significant upgrade arrived in September 2025 with the introduction of GST 2.0. The earlier four-slab structure was rationalized into two principal rates, 5 percent for essential goods and 18 percent as the standard rate, while retaining a 40 percent rate for sin and luxury goods. This simplification reduced classification complexity, improved transparency and made compliance easier for businesses of all sizes. The two-rate structure also enhanced audit efficiency, as fewer rate categories meant fewer interpretational disputes. International institutions took note of the reform's impact. The International Monetary Fund described GST 2.0 as a major step toward simplifying India's tax structure and improving compliance, while the OECD and World Bank acknowledged India's progress in digital tax administration. Even New Zealand's Ministry of Foreign Affairs and Trade noted visible consumer relief from the simplified GST structure. Such recognition underscores that the reforms were not merely administrative adjustments but meaningful structural progress with global credibility.

Indirect Tax Collections: Pre-GST vs GST Era

The economic impact of GST reforms is most clearly visible in India's indirect tax collections. In the nine years prior to GST, indirect tax revenue, derived from excise duty, service tax and state VAT, averaged between ₹5 and ₹6 lakh crore annually. Growth remained modest at around 6 to 8 percent per year, constrained by cascading taxes, limited digital compliance and widespread evasion. The taxpayer base hovered around 70 lakh, reflecting the dominance of the informal sector. Digital reporting was minimal, and the absence of a unified audit trail made enforcement difficult. The pre-GST system, though functional, lacked the structural capacity to support a rapidly modernizing economy.

The GST era presents a markedly different picture. GST collections in FY18 stood at approximately ₹7.2 lakh crore, rising to ₹18.08 lakh crore in FY23 and ₹20.14 lakh crore in FY24, an 11.7 percent year-on-year increase. By FY25, monthly collections consistently exceeded ₹1.8 lakh crore, translating to an

annualized figure of more than ₹22 lakh crore. This represents a three-to-four-fold increase compared to the pre-GST period. The taxpayer base expanded from roughly 70 lakh to more than 1.5 crore, reflecting a dramatic rise in formalization. GST buoyancy, the responsiveness of tax revenue to GDP growth, improved from 0.9 in the pre-GST era to between 1.2 and 1.3 post-GST, indicating stronger revenue performance relative to economic activity. Digital compliance became universal, with billions of invoices authenticated monthly through the e-invoicing system. The unified digital architecture reduced leakages, strengthened enforcement and provided policymakers with real-time insights into economic trends.

Economic Impact and MSME Transformation

Beyond revenue, GST reforms have contributed to broader economic efficiency. Logistics costs declined as check-posts were removed and e-way bills streamlined interstate movement. Supply-chain transparency improved due to digital invoice trails, reducing opportunities for tax evasion. MSMEs experienced operational improvements as they adopted accounting software, strengthened inventory management and embraced digital tools. The

predictable tax environment reduced uncertainty and improved business planning. GST 2.0 further reduced classification disputes, allowing MSMEs to focus more on production, customers and innovation rather than tax interpretation. The cumulative effect has been a more efficient, transparent and competitive business ecosystem.

Next-Generation GST Reforms for MSMEs

While GST has delivered substantial progress, further reforms can strengthen MSME competitiveness without compromising government revenue. ***Every hour saved on compliance is an hour that can be invested in customers, production or innovation.*** A single return mechanism for MSMEs, auto-populated from e-invoices and e-way bills, can significantly reduce compliance burden while maintaining data integrity. Automated input tax credit reconciliation can eliminate mismatch disputes and reduce working capital blockage. A risk-based audit framework can ensure that only high-risk cases are scrutinized, reducing harassment while preserving revenue. Simplifying the reverse charge mechanism and accelerating refund processing through AI-based systems can improve liquidity for MSMEs. Dedicated GST facilitation centers can provide handholding for digital compliance, improving voluntary participation. Standardized HSN classification lists for MSME sectors can eliminate interpretational disputes and reduce litigation. These reforms are revenue-neutral yet highly impactful, ensuring that simplification continues without weakening fiscal stability.

A practical set of GST reforms is needed to protect MSMEs when their input tax credit (ITC) is denied due to supplier defaults or departmental objections. The most important change is a **Verified Buyer Protection Mechanism**, under which MSMEs who possess a valid e-invoice, proof of payment through banking channels and genuine procurement documents should not lose ITC merely because the supplier failed to file returns or deposit tax. Once an invoice is authenticated on the GST system, the buyer's credit should be provisionally protected and recovery should be directed toward the defaulting supplier. Alongside this, automated supplier-risk scoring, a dual-confirmation ITC model, faster time-bound dispute resolution and a real-time ITC ledger can ensure transparency, reduce working-capital stress and prevent compliant MSMEs from being penalized for defaults committed by others, all without compromising government revenue.

India's Global Position

India today operates one of the world's largest digital indirect tax systems. Billions of invoices are processed monthly, real-time data flows across states, and the GSTN provides a unified platform for compliance, enforcement and analytics. International institutions have acknowledged India's progress, noting that GST has strengthened revenue administration, improved transparency and enhanced economic resilience. The evolution of GST demonstrates that successful tax systems are built through continuous refinement rather than one-time announcements. India's journey from a fragmented, paper-based system to a unified, digital and simplified framework stands out as one of the most ambitious tax transformations undertaken by any major emerging economy.

Conclusion: A System Built for Growth

GST reforms under the Modi government have fundamentally reshaped India's indirect tax landscape. From unifying a fragmented tax regime to improving transparency and revenue buoyancy, the reforms have laid the foundation for a more integrated economy. Yet the next leap lies in making compliance simpler, smarter and more predictable, particularly for MSMEs. Every hour saved on compliance is an hour that can be invested in customers, production or innovation. Because the true measure of a tax system is not how much of a business's time it consumes, but how much of that time it gives back.

○○○

Catalyzing the Engine of Viksit Bharat: 12 Years of Banking Reforms *through* MSME Lens

Wide Angle
CA Nirmal Kumar Ojha
National Joint Treasurer
Laghu Udyog Bharati
ojhabusinessconsultancy@gmail.com

Introduction: The Transformation of India's Economic Backbone

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) form the bedrock of the Indian socio-economic fabric. Contributing approximately 30% to India's Gross Domestic Product (GDP), 45% to manufacturing output, nearly 45% of total exports, and providing livelihoods to over 120 million citizens, the sector is the primary driver of equitable wealth distribution and grassroots industrialization.

Yet, for decades following independence, this vital sector remained severely credit-starved. Traditional banking viewed MSMEs through the lens of high risk, prohibitive transaction costs, and inadequate collateral. The past 12 years (2014-2026) under the leadership of Prime Minister Narendra Modi have engineered an unprecedented, systemic transformation in the Indian financial architecture. By dismantling structural bottlenecks, transitioning from physical collateral to verifiable cash-flow underwriting, and creating world-class Digital Public Infrastructure (DPI), banking reforms have shifted MSME finance from an era of bureaucratic exclusion to institutional empowerment.

The Pre-2014 Landscape: Structural Bottlenecks and Credit Starvation

To appreciate the depth of recent reforms, one must assess the state of MSME financing prior to 2014, which was plagued by deep structural inefficiencies:

Key Bottlenecks of Pre-2014 MSME Banking Architecture:

- **Collateral-Centric Dogma:** Credit restricted almost entirely to physical immovable asset owners; entrepreneurial viability and cash flows were discounted.
- **Twin Balance Sheet Crisis:** Public Sector Banks (PSBs) were weighed down by massive corporate NPAs and stressed balance sheets, crowding out small borrowers.
- **Informal Usurious Credit Trap:** Over 85% of micro units were forced to depend on unorganized lenders at punishing interest rates ranging between 24% and 36% annually.
- **Opaque Underwriting & Red Tape:** Paper-heavy, subjective appraisals resulted in turnaround times of 60 to 90 days, causing severe working capital distress.

The IFC-World Bank enterprise surveys estimated an addressable MSME credit gap exceeding ₹25 lakh crore in 2012-13. First-generation entrepreneurs, service providers, and micro-enterprises with high turnover but minimal fixed assets were structurally shut out from formal banking channels.

The 12-Year Transformation (2014-2026): A Paradigm Shift in MSME Banking

The post-2014 era replaced piecemeal incentives with systemic, structural overhauls across the financial sector:

A. Democratization of Micro-Credit: PMJDY and PMMY

The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) brought over 53 crore unbanked citizens into formal banking, creating the digital foundation for credit delivery. Building on this, the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) institutionalized micro-enterprises. Since inception, PMMY has disbursed over ₹30 lakh crore across Shishu, Kishore, and Tarun categories- with over 68% of sanctions allocated to women entrepreneurs. The Union Budget enhanced the Mudra limit under the 'Tarun Plus' category to ₹20 lakh for entrepreneurs who successfully repaid prior loans, directly addressing the missing middle.

B. Institutionalizing Credit Guarantees: CGTMSE & ECLGS

The Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) was overhauled by reducing annual guarantee fees, increasing the coverage ceiling up to ₹5 crore, and waiving legal action mandates for claims up to ₹10 lakh. Cumulative credit guarantee approvals have crossed ₹6 lakh crore.

During the COVID-19 pandemic, the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) provided 100% sovereign-backed collateral-free additional working capital term loans, injecting over ₹3.6 lakh crore of liquidity. SBI Research confirmed that ECLGS prevented at least 14.6 lakh MSME accounts from slipping into NPA status, preserving an estimated 60 million livelihoods.

C. Resolving the Bad-Loan Legacy: IBC, 2016 and PSB Consolidation

The enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016, along with the RBI's asset quality review, cleaned up legacy corporate NPAs under the 4R Strategy (Recognition, Resolution, Recapitalization, and Reforms). Gross NPAs of Scheduled Commercial Banks dropped from a peak of 11.2% in 2017–18 to a multi-decade low of under 2.8% by 2025–26, restoring bank balance sheets and creating capacity to expand MSME loan books. For MSMEs specifically, the introduction of the Pre-Packaged Insolvency Resolution Process (PPIRP) provided a faster, debtor-in-possession resolution framework.

The Step-by-Step Banking Journey for MSMEs (2014 to 2026)

The modernization of Indian MSME banking followed a carefully sequenced, four-stage strategic roadmap over the past twelve years:

Phase & Timeline	Strategic Focus	Landmark Initiatives	Systemic Impact
Phase-I (2014–2017)	Financial Inclusion & Identity	PMJDY, JAM Trinity, Udyog Aadhaar, Stand-Up India	Established digital bank accounts and simplified MSME registration via self-certification.
Phase-II (2017–2020)	Formalization & Transparent Underwriting	GST Rollout, TReDS Operationalization, PSB Loans in 59 Min, GeM Portal	Replaced subjective paper assessments with verified transaction data; institutionalized digital
Phase-III (2020–2023)	Crisis Resilience & Structural Redefinition	Aatmanirbhar Bharat Package, Revised MSME Composite Criteria, ECLGS, CGTMSE Infusion	Removed investment disincentives for growth; guaranteed liquidity during macroeconomic shocks.
Phase-IV (2023–2026)	Frictionless Data-Driven Ecosystem	Account Aggregator (AA), Unified Lending Interface (ULI), OCEN Protocols	Replaced collateral requirements with real-time financial data consent pipelines; cut loan sanction times to minutes.

How the Banking Evolution Revolutionized MSME Business

The operational environment for small enterprises has undergone fundamental changes across three core dimensions:

A. Transition from Balance-Sheet to Cash-Flow-Based Lending

Historically, banks underwrote loans based on historic financial statements submitted with a 6-to-12-month lag and physical real estate collateral. Today, credit assessment is anchored on verifiable, real-time transaction data. The Account Aggregator (AA) ecosystem and RBI's Unified Lending Interface (ULI) allow lenders to evaluate creditworthiness within minutes without physical documentation.

B. Liquidity Unlocking through TReDS and GeM

Delayed payments have historically drained MSME working capital. The Trade Receivables Discounting System (TReDS) has turned unpaid corporate and public sector invoices into liquid capital. Integrating TReDS with the Government e-Marketplace (GeM) and mandating PSUs and corporates with turnover exceeding ₹250 crore to onboard TReDS has expanded factoring volumes, lowering effective borrowing costs by 200-400 basis points.

C. Statutory Protection via Section 43B(h) of the Income-Tax Act

To address delayed payments, the central government enacted amendments under Section 43B(h) of the Income-Tax Act. By allowing tax deductions for buyers only upon actual payment to registered Micro and Small enterprises within the timelines mandated under the MSMED Act, 2006 (15 days without agreement, up to 45 days with agreement), commercial culture has seen a structural pivot toward timely payment discipline.

Grassroots Realities: Issues Faced by Rural Micro-Enterprises and Expected Resolutions

While tier-1 and tier-2 urban MSMEs have rapidly adapted to digital fintech credit, India's vast rural micro-industrial sector-encompassing village artisans, agro-processing units, handlooms, and rural fabricators-continues to confront distinct structural challenges:

Rural Micro-Enterprise Bottlenecks & Strategic Remedies

• **Credit Delivery Deficit & Brick-and-Mortar Gaps:** Rural Branches and Banking Correspondents (BCs) are often restricted to micro-savings and retail transfers, lacking appraisal capacity or delegation powers for term loans and working capital.

• **Land Title & Non-Agricultural (NA) Conversion Impediments:** Rural land records and ancestral commercial properties frequently lack clear cadastral titling or NA conversion certificates, leading to arbitrary loan rejections by conservative bank branches.

• **Informal Inflows & Cash-Economy Penalty:** Because rural micro units operate with high cash dependency and limited GST trail generation, algorithmic credit engines based on digital receipts fail to capture their true cash-flow health.

• **High Power & Cold-Chain Logistics Vulnerability:** Unreliable rural power feeders and lack of decentralized warehousing/cold chains cause heavy post-production wastage, eroding operating margins.

Expected Policy & Banking Resolutions for Rural Micro Units:

• **Dedicated 'Gramin Udyog Credit Card' (GUCC):** Roll out a specialized, revolving working capital credit card tailored for rural micro-manufacturing and agro-processing units with automatic credit limit enhancements tied to seasonal crop and procurement cycles.

• **Integration of Regional Rural Banks (RRBs) and DCCBs into ULI:** Upgrade the digital infrastructure of Regional Rural Banks and District Central Co-operative Banks to onboard them onto the Unified Lending Interface (ULI) and Account Aggregator network, democratizing credit at the taluka level.

• **Digitized Revenue Title Harmonization:** State Governments and RBI must formulate simplified hypothecation guidelines for rural non-agricultural commercial sheds without requiring exhaustive, expensive NA land conversions.

• **Sub-Target for Rural Micro Manufacturing under Priority Sector Lending (PSL):** Mandate a dedicated 3% carve-out within the overall MSME PSL allocation exclusively for rural manufacturing and processing micro-enterprises.

Proposals in Hand: Operational Reforms for Domestic Units & Import-Export Business

While structural reforms have expanded formal credit, key operational frictions continue to hinder the MSME ecosystem:

A. Domestic Regulatory Rationalization

• **Rationalization of 90-Day NPA Norm:** The rigid 90-day overdue norm does not reflect MSME operating cycles where corporate buyers take 90-120 days to settle bills. The NPA classification horizon must be extended to 180 days for active GST-compliant units.

• **Reforming External Credit Rating Requirements:** Replace mandatory third-party credit ratings for loans up to ₹25 crore with automated, internal scoring models calibrated on GST and tax compliance data.

• **Rationalization of Bank Charges & Prompt Title Return:** Enforce strict penal action against bank branches seeking informal collateral under CGTMSE, and establish digital title registries ensuring title deeds are returned within 15 days of loan closure.

B. Crucial Banking Reforms for Import-Export (Exim) MSMEs

To elevate India's MSME share in global trade to 60%, the banking and regulatory framework for Exim enterprises requires immediate modernization:

• **Subsidized & Institutionalized FX Hedging Desks:** MSME exporters operating on razor-thin margins are acutely vulnerable to currency volatility. Public sector banks must establish simplified, subsidized currency hedging desks that eliminate prohibitive minimum lot sizes and high margin requirements for small exporters.

• **Expansion of Pre- and Post-Shipment Export Credit:** Re-establish a universal, enhanced 4% Interest Equalization Scheme for both pre-shipment and post-shipment rupee export credit across all labor-intensive and engineering MSME categories.

• **Streamlining RBI EDPMS and IDPMS Systems:** Integrate the Export Data Processing and Monitoring System (EDPMS) and Import Data Processing and Monitoring System (IDPMS) with customs (ICEGATE) and banking portals to automate reconciliation, allowing simplified self-write-off and extension procedures without punitive cautionary listing for minor delays.

• **Cross-Border Trade Receivables Discounting:** Enable cross-border factoring on the International Trade Financing Services (ITFS) platforms set up at GIFT City (IFSC), connecting Indian small exporters directly with global liquidity pools at benchmark global interest rates.

Long-Term Strategy for Strengthening the Rupee & Currency Internationalization

A strong, stable, and globally accepted national currency is the ultimate safeguard for domestic MSMEs against imported inflation, raw material price shocks, and unhedged exchange rate risks. A deliberate, long-term roadmap for Rupee Internationalization and structural strength must encompass:

The Roadmap for Viksit Bharat 2047: The MSME Vision

As India marches toward its centenary of independence in 2047 with the goal of becoming a $30-trillion developed economy (Viksit Bharat), the MSME sector must scale from a survival-led model to a globally competitive manufacturing powerhouse.

Key quantitative targets for MSME Vision 2047 include:

- **Contribution to India's GDP:** Targeting an increase from ~30% today to 50% by 2047.
- **Share of National Exports:** Expanding from ~45% to over 60% of total export volumes.
- **Universal Formal Credit Access:** Reaching 95%+ coverage across all registered micro and small units.
- **Industrial Capability:** Transitioning from semi-automated shops to Industry 4.0/5.0 and net-zero green manufacturing.

Three Strategic Pillars for 2047:

High-Tech and Industry 4.0 Capital Access: Provide subsidized, long-tenure (10-to-15 year) capital financing facilities for automation, precision tooling, clean-tech, and advanced robotics to transition units from low-value assembly to high-margin global manufacturing.

Green Financing and ESG Transition:

With global markets adopting Carbon Border Adjustment Mechanisms (CBAM), Indian banking must establish specialized green credit lines at

concessional interest rates to assist small enterprises in decarbonizing operations.

Decentralized Cluster Financing:

Establish specialized, sector-focused MSME branches in Tier-2, Tier-3, and rural hubs to integrate traditional artisanal clusters and rural agro-enterprises into global supply networks.

Charter of Demands: Expected Support from Government of India and RBI

To turn the 2047 vision into actionable policy, targeted interventions are required from both the central government and the banking regulator:

A. From the Government of India (Ministry of Finance & Ministry of MSME)

- **Universal 3% Interest Equalization Scheme:** Re-establish and widen the interest subvention scheme across all manufacturing MSMEs to buffer small units against global interest rate volatility.
- **Expansion of the Self-Reliant India (SRI) Fund:** Scale the ₹50,000 crore equity infusion corpus under the SRI Fund to provide growth equity without forcing promoters to dilute control.
- **Mandatory TReDS Settlement for All Corporates:** Lower the TReDS onboarding threshold to companies with turnover of ₹100 crore, and introduce automated penalties on corporate tax filings for non-compliance.
- **Credit Guarantee for Green Transitions:** Establish an explicit 'Green CGTMSE' guarantee window with 90% coverage for capital investments in solar, waste management, and energy-efficient machinery.

B. From the Reserve Bank of India (RBI)

- **Special Liquidity Refinance Facility via SIDBI:** Create a permanent, low-cost liquidity refinance window dedicated to SIDBI and NBFCs specializing in micro-enterprise lending.
- **Calibrated Risk-Weights for MSME Portfolios:** Reduce capital risk-weights on bank exposures to micro and small enterprises that maintain spotless GST compliance and digital transaction trails.
- **Strengthening the Digital Co-Lending Framework:** Refine priority sector lending (PSL) guidelines to incentivize transparent co-lending partnerships between PSBs and technology-enabled NBFCs.

Conclusion: The Collective Mission of Laghu Udyog Bharati

The banking reforms implemented between 2014 and 2026 have built a strong, inclusive, and technology-driven foundation for enterprise finance. The shift from relationship-based lending to data-driven, rule-based credit delivery has democratized opportunities for millions of micro and small entrepreneurs across the country.

However, the journey to a $30-trillion economy by 2047 demands sustained policy focus. Laghu Udyog Bharati remains committed to serving as an active bridge between grassroots enterprises, the Government of India, and the Reserve Bank of India. By empowering rural micro-enterprises, modernizing Exim credit architecture, expanding the global footprint of the Indian Rupee, rationalizing NPA classifications, and unlocking green growth equity, India will establish an unshakeable foundation for industrial self-reliance (Aatmanirbhar Bharat) and shared national prosperity.

○○○

The first Steering Committee meeting for India Stonemart 2028 and the 11th Global Stone Technology Forum (GSTF) 2026 was held at Udyog Bhawan, Jaipur on 17th August. The meeting was chaired by Shri Suresh Ola (IAS), MD-RIICO. Preparations and progress regarding the events were discussed in detail. The 14th India Stonemart-2028 is scheduled to be held in Jaipur from February 17 to 20, 2028, while the 11th GSTF-2026 will take place in Udaipur on December 18–19. Senior officials from CDOS and RIICO, along with LUB National Joint General Secretary Shri Naresh Pareek, Former National Treasurer CA Yogesh Gautam, National Secretary Smt. Anju Singh, and Stonemart Convener Shri Natwar Lal Ajmera, were also present at the meeting.

Learning from India's Defining Startup Decade 2016-26 under NaMo Regime

Mega Opportunity
Gorakhnath Sunil Sirsikar
Architect of Impact & Entrepreneur
Member LUB's Core Team, Mass Comm.
gorakh@nickelwala.com

A startup is not a mystical concept reserved for techies, coders, venture capitalists or metropolitan founders. It begins when an individual or team turns a genuine problem into an innovative solution that can be repeated, scaled and sustained.

For many of us, including accomplished business leaders and public representatives, a "startup" can still sound like something which is meant for a club of technocrats or Ivy League alumni. Well it's not. Throw away the jargon and the idea is much simpler: a startup begins when a person or team identifies a real problem, creates a new or substantially better solution, and builds a model that can be repeated and expanded beyond one customer, one shop or even beyond the founder's own team.

Every *Idea* can become a Capable & Scalable Startup-

The opportunity is therefore not reserved for elite institutions, metropolitan networks or people already fluent in the language of finance and technology. A farmer who develops a scalable crop-monitoring method, a technician who redesigns an industrial process, a homemaker who turns a local solution into a repeatable service, a doctor who commercializes a device, or an MSME team that creates a new material can all begin a startup journey. Not every new business is a startup, and not every idea must seek venture capital. What matters is the ability to solve each genuine problem innovatively, assemble or acquire the necessary skills, build the right team and develop a solution capable of reaching many more users.

Let's look at when and how this opportunity started opening up. From 2014 onwards, Make in India, Swachh Bharat, Digital India, Skill India and a renewed infrastructure drive placed technology, manufacturing, skills and practical problem-solving at the centre of national development. They made large needs more

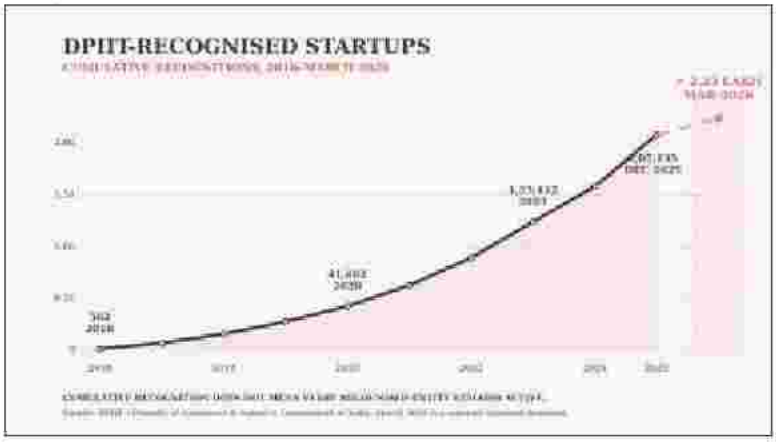

visible and created demand for better products, cleaner processes, digital services and local solutions. Startup India, launched on 16 January, 2016 with a 19-point Action Plan, then gave aspiring founders a clearer doorway through recognition, simpler rules, funding support, intellectual-property assistance, incubation and links between industry and academia. The change in scale is remarkable. India moved from around 500 DPIIT-recognized startups in 2016 to more than 2.23 lakh by March 2026, with more than 23 lakh direct jobs reported.

By June, the Government placed the figures above 2.35 lakh startups and around 24 lakh jobs; more than half were reported from Tier-II and Tier-III cities, and nearly half had at least one-woman director or partner. This does not mean that every recognized startup is funded, active or successful. It means that starting an innovation-led enterprise has become a credible ambition across Bharat. The question now is how more of these ventures can become reliable products, lasting companies, productive jo bs, exports and intellectual property. Valuation is one milestone. Nation-building requires value creation.

National Priorities have Opened Doors for Entrepreneurs

Startups do not grow in a vacuum. They grow when roads, digital systems, standards, customers and large public priorities make a problem easier to reach and solve. Make in India and the Production Linked Incentive schemes increased attention on sectors such as electronics, medical devices, automobiles, batteries, solar equipment, telecom, food processing and drones. For an entrepreneur, each large sector contains hundreds of smaller openings: a safer component, a cheaper sensor, better quality control, less waste, quicker maintenance or software that helps a factory work more efficiently.

Digital India and India Stack have lowered another barrier. Think of digital identity, instant payments, electronic documents and consent-based data exchange as common roads on which many businesses can travel. A fintech founder did not have to invent a national payment network before testing a useful service. UPI widened the field for experimentation, while the Government e-Marketplace gave qualifying young companies a possible route to public buyers.

The same is true of cleanliness, water, renewable energy, farming, mobility and financial inclusion. These programs brought everyday challenges into sharper focus: How can waste be sorted profitably? How can a farmer reduce crop loss? How can a small factory use less energy? How can a clinic serve a remote patient? A startup opportunity often begins with such a question. The enabling system is valuable when it helps a capable team test the answer, meet the required standard, find the first customer and repeat the solution at a larger scale.

What makes a Startup Different?

A startup is not simply a recently opened business. In everyday commercial language, it is a young enterprise searching for a repeatable and scalable way to solve a problem under conditions of uncertainty. Its most distinguishing features are usually innovation, the intelligent use of specialized skills, a model capable of growing beyond one location or founder, and the potential to create employment or wealth at scale.

The legal definition is necessarily more precise. Under the revised DPIIT framework notified in February 2026, an eligible entity is generally within 10 years of incorporation, has not exceeded annual turnover of Rs. 200 crore, and is working towards innovation or improvement of products, processes or services, or a scalable model with high potential for employment or wealth creation. A new deep-tech category recognizes the longer gestation of research-intensive companies, allowing up to twenty years and a turnover threshold of Rs. 300 crore.

That definition also explains why a startup and an MSME are not competing categories. "Startup" describes age, innovation and scalability under a recognition framework. "MSME" classifies an enterprise by investment and turnover under a different law. A company may be both. More importantly, even where the labels do not overlap, their capabilities can.

A Decade of Laying the Foundations for Today's Startup Opportunity

Over the past decade, India has gradually built a staircase for founders. Recognition and self-

certification made the first step easier. Patent and trademark support helped protect an original solution. Incubators and seed schemes helped some teams move from an idea to a prototype and a first market test. The Fund of Funds encouraged investment through professionally managed funds, while the credit-guarantee scheme opened another path for eligible borrowers. Procurement relaxations and GeM then gave qualified startups a chance to sell, because a credible first customer can be as valuable as a grant. Some figures make this foundation easier to picture. A recognized startup can receive an 80 per cent rebate on patent filing fees. Startups received more than 1.40 lakh GeM orders in FY 2025-26. More than 10,000 Atal Tinkering Labs now introduce school students in every district to experimentation and problem-solving. Around these sit many sector-specific programs: BIRAC for Biotechnology sector, RKVY-RAFTAAR for Agriculture, iDEX and ADITI for Defence, IN-SPACe for Space, NIDHI for Science and Technology, and MeitY programs for Digital ventures. A founder does not need to memories this alphabet soup. The useful lesson is that support now exists at several stages; the real skill is finding the right doorway for the problem, sector and maturity of the venture.

Innovation or Skills by themselves cannot Guarantee Progress or Success

An idea is not yet an innovation. It becomes one when people use it and a team can deliver it reliably. A clever water sensor that fails in summer heat is still only a promising prototype. A food product that customers like but cannot be produced safely and consistently is not ready to scale. Innovation becomes valuable through testing, correction and repeated use.

Skills are not limited to degrees or coding. A startup may need a mechanic who understands machines, a designer who makes the product easy to use, a salesperson who listens carefully, an accountant who protects cash and a technician who can repair the product in the field. Skill India, PMKVY, apprenticeships and programs such as FutureSkills Prime have widened routes to technical and digital learning. But a certificate is only a beginning; capability appears when that learning solves a customer's problem.

No founder needs to know everything. The stronger founder knows what is missing and brings together people with complementary strengths. An engineer may build the product but need help with pricing and sales. A market expert may understand the customer but need a manufacturing partner. A doctor with a device idea may need a biomedical engineer, a regulatory adviser and an experienced MSME supplier. The team turns individual knowledge into a working enterprise.

Five Spices of the Recipe:

Innovation, Skills, Team, Execution & Continuous learning. A startup grows stronger when all five factors improve together.

Execution is the everyday discipline behind the excitement: deciding who does what, testing before spending heavily, checking quality, collecting payment, responding to complaints and learning why something failed. Continuous learning means changing a feature when customers struggle with it, improving a process when defects appear and admitting bad news early enough to act. This is how a team turns energy into progress.

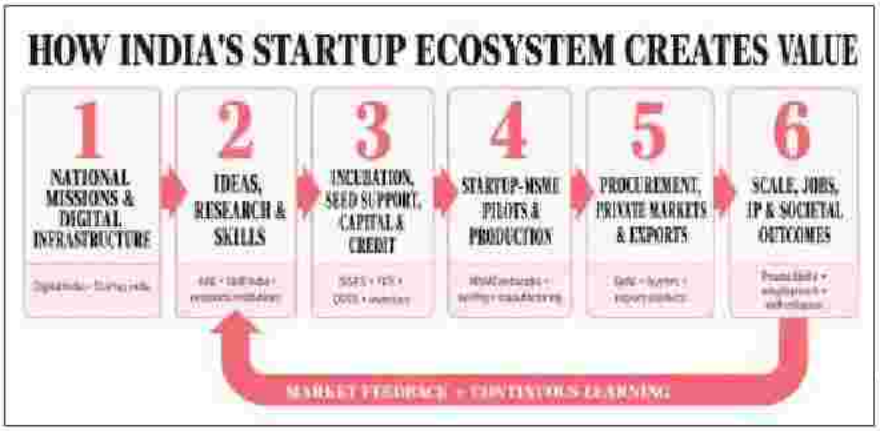

The need becomes even clearer in physical and regulated sectors. A medical device must be safe. A battery or drone must meet standards. An agricultural input must work outside the laboratory. An industrial machine needs installation, spare parts and after-sales service. Enthusiasm may begin the journey, but reliability, teamwork and disciplined learning carry it forward.

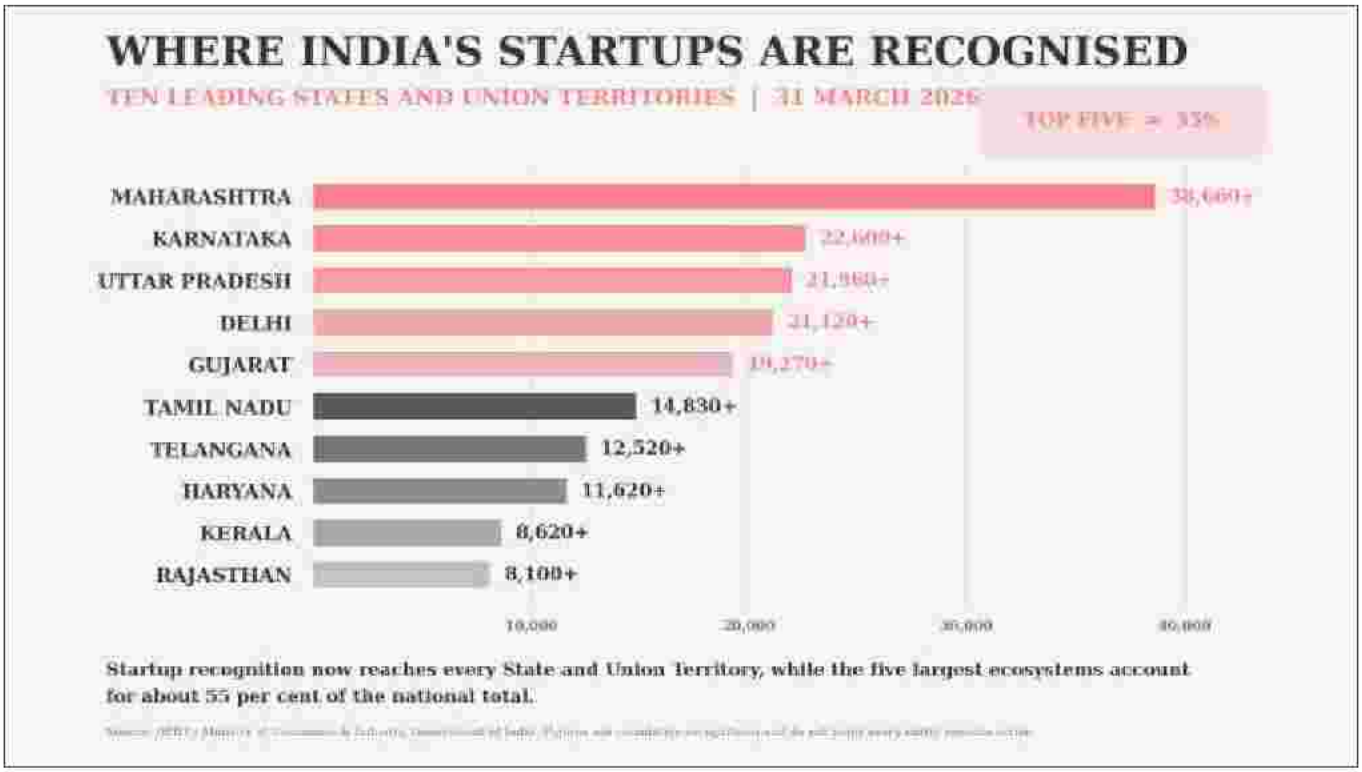

Startup-MSME Partnership Bharat Needs

India's established MSMEs possess assets that many startups spend years trying to build: production knowledge, vendor relationships, trained workers, distribution networks, customer trust and an instinct for cost. Startups bring complementary strengths: software, sensors, data, new materials, digital channels, fresh product

design and a willingness to challenge old assumptions.

The productive question is not, "Will startups replace MSMEs?" It is, "How can both make each other more competitive?" An agritech startup can work with a food-processing MSME to improve traceability and reduce waste. An industrial AI venture can help a factory predict downtime. A climate-tech company can convert waste into a saleable resource. A defence space startup may need precision components that an experienced small manufacturer can supply. An MSME with a respected product can use a fintech, logistics or SaaS partner to reach new markets.

This collaboration also gives startups something capital cannot purchase quickly: operating reality. It helps founders design for Indian price points, harsh conditions, serviceability, compliance and the variability of real supply chains. In return, MSMEs gain access to innovation without having to build every capability internally. LUB can become an active bridge through challenge statements, pilot programs, supplier discovery, founder-MSME meetings and sector-specific technology adoption forums.

There is Still a Long Way to Go

The opportunity is wider, but access is still uneven. Funding rises and falls, and much of it continues to gather in a few large cities. In one 2025 dataset, Bengaluru and Delhi together received 51 per cent of the funding reported. A founder in an emerging city may find a nearby incubator yet still struggle to reach an experienced mentor, a specialized laboratory, a patient investor or a first serious customer. Recognition has spread faster than all the resources needed to succeed.

Some startups will also close, and that is part of entrepreneurship. By January 2026, 6,789 recognized startups were listed as dissolved or struck off, although this cannot be treated as India's startup failure rate. The reasons are usually understandable: the customer did not need the product enough, it cost more to sell than the business earned, co-founders stopped trusting one another, cash ran out, quality slipped or the company

expanded before learning what worked. These are not fashionable phrases. They are ordinary business lessons that every new founder should understand early.

Deep-tech ventures face an even longer road because laboratories, certification, testing and industrial adoption take time. NITI Aayog has highlighted gaps in long-term finance, shared research facilities, links between academia and industry, and regulatory processes. The answer is not to lower India's ambition. It is to make mentoring more practical, testing more accessible, finance more patient and industry partnerships easier. Progress should ultimately be measured by products adopted, patents put to use, exports earned, good jobs sustained and problems solved, not registrations alone.

The next Decade: from More Startups to Stronger Enterprises

A startup is a disciplined attempt to solve a worthwhile problem in a fairly new or substantially better way, and to build a team and a model that can repeat the solution for many users. Any Indian can begin that journey because useful problems are everywhere, and people who live or work close to a problem often understand it better than distant experts. The first step is not registering a company or raising money. It is observing carefully, defining the problem clearly and proving that someone genuinely needs the proposed solution.

For founders, the message is equally clear. Funding is fuel, not the destination. Build for a genuine need. Protect and commercialize intellectual property. Recruit people who complement the founders. Measure cash, quality and customer outcomes. Learn continuously. Treat governance as an asset from the first day. Seek partnerships with manufacturers and market operators who understand execution.

Starting, however, raises very many basic questions that are rarely answered in simple language. Where do I begin? Is the problem I see truly startup-worthy? How do I turn it into a clear vision and mission? How can I test the idea before spending my savings? Where do I find the co-founders or the team members if I do not know them personally? Which networks, incubators, universities, industry associations, MSME groups and digital communities can help me reach mentors, laboratories, suppliers, customers and investors? What must I understand about registration, intellectual property, accounts, contracts and governance?

The series will address these questions alongside real company journeys. It will also flag traps: fake accelerators, guaranteed-return claims, Ponzi or investment schemes presented as startup opportunities, unverified grants, expensive consultants promising assured funding, investors who demand unexplained advance fees, and agreements that take away control or intellectual property without fair value. Ambition needs courage, but it also needs verification and sound advice.

Today, the startup opportunity has been democratized: it is no longer limited to technology experts, large investors or metropolitan founders. A second-generation steel trader, for example, has launched "Steel Yoga: We Bend Steel the Way You Want", transforming ordinary rebars into customized shapes and angles and earning a substantial premium over simply buying, loading and selling steel. Similar opportunities exist in every trade, industry and community, wherever knowledge, skill and innovation can solve a real problem or add meaningful value. The possibilities are endless, and the opportunity is yours to seize. Come let's build the Bharat we all dreamed of living in, one startup at a time!

LUB's Haryana state unit holds its EC Meeting to present its two-year vision document, outlining key priorities, proposed initiatives and the organisational roadmap on 13th August. Shri Arun Bajaj AIWC Member & State Prabhari; Shri Subh Adesh Mittal-North Zone Seh-Prabhari, Shri Raman Saluja-State President & Shri Manoj Rungta-General Secretary, and Shri Sanjay Data-State Treasurer. The brainstorming session was chaired by Shri Om Prakash Gupta-National General Secretary.

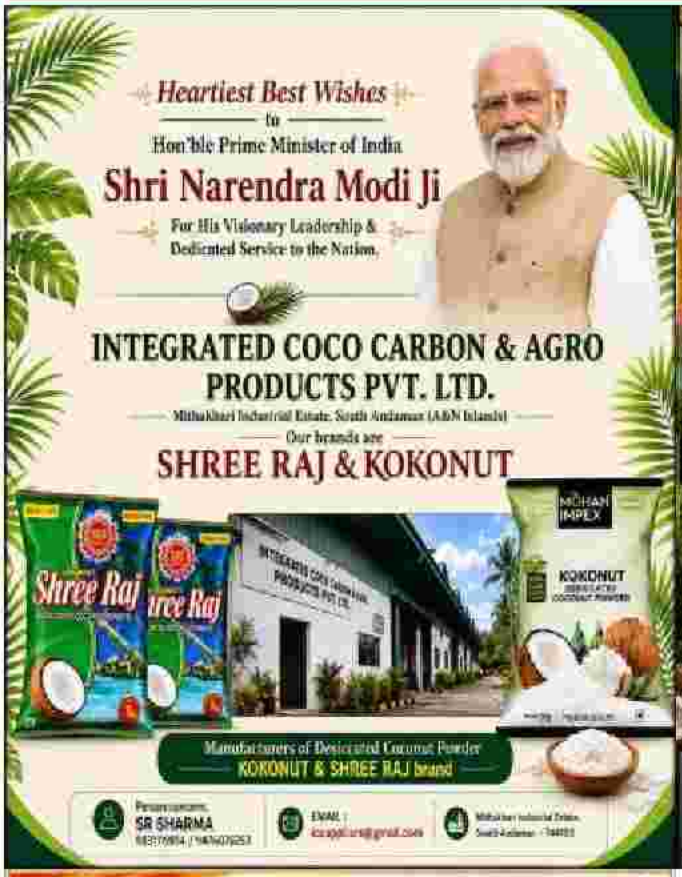

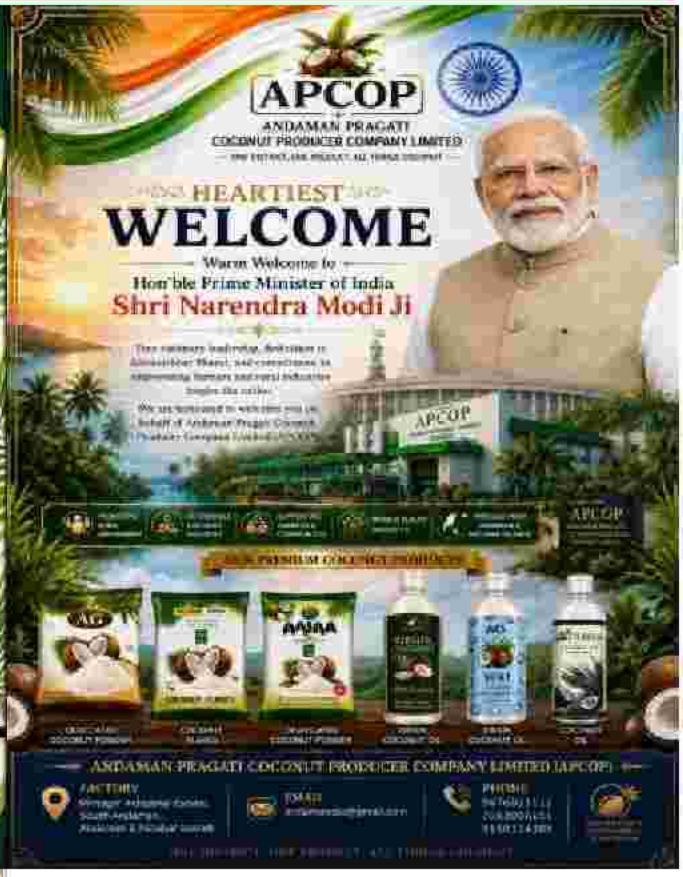

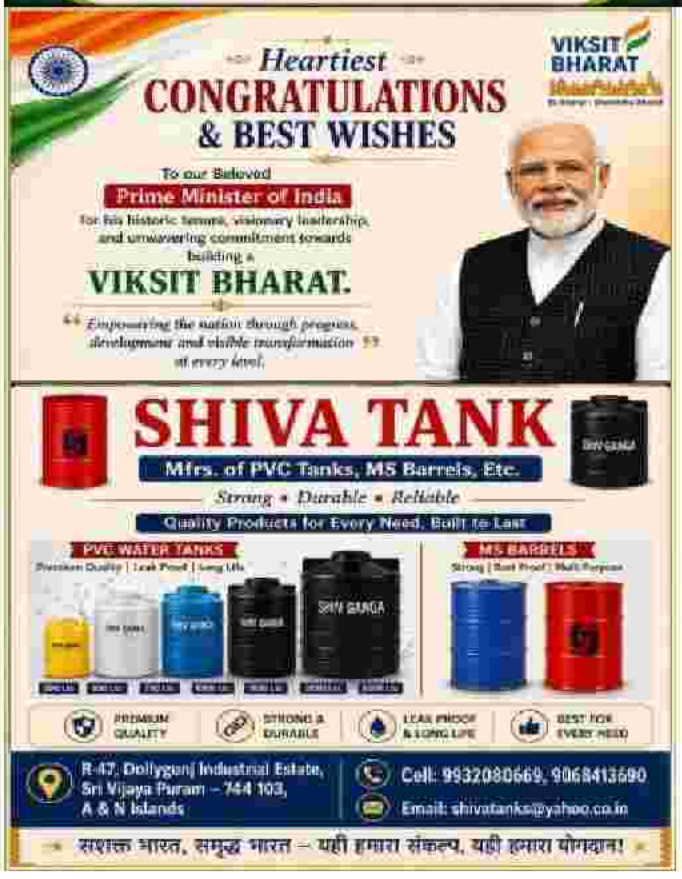

LUB's Meerut Anchal launched an Entrepreneurship Development Program (EDP) in collaboration with the Ministry of Textiles, Govt. of India (Office of the Development Commissioner for Handlooms). In the first phase, a 45-day training program for 30 women was initiated at the Deendayal Bunkar Kendra. The objective of this training is to equip women with practical skills in handloom and textile production, thereby enabling them to pursue self-employment, establish micro-enterprises, and achieve economic self-reliance. Eligible women who successfully complete the training will be provided with a handloom machine worth approximately ₹30,000-under a Ministry scheme-for a contribution of just ₹3,000, allowing them to start their own enterprises and become self-reliant.

लघु उद्योग भारती

Logo Connecting Industry with Skills, Technology & Expertise

*Laghu Udyog Bharati (LUB), through its **Industry-Academia and Technology Transfer Vertical**, continues to strengthen connections between industry, academia, research institutions and the wider innovation ecosystem, creating opportunities for MSMEs as well as young talent.*

Strengthening Industry-Academia Collaboration through Internships

Laghu Udyog Bharati hosted the Certificate Distribution Ceremony for the third batch of students from Zakir Husain Delhi College, celebrating the successful completion of their internship program on 10th August. Smt. Aarti Sehgal-GS LUB Delhi, Shri Jagdish Bishnoi and Shri Ashok Sharma from ZH Delhi College shared their perspectives on the internship and spoke about the successful partnership developed between ZHDC and LUB. Dr. Arshpreet Kaur, Nodal Officer - Research & Industry Collaborations-LUB addressed the students and emphasised the importance of problem-solving, communication, teamwork, digital skills, taking initiative, timely completion of work and staying updated with emerging technologies. The program reflects LUB's continued commitment to youth skilling and strengthening Industry-Academia collaboration by providing students with practical exposure to the MSME ecosystem.

Connecting MSME Challenges with Technology Solutions

LUB initiated another round of **collection of technical problem statements from members across India** to identify the specific technological challenges faced by MSMEs. The initiative seeks to connect these requirements with suitable **CSIR laboratories, academic institutions, faculty members and technology providers** that can offer potential solutions and opportunities for collaboration. This effort aims to bridge the gap between industry needs and available technological expertise while facilitating technology adoption and innovation among MSMEs.

Supporting Entrepreneurs through Business Growth and Mentorship

LUB has also partnered with the **Wadhwani Foundation** for a Business Growth & Mentorship Program, with 14 LUB members selected to participate. The 12-week program is designed for entrepreneurs looking to expand into new markets, strengthen operations, increase sales, launch new products, explore export opportunities, attract institutional customers or prepare the next generation for leadership. Participants will receive one-on-one mentoring from experienced industry experts, support from a dedicated Growth Advisor, AI-powered business assistance, practical execution sessions, a customized 90-day growth plan, and access to a network of entrepreneurs and ecosystem partners. The program is completely free of cost, with no fees and no equity involvement. It aims to empower participating entrepreneurs with practical strategies and actionable plans to accelerate and sustain business growth.

Together, these initiatives reflect LUB's continued commitment to connecting MSMEs with the right skills, technologies and expertise to foster innovation, enhance competitiveness and enable sustainable growth.

LAGHU UDYOG BHARATI

Office Bearers Nominated to Boards/Committees of Government

SN	Name & Designation	Contacts & Email-ID	Name of the Department
1.	Shri Madhu Sudan Dadu All India President	0-98102-56494 president@lubindia.com	Member, Governing Council of National Institute-MSME
2.	Shri Baldevbhai Govindbhai Prajapati All India Ex-President	0-98241-55666 gopsipharma@yahoo.com	Member, Employees Provident Fund Board
			Member, Advisory Committee Pharmaceuticals Sector, MP.
3.	Shri Sachin B. Sabnis All India Vice President	0-98452-73756 sachinsabnis@bfplindia.com	Member, Employees Provident Fund Board
			Non-Official Director on the Board of IRCTC
4.	Shri Saroj Kumar Sahoo All India Vice President	0-98743-93543 sksahoo_100@yahoo.co.in	Non-official part-time Director on the Board of National Research Development Corporation
5.	Shri Sameer Mundra All India Vice President	0-94250-48018 sameer_mundra@yahoo.co.in	Non-official Director on the Board of MIDHANI (21.08.2026 to 20.08.2029)
			Member, 16th General Council of V.V. Giri National Labour Institute, Employers Organisation
			Member of Governing Council/ General Body of MSME Technology Centre, Durg, M.P.
6.	Shri Naresh Chand Pareek All India Jt. General Secretary	0-93421-63719 npgranite@yahoo.com nareshpareekmedas@gmail.com	Member, Employees State Insurance Corporation
			Member, Advisory Committee for MSME
7.	Shri Ashish Deorah All India Jt. General Secretary	0-97060-44445 ashish.deorah@yummyfoods.co.in	Food Processing Sector, MP.
8.	Smt. Anju Bajaj All India Secretary	0-98108-89787 bajajanju55@gmail.com	Member, Central Advisory Board (CAB), Wage Cell
9.	Shri Nirmal Kumar Ojha All India Jt. Treasurer	0-94231-28611 ojhabusinessconsultancy@gmail.com	Member, Consultation Committee Associated with GST

10.	Shri Girish Arora Advisor, Andaman & Nicobar	0-94342-80295 arorapb@gmail.com	Member, National Traders Welfare Board
11.	Shri Amit Agarwal General Secretary, Uttar Pradesh	0-98370-26381 amit@kumarinternational.com	Non-Official Director (Independent) on the Board of Hemisphere Properties India Limited
12.	Shri K.M. Ravi Kumar General Secretary, Karnataka	0-98450-13077 generalsecretary@lubkarnataka.org; rkec12@gmail.com	Non-official Director on the Board of Mazagon Dock Shipbuilders Limited
13.	Shri Hariharan Ramamurthy All India Executive Member	0-95435-77333 srh@srimukhagroup.co.in	Member, Employees State Insurance Corporation
14.	Shri Ladli Prasad Gupta All India Executive Member	0-94151-27726 vmi_knp@yahoo.co.in	Member, National Safety Council
15.	Shri Partha Pratim Pathak President, Assam	0-98640-64319 info@freshairindia.com	Non-Official Director (Independent Director) on the Board of BEL, Bengaluru
16.	Shri Arun Soni General Secretary, Madhya Pradesh	0-94251-53436 arun.sonishrijee@gmail.com	Food Processing Sector, MP.
17.	Dr. Rajesh Gupta Head, Pharma Utpad Samooh	0-94895-84574 rajeshgupta622@gmail.com	Special Invitee, Committee for Reforms in the Pricing Framework for Drugs
18.	Shri Sumit Goel Delhi Prant, Jt. Gen. Secretary	0-981181-1203 shantipackaging@gmail.com	Member, Department of Training Technical Education, Govt. of NCT of Delhi
19.	Shri Shyam Sunder Jindal Secretary, Delhi Prant	0-93124-00900 oliveledlights@gmail.com	Member, Department of Training Technical Education, Govt. of NCT of Delhi
20.	Smt. Manjula Mishra Mass Comm.	0-83838-64698 md.holosafe@gmail.com	Non-Official Director on the Board of IRFC
21.	Smt. Seema Mishra General Secretary, Malwa Sambhag	0-88275-05348 handloomfabrics1980@gmail.com	Non-official Director on the Board of Directors of HMT Limited, Bengaluru

LUB is also invited to following forum:
1. Pre Budget Consultation with Hon. M/o Finance
2. Board of Trade under M/o Commerce & Industry
3. International Labor Conference by ILO at Geneva

Further LUB is also participating in various State Level Committees

○○○

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

जयपुर विकास प्राधिकरण

डबल इंजन सरकार की 2.5 वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

राजस्थान सरकार

युवा शक्ति को अवसर राजस्थान को नई उड़ान

निष्पक्ष, पारदर्शी और पेपर लीक रहित भर्तियां

रोजगार, कौशल विकास, भर्ती, स्टार्टअप और नवाचार के माध्यम से युवाओं के सशक्त भविष्य का निर्माण

रोजगार एवं भर्ती

- **1 लाख 78 हजार सरकारी पदों पर नियुक्तियां**
- 51,427 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण- भर्ती प्रक्रियाधीन
- आगामी समय में होने वाली भर्तियां- 81,023 पद
- 70,031 पदों पर भर्ती की तैयारी

कौशल विकास एवं शिक्षा

- **3.58 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण**
- 76 नए राजकीय महाविद्यालय स्थापित
- **88,724 विद्यार्थियों को टैबलेट/लैपटॉप वितरण**
- 42,509 युवाओं को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ

टेक्नोलॉजी एवं भविष्य

- राजस्थान AI-ML पॉलिसी लागू
- AVGC-XR पॉलिसी से एनीमेशन, गेमिंग और डिजिटल रोजगार को बढ़ावा
- Rajasthan Digi Fest 2026 का सफल आयोजन

खेल एवं युवा सशक्तिकरण

- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का सफल आयोजन
- मुख्यमंत्री स्पोर्ट्सपर्सन बीमा योजना लागू
- राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम (RTOP) योजना शुरू

पारदर्शी भर्ती

- भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए एसआईटी का गठन
- **569 आरोपियों की गिरफ्तारी, 157 एफआईआर दर्ज**
- 410 भर्ती परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित

युवा कल्याण

- Rajasthan Coaching Centres (Control & Regulation) Bill लागू
- **माय भारत पोर्टल पर 19.40 लाख से अधिक युवा पंजीकृत, देश में दूसरा स्थान**

उच्च शिक्षा एवं अवसर

- **PRIME योजना से मेधावी विद्यार्थियों को रिसर्च और इंटर्नशिप के अवसर**
- Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDP) शुरू
- EV, Renewable Energy, BFSI, HR और Tourism जैसे नए रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम शुरू

स्टार्टअप एवं नवाचार

- राज्य में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 8,780
- **स्टार्टअप निवेश ₹250 करोड़ से बढ़कर ₹1,054 करोड़**
- 9 इंक्यूबेशन सेंटर और 65 लॉन्चपैड स्थापित
- **1,062 स्टार्टअप्स को ₹33.94 करोड़ की फंडिंग**

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

UDYOG TIMES OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI | August - 2026 | Registration No. RAJBIL/2016/69093 Postal Reg. No. : Jaipur City/433/2020-22

Narendra Modi
Prime Minister

MAGNETIC MAHARASHTRA

Devendra Fadnavis
Chief Minister

Dighi Port Industrial Area (DPIA)

India's Next Gateway for Port Led Industrial Growth

Strategically located. Future ready. Built for global trade.

DPIA is a flagship greenfield industrial development by Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC), envisioned as a port-led industrial smart city that accelerates manufacturing, exports, and logistics-driven growth.

Total Area: 6113 acres

Total Plots Available: 250 (in first slot)

WHY INVEST IN DPIA?

Superior Connectivity

- **Roadways**
  Mumbai-Goa NH-66: 1 Km
  Kolad-Pune NH-753F: 5 Km
  Mumbai Trans Harbour Link: 110 Km
- **Railways**
  Indapur: 7 Km | Mangaon: 15 Km | Kolad: 5 Km
- **Airports**
  Navi Mumbai: 95 Km | Pune: 116 Km
  Mumbai: 125 Km
- **Seaports**
  Dighi: 60 Km
  JNPT: 95 Km
  Mumbai: 125 Km
  Proposed Vadhvan Port: 250 Km

Designed for Long Term Growth

DPIA is a future ready economic hub aligned with the vision of Viksit Bharat, offering investors:

- Lower logistics costs
- Faster market access
- Scalable land availability
- Government backed development and facilitation

Common Infrastructure

Infrastructure is in full swing at complete stage which includes:

1. Approach road and internal road over length of 32 km
2. Pipeline, WTP and electrical infrastructure is also on the verge of completion
3. Grade separate to connect area to Mumbai - Goa highway is planned

Enquire | Invest

Scan QR code to apply for MIDC land allotment on MILAAP portal

MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of Maharashtra Undertaking)

Follow us
lubindia
@lubBharat
laghu-udyog-bharati
lubindia
lub.india

LUB's Monthly Magazine Published by Madhu Sudan Dadu Printed at Raj Blocks, 22 Godown Ind. Area Kartapura, JAIPUR-302019